



देवेन्द्र कौशिक

# आधुनिक मध्य एशिया

(१९वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर अब तक का इतिहास)



प्रगति प्रकाशन • मास्को

अनुवादक अली अशरफ

Д. КАУШИК

Средняя Азия в новые времена

*На языке хинди*

हिन्दी अनुवाद • प्रगति प्रकाशन • १९७७

सोवियत संघ में मुद्रित ।

K  $\frac{11601-382}{014(01)-77}$  575-76



१. प्रस्तावना अध्याय । बुद्धारा और स्वार्थ लोक सोवियत जनतन्त्र	
से सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में सम्मेलन	२४२
नया अध्याय । सोवियत जातीय जनतन्त्रों का निर्माण	२५६
नया अध्याय । आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन	२७२
उपसंहार	३२१



लेखका के लिखे हुए हैं, जिन्हें आमूदरिया के उत्तर, हिंदूकुश के परे समाजवादी निमाण की उपलब्धियाँ की बाबत सच कहने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालाँकि ये ऐसी सफलताएँ हैं, जिनका उल्लेख भारतीय गणराज्य के प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद ने सोवियत संघ की अपनी यात्राओं के बाद उत्साहपूर्वक किया।

इसलिए यह आशा की जा सकती है कि इस पुस्तक का विशेष दिलचस्पी से पढ़ा जायगा। लेखक एक भारतीय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने सोवियत संघ में वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान अपने तथ्य जमा किये। वह घपहल ताश्कंद में रहे जो उज्बेकिस्तान की राजधानी और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थल है। वही उन्होंने अपना थीसिस लिखा और सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, जिनकी बदौलत उन्हें विज्ञान (इतिहास) के कंडिडेट (पीएच०डी०) की उपाधि मिली।

बड़े जातियाँ में यह कहावत है कि किसी चीज के बारे में सोचें बार-बार मुनन से अच्छा उसको एक बार देख लेना है। देवेन्द्र कौशिक ने सोवियत मध्य एशिया में नए सोवियत समाज को घुड़ अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने देखा है कि वह पेचीदा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और उन्नत विज्ञान तथा संस्कृति के फल से लाभान्वित हो रहा है।

एक ऐसे इतिहासकार की हैसियत से जिनने मध्य एशियाई जनजातों का अतीत का गहरा अध्ययन किया है, यह भारतीय विद्वान इस स्थिति में थे कि उन विज्ञान परिवर्तन का सही मूल्यांकन करें, जो सोवियत संघ के उग्र भाग में हुए हैं। वास्तव में वह यही बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान के लोगों ने (यह कज़ाख़स्तान की बात कम करते हैं) १९वाँ सदी के पूर्वार्द्ध से हमारे जमाने तक क्या रास्ता तय किया है। उन्होंने अनंत प्रशासित स्लावजा साम्यवादी मार-मूचिया पत्र-पत्रिका तथा पुरा संशोधन की मामूली का उपयोग किया है। उनकी पुस्तक वास्तव में तथ्यात्मक नहीं है, मगर कुछ-कुछ बातें सच हैं, जो कुछ लोग धर्म के नाम से नकारते हैं। उन्होंने अपने तथ्यों का प्रमाण दिया

है और उचित कालप्रमाणानुसार पेश किया है जिस से उनका महान् महत्त्व चिन्तन का परिचय मिलता है।

लेखक ने १६वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मध्य एशिया के पान शासित प्रशासन-बुधारा, ग्रीका और कोचान-की स्थिति का वर्णन किया है और टीका ही उनका अत्यन्त प्राथमिक सैनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन पर डार दिया है। वह मध्य एशिया में अंग्रेजों की साजिश और व्यापारिक तथा राजनीतिक पुनर्गठन की कागिशा, और उस इलाके में जारशाही के सैनिक विस्तार पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने यह विस्तृत सही कहा है कि जारशाही के अधिनारिया द्वारा वहाँ स्थापित प्रशासन औपनिवेशिक था, पर वह यह भी बताते हैं कि वहाँ प्रगतिशील हमी वैज्ञानिकों का, जिन में इतिहासविज्ञ भूवैज्ञानिक वनस्पतिज्ञ और प्राणिविज्ञ समी थे, कार्यवाप बहुत महत्त्वपूर्ण था। औपनिवेशिक तुर्किस्तान अथवा के विश्लेषण में लेखक इस सही नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस इला में पूजीवाद से पहले के संस्था की प्रमुखा थी।

पुस्तक का एक मूल्यवान पहलू यह है कि यह वादायक है। लेखक तथा को इकट्ठा करके इतिहास के पूजीवादी जानसाजों की कुत्सापूर्ण मनगढन्त का परदाफाश करते हैं, जिन्होंने सोवियत यथायता को ताड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयत्न किया है। इनमें जेफ्राफी ह्रीलर रिचर्ड पाइप्स, ह्यूग सीटन-वाटसन, अलेक्सांद्र पान और स० जेवाक्की हैं। देवेद्र कौशिक ने ह्रीलर के इस दाव का खंडन किया है कि बुधारा अक्टूबर क्रांति से पहले उन्नति कर रहा था। उस अंग्रेज लेखक ने मध्य युग के उस अधकारमय अवशेष, बुधारा के सामंती उपराज को बड़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया है, ताकि सोवियत युग में बुधारा नज़लिस्तान में जा शानदार परिवर्तन हुए हैं, उनके अमर को कम करे।

कौशिक ने अंग्रेज और अमरीकी "सोवियतज्ञों" के इस खूब दावे की धज्जिया उड़ाई है कि मध्य एशिया में समाजवादी क्रांति बाहर से लाई गई और लागू पर ख़वरदस्ती लादी गई थी। वह साबित करते हैं कि शोषित जनता में—उज़बेक, ताजिक, त्रिगिजा और तुर्कमाना में—समाजवादी क्रांति की ज़मीन तयार थी और वे अक्टूबर क्रांति की विजय



के लिए सावित सत्ता के लिए, जिसे वे स्वयं अपनी सत्ता मानते थे, वीरतापूर्वक लड़े। भारतीय विद्वान न ह्यूटनर के इस कथन का मजाक उड़ाया है कि मध्य एशिया का अथनल आज औपनिवेशिक है।

मुझे सब से अच्छी बात यह लगी कि लेखक ने मध्य एशिया और भारत के इतिहास में समान तत्वा की हमेशा तुलना करने का प्रयास किया है। उन्होंने आधुनिक युग में उनके संबंध का वर्णन अधिकतर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय अभिलेखागार की भूली विसरी दस्तावेजों के आधार पर किया है। इस प्रसंग में मैं उस दिलचस्प सूचना की चर्चा करना चाहूंगा, जो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय मूर्ति आंदोलन में हिस्सा लेनेवाला द्वारा सावित हम की यात्रा और प्ला० इ० लेनिन से उनकी भेंट के बारे में दी है।

मुझे आशा है कि भारतीय स्वाधीनता के सेनानियों—महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू—के दश में इस पुस्तक के दूसरे भाग पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिस में मध्य एशिया की जातियाँ के इतिहास के आधुनिकतम दौर—तुर्किस्तान में, बुखारा और खीवा खानशाही में श्रमजीवी जनमण की सत्ता की विजयी और सुदृढ़ बनाने के लिए उनका संघर्ष, राष्ट्रीय प्रभुसत्ताप्राप्त राष्ट्रीय जनतंत्र की स्थापना, शासन वर्ग का उन्मूलन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का अंत और उद्योग कृषि तथा संस्कृति का समानतादी स्थापित—पर प्रकाश डाला गया है। इन सब की इस पुस्तक में सविस्तार चर्चा की गई है। इन अध्ययन से लेखक के स्वदेशवासी जगत् में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आरशाही हम के पिछड़े औपनिवेशिक इलाकों का समाजवादी स्थापित करने तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी कम मुद्दत में उन्हें वर्तमान प्रभुसत्ता प्राप्त और उन्नत आधुनिक कृषि जनतंत्र बनाने के लिए क्या उपाय करने और कौन से साधन अपनाए पड़ें।

लेखक ने महात्मा को केवल कहीं कहीं कुछ संक्षिप्त किया गया जिसमें विषय वस्तु पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ कहीं हम टिप्पणी करने, या लेखक के किसी कथन पर बल देने की जरूरत हुई है, हम ने फुटनोट में 'ग०' का चिह्न लगाकर ऐसा किया है। चित्र भी हम ने चुने हैं।

न० आ० लालन  
विद्वान (इतिहास) के दायरे

हम भारतवासियों को मध्य एशिया की घटनाओं में हमेशा गहरी दिलचस्पी रही है। अनेक बार इन घटनाओं ने हमारे इतिहास की गति को प्रभावित किया है। ऐसे समय जबकि सोवियत संघ तथा भारत के जनगण की मंजूरी बिना नए जार पण्डित एतिहासिक विकास में हमारी दिलचस्पी और गहरी हो। प्रस्तुत पुस्तक में १९वीं सदी के शुरु से लेकर लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक के मध्य एशिया के आधुनिक इतिहास पर विचार किया गया है।

प्राक्कथन

दूर अतीत में मध्य एशिया का बड़ा महत्व था, भिन्न भिन्न सभ्यताओं और साम्यताओं की धाराएँ वहाँ आकर मिलती थीं। मगर १५वीं सदी के अंत में महान नाविकों की युगप्रवर्तों यात्राओं के बाद वह गुमनामी में पड़ गया। लेकिन १९वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों से जारशाही रुस तथा ब्रिटन की औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता के प्रभाव के कारण इस इलाके का कुछ-कुछ पुराना महत्व फिर बहाल हो गया। इस प्रकार मध्य एशिया का आधुनिक इतिहास जब शुरू हुआ, उस समय दो प्रतिद्वंद्वी पश्चिमी साम्राज्यों का साया इस इलाके पर था। मध्य एशिया की जातियाँ सामंती खानों के कुशासन तले अत्यंत आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की स्थिति में पड़ी हुई थीं। उनकी हैसियत दो यूरोपीय शक्तियों की औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता में शतरंज के मोहरा की थी।

इस पुस्तक की तैयारी में मैंने जो काय अपने सामने रखा है, वह था मध्य एशिया में जारशाही

रूस की बदेशिक नीति के उद्देश्यों की छानबीन करना, जहाँ तक उसका संबंध साम्राज्य की अदरुनी, खासकर आर्थिक स्थिति से था। मेरा दूसरा लक्ष्य मध्य एशिया में आंग्लरूसी प्रतिद्वन्द्विता की समस्या का आलोचनात्मक तथा व्यापक अध्ययन करना था। मध्य एशिया में जारशाही सरकार के आक्रामक चरित्र के बावजूद उसने प्रचलित आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत पर कब्जा करने का कभी इरादा नहीं किया। भारत पर रूसी आक्रमण का हौआ अंग्रेज साम्राज्यवादी हलकों ने झूठमठ खड़ा किया था क्योंकि वे मध्य एशिया में अपनी विस्तारवादी कारवाहियों पर परदा डालना चाहते थे। मैंने रूसी तथा भारतीय मूल सामग्रियों की सहायता से मध्य एशिया में ब्रिटेन के आक्रामक मनसूबों का परदाफाश किया है। मध्य एशिया में अंग्रेजों की साजिश का ही प्रभाव था कि उस इलाके पर रूसी कब्जे की रफ्तार तेज हो गई, जहाँ बुनियादी तौर पर विकासमान पूँजीवाद की विस्फारवादी आवश्यकताओं का नतीजा था।

मध्य एशिया पर रूसी कब्जा वस्तुनिष्ठ रूप से उस क्षेत्र के ऐतिहासिक विनाश के लिए प्रगतिशील महत्त्व रखता है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस इलाके में प्रारम्भिक पूँजीवाद का उदभव हुआ जिसके कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेज हो गये।\*

१९१७ की अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति ने मध्य एशिया की जातियों में जीवन में नया युग शुरू किया। क्रांति में पहले मध्य एशिया जारशाही रूस का उपनिवेश था। उसके विनाश का स्तर पूँजीवाद से पहले का था। उसका अथर्व पिछड़ा हुआ था और जीवन-स्तर दरिद्रता का हृत् तन नीच गिरा हुआ था। क्रांति के बाद मध्य एशिया का जानिया में अल्प मात्रिकत जानिया के साथ मिलकर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कम

\*मान्यत इतिहासकारों की राय में इस कब्जे का मुख्य प्रगतिशील पहलू यह था कि उसने मध्य एशिया में उत्पीड़ित श्रमजीवी जनगण का रूसी साम्राज्य की क्रांतिकारी पंक्तियों में जोड़ दिया और यह चीज भविष्य में जार, पूँजीपतियों और जमातों के शासन का तन्ना उखटन का निम्न, मार तथा में समाजवादी क्रांति की विजय के लिए वन मरत्वपूर्ण साबित हुआ।—स०

समय में एक समाजवादी समाज का निर्माण किया। समाजवादी बहुजातीय राज्य की स्थिति में, जो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित था, इस भूतपूर्व उपनिवेश में जिस ज़ारशाही साम्राज्य की परिधि में वतपूर्वक घेर रखा गया था, सत्तार के समक्ष स्वेच्छापूर्वक त्रिरात्राना सन्ध का ज्वलंत उदाहरण पेश किया।

कुछ और सोवियत जातियाँ की तरह मध्य एशिया के जनगण भी सत्तार में पहले से जा पूँजीवादपूर्व अवस्था से समाजवाद में अपने सन्ध में पूँजीवाद से बचकर निरन्तर गये। उनका अनुभव उन राष्ट्रों के लिए दिलचस्प होगा, जिन्होंने औपनिवेशिक गुलामी का जूझा उतार फेंका है और स्वतंत्र आपन तथा राजनीतिक विकास का रास्ता अपनाया है। प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप में बताया गया है कि मध्य एशिया के लोगों ने न केवल साम्यवाद सत्ता की स्थापना की अपने आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर किया, समाजवाद का निर्माण किया और तब से अब तक क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की।

आधुनिक मध्य एशिया के इतिहास के अध्ययन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अब तक उपेक्षित रहा है। इस हलाके से संबंधित काफी सामग्री भाग्यीय अभिलेखागारा में मौजूद है और इस सामग्री तथा मध्य एशिया तथा भारत की समस्याओं के प्रसंग में इसकी छानबीन वाछनीय है। मन हम मूल सामग्री का कुछ उपयोग किया है। इस किताब में मध्य एशिया और भारत के संबंधों पर भी एक अध्याय जोड़ा गया है। इस शीर्षक के अंतर्गत सिक्यम या चीनी तुकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है क्योंकि मध्य एशिया में आग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता से इसका गहरा संबंध है।

मैं बहुत से सोवियत विद्वानों तथा लेखकों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके अनुसंधानों और कृतियों का मैं व्यापक उपयोग किया है।

इसी तरह मैं आभारी हूँ सोवियत प्राकर्मरगण में ग० ग० बहाबोव, न० अ० खालफिन, अ० अ० गोदियेवा, ख० त० तुमनोव, ताशकंद के संबंधी ग० अ० हिम्यानीव, त० अ० तुतुनजान तथा व० दूबनिकोव का, जिन्होंने अपने विचारों से इस पुस्तक में प्रस्तुत समस्याओं पर ज्यादा अच्छी तरह दृष्टिपात करने और समझने में मेरी सहायता की।

विशेष रूप से मैं प्रोफेसर न० अ० खालफिन का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया और इस के बारे में कुछ शब्द लिखे हैं।

मैं अपने मित्रा सवथी सुरेश चंद्र अग्रवाल, साधुराम और शक्तिप्रसाद के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पाठ्य लिपि पढ़ी और कई बार आभार सुझाव दिये।

अपनी पत्नी राधा तुंगेश्वरी का मैं बहुत आभारी हूँ जिनकी सहायता और प्रोत्साहन इस काम का पूरा करने में मेरे लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुए।

इस पुस्तक को कई प्रकार की सहायता से तैयार पहुँचा है। मैं डॉ० बुद्धप्रकाश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे पहले मध्य एशिया का इतिहास में मेरी दिलचस्पी पैदा की।

विभिन्न पुस्तकालयों के कमियाँ के सौजन्य तथा सहयोग के लिए भी मुझे धन्यवाद देना चाहिये जहाँ से मैं इस कृति के लिए सामग्री प्राप्त की। इन में खासकर उल्लेखनीय है मास्को का लेनिन पुस्तकालय, ताशकंद का अलीशेर नवाई पुस्तकालय, उज्बेक सो० सं० जनतन्त्र की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संस्थान के पुरालेख संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंडियन नाउसिल आफ बुक एण्ड एफेयर्स, नई दिल्ली का पुस्तकालय और लन्दन का ब्रिटिश म्यूजियम। मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा पंजाब राज्य अभिलेखागार, पटियाला के अधिजातियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने रिवाज मुझे देखने दिये और उनका प्रयोग करने की मुझे इजाजत दी।

१९६२ से १९६५ तक लेनिन राज्य विश्वविद्यालय ताशकंद की पत्राणिका में मुझे भाग्यवत सहायता से सामग्री जुटान में बड़ी सहायता मिली।

इस काम का पूरा करने में और जिन लोगों ने तरह तरह से योगदान दिया, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। परन्तु मूल्यांकन और व्याख्या मेरा अपनी ही और कुछ जुटिया रह गई है ता मैं उनकी पूरा जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ।

देवेन्द्र कौशिक

नई दिल्ली,

मार्च १९६८

श्री जे बगरहटा, श्री  
श्री हगिज, श्री  
श्री याद, श्री  
श्री याद, श्री

भूमि

पाच सोवियत जनतंत्र—कजाखस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, गिजस्तान और तुक्मानिस्तान—एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं जिनके त्तर में पश्चिमी साइबेरिया दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान पश्चिम में बोल्गा और कास्पियन सागर और पूर्व में चीन हैं। इन जनतंत्रों में लगभग तीन करोड़ लोग रहते हैं, जो सोवियत संघ की कुल आबादी का दसवा हिस्सा हैं। इनका क्षेत्रफल ४० लाख वर्ग किलोमीटर है जो सोवियत संघ का छठा भाग है। कजाखस्तान का निकाल दिया जाये, तो मध्य एशिया का क्षेत्रफल कोई १३ लाख वर्ग किलोमीटर है। सब पूछिए ता सोवियत मध्य एशिया का नाम उपयुक्त पाच में सब केवल चार पर ही लागू होता है और उसमें कजाखस्तान शामिल नहीं है, जो नसली और सांस्कृतिक समानता के बावजूद भौगोलिक दृष्टि से मध्य एशिया से भिन्न है। यह एक स्टेपी इलाका है और जारशाही के जमाने के तथा सोवियत लड़का ने भी इसे अलग माना है।

इस पूरे क्षेत्र में मौसम तथा प्राकृतिक स्थितियाँ की अत्यंत विविधता पायी जाती है। पश्चिम और उत्तर में विशाल मैदान हैं। पूर्व और दक्षिण में काफी बड़ा इलाका पहाड़ी है। एक बड़ी पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम में कोपेत दाग से पूर्व में पामीर और तियान शान तक मध्य एशिया को अप

महाद्वीप से अलग करती है। इन इलाकों में बड़ा भेद पाया जाता है विशाल मरुत हैं जिनमें निचान समुद्र तल से नीचे पहुँच जाती है और पहाड़ा की चाटिया मरुत बर्फ से ढकी रहती है, घनी आबादीवाला नखलिस्तान के चारों ओर निजान रेगिस्तान है। पहाड़ों पर उत्तरध्रुवीय हिमपात है ता निचले मैदानों में उष्णदेशीय गर्मी। उत्तर में मौसम शीताण है और दक्षिण में गर्म है और गर्मियों में अत्यन्त शुष्क हो जाता है। समुद्रों में बहुत दूर होने के कारण मौसम वास्तव में महाद्वीपीय है। पहाड़ा की चाटिया साल भर बर्फ से ढकी रहती है और आमू-दरिया की घाटी में तरबीज में तापमान छाव में  $+50^{\circ}$  सेटीग्रेड तक पहुँच जाता है जो पूरे आविष्यत सघन में सबसे अधिक गर्म है, जबकि मध्य तियाण शान और पामीर में जुलाई में औसत तापमान क्रमशः  $+5^{\circ}$  और  $+15^{\circ}$  है जो जाड़ा में  $-40^{\circ}$  तक गिर जाता है। पर्वतीय इलाकों को छोड़कर हिमपात बहुत कम होता है। उत्तर में अराल सागर साल के कई महीने जमा रहता है और यही हान मिरदरिया के निचले मुहाने का है। अरब रेगिस्तानी और रेगिस्तानी इलाकों की आम विशेषता कृपानी हवा है।

भौगोलिक दृष्टि में मध्य एशिया और कजाखस्तान को चार हिस्सों में बाँटा जा सकता है स्तपी जिसमें उत्तर कजाखस्तान या परती-जमीन का बतारा शामिल है अरब रेगिस्तान, जो लगभग सारे शेष कजाखस्तान में फैला हुआ है इसमें दक्षिण में रेगिस्तान का इलाका, जो पश्चिम में रंगान और पूर में चान की सीमा तक फैला हुआ है, और पामीर और तियाण शान का पहाड़ी इलाका।

मध्य एशिया का बड़ी और छोटी नदियाँ जिन्हें बारह महीने बर्फ में पानी मिलता रहता है इसके नखलिस्तानों का हराभरा बनाव रहता है। ये नदियाँ आमू-दरिया और सिर-दरिया हैं जिनके मात पामीर और तियाण शान में हैं छोटी नदियाँ में ज़रफ़शान, चू, मुग़ान, तजन और आरारत हैं। कजाखस्तान में इरतिश, ईसी ज़रान और इतिम नदियाँ बहती हैं। ये इलाकों की मरुतपूर्ण सीमा में अरब सागर बनगान और तथा इरती-जान शान हैं।

हिमवत पर्वतो तथा मूखे रेगिस्तानो से मध्य एशिया के लोगो की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति मे कोई बाधा नहीं पड़ी। सुदूर अतीत स वहाँ अत्यन्त विरसित कृषि सभ्यता फलती फूलती रही है जिसका आधार सिचाई था। अनुकूल प्राकृतिक स्थितियाँ, जैसे गर्मी के लम्बे मौसम, उपजाऊ लोएस भूमि सिचाई की गुजादश मैदानों और पहाड़ियों पर बड़े चरागाह और प्रचुर खनिज धन की बढौलत नाना प्रकार का आर्थिक कायकलाप सम्भव हुआ।

मध्य एशिया और कजाखस्तान की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए निणायक महत्त्व की रही है। समुद्री रास्ता की खाज स पहले पूर्वी तथा मध्य एशिया का पूर्वी यूरोप से तथा निकट पूव क देशों से जाइनवाले मुख्य व्यापारिक रास्ते इसी इलाके स होकर गुजरते थे। आज के विमान और मू-संचार की मेवाए भी, जा सोवियत संघ को ईरान, अफगानिस्तान, भारत और चीन मे जोड़ती हे, मध्य एशिया और कजाखस्तान स होकर गुजरती है।

## लोग

मध्य एशिया सभ्यता के सब से पुराने केन्द्रों मे से एक है। यहाँ सोवियत पुरातत्वज्ञान न अनेक अवशेषों की खुदाई की है जिनका सबध पुरापाषाण युग स है। कजाखस्तान के तलस और जाम्बूल इलाके से और दक्षिण उजबेकिस्तान मे तशिक ताश से माउस्तेरियाई अवधि और उससे भी पहले के समय की चीजे मिली है। अनेक मध्य एशियाई कबीले बड़ाहरण के लिए दक्षिण तुर्कमानिस्तान मे जैर्दुन वम्बी के लोग नवपाषाण युग मे ही कृषि और पशुपालन करने लगे थे। दक्षिण तुर्कमानिस्तान मे अनाउ संस्कृति के लोगो को ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी मे ही कृषि का ज्ञान था। प्रारम्भिक लौह युग संस्कृति ईसा पूर्व पचम सहस्राब्दी मे प्राचीन ख्वारज्म मे मौजूद थी। यह संस्कृति मुख्यतः कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी। ख्वारज्म मे सिचाई की नहरों का जाल सा बिछा हुआ था। अन्य समकालीन संस्कृतियों मे, जा कृषि तथा शहरी जीवन क उच्च



स्तर पर पहुंच गई थी बैबिलोनिया और सोगदियाना का उल्लेख किया जा सकता है। स्तेपी क्षेत्र के लोग ताम्रयुग में ईसाई बाल से एक हजार वर्ष पूर्व सिचाई से अवगत थे।

प्राचीन मध्य एशिया तथा स्तेपी क्षेत्र की आदिम आबादी उसी ईरानी वंशमूल की थी जिससे फारस बाले थे। मध्य एशिया के सबसे पुराने लोग जिनका हाल हम मालूम है—जरफशान घाटी के सोगदियान और ब्रामू दरिया के निचले किनारे पर बसे हुए स्वारख्मी—इसी वंशमूल से थे। उनका इलाका अक्मेनेद राज्य का हिस्सा था। यह पहला विश्व साम्राज्य था जिसका इतिहास को ज्ञान है। राजा दारी ने (५२२-४८६ ई० पू०) अपने शिलालेखों में सोगदियानों और स्वारख्मियों की चर्चा करते हुए उन्हें अपनी प्रजा बताया है। उन्होंने यूनान के विरुद्ध उसकी लड़ाई में भाग लिया था।

सिक्न्दर महान के आक्रमण के समय तक स्वारख्मी फारस का प्रांत नहीं रह गया था। मगर सोगदियान उस समय तक फारस के शासन में अधीन थे और वे सिक्न्दर के खिलाफ लड़े। अक्मेनेद राज्य को सिक्न्दर महान ने नष्ट कर दिया और इसके इलाके यूनानी-मकदूनी साम्राज्य में शामिल कर लिये गए। उसी सदी में इसका पतन होने के बाद मध्य एशिया का काफी बड़ा हिस्सा सेल्युकस राज्य में मिला लिया गया। ईसा पूर्व तीसरी सदी में मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में सेल्युकस का तटस्थ स्थायी विद्रोह के कारण उलट गया। उनके स्थान पर पार्थिया आये। लेनित पाकिया ने हमने के बावजूद स्वतंत्र यूनानी-बैबिलोनियाई राज्य १४०-१३० ई० पू० तक कायम रहा। कुछ अंशों बाद यूनानी-बैबिलोनियाई का स्थान पर कुषान राज्य स्थापित हुआ। कुषान युग मध्य एशिया के लिए सांस्कृतिक तथा आर्थिक विस्तार का जमाना था। इस क्षेत्र का समृद्धि का कारण यह भी था कि वह चीन का फारस और रामन जंगल से मिलने वाले “महान रेशमी मार्ग” पर स्थित था।

तीसरी सदी ईसवी के अंत में कुषान सत्ता का पतन शुरू हो गया। चौथा सदी ईसवी में जयनार्द या यज्ञातुष नामक एक खोने में जिनका कुषान में संबंध था और जो उनके शासन में अधीन था, बैबिलोनिया पर

बन्ना कर लिया और मध्य एशिया में कुपान शासन की इट से इट बजती दी। परन्तु श्वेत हूणा का शासन बहुत दिन नहीं चला। ५६३-५६७ ईसवी में इफ्रयाइया को जेतीसुव वं तुर्कों ने परास्त कर दिया और मचूरिया से बाले सागर तक पले घगान शासन में शामिल कर लिया। छठी सदी ईसवी के शत तक घगान शासन दो भागों में बंट गया और उसके पश्चिमी भाग पर मुसलमान अरबों का अधिकार कर लिया।

मध्य एशिया में अरबों का दखल आठवीं सदी के प्रारम्भ में इब्न मुस्लिम वं नतत्व में हुआ। वह घुरासान का राजपाल था। सारे इलाके में वे तलवार और आग लेकर बढे और शानदार सांस्कृतिक ध्वजाने नष्ट कर डाले जैसे पञ्जीकन्द के मन्दिर में गिला और अग्नय यादगारे। अरबों की इन सत्यानाशी हरकतों का वर्णन अल बरूनी ने बड़े आग्रह के साथ किया है। उनका वर्णनानुसार इब्न मुस्लिम ने उन सारे विद्वानों को मार डाला जो ह्वारस्म के इतिहास और भाषा का ज्ञान रखते थे, जिससे इसलामी युग से पहले का इतिहास के बारे में कुछ जानना असम्भव हो गया। स्थानीय जनगण ने जिह्म तुर्कों की वीलो का समर्थन प्राप्त था, अरबों का बड़ा विरोध किया। यह जनविरोध कोई पचास वर्ष तक जारी रहा। इसके विपरीत सामाजी ईरान पर बन्ना करने में अरबों की केवल १५ वर्ष लगे थे। अरब शासन में बड़ा अत्याचार होता था। किसान करो के भारी बोझ से त्राहि-त्राहि कर रहे थे जबकि जमींदारों का सागी सुविधाएँ हासिल थी। अरबों ने मध्य एशिया में तलवार के बल पर इसलाम फलाया। इस धर्म परिवर्तन से उठाने स्थानीय लोगों में समान दृष्टिकोण के आधार पर एकता स्थापित करने का काम लिया। इसलाम के साथ अरबी भाषा भी फैली, जो शासन, साहित्य और विज्ञान की भाषा बन गई। लेकिन आम लोग स्थानीय ईरानी और तुर्कों बोलिया बोलते रहे। लोगों की नस्ली बनावट पर अरबों का कोई खास असर नहीं पड़ा। मध्य एशिया में आज जो अरब बस हुए हैं, वे उन लोगों की सतान हैं, जो बहुत बाद में तैमूर के समय आकर आवाद हुए थे। इसलाम की विजय कजाखस्तान के केवल दक्षिणी भाग तक सीमित थी। स्तेपी इलाके वं तुर्कों की वीलो उस समय तक स्वतन्त्र थे। तुर्कों ने

पहले आठवीं सदी में जैतीसुव में तिमुरगेशियो से और बाद में (८वीं से १०वीं सदी तक) करलूका से एका कर लिया था। पश्चिम की ओर, सिरन्दरिया के निचले भागों में तुर्क कबीलो और ओगुजा के शक्तिशाली सघ का प्रभुत्व था। इन कबीलो में आनाज की खेती के साथ पशुपालन भी होता था और शहरों में उनके व्यापार-केन्द्र भी थे। ओगुजा का कर्ग्यगीकद शहर था। वे इफ्यलाण्यो की सत्तान थे, जो छठी और सातवीं सदी ईसवी में तुर्कों के प्रभाव में आ गये थे। इस मुख्य तुर्की इफ्यलाई नस्ली तत्व के अलावा ८वीं से १०वीं सदी के जमाने में ओगुजा में हिन्द-यूरोपीय कबीले भी काफी संख्या में आ मिले जैसे तुखार और यासोव आलान।

ओगुजा के पड़ोस में, अराल सागर के इलाके में, इस दौर में पचेनेग कबीलों का सघ स्थापित हुआ। उनका नस्ली आधार पुराने शक-भसागात कबीले थे। उनपर भी तुर्कों का असर पड़ा था।

९वीं और १०वीं सदियों के दौरान में सामानियों का राज्य कामम हुआ (८७४-९६९ ईसवी) जिसमें ईरान और मध्य एशिया दोनों शामिल थे। इसका केन्द्र बुखारा था। सामानी राज्य में भावरान्महर, ख्वारस्म, सिरन्दरिया के इलाके, तुर्कमानिस्तान का भाग ईरान और अफगानिस्तान शामिल थे। इसमें इस इलाके के नस्ली और सांस्कृतिक इतिहास में बड़ी भूमिका प्राप्त की। सामानी शासनकाल में ताजिक फारसी भाषा दूर दूर तक पानी और यही वह समय था जब महान कविया रुदकी और फिरदीसी ने अपनी अमर कृतिमा लिखी। परंतु विज्ञान की भाषा अरबी बनो रहा।

८वीं सदी के अंत और ९वीं सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया में मन्ना साहित्यिक पुनरुत्थान हुआ। अरब गणित शास्त्र का संस्थापक मुहम्मद इब्न मुसा अल-खारिस्मी की कृतियाँ इसी दौर की हैं। उन्हीं की कृति "अल-जब्र" के शीर्षक से अलजेब्रा नाम पड़ा। वह केवल गणित शास्त्र ही नहीं घमास भूगोल तथा इतिहासकार भी थे। उनकी कृतियाँ में भारतीय वाज्यगणि और यूनानी ज्यामिति का संश्लेषण था जो प्राचीन गणित विज्ञान का आधार है। अल-खारिस्मी ने गणित शास्त्र की कृतियाँ पुरानी फारसी परम्परा का उपयोग किया जिनपर भारतीय

तथा यूनानी सभ्यता का बड़ा असर पड़ा था और जिनकी उत्पत्ति सिचाई, व्यापार और निर्माण की व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर हुई थी। अरबा ने गणित विज्ञान उन्ही की वितावा से सीखा।

अबू नस्र अल फाराबी (मृत्यु ९५० ईसवी) ने दार्शनिक टीकाएँ लिखी और उन्हें कुछ लोग पूब का अरस्तू कहते हैं। उनका दृष्टिकोण म भौतिकवाद का असर था जिस कारण मुस्लाभा ने उनपर बड़ा अत्याचार किया। उनके भौतिकवादी विचारों ने मध्य एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक अबू भली इब्न-सीना (९८०-१०३७ ईसवी) का प्रेरित किया जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र और दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी। चिकित्सा शास्त्र पर उनकी वितावा में सबसे प्रसिद्ध 'अल-कानून फितीब्व' है जिसका अनुवाद १२वीं सदी में लातीनी में हुआ था और जिसे कई छ सौ साल तक पूब और पश्चिम के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक मानते रहे।

द्वारजम सभ्यता में एक और महान व्यक्ति अल-बेल्ही (९७३-१०४८ ईसवी) थे जो इब्न-सीना के समकालीन थे। इनका जन्म एक गाँव में हुआ था, जो आजकल कराकुरपाक स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र में है। उनकी "विताब उल हिद" एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक और मानव जाति ज्ञान सम्बन्धी कृति है जिसका जोड़ मध्ययुगीन साहित्य में नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति, भूगोलविद, खनिज विज्ञानी, जाति विज्ञानी, इतिहासकार तथा कवि के रूप में भी उन्हें बड़ी मायता प्राप्त थी। वह एक महान और निष्ठ देशभक्त थे, जिन्होंने विजेताओं की सत्यानाशी हरकतों की बड़ी आलोचना की। इसके साथ-साथ वह अनेक जातियों की सभ्यता की बड़ी आलोचना की। इसका साथ-साथ उनका दृष्टिकोण सहज भौतिकवादी था। वह भौतिक जगत की परिघटनाओं और नियमों का ज्ञान प्राप्त करने में मानव-बुद्धि की भूमिका पर जोर देते थे। परन्तु इब्न-सीना और अल-बेल्ही के वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी विचारों को प्रतिक्रियावादी धार्मिक विचारधारा से नुकसान पहुँचा, जो उस समय मध्य एशिया पर हावी थी। मावरान्-नहर में ११वीं और १२वीं सदियों में इराक से सूफी मत के रहस्यवादी विचारों का प्रचार हुआ।

मध्य एशिया में १०वीं और ११वीं सदियों में सामंती संघों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इससे इस इलाके के जातीय इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। अब जातीय समूहों की निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुई। ९वीं और १०वीं सदी के बीच के काल में एक जाति-समूह का रूप में ताजिकों की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया की जातियों में सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। उनकी भाषा पहले ही सामान्य राज्यकार्य में विकसित हो चुकी थी। सोगदियान और बैक्ट्रियान उनके पुराने पूज्य थे।

ताजिकों के वतन से मिले हुए इलाके में उज्बेक जाति की उत्पत्ति हुई। उज्बेकों के ऐतिहासिक पूज्य स्थानीय मध्य एशियाई जनगण जैसे टारखमी, सागदियान, मसागात और शक थे। इससे पहले के दौर में स्लेपी के तुर्कों कबीले भावरान्हर के क्षेत्र की खरफशान, फरगाना, चाच, टारखम आदि की वादिया में आकर बस गए थे। तुर्क इन स्थानीय कृषि लोगों में घुस मिल गए। उन्होंने उनका अधिक रहन-सहन और सांस्कृतिक आदर्श अपना ली। और स्थानीय लोग न जो ईरानी भाषा बोलते थे, तुर्कों की भाषा अपना ली। जातीय मेलजोल की यह प्रक्रिया ११वीं और १२वीं सदियों में जारी से जारी थी। उसी समय आम और मिरानिया जातियों के बीच के इलाके में एक तुर्की भाषा बोलनेवाली जाति की बुनियाद पड़ी, जो आगे चलकर उज्बेक बनी जान लगी।

१०वीं सदी के अंत में सामानी साम्राज्य का पतन हुआ था। सुल्तान हारिमा न केन्द्र का हक मानने से इनकार कर लिया। अलग होने की प्रवृत्ति में जोर पड़ा। भारी बरा की थजह से विमानों में असंतोष का भाग भड़की और पूरे साम्राज्य में गहरा सामाजिक संकट फैल गया। सुल्तानगीन न मजनी व राजवंश की स्थापना की और बागदाद न बागदाद और जनीमुन व इराक में बाराखानिया व शमिशानी तुर्क राजवंश की बुनियाद डाली। मध्य एशिया और उज्बेकस्तान में बाराखाना शासनान उम शेर व जानाव तथा सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। उमा समय में पूर्वी तुर्किस्तान तथा मध्य एशिया व जातीय समूहों का सम्मिश्रण हुआ जिसमें परस्पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा।

उस जमाने में तुर्क कबीले जैतीमुव में और चाच इलाके के निकट सिर-दरिया के पास-पास बस हुए थे। उनमें सबसे शक्तिशाली करलूक कबीला था, जो तलस नदी की घाटी से पूर्वी तुर्किस्तान में तरीम नदी तक फैला हुआ था। ये बड़े सुसज्जित लोग थे, जो शहरो और गावों में रहते और पशुपालन, घेंतीवारी और शिवार करते थे। दूसरा बड़ा तुर्क कबीला चिगिल था, जो मुख्यतः इस्तीव-बूल झील के उत्तर-पूर्व ताराज में बसा हुआ था। इतिहासज्ञों का कहना है कि इस कबीले के पाम छोड़े, भेड़ बकरी और मवेशी बहुत थे और करलूकों की तरह यों लाग भी शहरों और गावों में रहा करते थे। एक और तुर्की कबीला, याग्मा, जिसका पशु अधिकतर शिवार और पशुपालन था पूर्वी तुर्किस्तान में इस्तीव-बूल झील के दक्षिणी क्षेत्र में आबाद था। तियुरगेशी कबीले, जिनमें तुखसी और अरगी शामिल थे और जिनके राज्य की स्थापना ८वीं सदी में हुई, करलूकों से पराजित हो गये थे। इन कबीलों का गहरा सांस्कृतिक संबंध मावरांनहर के लोगों से था और उनकी तुर्की भाषा में सोंगदियान का मिश्रण हो गया था।

इस अवधि में मध्य एशिया के स्थानीय लोगों की राजनीतिक एकबद्धता काराखानी राज्य में तुर्की कबीलों से हुई, जिसके फलस्वरूप गहरा परस्पर प्रभाव पड़ा। सम्य वृषि प्रधान इलाके के वासियों से खानाबदोश तथा अद्ध-खानाबदोश तुर्क आप्रवासियों के सम्मिश्रण का सविस्तार वणन "कुदतकु विलीक" में किया गया है। यह बड़ी अच्छी ऐतिहासिक वृत्ति है जिसे युसूफ खास हाजिब बलसगूनी ने ११वीं सदी के आरम्भ में लिखा था। इस दौर में मध्य एशिया के नखलिस्तानों में तुर्की नस्ल के लोगों की संख्या बढ़ गयी और स्थानीय लोगों ने धीरे-धीरे तुर्की भाषा अपना ली। आज उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में तुर्की भाषा बोलनेवाले लोगों का बहुमत हो गया। महमूद काशगरी - काराखानी तुर्क आप्रवादि - द्वारा लिखित "दीवान-उल-लुगत अतुक" के अध्ययन से पता चलता है कि ११वीं सदी में उज्बेक भाषा के निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी।

इसी दौर में तुर्कमान, कराकल्पाक और कजाख लोगों के जातीय निमाण में स्तेपी कबीलो तथा अराल सागर के निकट रहनेवाले जनगण के ज़ारतार स्थानांतरण ने भी निर्णायक भूमिका अदा की। तुर्कमानों का जातीय निमाण अराली कास्पियन स्तेपी के दाखो और मसागता का क्वायली एकबद्धता से हुआ जिनपर तुर्की प्रभाव पहले ही पड़ चुका था। इनकी बनावट में मुख्य नस्ली तत्त्व ओगुज़ कबीले थे जिनका एक भाग ताहिर मियर्ज़ा के कथनानुसार १० वीं सदी के अंत में ही तुर्कमान कहलाने लगा था। ११ वीं सदी में काराखानियों से उनके सघन के दौरान में निचले सिर दरिया के ओगुज़ा में सलजूकी राज्य की उत्पत्ति हुई। उन्होंने न केवल काराखानी राज्य पर, बल्कि गज़नवी क्षेत्र पर भी कब्ज़ा कर लिया था। सलजूक तुर्क ओगुज़ सिर दरिया के इलाके में वर्तमान तुर्कमान सोवियत मजाजवादी जनतंत्र के क्षेत्र में दाखिल हुए। ओगुज़ क्वायली नामों का रिवाज तुर्कमानी कबीलो में २० वीं सदी के प्रारम्भ तक था। सलजूकों के आगमन से उज़बेकों का भी जातीय निर्माण काफी प्रभावित हुआ। इन से द्यारखम और बुयारा के कुछ हिस्सा की आबादी पर तुर्की प्रभाव पड़ा। आज भी समरकन्द क्षेत्र में तुर्कमान नाम का एक जातीय समूह बसा हुआ है। यह आगुज़ तुर्कमान की सतान है, जो मिर-अरिया से आकर यहाँ बग और उज़बेक में घुल मिल गये थे।

इसी अवधि में पचेनगा के पीछे-पीछे आगुज़ा के एक अन्य भाग का आगमन जिमकी जिहा दक्षिण स्तेपी की ओर था, और अराल सागर क्षेत्र में दक्षिण से रिपचाता का प्रवेश कराकल्पाक जातीय समूह की निमाण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी हुआ। कराकल्पाक के पुराने पूर्वज अराल सागर क्षेत्र के कबीले (यानी सगुका के अन्तर्गत में "अन्तर्गत और दायाँ व मसागता") और अनामियान-पचेनगा के पूर्वज थे। पचेनगा और आगुज़ा का एक भाग के पश्चिम की ओर प्रवास कर जान के बाद अराल क्षेत्र में आगे बढ़ा और दूसरे में निम्न आ गये। इन आगुज़-अननग मम्मिआन में आगुज़ा जाति का विभाग हुआ। ११ वीं सदी में रिपचाता द्वारा अराल क्षेत्र में स्थित में आगुज़ा का सामूहिक विभाग का एक भाग का एक भाग हुआ। कराकल्पाक का आगुज़ा का

भाषा स्वीकार कर ली और १२वीं सदी तक कराकल्पाक का जातीय नाम प्रचलित हो चुका था।

कज़ाख़ा का जातीय विकास मुख्यतः शक और उसुन नामक स्तेपी कबीला के आधार पर शुरू हुआ जिसमें दूण जातीय तत्त्वा का भी काफी बड़ा हाथ था। इसके अलावा तुर्क खगानशासन तथा दक्षिण कज़ाख़स्तान के प्रारम्भिक मध्ययुगीन राज्या न भी इस प्रक्रिया में सहायता की। १० वीं और ११ वीं सदियों में किपचाक ने पश्चिमी और मध्य कज़ाख़स्तान में कई कबायली सभ्य स्थापित कर लिए थे जिनका प्रभाव १२ वीं सदी में इरतिश से दूनपर तक फैल गया था। कज़ाख़ जातीय समूह की उत्पत्ति स्तेपी के तुर्क कबीला से किपचाक के सम्मिश्रण से हुई। उरवेक, किगिज़, कराकल्पाक और बाश्कीर जैसी अन्य तुर्क जातियाँ भी कपचाक कबीले शामिल थे।

किगिज़ा का निर्माण मध्य एशिया से बाहर के क्षेत्र में, शायद पूर्वी तियान शान के तुर्क कबीला में शुरू हुआ। किगिज़ा ने ६ वीं और १० वीं सदियों में ऊपरी येनिसेई में स्वयं अपना राज्य स्थापित कर लिया था जिसने मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। येनिसेई और तियान शान के किगिज़ो का संबंध आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। तियान शान के किगिज़ कबीला का, जो उस जगह बढ आये थे जहाँ आज किगिज़ सोवियत समाजवादी जनतन्त्र है, मध्य एशिया की स्थानीय आबादी से सम्मिश्रण मंगोल आक्रमण के समय शुरू हो गया था। मध्य एशिया के किगिज़ो पर अल्ताई, इरतिश, मंगोलिया और सिक्याग के लोगों का सांस्कृतिक असर स्पष्ट दिखाई देता है, यद्यपि उनकी संस्कृति की अनेक विशेषताएँ स्थानीय आबादी से उनके सम्मिश्रण के कारण उत्पन्न हुईं। १७ वीं सदी में येनिसेई किगिज़ा की रूसियों से मुठभेड हुई और उनका बड़ा हिस्सा उस समय जुगारिया में बस गया और दूसरे साइबेरिया के खाकासियों और तुवानो में घुल मिल गये।

१२ वीं सदी में खानाबदोश कराकिताई सुदूर पूर्व से चले आये और उहान जैतीसुब में एक राज्य स्थापित किया और भाबरानहर पर अधिकार कर लिया। उनके आने का मध्य एशिया की जातीय बनावट पर स्पष्ट



प्रभाव पड़ा। जाहिर है कि उनका एक हिस्सा तुर्क कबीला में विलीन हो गया और उनकी भाषा अपना ली। उनका कबायली नाम किताई उर्रेसा, कराकल्पाको, कजाखा और किगिजा में प्रचलित हो गया।

मध्य एशिया में कराकिताइयो का शासन बहुत दिन नहीं रहा और १३ वीं सदी के शुरू में उनका स्थान ट्टारजम शाहा ने लिया, जिन्होंने सलजूकिया की सत्ता को नष्ट कर लिया और एक शानदार सामन्ती साम्राज्य की स्थापना की जिसमें मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और आज़रबैजान शामिल थे। ट्टारजम शाहा के शासन में सामन्तवाद का विकास की चरम सीमा पर पहुँच गया था जिसकी अभिव्यक्ति शहरों, व्यापार, दम्नकारी और सभ्यता के विकास में हुई।

चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमकों ने १२१६-१२२१ ईस्वी में ट्टारजम शाहा के राज्य का नष्ट कर दिया। मंगोलों ने बड़ी तबाही और बर्बादी मचाई। इस कारण ऐसा आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन छा गया जिससे मध्य एशिया बहुत असें तक उबर नहीं पाया। मंगोल लश्करों का बड़ा भाग, जिनमें मध्य एशिया का पराजित किया, कृषि कार्य तथा अन्य तुर्की कबीलों पर आधारित था जिन्होंने मंगोल कबायली नाम जमे टून्गिरान लिया, मंगोल आदि स्वीकार कर लिए थे। इन नामों में अक्सर उर्रेसा, कजाखा और कराकल्पाका में रह गये हैं, मगर इन में उनका मंगोलों में उत्पन्न होने कोई ज़रूर नहीं। मंगोल विजेता आक्रान्तों से स्थानीय लोगों में घुल मिल गया और उन्होंने इस्लाम धर्म और तुर्की भाषा दादा या ग्रीसर कर लिया।

१८वां शताब्दी में यहाँ के मंगोल कबीलों में, जिनमें तुर्की प्रभाव पड़ा था, महान विजेता तैमूर का जन्म हुआ जिसने ३६ वर्षों में लगातार अभियानों में उसे एक राज्य स्थापित किया, जो भारत से चालीस तक और शाम (तांगिया) में तक फैला हुआ था। तैमूर भारत, ईरान और शाम में कर्नातकों और वाग्नूशियानों का दाग बनारस माघ से छाया दिखाते मंगोलों में यहाँ ग़लत का भगवान और गुरु अमीर के मंगोलों का निर्माण किया। उमरावों का उत्तम वेत विमान का बड़ा प्रेम था और उमा के हाथ-पांव में मंगोलों के मन्दिर में अद्यावत् विमानों का

पाठ्यक्रम होने लगा। आगे चलकर हेरात और गमरा नाम विद्या के दो बड़े केंद्र बन गए। उलुग बा और गमरा में एक गंगालीय कथशाला का निर्माण कराया। उग्रा नाम काजी ज्ञान स्त्री गियागुदीन जमने और अपनी बुद्धि जैम प्रगति गंगोतिका के साथ गजद है। उमकी गंगोलीय सागनिया अपनी गूमता के लिए प्रसिद्ध है। उलुग बन की दुर्घात मृत्यु घर्मोमत मुत्तामा के हाथों से हुई।

प्रसिद्ध उरख बरि अपनी नवाई यही रहत थे। उनकी टुनिया में पुरानी उरख भाषा अपनी शुद्धता के तम बिन्दु पर पहुँच गई। उनकी गजला के "चार दीवान", "गमना" तथा उनकी अन्य टुनिया मध्य एशिया तथा विश्व साहित्य का बन्धुत्व दा है। उनका सपथ अध्यात्मिक विद्या शिक्षण तथा जीवन का गुपी बान के लिए था। उनका रामवानीन व्यक्तिया में हपीजी आरत अन्दुरखान समरादी मीरखा और घोदमीर जस प्रतिष्ठित इतिहासकार थे जिनकी टुनिया से मध्य एशिया तथा अन्य देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर अच्छी रोशनी पड़ती है।

स्वयं ओर्दु का विघटन १६वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इस मध्य एशिया और बजायस्तान के लोगों के जातीय विवास पर अर पड़ा। १५वीं सदी में देशी विपचाव में नये शक्तिशाली बचायती सभ की उत्पत्ति हुई जिनमें से एक सिर-दरिया के निचले क्षेत्र में सफे ओर्दु के इलाके में स्थित था। इस सभ में एक बचीला था जो १४वीं सदी में उरख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। १५वीं सदी के अंत में इन स्तेपी बचीला ने शैवानी घान के नेतृत्व में पतनोमुख तमूरी राज्य को पराजित कर लिया। शैवानी घान के साथ जा उरख बचीले मध्य एशिया गये थे, वही बस गए और धीरे-धीरे तुर्क और ताजिक आवादी में घुल मिल गये। अब उरख शब्द का प्रयोग केवल आप्रवासियों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी किया जाने लगा। देशी विपचाव तुर्क बचीलो के मिल जाने के बाद उरख लोग का जातीय निर्माण पूरा हो गया। १५वीं सदी के मध्य में सामंती विघटन के कारण चू नदी के क्षेत्र

म छोटे छोटे प्रदेश स्थापित हुए, जो धीरे धीरे १६वीं सदी में बजाय खानशाही के रूप में विकसित हुए। इस से बजाय जातीय समूह का निर्माण पूरा हुआ। प्रारम्भ में इस के निवासियों को उज्ज्व बजाय और बाद में केवल बजाय कहा जाता था।

इस प्रकार १५वीं से १६वीं सदी तक विकसित सामंतवाद की स्थितियों में और दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप मध्य एशिया तथा बजायस्तान के सभी प्रधान जातीय समूहों का गठन हो चुका था।\*

मदिया के दौरान मध्य एशिया के लोगों ने स्वयं अपनी शानदार सभ्यता विकसित कर ली थी और कृषि, सिंचाई, कला तथा दस्तकारी, धातु विज्ञानों तथा साहित्य में और साथ ही युद्ध की कला में मुख्य सफलताएं प्राप्त कर ली थी, जो अथ प्राचीन तथा मध्य युगीन सभ्यताओं की उपलब्धियों का मुकाबला कर सकती थी। मध्य एशिया के लोग न भारत, चीन, मेसोपोटामिया और ईरान की सभ्यताओं से बहुत कुछ लिया और उसे स्वयं अपनी सृजनशील प्रतिभा से और समृद्ध किया। उन्होंने इन पड़ोसी देशों की सभ्यताओं को प्रभावित भी किया। चीनियों ने अगूर को वास्तुशिल्प उपजाना, जंगी घोड़े पालना और शीशे बनाना मध्य एशिया से सीखा। आज की मंगोल और मचूरियाई लिपि पर सोगरियन लिपि का असर आज भी बाकी है, जिसे उन लोगों ने प्राचीन समय में अपनाया था। यूरोप और एशिया ने युद्ध में घुड़सवार रिसाल का उपयोग मध्य एशिया से सीखा। वाणज बनाने की कला चीन से यूरोप में इसी क्षेत्र में हारने पहुंची। मध्य एशिया के वस्तुनिष्ठ न अथ गणितीय शास्त्र तथा पुरातन विज्ञान को विकसित किया जिसे आगे चलकर मध्ययुगीन यूरोप में अपनाया। मध्य एशिया के वास्तुशिल्प न भी पड़ोसी देशों के वास्तुशिल्प में विकास को प्रभावित किया।

मध्य एशिया की जातियाँ प्राचीन काल के विभिन्न नस्ली समूहों का सम्मिश्रण हैं। उन्हीं और ताजिकों की रचना में सोगरियन का हिस्सा

\* २० 'मध्य एशिया और बजायस्तान के जनगण', मासिक १९६२ मध्य १ पृष्ठ ८१-१०३। (अंग्रेजी संस्करण)

है। तुर्कमाना, करावल्पाका, बज्जाया, उखेवा और किसी हद तक ताजिकों की रचना में शक और ममागात अश शामिल है। मध्य एशिया की अधिकांश जातियाँ की उत्पत्ति में, चाहे वे ईरानी भाषा बोलनेवाली हों या तुर्की, प्राचीन तुर्क बबीला की भूमिका रही है। आगे चलकर उखेवा, बज्जाया और किसी हद तक करावल्पाका और अश लोगों के गठन में विपचाव अश दाखिल हुआ। अतः मध्य एशिया की जातियाँ सभी एक दूसरे से संबद्ध हैं, उनमें पुराने नस्लों रिश्ते हैं। इसी कारण उनकी सभ्यता, अथवा और जीवन पद्धति में अनेक बातें समान हैं। उनके समान ऐतिहासिक विषयों तथा बदेशिक हमलावरों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष ने एकता के इन रिश्तों का और सुदृढ़ बनाया है। परन्तु साथ ही यह बात नजरअन्दाज नहीं करनी चाहिए कि हर समूह ने अपनी अलग सांस्कृतिक विशेषताएँ कायम रखी हैं जिनके आधार पर मध्य एशिया के विभिन्न जातीय समूहों का गठन हुआ। सब ईरानवाद तथा सब-तुर्कवाद के समर्थक हैं। सब ईरानवाद की धारणा मध्य एशिया की जातियों के विशिष्ट ऐतिहासिक विकास की स्पष्ट उपेक्षा है तथा उनकी सभ्यता पर ईरानी कला और वास्तुशिल्प के प्रभाव और छाप को अनावश्यक तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना है। सब-तुर्कवाद को भी ऐतिहासिक यथार्थ से कोई तौर पर एक इकाई में मिलाने का व्यर्थ प्रयास है, जो उनके स्वतंत्र ऐतिहासिक विकास की वास्तविकता को नजरअन्दाज करता है। ऐसे सिद्धान्त दूरवर्ती राजनीतिक धारणा से पेश किये जाते हैं।

मध्य एशिया की जातियाँ तीन सदियों के दौरान (१६ वीं सदी से १९ वीं सदी के मध्य तक) उखेवा वंश के खान शासन के अधीन रही। उसके बाद ज़ारशाही के रूसी साम्राज्य ने उन्हें अपने अदर में ला लिया। अगले कुछ समान बातें जैसे भाषा और सभ्यता पहले से मौजूद थी और राष्ट्रीय चेतना की कापल फूटने लगी थी, खान शासन के अंतर्गत स्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें और अधिक जातीय सुगठन हो सके। ख्वारस्म शाहों के ब्रह्मवृत्त शासन के अंतर्गत जो प्रगतिशील विकास शुरू हुआ था

उमका मगोल आक्रमण ने अस्त व्यस्त कर दिया और तब से सामंती विप्लव का युग प्रारम्भ हुआ। सामंती खान शासनो में विभाजित मध्य एशिया सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में बहुत पिछड़ गया। खान शासित प्रदेशों में लगातार परस्पर युद्धों के कारण इसके अर्थतंत्र का विकास धीरे-धीरे हो गया। उत्पादन शक्तियों के विकास का नीचा स्तर, कृषि और शिल्पकारी में गतिराध न जातीय समूहों के मठों की नुकसान पहुंचाया।

बुखारा खाना और कोकान के उखेक खान शासन की जातीय बनावट में विषमता थी। खानों में उखेक, तुर्कमान, कराकताक और कजाख रहते थे। उखेक और बटे हुए थे, इनमें मात, जो प्राचीन स्थानों निवासियों की सत्ताएं, और देशी विप्लव उखेक थे जिनमें अरब कबील और निरखे की विशेषताएं थीं भी मौजूद थीं। खानों के खान तुर्कमान और कराकताक का उत्पीड़न करते थे। उन्हें अनोपजाऊ जमान पर बसाने, मारी कर लगाते, उनसे बेगार लेते और अनिवार्य सैनिक गणों में भरती करते थे। उनका निद्राहा का बड़ी बरहमी से कुचल गया जाता था। बुखारा के खानशाही में सामंती उखेक अमिजात बग का निषेधाधिकार प्राप्त था और वे ताजिकों पर अत्याचार करते थे।

कुछ पश्चिमी लेखकों का यह दावा कि मध्य एशिया की जातियों का गठन का विषमता की बात सब-नुकवाद का विरोध करने का लिए प्राण-तन्त्र सामंती शासन द्वारा मढ़ी गई है, तथ्या का सबंध मिथ्या वणता है। १८६३ में ही म० यानिकोव ने, जिन्होंने बुखारा की यात्रा की थी लिखा था कि वहाँ की यात्राशाही में मान त्रिलकुत विभिन्न गमह अमली प्रजाति विशेष गठित थे जावन अतंत मग्न थे और उनमें एक में विप्लव ११ बाद आया गया था।\* यही सामंती लड़ाई के कारण जा मछा

\* 'गा' का शब्द जो १९१७ की प्राति में पहल इस्तेमाल किया गया था, उखेक में बर्त गया नहीं गया। इसमें जातीय उत्पत्ति का वर्ण सामाजिक अर्थों का सबंध होता था। इसका मतलब था 'अशिया' या 'अशिया' और 'अशिया' या 'अशिया' या 'अशिया' ।-सं० १० १० यानिकोव, 'बुखारा यात्राशाही का वणता', म० यानिकोव, १८६३ पृष्ठ १३ ७१। (यंगी मग्नवण)

- बहुत घट गई थी। अध्यात्मिक साहित्य लुप्त हो गया था और धर्म का बोल
- वाला था। मध्ययुगीन मध्य एशियाई पगानना गणितशास्त्रिया तथा
- चिकित्सा विज्ञानिया की ज्ञानदार उपलब्धिया भुना दी गई थी और
- प्राकृतिक विज्ञाना का अध्ययन पाप समझा जाने लगा था। सामाजिक
- जीवन पर इस्लाम की सखीण रुढ़िया का प्रभुत्व जातीय चेतना के विकास
- में बाधक बना हुआ था। अनजाने अबाध लाग मुल्लाघा के धार्मिक प्रचार
- का शिकार ५ जिसमें तमाम मुसलमाना की मिथ्या एकता पर जोर दिया
- जाता था। इससे आगे चलकर सब इस्लामवाद के समर्थक ने फायदा
- उठाना चाहा। इस तमाम धर्महनीय सामाजिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक
- गतिराध के बावजूद जनगण की सज्जनात्मक प्रतिभा ने बितने ही दीप्तिमान
- कविया और प्रगतिशील विचारका का जन्म दिया जिन्होंने सामाजिक
- अघाय और उत्पीड़न का विरोध किया और कबायली परम्परा और
- धार्मिक विचारधारा से नाता तोड़ लिया। उनमें उदाहरण के लिए
- अद्भुत उर्दू कवि तुर्दी (१७वीं सदी के अंत और १८वीं के प्रारम्भ
- में) थे। उन्होंने केवल लड़ने का आवाहन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं
- बुधारा के सामंती जालिम सुबहान कुली खान के दुशासन के विरुद्ध
- जनगण के सशस्त्र सघर्ष में भाग लिया। इस सघर्ष में तुर्दी अलग अलग
- उर्दू कबीला को एकताबद्ध करना चाहते थे। तुर्कमान कबीला की एकता
- का ऐसा ही नारा महान तुर्कमान कवि और विचारक मखदुम कुली न
- दिया था।

उस जमान की प्रतिकूल स्थितिया के बावजूद मध्य एशिया की जातिमो  
म से हर एक ने अपनी एक समान भाषा, जीवन पद्धति और संस्कृति  
विकसित कर ली थी। परन्तु उच्चतर अवस्था में उनका जातीय  
विकास उनके आधिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण रुक  
गया था। मध्य एशिया और कजाखस्तान के जारशाही के रूसी साम्राज्य  
में मिल जान के बाद ही वहाँ प्रारम्भिक पूँजीवादी उत्था की उत्पत्ति होने लगी।  
कुल मिलाकर पिछड़े हुए खानशाहिया का अधिक विकसित रूस में विलयन  
वस्तुनिष्ठ दृष्टि से प्रगतिशील कदम था। लगातार परस्पर लड़ाइयों के  
अंत और पूँजीवादी सबंध के प्रवेश ने सामंती गतिरोध को दूर करन

म सहायता की। रेलवे के निर्माण, व्यापार के विस्तार, और कपास जैसे विदेशी कृषिक पैदावारों के विकास न रूसी साम्राज्य के इस दूर स्थित देशों का विश्व मंडी की मसलदार में पहुंचा दिया। इस नये पूँजीवादी विकास के आधार पर मध्य एशिया के ये जातीय समूह पूँजीवादी जातियों में गठित हो गए।\*

परंतु गठन की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और ज़ारशाह का सैनिक साम्राज्यवाद तथा औपनिवेशिक उत्पीड़न की नीति इसमें बाध पड़ी। इसका प्रति पूँजीवाद के आधार पर नहीं बल्कि अकतूबर समाजवादी क्रांति का विजय के बाद समाजवाद के आधार पर हुई। अकतूबर क्रांति ने मध्य एशिया और कजाखस्तान की जातियों के लिए स्वतंत्र गणराज्य विकास का रास्ता खोल दिया। सोवियत सरकार ने १९२४ में जातीय राज्य सीमाओं का निर्धारण किया जिससे मध्य एशिया के जनगण का अपनी जातीय गठन में प्रयास में सहायता मिली। जातीय जनतंत्रों के निर्माण से उनकी साम्यवादी और आर्थिक उत्पत्ति तेजी से हुई। जैसा कि ऊपर कहा गया, इन लोगों का जातीय गठन वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का नतीजा था और सोवियत जातीय जनतंत्रों के कृत्रिम निर्माण के कारण जान-बूझकर गुमराह करने के लिए लगाए जाते हैं और उनके पाँच राजनयिक उद्देश्य काम कर रहा है।

ताजिक गणराज्य की स्थापना के बाद में मध्य एशिया में छह समाजवादी जातियों की गठन हो चुकी थी। वे हैं उज़्बेक, कजाख ताजिक, किर्गिज़ तुर्गेश और ततरमान। उज़्बेकों की जनसंख्या ६०,१४,००० है और ये ताजिकों से थोड़ी बड़ी जाति है। इनमें १६,७३,००० मध्य एशिया और कजाखस्तान में रहते हैं (५०,३६,००० उज़्बेक ताजिक समाजवादी जनतंत्र में)। ताजिकों में कजाखों की कुल संख्या ३६,२२,००० है जिसमें २७,६५,००० अपने जातीय जातंत्र, कजाख सां० गण० जाति में रहे हैं। ताजिकों का कुल संख्या १३,६७,००० है जिसमें १०,११,००० ताजिक सां० गण० जनतंत्र में रहते हैं। पूरे ताजिकों में

मे तुक्मानो की सख्या १०,०२,००० है जिनमे ६,२४,००० तुक्मान सो० स० जनतन्त्र मे हैं। सोवियत सघ म किगिजा की कुल सख्या ६,६६,००० है, जिनमे किगिज सो० स० जनतन्त्र मे ८,३७,००० रहते है। कराकल्पाको की सख्या १,७३,००० है। इनका एक स्वायत्त जनतन्त्र उज्बेक सो० स० ज० के भीतर है जिसमे १,६८,००० कराकल्पाव है।

इन प्रधान जातिया के अलावा कई और छोटी जातिया भी है। इनमे ६५,००० उईगूर हैं ( जो अधिकतर कजाख सो० स० ज० के अत्मा अता क्षेत्र म और किगिज सो० स० ज० की फरगाना घाटी मे रहते ह ), २२,००० दूगान हैं, जो चीनी मुसलमान है, २,१२,००० कारियाई और ७,८०,००० तातार हैं ( ४,४५,००० उज्बेक सो० स० ज० मे और १,६२,००० कजाख सो० स० ज० मे रहते है )।

मध्य एशिया तथा कजाखस्तान की आवादी मे कुछ स्लाव भी ह। इन मे रूसी (६२,१५,०००), उक्रेनी (१०,३५,०००) और बेलोरूसी (१,०७,०००) हैं।

सोवियत मध्य एशिया के बाहर १२,००,००० उज्बेक और २६,००,००० से अधिक ताजिक अफगानिस्तान मे है। ६,५०,००० तुक्मान ईरान, इराक और अफगानिस्तान मे हैं, और चीनी लोक जनतन्त्र मे सिक्क्याग मे ५,०६,००० कजाख, ७१,००० किगिज, १४,००० उज्बेक और उत्तने ही ताजिक हैं।\*

\* ये सब आंकड़े १९५६ की जनगणना पर आधारित है।  
 ८० "मध्य एशिया और कजाखस्तान के जनगण", मास्को, १९६२, खण्ड १, पृष्ठ ११-१२। ( रूसी संस्करण )

१९७० की जनगणना के अनुसार सावियत सघ मे ६१,६५,००० उज्बेक, ५२,६६,००० कजाख, २१,३६,००० ताजिक, १५,२५,००० तुक्मान तथा १४,५२,००० किगिज हैं। अत सोवियत सघ मे रूसियो तथा उक्रेनियो के बाद तीसरी सबसे बडी सख्या उज्बेको की है। दे० 'सोवियत सघ का अथतत्त्व, १९२२-१९७२', मास्को, १९७२, पृष्ठ ३१। ( रूसी संस्करण )



### मध्य एशिया के ग्यान शासन

रूस का अधिकार होने से पहले मध्य एशिया की भूमि पर तीन ग्यान शासन थे। ज़रफ़शान नदी के क्षेत्र में बुखारा और निचली आराल दरिया पर छोटा कोकान से अधिक पुराने थे जिसकी स्थापना १८वां सदी के अन्त में हुई थी। १९वीं सदी के शुरू में कोकान में ताशाकंद पर पकड़ कर लिया जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापार-केंद्र था और जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नगर-राज्य के रूप में था। उपन्द्रा रित्तिज और तजाग्य खानाद्वारा की लहर का रोकने के लिए काज़ान ग्यान शासन ने सिरदरिया से और ईली नदिया पर अनेक किल्ले का निर्माण किया।

प्राचीन ग्यान शासन का संस्थापक मिन बश का आन्तिम ग्यान था। वर्ष १७६८-१७६९ में अपने पिता नरजुता बि के बाद गद्दी पर बैठा, जो १७८४ में पमारा का बेग था। बुखारा ग्यान शासन की स्थापना १७५३ में मंगित साबिश ने की। पहले शासन स्वयं अपने का ग्यान कहा करता था। उनमें हैज़र (१८००-१८२६) पहला व्यक्ति था, जिसने अन्त का अमीर कहा गया। उसका उत्तराधिकारी तमुता एक अन्धकार था, जिसकी भाँति पहानी ग्यान शासन पर बन्दा करने का था। पीछे का ग्यान शासन शास्त्रमय था पुराने राज का उत्तराधिकारी था।

१८वीं सदी में इसपर उल्लेख इनाको या शक्तिशाली जामीरदारों का शासन था, जो चंगेज खान की सत्ता खानों के अधीन शासन करते आ रहे थे। इनाक इलतुजेर ने १६वीं सदी के प्रारम्भ में अपने को खीवा का खान घोषित किया और अपने वंश की स्थापना की, जिसका शासन १६२० तक जारी रहा। १६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रूसी प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में फैल गया और जारशाही रूस सर्वोपरि सत्ता बन गया। कोकान के खान शासित क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया और बुखारा और खीवा को अपना अधीन राज्य बना लिया।

१६वीं सदी के प्रारम्भ में तीनो मध्य एशियाई खान शासित क्षेत्रों की जनसंख्या ४० लाख थी, जो सदी के मध्य तक बढ़कर ५० लाख हो गयी थी। खान-शासित क्षेत्रों में बुखारा की आबादी सबसे अधिक, कोई ३० लाख थी, कोकान की १५ लाख, और खीवा की सबसे कम—केवल ५ लाख थी।\* आबादी का बड़ा हिस्सा नखलिस्तानों और नदी घाटियाँ, खासकर सिर-दरिया, अमू दरिया, जरफशान, कशका दरिया और सुर्खान-दरिया की घाटियाँ में और ताशकन्द, बुखारा, कोकान और समरकन्द जैसे बड़े शहरों में बसा हुआ था। भद्र रेगिस्तानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में, जो मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे, खानाबदोश कबीले आबारा घूमा करते थे।

तीनों खान शासन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामंती राज्य थे, जिनमें दास प्रथा के अवशेष चले आ रहे थे।

रूस, पारस तथा अन्य पड़ोसी देशों से पकड़ कर लाये हुए गुलामों का व्यापार बहा हुआ करता था। तुर्कमान, कजाख और किर्गिज खाना-बदोशों में कबीला जिरगा व्यवस्था के प्रबल अवशेष थे। लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन और बागबानी था। कपास की उपज बहुत कम थी और जा भी थी, वह बहुत घटिया किस्म की थी। शहर दस्तकारी और व्यापार

---

\* न० अ० खालफिन, "मध्य एशिया में रूस की नीति", मास्को १९६०, पृष्ठ १६ तथा उसी लेखक द्वारा "रूस द्वारा मध्य एशिया का समावेशन", मास्को, १९६५, पृष्ठ ५२। (रूसी संस्करण)

का केन्द्र थे। बुधारा, कोकान, ताशकन्द और समरकन्द के दस्तकारों का बनाया हुआ सूती और रेशमी कपड़ा पूव के विभिन्न देशों तथा रूसी साम्राज्य में भी बिका करता था। प्राकृतिक साधनों की बहुतायत थी, मगर बहुमूल्य खनिज पदार्थ छोटे पैमाने पर निकाले जाते थे और इसी कारण उनकी लागत रूस से आयात किये हुए खनिज पदार्थों से अधिक होती थी।

रूस का बाज़ भारी था और अधिकतर जिस के रूप में वसूल किये जाते थे जिसका मुद्रा-माल सवधानों के विकास पर बुरा असर पड़ता था। सामंती उत्पीड़न और साहूकारों की लूट-छसोट के कारण दस्तकारी और कृषि की उन्नति रुकी हुई थी। सामंती विखंडन, लगातार परस्पर युद्ध तथा विभिन्न जातीय समूहों के आपसी संघर्ष से खान-शासित क्षेत्रों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो चुका था।

अमीरा और पाना, बेको, बाइयो और बीओ\* द्वारा भारी शोषण के विरुद्ध सभी जातीय समूहों के देहकानों का वग-संघर्ष सामंतविरोधी जन विद्रोहों के रूप में उभर पड़ा, जो १९वीं सदी के पूर्वार्द्ध की आम विशेषता थी। ऐसे सामंतविरोधी आन्दोलनों में १८२१-१८२५ में कित्तई विप्लव (बुधारा का एक उज्ज्वल कबीले) १८२६ में समरकन्द के दस्तकारों १८२७ और १८५५-१८५६ में चीवा के गरीब शहरिया और कित्तई १८१४ में ताशकन्द का विद्रोह तथा १८५६-१८५८ में दक्षिणी कजाखस्तान में इसी प्रकार के विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।\*\* अथर्वर युगलों और कानान का अधिवास, पासवर ताशकन्द बेकों के भ्रष्टाचार का कारण कजाख तनीला में विद्रोह किया और १८५८ में सुगस्तान शहर पर चढ़ दीडे। रूसी यात्री न० अ० सवेत्सोव न, जिस

\* बेको—गूबा का सामन्ती गवर्नर। बाई—घाँसी जमीन्दार या मयगिया के स्वामी। बी—कबील या जिरगे का सरदार।—स०

\*\* १० १० इवानोव, मध्य एशिया के इतिहास पर लेख (१६ वां खण्ड में १९५५ खण्ड का मध्य खण्ड)”, मास्को, १९५८, पृष्ठ १३५-१३६ १६७ २००, २१२। (रुमा संस्करण)

कोकान सिपाहियों ने पकड़ लिया था, इस उपद्रव को अपनी आखो देखा और ब्योरेवार इसके कारणों का वर्णन किया है।\* सभी रूसी यात्री इस बात पर सहमत थे कि खान-शासित क्षेत्रों के लोगों में बड़ा असंतोष था, जिसका कारण सामंती उत्पीड़न की असहनीय स्थिति थी।\*\* उनकी शहादत से ब्रिटिश लेखक जे० ह्वीलर का दावा कि खान शासनो में व्यापारिक जीवन में "बड़ी सरगर्मी" थी, झूठा साबित हो जाता है। उसका उद्देश्य ज़ारशाही रूस द्वारा मध्य एशिया पर कब्जे के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील पहलू से इनकार करना है।\*\*\* प० इ० नेवोलसिन ने १४ नवम्बर, १८५० को ओरेनबुर्ग से लिखा था कि खान शासित क्षेत्रों के लोग अत्यंत गरीब और उत्पीड़ित हैं, और धनी व्यापारी अधिकारियों की लूट-खसोट से बचने के लिए अपना धन छिपा कर रखते हैं।\*\*\*\*

\* न० अ० सेवेत्सॉव, "एक महीने तक कोकान का कैदी"—'रुस्कोये स्लोवो', अंक १०, पृष्ठ २६०-२६२। (रूसी संस्करण)

\*\* दे० न० मुराव्योव, "१८१६-१८२० में तुर्कमानिस्तान और खीवा की यात्रा", मास्को, १८२२, पृष्ठ १०१, अ० चेरन्यायेवा, "मध्य एशिया की चेरन्यायेव की यात्रा, १८५७-१८५६"—'इस्तोरीचेत्स्की वेस्तनिक', जून १९१५, पृष्ठ ८४४, व० व० वेत्यामीनोव-जेर्नॉव, "कोकान खानशाही के बारे में कुछ तथ्य"—'वेस्तनिक रुस्स्वोगो गेओग्राफीचेत्स्वोगो ओब्येत्स्त्वा', १८५६, भाग १, पृष्ठ ११३-११५, न० ग० ज़लसोव, "१८५८ में खीवा तथा बुखारा में कनल इग्न्यात्सेव का मिशन"—'रुस्की वेस्तनिक', अंक २-३, १८७१, पृष्ठ ५६ म० इ० इवानिन, "खीवा तथा आमू-दरिया"—'मोस्कोई स्वनिक', अंक ८-९, १८६४, पृष्ठ १६६। (रूसी संस्करण)

\*\*\* दे० G Wheeler, *The Modern History of Soviet Central Asia* London, 1964 pp 44 47

\*\*\*\* प० इ० नेवोलसिन, "मध्य एशिया से रूस के व्यापार के बारे में लेख"—'ज़पीस्की रुस्स्वोगो गेओग्राफीचेत्स्वोगो ओब्येत्स्त्वा', पुस्तक १०, मास्को, १८६५, पृष्ठ १५। (रूसी संस्करण)

## रूस और मध्य एशिया

खान शासित क्षेत्रों और रूस के बीच व्यापार और राजनयिक संबंध कमालेश नियमित रूप के थे। १६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रूस से आठ प्रतिनिधि दल मध्य एशिया आये, १७वीं सदी में खीवा से वारह और बुखारा से तेरह प्रतिनिधि दल रूस आये। रूसी दल इस प्लान के वार में बहुमूल्य सूचनाएं ले गये। रूस और मध्य एशिया के संबंध केवल प्रतिनिधियों के आगमन प्रगमन और तिजारती कार्गो तक ही सीमित नहीं थे। १७वां सदी के बुखारा और ताशकंद के उत्प्रेषण बड़ी सख्या में साइबेरिया में बसे गये। इनमें व्यापारी किसान और कारीगर थे। रूसी सरकार ने उन्हें प्रारम्भिक, आस्वादा और वाश्कीर इलाका में बसे सुविधाएं दी।\*

य मध्य १८वीं सदी में और सफल हुए, जब लघु आर मध्य वज्राय आर की अपीन पर वजाखस्तान का बड़ा भाग रूस में शामिल कर लिया गया। १९वीं सदी में रूस और मध्य एशिया के आर्थिक संबंधों में नया विस्तार पैदा हुआ। अगर १९वीं सदी के प्रारम्भ में रूस से सालाना निर्यात १० लाख रुबल का होता था, तो १८२५ में वह बढ़कर ४० लाख रुबल तक और सन् १८५० में मध्य में टैंड कराइ रुबल तक पहुंच गया। मध्य एशिया में सामानों का आयात भी इसी के अनुकूल बढ़ा। उनका मूल्य १८५० में २० लाख रुबल से बढ़कर १८५० में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई।

१९वां सदी का प्रारम्भ रूस के आर्थिक जीवन में बड़े महत्त्व का समाना था। पुरानी सामन्ती भ्रष्टाचार पर आधारित प्रयत्न का विघटन हो रहा था और उमरा स्याम नये पूजीमाली सतह से रह रहे थे। पुरानी रिमान-कारिगर अर्थतन्त्र तब भी म मान उत्पन्न रूप धारण कर रहा था और फार्मिया की संस्था बगल बढ़ रही थी। १८०६-१८२६

“मध्य एशिया और वजाखस्तान के जनगण” गृह १, पृष्ठ ६८।

ग. १८२५ “रूस द्वारा मध्य एशिया का समामान” -

रूस में मध्य एशिया के समामान के प्रगतिमान महत्त्व के विषय पर वजाखि प्रगतिगत के मध्य, ताशकंद १८५६ पृष्ठ १२। (रूसी समारण)

के बीच रूस में औद्योगिक उद्योगों की संख्या २४०२ से बढ़कर ५२६१ हुई और १८६० में १५,३८८ तक पहुंच गई। १८०४ में केवल ६५२ हजार मजदूर औद्योगिक उद्योगों में काम करते थे, १८२५ में उनकी संख्या २१०६ हजार और १८६० में ६५६१ हजार तक पहुंच गई थी।\* रूस में पूंजीवाद के तीव्र विकास के इस दौर में मशीनों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अदरुनी मशीन छोटी थी और १९वीं सदी के चौथे दशक से रूस के सूती कपड़े का निर्यात तेजी से कम होने लगा। छठे दशक तक मशीन निर्मित सस्ते ब्रिटिश और जर्मन सूती कपड़े ने रूसी कपड़े को संयुक्त राज्य अमेरिका की मशीनों से बाहर निकाल कर दिया। और इससे अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं अपनी फैक्ट्रियां खोलीं कर रहा था। ब्रिटेन और स्वीडन की बड़ी प्रतियोगिता के कारण धातु निर्यात भी कम हो गया था। ऐसी स्थिति में रूसी औद्योगिक हल्के इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि बाहरी मशीन के रूप में मध्य एशिया पर कब्जा करे। अतः हम अ. सेम्योनोव को मध्य एशिया में रूसी सूती कपड़े, रेशम और लोहे के सामान के लिए व्यापक मशीन प्राप्त करने की सिफारिश करते हुए पाते हैं।\*\*

जोर निकोलाई प्रथम ने १८३६ में ही एशिया से रूस के व्यापार संबंधों के बारे में विभिन्न सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की थी। इसने समस्या में वैदेशिक मामला, युद्ध और वित्त-मंत्रि तथा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रधान थे। उसी साल अ. इ. ३० की जहां रूस को अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा प्रतियोगिता का सामना नहीं करना था।\*\*\* मध्य एशिया से रूस के व्यापार के महत्व पर व्यापार

\*प. ३०. त्याश्चेको, "सोवियत संघ के अर्थतंत्र का इतिहास", मास्को, १९४७ खण्ड १ पृष्ठ ५३५। (रूसी संस्करण)

\*\*अ. सेम्योनोव, '१७वीं शताब्दी के मध्य से १८५८ तक रूस के विदेश व्यापार तथा उद्योग के बारे में ऐतिहासिक सूचनाओं का अध्ययन', सेंट पीटर्सबर्ग, १८५६, भाग ३, पृष्ठ ७२। (रूसी संस्करण)

\*\*\*न. अ. खालफिन, "रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन", पृष्ठ ६६।

सन्धी पत्रिकाओं और आद्योगिक हल्को में जोर दिया जाने लगा। ग० ई० दानिलेम्स्की ने भी, जिन्होंने १८८२ में चीन की यात्रा की, मध्य एशिया के साथ रूस के व्यापार को विकसित करने के सुझाव का समर्थन किया। १८४६ में चिखाचोव नामी प्रमुख भूगोलविद और यात्री ने रूसी साम्राज्य के लिए मध्य एशिया के साथ व्यापार के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उनके म्यास में इस इलाके के साथ रूसी व्यापार बढ़ाने के पक्ष में आग्रह भूमरीकी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति थी। उनका समर्थन उनके समकालीन य० व० खान्कोव ने किया। मध्य एशिया के साथ रूसी साम्राज्य के आर्थिक संबंधों के विकास का एक कार्यक्रम य० ई० नरालमिन ने तैयार किया था। वह रूसी भौगोलिक समाज की ओर से व्यापार संबंधी सूचना जमा करने १८५० में ओरेनबुर्ग और वास्पियन क्षेत्र में गये। उनका समाज के एक नेता मुराव्योव के नाम अपने एक पत्र में उन्होंने मध्य एशिया में सक्रिय नीति अपनाने का समर्थन किया। इसी के साथ उन्होंने यह सुझाव भी रखा कि आराम और सिरदरियाघा का रथ वास्पियन गागर की तरफ मोड़ दिया जाये, ताकि मध्य एशिया से व्यापार की सम्भावना बड़ाई जा सके। यद्यपि यह सुझाव उस समय के लिए अवांछित था, परन्तु इससे यह तो अदाजा होता है कि मध्य एशिया के साथ व्यापार के विनाश या उन दिना कितना महत्त्व दिया जा रहा था।

यद्यपि १९वां शताब्दी के छठे दशक तक रूस के पूर वैदेशिक व्यापार में मध्य एशिया के व्यापार का अनुपात बहुत कम था (२ ५ प्रतिशत से शायद ही कुछ ज्यादा ही) \* मगर इसमें वृद्धि की सम्भावनाएँ उज्ज्वल थी।

मध्य एशिया में

अपेक्षा के भनसूत्रे

मध्य एशिया का ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का ही नहीं, बल्कि उसके भीतर तथा राजनीति में कुछ का भी निशाना बनाया गया।

ब्रिटिश औपनिवेशिक हल्के अपने निमित्त सामाना के लिए बड़ी मढियों की खातिर और आसानी से बच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपने औपनिवेशिक इलाकों में विस्तार करने के इच्छुक थे। पूर्वी दशा के पिछड़ेपन के कारण उन्हें इस काम में आसानी हुई। इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने एशियाई राज्यों के विरुद्ध अनेक औपनिवेशिक लड़ाइया लड़ी।

मध्य एशिया में ब्रिटेन के विस्तारवादी उद्देश्य १८१२ में ही प्रकट हो चुके थे, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक वरिष्ठ अधिकारी विलियम मूरफ़ाफ़्ट ने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित एजेंटों का एक दल मध्य एशिया भेजा। मीर इस्मत-उल्ला ने इस क्षेत्र की विस्तारपूर्वक यात्रा की और जासूसी का काम किया। उसने अटक से कश्मीर, तिब्बत, यारकन्द, काशगर, कोकान, समरकन्द, बुखारा, खल्ज, खुल्मा, बामिया और काबुल तक लम्बा फासला तय किया। उसने बुखारा अमीरशासन का ब्योरेवार वर्णन किया जिसमें अधिकारिया की सभ्यता तब लिखी थी और दक्षिणी तुर्किस्तान में खुल्मा के शासक विलिच अली बेक से बातचीत में अंग्रेजों के समयन में प्रचार किया।\* इस तरह बड़ी हाशियारी के साथ मध्य एशिया में अंग्रेजों के औपनिवेशिक विस्तार के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। बाद में १८१६-१८२५ में मूरफ़ाफ़्ट और जॉर्ज ट्रेवेक ने कम्पनी की सेना के लिए घोड़े खरीदने के वहाने बुखारा की स्थिति की एक और जांच पड़ताल की।

चौथे दशक के प्रारम्भ में अलेक्सांद्र बन्स नामक एक अंग्रेज गुप्तचर अधिकारी एक अभियान दल लेकर बुखारा पहुँचा। उसने सैनिक तथा सामाजिक राजनीतिक सूचना जमा की जिसकी ज़रूरत अंग्रेजों को मध्य एशिया में अपनी अपहारक योजना के लिए थी। उसके साथ इस यात्रा में एक कश्मीरी पंडित मोहन लाल भी थे। बन्स दल का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक तथा सैनिक सूचना प्राप्त करना था। यह बात मोहन लाल के अपने "सफरनामे" के बयान से स्पष्ट है। मोहन लाल का विचार

\* *Travels in Central Asia by Meer Izzut Oollah in the Years 1812 13, Calcutta, 1872 pp 58—75 93*



या कि बुखारा के साथ अंग्रेजा के "व्यापारिक या राजनीतिक" संबंध स्थापित करने के लिए वातावरण बहुत अनुकूल था। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें "दर नहीं करनी चाहिये", क्योंकि "कोई शक्ति हमारे (अंग्रेजा के) इरादा का इस समय पहले से अंदाजा नहीं कर सकेगी"।\* मोहन लाल ने बुखारा की सैनिक शक्ति के बारे में काफी ब्योरेवार सूचना इकट्ठा की। बुखारा में मूरथापट के मिशन के गैर-सरकारी स्वरूप पर अवमर जार दिया जाता है। कहा जाता है कि उसकी बुखारा यात्रा की सम्पत्ति भारत सरकार ने अनिच्छापूर्वक दी थी और गवर्नर-जनरल ने उसे बाई गजनीति से सत्ता देने से इनकार कर दिया था। परन्तु मूरथापट जिता देना इस यात्रा में रहे उन्हें इसकी तनखाह दी गई और वागजात का खाना सरकार की सम्पत्ति माना गया।\*\* जब कुदुज सरदार ने कहा कि 'अंग्रेजी सरकार ने भारत से तुकिस्तान तक हर बड़े शहर में अपना जामूना का जाल बिछा रखा है' और बई आदमिया का नाम दिया, जो यह काम करने थे, तो मूरथापट ने इससे इनकार नहीं दिया बल्कि उनकी रूकियत यह कहकर पेश की कि "इसकी जरूरत प्राप्त के बादशाह के इरादा का भंग करने के लिए पड़ी है जिन्होंने यह घोषणा की है कि वह ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। इसी कारण उनकी गतिविधि की गहराई से देखना उस देश की सरकार के लिए जरूरी हो गया।" \* घाटे परीक्षण की बातें जामूसी के लिए बहाना मान लीं। यह हमें यह स्पष्ट होता है कि आगे चलकर अपना सौभाग्य समीक्षण

---

\* Mohan Lal *Travels in the Punjab Afghanistan and Turkesan to Balkh Bo'hara and Herat and a Visit to Great Britain and Germany* London 1846 pp 150—151

Horace Hayman Wilson *Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab by Mr William Moorcraft and Mr Geo. Trebeck from 1819 to 1825 prepared for the press from original journals and correspondence* Vol I London p XXVI

न। ग. २ पृष्ठ ६३२-६३३।

वे अंग्रेज सदस्यां न बहुत कम पाड़े परीद और बनल रिजव ने जिमे भारत सरकार द्वारा 'प्रथम श्रेणी के तुक्मान घोड़े नस्ल बढ़ान के उद्देश्य से खरीदने पर ३०० पाउंड खच करने का अधिकार दिया गया था, एव पेनी भी खच नहीं किया"।\* पांड किसी काम के नहीं पाये गये। १८३८ म हेरात अंग्रेजी जामूसी और विध्वसी कारवाइया का केन्द्र बन गया जिनका निदेशन मेजर ट'भारती टाड कर रहा था। बनल स्टांडाड का तेहरान की ब्रिटिश कौंसलेट स बुधारा भजा गया। दूसरे जामूस हेरात स खीवा और कावान भेज गय। १८३९ म मेजर टाड न एक व्यक्ति मुत्ता हुसैन का खीवा भजा जिसन खान का एक राइफन भेंट की। शीघ्र ही कप्तान जेम्स ऐवट भी उसने पीछे पीछे वहा पहुचा। १ मई १८४० को जब वह नावा अलकमाद्राज्य के निकट सडका और किला की छान-चीन कर रहा था रूसिया ने उस पकड लिया। गिरफ्तार होने पर उसन यह जाहिर किया कि वह खान का आदमी है और इसक सबूत म एक जाली दस्तावेज भी पेश की। उसे ओरेनबुर्ग और वहा स सेट पीटसवर्ग स जाया गया। वहा से उस लत्तन भेज दिया गया। जब ऐवट के मिशन को अपना उद्देश्य पूरा करने, यानी रूस और खीवा का लढान म सफलता नहीं मिली, तो रिचमड शेक्सपियर को वहा विध्वसक कारवाई के लिए भेजा गया। सोवियत इतिहासकार खालफिन के अनुसार सावियत केंद्रीय राज्य अभिलेखागार म शेक्सपियर के जो कागज सुरक्षित रखे गये है, उनस स्पष्ट है कि "भारत की सुरक्षा" करने के बहाने कुछ नयी "प्रतिरक्षात्मक" कारवाइया की योजना बनायी जा रही थी। अपने साम्राज्य क विस्तार के लिए अंग्रेजा को यह बहाना बहुत पसंद था। वास्तव म इसका उद्देश्य दक्षिण तुर्किस्तान के अर्द्ध स्वतन्त्र राज्यों पर आसानी स कब्जा करना था। खीवा स रूस जान के लिए शेक्सपियर ने यह बहाना दिया कि वह रूसी गुलामों क साथ जाना चाहता है।

\* G N Curzon *Russia in Central Asia* London 1889  
pp 130—131 see Lt A C Yate *Travels with the Afghan*  
*Boundary Commission*, 1887 p 457

था कि युगारा ने गाय भ्रष्टा व "व्यापारि या राजाति" मन्त्र स्थापित करा व निरा वातावरण उत्पन्न करवाया। उन्होंने मुगल को कि इसमें "दर नहीं करता तात्पर्य", क्योंकि "वा" शक्ति हमारे (भ्रष्टा व) इरादा या उस समय पहले से भ्रष्टा नहीं कर सकता।\* मान लाल न युगारा की सक्ति शक्ति व वायु म वासी व्यापार गुना इवद्धा की। युगारा म मन्त्राष्ट ने मिता ने गरजगरी स्थान पर भ्रष्टा जार दिया जाता है। वहा जाता है कि उसी युगारा याता या सम्पत्ति भारत सरकार ने भ्रष्टापूर्वक व थी और गरजगरी-जनरल व उस बाद राजनीतिर ताता दन म इनकार कर दिया था। परन्तु मन्त्राष्ट श्रित्त दिना इस याता म रह उत इसी तात्पर्य की गई और वायुधान को वगाल सरकार की सम्पत्ति माना गया। \* जब तुदुज सरकार व था कि भ्रष्टाजी सरकार ने भारत स तुकिमान तब हर बड़े शहर म भ्रष्ट जासूस का जाल बिछा रखा है" और बर्न भ्रष्टमिया का नाम दिया, जा यह काम करत व, ता मन्त्राष्ट न इसम इनकार नहीं किया बल्कि उसकी वैश्वियत यह बहुर पक्ष की कि 'इसकी जरूरत फ्रांस के बान्शाह के इरादा को भंग करने व लिए पड़ी है जिहाँ यह घापणा की है कि वह ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। नती कारण उसकी गतिविधि की छवर रखना उस दश की सरकार के लिए जरूरत हा गया"।\*\*\* छोटे खरीदन की बात जासूसी के लिए बढ़ाना मात्र थी। यह इस से स्पष्ट होता है कि आगे चलकर भ्रष्टान सीमा बन्दीगत

\* Mohan Lal *Travels in the Punjab Afghanistan and Turkestan to Balkh Bokhara and Herat and a Visit to Great Britain and Germany* London 1846 pp 150—151

\*\* Horace Hayman Wilson *Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab by Mr William Moorcraft and Mr George Trebeck from 1819 to 1825 prepared for the press from original journals and correspondence, Vol I* London p XXVI

\*\*\*वही खण्ड २, पृष्ठ ४७२-४७३।

वे अंग्रेज सदस्या ने बहुत कम घाटे परीदे और वनल रिजवे ने, जिसे भारत सरकार द्वारा "प्रथम श्रेणी के तुक्मान घोड़े नस्ल बढ़ान के उद्देश्य स खरीदने पर ३०० पाउंड खच करने का अधिनार दिया गया था, एव पेनी भी खच नहीं किया'।\* घोड़े किसी काम के नहीं पाये गये। १८३८ म हेरात अंग्रेजी जासूसी और विध्वसी कारवाइया का केंद्र बन गया, जिनका निदेशन मजर ड धारसी टाड कर रहा था। वनल स्टाडडाट को तेहरान की ब्रिटिश वासलेट स बुखारा भेजा गया। दूसरे जामूम हेरात स खीवा और कोवान भेजे गये। १८३९ म मजर टाड ने एक व्यक्ति मुला हुसैन को खीवा भेजा जिसने खान का एक राइफल भट की। शीघ्र ही कप्तान जम्स एबट भी उमक पीछे पीछे वहा पहुचा। मई १८४० का, जब वह नोबो अलकसाद्राक्स के निकट सडका और विला की छान-चीन कर रहा था रुसिया न उस पकड लिया। गिरफ्तार होने पर उसने यह जाहिर किया कि वह खान का आदमी है और इसक सबूत म एक जाली दस्तावेज भी वेश की। उस ओरेनबुग और वहा स सेट पीटसबग ले जाया गया। वहा से उस सदन भेज दिया गया। जब एबट के मिशन को अपना उद्देश्य पूरा करने यानी रुस और खीवा का लडान मे सफलता नहीं मिली, तो रिचमड शेक्सपियर को वहा विध्वसक कारवाई के लिए भेजा गया। सोनियत इतिहासकार खालफिन के अनुसार सावियत के द्रीय राज्य अभिलेखागार म शेक्सपियर के जो कागज सुरक्षित रखे गये है, उनसे स्पष्ट है कि "भारत की सुरक्षा" करन के बहाने कुछ नयी "प्रतिरक्षात्मक कारवाइया की याजना बनायी जा रही थी। अपन साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजो को यह बहाना बहुत पसद था। वास्तव म इसका उद्देश्य दक्षिण तुकिस्तान के अख स्वतंत्र राज्या पर आसानी से कब्जा करना था। खीवा स रुस जान के लिए शेक्सपियर ने यह बहाना किया कि वह रुसी गुलामा के साथ जाना चाहता है।

\* G N Curzon *Russia in Central Asia* London 1889  
pp 130—131 see Lt A C Yate *Travels with the Afghan*  
*Boundary Commission* 1887 p 457

सितम्बर १८४० में वह आरेनबुग पहुँचा, मगर उसे निगरानी में रखा गया और लन्दन भेज दिया गया।\*

रालिनसन का कहना है कि जेम्स ऐवट को हरात में अग्रजों द्वारा मेजर टाड न छोड़ा खाना दिया था। ऐवट ने मैन्म और एलफिन्स्टन के समय के रिवाज के अनुसार गुमान रखा कि रगिया को इन इलाकों से हमेशा के लिए निवास बाहर करना चाहिए "और समान दुश्मन से नाता ताड़ने के लिए पुरस्कार के रूप में इंग्लैंड में साथ प्रतिरक्षात्मक आक्रमण संधि का प्रस्ताव रखा गया"। लेकिन रालिनसन का कहना है कि ऐसा करने का ऐवट का आदेश नहीं दिया गया था। आदेश में बदन रूसी गुलामों को मुक्त करने की बात थी।\*\* वैम्बरी का कहना है कि अग्रजों ने तीन खान शायों के साथ रुम के खिलाफ "आक्रमण प्रतिरक्षात्मक संधि" करने की योजना बनाई थी।\*\*\* लेकिन उसकी राय में दोष स्ट्राइडट और कानाल्सी का था, जो इस उद्देश्य का प्राप्त करने के योग्य नहीं थे।

रालिनसन ने लिखा है कि चौथे दशक में अतिम वर्षों में अग्रज "हिंदूकुश की उत्तरी ढलान पर सिगान पर कब्जा करने और आगे बढ़ाकर तक बढ़ने की तैयारी" कर रहे थे।\*\*\*\* लेकिन बहादुर अफगानों के कड़े प्रतिरोध के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सका। क्रोमियाई युद्ध के दौरान में इंग्लैंड ने जाजिया के रास्ते मध्य एशिया में एक बड़ी सेना भेजने की योजना बनायी थी। लेकिन चूँकि वे "फ्रांसीसी सहयोग पर भरोसा नहीं कर सकते थे", इसलिए इस योजना को त्यागना पड़ा।\*\*\*\*

\*दे० न० अ० खालफिन का लेख '१९वीं सदी के चौथे तथा पाँचवें दशकों में मध्य एशिया में अग्रजों का विस्तार तथा रिचमंड शेक्सपियर का मिशन' - 'इस्तोरिया एस० एम० एस० एर०' १९५८, अंक २। (रूसी संस्करण)

\*\* H Rawlinson *England and Russia in the East* London 1875 pp 153—154

\*\*\* A Vambéry *History of Bokhara* London, 1873 pp 384—388

\*\*\*\*ह० रालिनसन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५२।

\*\*\*\*\*वही, पृष्ठ १८२-१८३।



की सहायता व निष्पत्ति विशेष रूप में प्रशिक्षित भारतीय एजेंटों का एक दल बनाया गया था जिसमें प्रमुख थे पंडित भाषन, पंडित माहान, भाई दावान सिंह और गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी की डायरी का अनुवाद पत्रिका में पंजाब राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। यह दस्तावेज़ लिखने के लिए १० मितम्बर, १८६५ का पंजाब से रवाना हुआ और १८६७ में प्रारम्भ में नोटा। इस मुद्रित में उमन बुधारा, कानान, पंजाब, समरान और ताशान की यात्रा की। यह बुधारा में दो महीने छूट गिना और यहाँ से फरवरी १८६६ में कानान गया। यहाँ यह एक महीना रहा। बुधारा में उसने "बुधारा दरबार के सदस्यों से परिचय किया और उसकी विस्तारपूर्ण रिपोर्ट लिखी।" अपनी रिपोर्ट में उसने आस-पास के इलाक़ों के परिवेश, इसका बारह दरवाज़ावाली दीवारों की चौड़ाई का ब्यारब्यार बणन किया है। उनकी राय में यह 'सुरक्षा करने में योग्य नहीं थी'। उसने यह भी लिखा कि "सना में कोई अनुशासन नहीं और उसका पास २०० तापें थी, जो विलुप्त होकर थी। उसने चिराग़ों और शहरिसब्ब (बुधारा में) के सैनिक उपकरण और प्रतिरक्षा-भूमता तथा जिरज़क के निवट रूसी जिलाबन्दी के बारे में भी रिपोर्ट भेजी।" मुहम्मद इब्न मुहम्मद, मिर्जा बाबा किलाबनार और खबरनवीस मुहम्मद तियाज की सहायता से उसने पान पदार्थों पान से भेंट की। कानान से गुलाम रब्बानी ने ताशानन्द की तीन यात्राएँ की जिनके दौरान उसने किलाबन्दी, जलागार आदि का ठीक-ठीक अध्ययन किया। उन्होंने नदियाँ के पानी के रंग तथा पत्थरों और खनिज पदार्थों की प्रकृति तथा का उल्लेख किया। ताशानन्द पर रूसी कब्ज़े से व्यापारियों में आतंक फैला हुआ था। इससे फायदा उठाकर गुलाम रब्बानी ने उनकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी दिलाने के लिए रूसी जनरल चेरन्यायेव के पास जाकर बहने सुनने की तत्परता व्यक्त की। कानान के व्यापारियों के

लिए इस "मानवीय" सेवा का यह स्वेच्छापूर्ण प्रस्ताव भी दरअसल एक वहाना था, जसाकि पहले व अवसरा पर "घाटा की धरोदारी" और "रूसी गुलामा की मुक्ति" थी। इसका राजनीतिक उद्देश्य कुछ और था। गुलाम रब्बानी ने अपनी डायरी में लिखा है 'इस (ताशकन्द) की यात्रा करने वाले अपनी जान का जायिम में नहीं डालेगा, परन्तु तैलक के सामने एक उद्देश्य था (बल जाड़ा गया है) इसलिए उसने यद् इसकी इच्छा प्रकट की।' \* उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, जब हम दफ्त हैं कि यह जनरल बेरन्गायव व साथ साथ ताशकन्द व पास चिरचिक की तय गया और उनकी गतिविधि पर नज़र रखता रहा। जय वह भारत लौटा, तो बुधारा दरबार का एक वकील उसका था। बल्क में वह इस वकील का साथ लेकर फ़ैज़ माहद (एक दूसरे अग्रेज़ एजेंट) से मिला। और भाई दीवान सिंह व जल्दी बुलाने पर बदख़शान चला गया। वकील स्वयं काबुल रवाना हुआ जहाँ रब्बानी बाद में भाकर उससे मिला। मध्य एशिया में अग्रेज़ा व आश्रामक मनसूबा से रूसी शासन हल्ला में काफी परसानी हुई। विप्रासमान पूजावाद की ज़रूरत व हनु रूसिया ने शीघ्रतापूर्वक मध्य एशिया पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह व अग्रेज़ा पर बाज़ी ले गये।

\* वही, पृष्ठ ३६-३७।



## रूसी विस्तार

एशिया में रूस का विस्तार १६वीं सदी में शुरू हुआ। मॉस्को महान राज्य ने मंगोला का जमा उतार फरने के बाद तुरंत ही एशिया पर धावा बाल दिया। १५५२ में इवान भयानक ने कज़ान पर और १५५६ में वात्गा के दहान में आस्ताया पर अधिकार कर लिया। सत्रहवीं सदी के अंत में रूसी प्रशासित मठासागर तक जा पहुंचे। इस विस्तार का बाधा कज़ाक़ा नें उठाया था। उन्हें आदिम रबीला ने प्रतिरोध का काम ही सामना करना पड़ा और थोड़े ही दिनों में रूसी अधिपतिया की संगत उनसे बढ़ गयी। साइबेरिया से दक्षिण की ओर बढ़ाव मठारहवीं सदी में शुरू हुआ, पहले स्तपी क्षेत्र में और फिर तुर्किस्तान में। यह कहा जा सकता है कि स्तपी इलाके में रूस का विस्तार १७३० में शुरू हुआ, जब सयु अर्दु के खान, अबुल खैर ने रूसी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। खान प्रदेशों की ओर रूसिया का बढ़ाव उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में शुरू हुआ।

१८२४ में कास्पियन और अराल सागरों के धायुमंडलीय दाव का अध्ययन करने के लिए एक "वैज्ञानिक" दल भेजा गया जिसके समयन के लिए कज़ाक़ पैदल सेना का आधा बटालियन और छह तोपें थीं। १८३४ में कास्पियन सागर के उत्तरपूर्वी तट पर नावो प्रलेक्साद्रोव्स्क के किले में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई जिसका उद्देश्य खोवा से

व्यापार को बढ़ाना था। १८३६ में जनरल व० पेरोव्स्की के नेतृत्व में खीवा अभियान शुरू हुआ जिसमें ५,००० सैनिक, २२ तापें, १०,००० ऊट और २,००० विभिन्न कुत्ते और ऊटवान थे। यह अभियान भी वेकाविच और मुराव्योव के अभियानों की तरह असफल रहा। बंबल एक हजार सैनिक किसी प्रकार लौट सके और बाकी असाधारण रूप से बड़े जाड़ में मर गये। तुरंत ही एक और अभियान की तैयारी शुरू हुई और खीवा के खान ने इसकी सूचना पाकर शांति का आग्रह किया। उसने खीवा में सभी रूसी बन्धियों को रिहा कर दिया और अपनी प्रजा में उन लोगों का, जो रूसी व्यापारियों पर हमला करेंगे, मृत्यु-दंड की धमकी दी। खीवा के साथ एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर भी हुए, जिसके अनुसार खीवा ने वादा किया कि वह रूसियों पर हमला नहीं करेगा और उन्हें गुलाम बनाना बन्द कर देगा। मगर रूस के प्रति खीवा की शत्रुता जारी रही। खान ने छुल्लम-पुल्ला बजाय विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें रूस के खिलाफ भड़काया।

रूसी सरकार ने अब मध्य एशियाई खानशासन से अपने व्यवहार का तरीका बदल दिया। इसने रेगिस्तान के रास्ते सैनिक अभियान भेजने के बजाय, जिसमें बार-बार असफल होना पड़ता था, धीरे-धीरे, मगर नियमित रूप से बढ़ने का निश्चय किया। १८४६ में ओरेनबुर्ग के गवर्नर ने अराल सागर के निकट सिर-दरिया पर एक किले का निर्माण किया, जहाँ बढ़नेवाले रूसी दस्तों की सहायता के लिए एक जहाजी बेंडा खड़ा था। उस समय तक वेनिस्सारी के नेतृत्व में बजाख विद्रोह कुचल दिया गया था। १८५३ में जनरल पेरोव्स्की ने आक मस्जिद पर अधिकार कर लिया, जो कोकानवालों का एक किला था। यहाँ क्रोमियाई युद्ध के कारण रूसियों का आगे बढ़ना कुछ असें के लिए रुक गया।

क्रोमियाई युद्ध में ज़ारशाही रूस की हार के कारण बात्कन और निकट पूर्व से रूस की दिलचस्पी का रख सुद्धर पूर्व और मध्य एशिया की ओर मुड़ गया। यूरोप में रूसी साम्राज्य का रास्ता, जैसा बाल माक्स ने लिखा था, अब बन्द हो गया था। रूसी साम्राज्य के विदेश मंत्री अ० गोर्चाकोव ने १८५८ में लंदन स्थित रूसी राजदूत बुन्कोव को आदेश

भेजे जिनसे यह नीति-परिवर्तन निपायी देता है। विदेश मंत्री न पूव म  
रूस के लिए वदम बढ़ाने की पूरी स्तत्रता प्राप्त करने की इच्छा पर  
चल दिया। ब्रिटेन से दृष्टापूर्वक यह वह देना था कि अगर वह रूस के  
साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो उसे पूव म रूस के हिता को उचित  
मायता देनी होगी। तदन स्थित रूसी राजदूत के नाम आदेश म यह  
निर्धारित कर दिया गया कि रूसी नीति का मुख्य उद्देश्य "एशिया में  
रूसी उद्योग, व्यापार और ससृष्टि के प्रभाव का सफल बनाना था"।<sup>\*</sup>  
जनवरी १८५६ में जनरल ब्लास्वग ने घोषणा की कि रूस का भविष्य  
यूरोप से संबंधित नहीं है और इसलिए उसे अपनी दिलचस्पी का रज  
एशिया की ओर मोड़ना चाहिये। १८५७ में यू० अ० गार्गेमाइस्टर ने  
लिखा कि यूरोप की तुलना में एशिया के साथ रूस के व्यापार की वृद्धि  
की दर वही अधिक है और जहां निमित्त सामान यूरोप में उसके निर्यात  
का बहुत छोटा भाग था, वहां एशिया में वह उसके निर्यात का आधा  
था। उसने सिफारिश की कि आर्थिक कारणों से मध्य एशिया पर कब्जा  
कर लेना चाहिये। वह इलाका रूस की रेलों के लिए बहुत अनुकूल है  
और सिरदरिया में ताश्कन्द के निकट तक जहाजरानी हो सकती है।<sup>\*\*</sup>  
मध्य एशिया पर रूस के कब्जे के आर्थिक परिणामों का विषय रूस के  
राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, जनरलों और पत्रकारों में सार्वप्रिय था। रूसी  
साम्राज्य के वैदेशिक व्यापार और उद्योग के बारे में अ० सेम्योनोव का  
कृतियों और साथ ही वित्त मंत्री के सलाहकार, यू० गार्गेमाइस्टर और  
फ० तनर, प्रसिद्ध उद्योगपति और व्यापारी अ० शिपाव प्राच्यवेत्ता  
ई० बैरजिन और व० प्रिगेर्येव, यात्री-लेखक म० इवानिन की कृतियों  
ने रूस में मध्य एशिया के प्रति बड़ी दिलचस्पी पैदा की। "रुस्की वेस्तनिक",  
मोस्कोई स्वनिक और "एकोनोमिचेस्की उवाज्दातेल" जैसी पत्रिकाएँ

\* व० नोल्डे, "बिस्माक का पीट्सबर्ग मिशन, १८५६-१८६२",  
प्राग, १९२५, पृष्ठ ६४-६५ (रूसी संस्करण), न० अ० खालकिन,  
रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन, पृष्ठ ८३।

\*\* व० अ० गार्गेमाइस्टर, 'रूस के उद्योग तथा व्यापार पर विचार',  
- 'रुस्की वेस्तनिक', १८५७ अंक १ पृष्ठ ३८-३९।

न अनवर पृष्ठ मध्य एशिया की गतिविधिया के बारे में दिये। अ० शिपोव ने रूस का कच्चे सामान, घासकर कपास के भावी प्रदाता के रूप में मध्य एशिया की भूमिका पर जोर दिया।\*

पूजीपति वग से गहरे संबंध रखनेवाले शासक हल्का ने मध्य एशिया का रूसी साम्राज्य में मिला लेने के इस व्यापक आन्दोलन का समर्थन किया। १८५६ में बार्नेशियाई कमांडर अ० ई० बर्गातिन्स्की ने ज़ार अलक्सान्द्र द्वितीय के सामने यह सुझाव पेश किया कि कास्पियन से अराल सागर तक पुराने कारवान-मार्ग के बजाय रेलवे का निर्माण किया जाये। उनका सुझाव का उद्देश्य उनके प्रभाव का दूर करना था। इस सुझाव पर बर्गातिन्स्की का ईरान में अंग्रेजों की कारवाइया से चिन्ता हो गई थी और उनका सुझाव का उद्देश्य उनके प्रभाव का दूर करना था। इस सुझाव पर असाधारण समिति में विचार किया गया जिसने विदेश मंत्री गोर्चकोव और जनरल परोखोव के विरोध के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया। समिति ने कास्पियन से अराल सागर तक और फिर उसको बढ़ा कर बामू और सिर-दरिया तक सीधा संबंध स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली, मगर उसका कार्यान्वयन अधिक अनुकूल समय तक के लिए स्थगित कर दिया।

क्रैमियाई युद्ध के पहले ही मध्य एशिया से व्यापार करनेवाले औद्योगिक पक्ष, व्यापारी कम्पनिया और परिवहन संगठन कायम होने लगे थे। सरकार ने मरकरी स्टीमर कम्पनी (१८४६ में स्थापित) तथा बरानोव और येनिजारोव के व्यापार-गृहा को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया। एक प्रमुख रूसी उद्योगपति कोकोरेव और सेवास्तोपोल के बीच धूलोव ने कास्पियन मार्गों पर एक स्मरण-पत्र पेश किया और मध्य एशिया के खानशासित प्रदेशों से व्यापार के लिए उनके विशेष महत्त्व पर जोर दिया। ट्रांसकास्पियन व्यापार सत्था २० लाख रूबल की पूंजी से संगठित की गई। इसे बर्गातिन्स्की और ग्राड प्रिंस बोसततीन निकोलायविच का समर्थन प्राप्त था। १८५८ में बेंगलदावी ने फ्रांसोवोदस्क में मछली पकड़ने का एक केंद्र कायम करने का सुझाव पेश किया।

\*अ० शिपोव, "सूची पकड़े का उद्योग तथा रूस के लिए इसका महत्त्व", मास्का, १८५७-१८५८, पृष्ठ ४२। (रूसी संस्करण)

उन्होंने तुर्कमान कबीला से व्यापार करने का भी सुझाव रखा जिस ओरेनबुर्ग के गवर्नर-जनरल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय उसपर ध्यान नहीं दिया जा सका।

गोचाखोव न वोवालेन्स्की का वैदेशिक मामला के मंत्रालय में एशियाई विभाग का निदेशक नियुक्त किया। उनकी देखरेख में पहली दशा का सर्वव्यापी अध्ययन किया गया और मध्य एशिया में ज़ारशाही हम क विस्तार के लिए रास्ता साफ किया गया। १८५८ में व्यापारिक, राजनीतिक और गुप्तचर मंडल ईरान, मध्य एशिया के खान शासित प्रदेशों और काशगर में भेजे गए। सीना रूसी मटना (जिनका प्रमुख नि० खानिकाय, न० इन्नात्येव और च० क्लोपात्ताय थे) का रूप यद्यपि भिन्न था (खानिकाय "वैज्ञानिक" याजयात्ता तथा इन्नात्येव सरकार राजनयिक मंडल के नेता थे और क्लोपात्ताय मुसलमान व्यापारी के रूप में गया था) मगर उनका उद्देश्य एक ही था—पड़ोसी देशों का राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का गहरा अध्ययन करना। इन मन्त्रों ने खुरासान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया के खान शासित प्रदेशों और पश्चिमी चीन के लोगों और साथ ही इन इलाकों में अंग्रेजों की घुमपठ के बारे में बहुमूल्य सूचना जमा की। इसी के साथ उन्होंने वहाँ रूस का असर फैलाने का भी प्रयास किया। खीवा और बुखारा से इन्नात्येव के मिशन के लौट आने पर ज़ारशाही सरकार ने मध्य एशिया में प्रत्यक्ष विस्तार की सक्रिय तैयारियाँ शुरू कीं। दोनों इन्नात्येव तथा ओरेनबुर्ग के गवर्नर-जनरल कातेनिन पश्चिमी साइबेरिया लाइन का ओरेनबुर्ग की लाइन से मिला देने के समर्थक थे। १८६० में ज़ारशाही सरकार ने इस्तीक-कूल और पिश्पक इलाकों में गुप्तचर मंडल भेजे।\* १८६१ में मेजर जनरल त्सिमेरमन ने कोकान खान शासित प्रदेश की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजी। उन्होंने मध्य एशिया की भूद्वी में अधिक रूसी सामानों के परिचालन के लिए खान प्रशासन पर अधिक दबाव डालने की सिफारिश की।

\* न० अ० खालफिन, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ११७-११८।

कोकान के खिलाफ जोरदार बारवाई के एक और प्रभावशाली समयक युद्ध मंत्री ८० अ० मिल्यूतिन थे। वह आरेनबुग के गवरनर जनरल बेजाक की सलाह पर काम करते थे। बेजाक ने १८६१ में सिर-दरिया की लाइन की यात्रा की और यह राय बनायी कि ताशकंद पर जितनी जल्दी हा सके कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इससे कोकान के साथ रुस की सीमा सुविधाजनक हो जायेगी और ताशकंद पर कब्जा होने से व्यापार की बढ़ाने में आसानी होगी। बुखारा, चीन और रुस के व्यापारी रास्ते ताशकंद से होकर गुजरते थे। इसलिए इस शहर पर रुस का कब्जा होने से इन देशों से, खासकर चीनी तुकिस्तान से व्यापार में वृद्धि हो सकती थी और बुखारा पर उसका असर भी बढ़ सकता था।

वैदेशिक मामलों के मंत्रालय को भय था कि मध्य एशिया में अति सक्रिय नीति से ब्रिटेन की शक्त बढ़ जायेगी। लेकिन बेजाक का विचार था कि सिर-दरिया तक रुस का विस्तार होने से ब्रिटेन कोई असाधारण प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, जो वह आमु-दरिया तक बढ़ने की सुरत में व्यक्त कर सकता है। यद्यपि चार नौ बेजाक के विचारों को स्वीकार किया, फिर भी केवल चार साल गुजरने के बाद ही ताशकंद को रुसी के नियंत्रण में लाया गया। अतः में ताशकंद पर कब्जा स्थानीय कमांडर जनरल चेरन्यायेव की फौरी बारवाई द्वारा हुआ, जो बड़ी हद तक अनाधिकृत थी।

अक्टूबर १८६४ में, ठीक उही दिनों में, जब जनरल चेरन्यायेव ने ताशकंद पर अपना पहला असफल हमला किया, इस बारवाई के औचित्य को इस बुनियाद पर स्पष्ट रूप में अस्वीकार कर दिया गया कि इससे अनिवार्यतः रूसी साम्राज्य सभी मध्य एशियाई झगड़ा में फस जायेगा। लेकिन वैदेशिक कार्यालय के सरकारी स्मृतिपत्र में, जहाँ "हमला करके रूसी प्रभाव की सीमाओं को फैलाने" की इच्छा से इनकार किया गया था, बहुत सी गोलमोल बातें भी वही गई थी। अतः जहाँ १८६४ में चार द्वारा स्वीकृत मध्य एशिया में कारवाइयों की योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि मध्य एशिया में और अधिक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है, वही यह वक्तव्य भी दिया गया था कि पूरे

काकान खान शासित प्रदेश पर अधिचार करना "अनिवार्य" है। इसमें "साम्राज्य के और अधिन विस्तार" के अनौचित्य की सारी बात बमारी होकर रह गई।

जब जून १८६५ में चेरयायेव ने ताशकन्द पर कब्जा कर लिया, तो खातफिन के बयानानुसार वह ऐसा काम कर रहा था, "जो वास्तव में इसी साम्राज्य की सरकार और सैनिक-मामती अभिजात वर्ग तथा व्यापार और औद्योगिक हल्का के विचारों के तदनुरूप था"। वह भलाभाति समझता था कि राजनयिक विभाग की यह अपील कि मध्य एशिया में विस्तार रोक दिया जाये, एक विशेष प्रकार की चाल थी, धाँखे की ठूठी जो ब्रिटेन के विरोध के डर से पड़ी की जा रही थी। विस्तारवादी तत्वों की राजधानी में और स्वयं उसने निवृत्ततम साधिया में जो समयन प्राप्त था, उससे चेरयायेव ने लाभ उठाया। वह जानता था कि "उसकी इस 'स्वतंत्र' धारवाही के लिए उससे कोई पूछताछ नहीं की जायेगी, बल्कि उलटे उसे पदक और तरफकी मिलन का विश्वास था"।\*

जब चेरयायेव ने ताशकन्द पर कब्जा किया, तो कुल २५ हसी मारे गये और ८६ घायल हुए। विरोध बहुत सीमित था। पहले वदेशिक मामलों के मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि ताशकन्द का इसी साम्राज्य में मिला लेने की उसकी कोई इच्छा है। उसका विचार था कि ताशकन्द और उसने आस-पास के इलाके को एक अलहदा खान प्रशासन में परिणत कर दिया जाये जिसपर जारशाही का पूरा नियंत्रण हो और जो इसी साम्राज्य और बुखारा के बीच मध्यवर्ती राज का काम करे। चेरयायेव ने इस राय का विरोध किया, भगर आरेनबुर्ग के नवनियुक्त गवर्नर जनरल त्रिजानोव्स्की ने इसका समयन किया। ताशकन्द के लोगो से जब अपना खान चुनने को कहा गया तो उन्होंने चेरयायेव के नाम वक्तव्य में इस बात को ज्यादा पसंद किया कि ताशकन्द की नागरिक सरकार चेरयायेव के हाथ में रहे और धार्मिक और अदालती प्रशासन काही

\* न० अ० खातफिन, "मध्य एशिया में रूस की नीति", पृष्ठ १७८-१७९।

कता, या धार्मिक कानून के सर्वोच्च आयाधीन के सुपुद कर दिया जाये जिसके लिए बेरन्यायेव की मजूरी जरूरी हो। अगस्त १८६६ में ताशकंद का रूस का अंग घोषित कर दिया गया।

१८६७ में तुकिस्तान के गवर्नर जनरल का क्षेत्र स्थापित किया गया, जिसका प्रधान केंद्र ताशकंद था। जनरल व० प० काउफमन को पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। मार्च १८६८ में बुखारा के अमीर मुजफ्फरुद्दीन ने रूसियों के खिलाफ जेहाद का एलान कर दिया। जनरल काउफमन ने अप्रैल १८६८ में समरकंद पर छावा बोल दिया और बुखारा की सेनाओं को पराजित करके २ मई को शहर में प्रवेश किया। समरकंद की पराजय से बुखारा की शान मिट्टी में मिल गई और उसे एक सधि स्वीकार करनी पड़ी जिससे खान प्रशासन पराधीन हो गया।

१८६४-१८६८ के दौरान में मध्य एशिया के दो सबसे बड़ी खान-शासित क्षेत्रों बोकान और बुखारा की बिल्कुल शिक्स्त हो गई। राजनयिक कारणों से उनको मिला लेने का निश्चय उस समय नहीं किया गया। १८६८ में बोकान के खान खुदायार खान और बुखारा के अमीर मुजफ्फरुद्दीन के साथ शांति-संधिया की गई जिनके अनुसार उहाने रूस द्वारा वास्तव में जीती हुई भूमि छोड़ दी, अपनी पराधीन स्थिति स्वीकार की और रूसियों को अत्यंत लाभदायक शर्तों पर व्यापार का अधिकार दिया।

बोकान की सधि से रूसी व्यापारियों को खान शासित प्रदेश के सभी शहरों में जान, कारवान-सराये स्थापित करने और व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। आयात कर के मामले में रूसी और मुसलमान व्यापारियों में अंतर मिटा देने का निश्चय किया गया और पड़ोसी राज्यों का जानेवाले रूसी कारवानों को बिना रोक-टोक आने जाने का अधिकार मिल गया। रूसियों को केवल २५ प्रतिशत महमूल दना था। उतना ही मुसलमान व्यापारी दिया करते थे। और इसके अलावा भय विदेशियों के मुकाबले में रूसियों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हुईं। खान शासित प्रदेश का आघा इलाका हाथ से निकल गया और बाकी आघा रूस का संरक्षित क्षेत्र हो गया। बुखारा के साथ सधि पर अमीर न जून



१८६८ में हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार समरनन्द, तत्ता-बुगान और जरफखान का पूरा जिला रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया और इसके अलावा पांच लाख रुबल का हरजाना देना पड़ा। इसमें व्यापार का सुविधाओं के सबब में बड़ा धागा भी था। रोगों की तरह बुगारा भी इस के अधीन हो गया।

चीन की चारों पांच वर्ष बाद आयी। १८७३ के वसंत में रूस ने उमको परास्त कर लिया और उसे अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। अगस्त १८७३ में जारल वाउफमन और चीन के शासक सपद माट्स्मन रहोम खान ने शांति-संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इस संधि ने खान को यह स्वीकार करने पर विवश कर दिया कि वह "तमाम रूस के सम्राट का भदना चाकर" है और "पड़ोस के शासकों और खानों से सभी प्रत्यक्ष और दोस्ताना संबंधों का परित्याग करता है। आमू-नरिया का पूरा दाहिना तट और उसके मिला हुआ चीन का इलाका रूस को दे दिया गया और उसे आमूर-नरिया में बिना रोक-टोक जहाजरानी का अधिकार भी मिल गया। रूसियों को आमूर-नरिया के बायें तट पर गंदम और घाट बनाने और फैक्ट्रियां कायम करने का अधिकार मिल गया। रूसी व्यापारियों और कारवानों को पूरे खान शासित प्रदेश में यात्रा की आजादी मिल गई और खान ने उनकी विशेष सुरक्षा का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इसके अलावा उन्हें चुगी-कर भदा करने से भी मुक्ति मिल गई। संधि में ऐसी धारा भी निहित थी जिसके अनुसार खोवा में रूसिया का अतिरिक्त देशीय अधिकार प्राप्त था। चीन ने दास पपा मिटान और १८६३ तक कुल मिलाकर २२ लाख रुबल मुद्रा का हरजाना भुगतान करने के सबब में भी धाराएं थी। खोवा के साथ यह संधि विल्कुल औपनिवेशिक संधि थी जसी पश्चिमी शक्तियां ने चीन पर थोपी थी। इस संधि से और इसके पहले बोकार और बुखारा के साथ संधियों से इन तीनों खान शासित प्रदेशों पर रूस का आधिकार अधिक निश्चित हो गया।

जारशाही रूस द्वारा खान शासित प्रदेश के मिला लिये जाने पर खोवा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसपर दिलचस्प रोशनी एक समवालीन

अंग्रेज ने डाली है, जो मध्य एशिया की घटनाओं का साक्षी था। मकगाहन ने लिखा था कि उसे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरजाने की रकम अदा होने से पहले ही खान की मृत्यु या किसी और घटना के कारण शायद स्वयं सोगो के अनुरोध पर, रूसियों को अपने हाथों में सत्ता लेने का मौका मिल जायेगा।\*

इसके बाद तेव्हे तुक्मानो की, जो अतरेक घाटी में बसे हुए थे और मव नखलिस्तान में रहनेवाले सरापा की बारी आयी। खीवा को अधीन कर लेने के बाद रूस के विस्तार के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। रूसी हमले के प्रति सगठित विरोध का अंतिम आभास भी गायब हो जाता रहा और ज़ार महान खान शासित प्रदेशों का निर्विरोध अधिपति बन गया। पश्चिम की ओर रूस का प्रभाव कास्नोवोदस्क की कास्पियन बंदरगाह में, जिस जनरल स्तोलेतोव ने १८६६ में कायम किया था, मजबूती के साथ जम चुका था। आमु-दरिया पश्चिम की नयी सीमा थी। परन्तु आमु दरिया और कास्पियन के बीच का इलाका अपराजित रह गया था। यहाँ कोई सगठित राज्य नहीं था और इस इलाके में तुक्मान बसे हुए थे, जिनकी पराजय की कहानी मध्य एशिया पर रूसी कब्जे के इतिहास का अंतिम अध्याय है।

लेकिन इससे पहले कि रूस तुक्माना पर चढ़ाई करता, कोकान में विरोधी आन्दोलन फैल गया। खान खुदायार खान के बेटे नसीरुद्दीन खान के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचल दिया गया और कोकान के खान-शासित प्रदेश को २ मार्च, १८७६ को रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका नया नाम रखा गया—सूवा फरगाना।

ट्रांसकास्पियन सैनिक जिले का निर्माण १८७४ में मेजर-जनरल लोमाकिन की मातहत में किया गया था। १८७७ में लोमाकिन ने कास्नोवोदस्क से २०० मील पूर्व किज़िल अरवात के तेव्हे किले पर चढ़ाई की, मगर बड़े प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। उसने अखाल नखलिस्तान

\* T A MacGahan *Campaigning on the Oxus and the Fall of Khiva* London, 1874, p 295

मे गेआफ-तेपे ज़िले म दागिल-तेप पर चढ़ाई करन की चेष्टा की, मगर तुक्मान यादवाआ न उसे विफल कर दिया। प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करन के लिए जनरल म० स्वाइसेव का तुक्माना का पराजित करन के लिए भेजा गया (वह रीवा और ब्रावान के विरुद्ध अभियाना म भाग ल चला था और रूसी-तुर्की युद्ध के दौरान एट्रियाणाप्पन और प्लेवना पर कब्जा किया था)।

लोमाकिन ने ऊटा का प्रयाग किया था, जो उस लम्बी कठिन राह म हजारों की सख्या मे मर गया। इसलिए स्वाइसेव ने वापस का सहारा लिया। एक विशेष रेलवे बटालियन की स्थापना की गई जिसन अभियान की प्रगति के साथ-साथ ट्रांसकाम्पियन रेलवे का निर्माण किया। आस्ताबोदस्क मे एक जल शोधक यंत्र स्थापित किया गया ताकि पीन के पानी की कमी नहीं हो। सारी तयारियां हो जाने के बाद तुक्माना के खिलाफ हमला बोल दिया गया। घिरे हुए तुक्माना ने वीरतापूर्वक लड़ाई की और गेआफ-तेप भारी लड़ाई के बाद पराजित हुआ। इसके पतन के बाद अखाल नखलिस्तान पर रूसिया का कब्जा हो गया।

अब केवल मव पर कब्जा करना रह गया था। उसको रूसी साम्राज्य म बड़ी चतुर कूटनीति से एक हाथियार काकेशियाई मुसलमान अलीखानोव की काशिश से मिलाया गया। उस गुल जमाल का सहयोग मिल गया जो अतिम महान तुक्मान सरदार नूर वर्दी खान की विधवा थी। २१ जनवरी, १८८४ को तुक्मान कबायली सरदार अशकाबाद मे इकट्ठा हुए और उन्होंने जार की वफादारी की प्रतिज्ञा की। उसके कुछ ही दिन बाद मव के दक्षिण म सगीक कबीले न हाथियार डाल दिये और इस प्रकार पूरा इलाका पराजित हो गया।

रूसी विजय और मध्य एशिया पर कब्जे के ऐतिहासिक महत्व पर सावधान और पश्चिमी इतिहासज्ञ बहुत भिन्न विचार पकट करते हैं। जारशाही रूस द्वारा मध्य एशिया पर कब्जे से जारशाही का औपनिवेशिक उत्पीड़न बढ़ गया। लेकिन रूसी साम्राज्य मे इन लोगों के मिता लेने का एक दूसरा पहलू भी था। इससे उनकी नियति रूस की प्रगतिशील शक्तियों से, रूसी जातिकारी आन्दोलन से सबद्ध हो गयी। इसलिए रूस म मध्य

एशिया के मिला लिये जाने का वस्तुनिष्ठ दृष्टि से प्रगतिशील स्वरूप था। रूसी कब्जे के इस प्रगतिशील ऐतिहासिक स्वरूप को कभी कभी कुछ सोवियत लेखक अतिशयोक्ति के साथ पेश करते हैं, जिनमें से कुछ यहां तक कह जाते हैं कि रूस में विलयन मध्य एशिया के जनगण का “सदियों पुराना स्वप्न” था। लेकिन बहुतेरे सोवियत इतिहासज्ञों ने इस सबाल पर वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए, एक सोवियत उर्बेक विद्वान प्र० म० अमीनोव ने रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के “प्रगतिशील महत्व को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की प्रवृत्ति” की निंदा की।\* वह लिखते हैं

“इसका यह नतीजा नहीं होना चाहिये कि साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी सार पर, जारशाही की औपनिवेशिक नीति के स्वरूप और उद्देश्यों पर परदा डाल दिया जाये, जो मध्य एशिया के धन को लूटकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्न कर रही थी।”\*\*

जारशाही ने मध्य एशिया में कठोर औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रखा था जिसका हित स्थानीय जनता और रूसी मजदूर वर्ग दोनों के हितों के विरुद्ध था। हाल ही में मध्य एशिया के विलयन के प्रगतिशील स्वरूप पर ज़रूरत से ज्यादा जोर देने की प्रवृत्ति को सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सह सदस्य प्र० प्र० किम ने आलोचना का विषय बनाया है। किम ने सोवियत लेखकों पर इस मामले में दृष्टिकोण के “कुछ आधुनिकीकरण” का आराप लगाया है। उन्होंने इस तक की आलोचना की है, जो सोवियत साहित्य में अक्सर पेश किया जाता है, कि अगर मध्य एशिया की जातियों का विलयन रूस में नहीं हुआ होता, तो वे अक्षुब्ध जाति के बाद सोवियत जातियों के विरादराना संघ में एकताबद्ध नहीं होती। उन्होंने कहा

“हर एक सत्य की तरह, ऐतिहासिक सत्य भी ठोस होता है। जब हम रूस के साथ जातियों के विलयन के प्रगतिशील परिणामों की बात

\* प्र० म० अमीनोव, “मध्य एशिया का आर्थिक विकास”, ताशकन्द, १९५६, पृष्ठ १६। (रूसी संस्करण)

\*\* वही, पृष्ठ १७५-१७६।

करते हैं, तो हमारे मन में वे प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जो इन जातियों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुराने सामंती या पूँजीवादी जमींदार रूप की ठोस ऐतिहासिक स्थितियों में हुए। हम जब प्रगतिमान परिणामों की बात करते हैं, तो साथ ही हम यह स्वीकार करते हैं कि जातीय स्वतंत्रता के छिन जाने से उनका कितना नुकसान हुआ।”\*

## मध्य एशिया में

### आंग्ल-रूसी प्रतिद्वंद्विता

१९ वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भी जबकि मध्य एशिया में हम का मुख्य प्रघात अभी शुरू नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने आंग्ल-रूसी संबंधों की अपनी अनूठी व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी। अंग्रेजों के अनुसार रूस बराबर एक के बाद एक इलाक़ों पर कब्ज़ा करते हुए भारत की सीमाओं की ओर बढ़ता जा रहा था। कहा जाता था कि रूस के बढ़ने का लक्ष्य भारत था और इसलिए ब्रिटेन जो कुछ कर रहा था, वह भारत की सुरक्षा और तुर्की साम्राज्य की अखंडता के लिए, जो यूरोप और भारत के बीच में एक पुल के समान था, कर रहा था। ६० उकहाट और बाद में ८० रालिनसन जैसे लेखकों ने इस विचार को बराबर फैलाने का प्रयास किया।

लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर पूर्वाग्रह पर आधारित था। बात ऐसी नहीं थी कि रूस बस बराबर बढ़ता जा रहा था और ब्रिटेन केवल प्रतिरक्षा कर रहा था। वास्तव में मध्य एशिया में दो आक्रामक लहरें आकर मिलीं।\*\* मध्य एशिया के प्रति ब्रिटेन और रूस दोनों की नीति आक्रामक थी, और हर एक दूसरे पर आरोप लगाता था।

\* “इतिहास और समाजशास्त्र”, मास्को, १९६४, पृष्ठ १२७-१२८।  
(रूसी संस्करण)

\*\* “कूटनीति का इतिहास”, मास्को, १९६३, खण्ड २, पृष्ठ ६०।  
(रूसी संस्करण)

दोनों शक्तियों में प्रतिद्वन्द्विता का असली कारण सामरिक विचार और व्यापारिक हित थे और साथ ही अपने अधीन देशों पर नियंत्रण और दृढ़ करने की इच्छा भी थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को डर था कि किसी विदेशी मेना के सीमा के निवृत्त आने से अनिवार्यतः उनके शासन के विरुद्ध जन का क्रोध उठ जायेगा। इसलिए वे आस-पास के देशों—फारस, अफगानिस्तान, सिक्किम और बर्मा में अपना प्रभाव फैलाना और अगर सम्भव हो तो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इन दोनों शक्तियों द्वारा कब्जा करने का कारण आम तौर पर कच्चे सामान के आत और उनके पूँजीवादी उद्योगों के तैयार माल के लिए मंडी हासिल करने की जरूरत होती थी। इस दृष्टि से मध्य एशिया की कपास रुसी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गयी।

मध्य एशिया के लिए आम नीति खदक में ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा निर्धारित होती थी, मगर उसका ठोस रूप में अमल में लाने का काम भारत में वादसराय के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रिटिश एजेंट, जो माघारणत गुप्तचर अफसर होते थे, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और पश्चिमी चीन जाते और वहाँ अकसर स्थानीय एजेंटों को भरती करते थे। तुर्की के सुलतान के एजेंट भी अफ्रेको की सक्रिय सहायता किया करते थे। मध्य एशिया में जासूसी और विध्वंसक कारवाइयों की ब्रिटिश नीति सरकारी कूटनीति से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। रुसी पक्ष में भी तुर्किस्तान का गवरनर-जनरल सेट पीटसबर्ग के नियंत्रण से काफी हद तक स्वतंत्र था और स्थानीय मामलों का शासक और कबायली सरदारों में उसने अपने जासूसों का जाल बिछा रखा था।

मध्य एशिया में ब्रिटिश विस्तार का मुख्य विषय अफगानिस्तान था। वहाँ से अफ्रेको तुर्कमानिस्तान में घुसने की तैयारी कर रहे थे। अफ्रेको ने पहला अफगान युद्ध १९वीं सदी के चौथे दशक में चलाया, जब रुस का फैलता हुआ साम्राज्य अभी भारत की सीमाओं से दूर था। यह आक्रमक युद्ध अफगानिस्तान पर, जो दुश्मन नहीं था, ऐसे समय थापा गया, जबकि फारस में हेरात की घेराबंदी उठा ली थी और रुसी एजेंट वित्तवेचक को वापस बुलाकर अनाधिकृत घोषित कर दिया गया था।

१८६६ म सामंती सघर्षों का दौर समाप्त हो गया था, जा विगत छह वर्षों से अफगानिस्तान म जारी थे। अमीर शेर अली ने अपने विराट्पिता को परास्त कर दिया और अफगानिस्तान म अपने नियंत्रण म कद्राफत राज्य स्थापित कर लिया था। लाड मेया न अमीर का अपना ताबान और अफगानिस्तान म ब्रिटिश प्रभाव का यत्न बनान का निश्चय किया। लाड मेयो ने शेर अली का भारत आने का नियंत्रण लिया और माच १८६६ म अम्बाला मे वे मिले। अमीर ने यह माग की कि मन्त्री-संघि कर ली जाये और अंग्रेज उसके छोटे बेटे अब्दुल्लाह खान को अफगान राज गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी मान ले। परन्तु लाड मेयो इस पर राजी नहीं हुआ। अंग्रेज राज गद्दी के विभिन्न दावेदारों को एक दूसरे से लड़ान का खेल छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उसन अमीर को अपना दोस्ती का विश्वास दिलाया।

१८६६ के शुरू म ब्रिटेन मे ग्लैडस्टन के नेतृत्व म लिबरल पार्टी की सरकार ने जारशाही सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि मध्य एशिया म ब्रिटेन और रूस के अधीन इलाकों के बीच तटस्थ क्षेत्र का निर्माण किया जाये। दोनों शक्तियाँ इस तटस्थ क्षेत्र का सम्मान करें। इसका उद्देश्य यह था कि दोनों के इलाका की समान सीमा नहीं होने पाये। रूसी सरकार ऐसे तटस्थ क्षेत्र के निर्माण पर राजी हो गयी और उसन सुझाव दिया कि इसमे अफगानिस्तान को शामिल करना चाहिये। मकसद यह था कि ब्रिटेन उसको हडप न कर सके। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर की ओर उस क्षेत्र का विस्तार करने का सुझाव दिया। इसपर दोनों सरकारों ने पत्र-व्यवहार का लम्बा सिलसिला चला, जिसका फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसे "क्लैरेडन गोर्चकॉव समझौता" कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की राय थी कि अफगानिस्तान तटस्थ क्षेत्र की शत पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सीमाएँ ठीक से निर्धारित नहीं हैं।

इसके बाद आंग्ल और भारत म उसके सहकारियों ने तजवीज पेश की कि ऊपरी आक्सस को वह सीमा हानी चाहिए जिसे किसी शक्ति की सेनाएँ नहीं पार कर सके। तटस्थ क्षेत्र के संबंध म बातचीत फिर शुरू हुई, जब भारतीय प्रशासन का एक अधिकारी ट० ड० फोरसाइथ

नवम्बर १८६६ में सेट पीट्सबर्ग गया। उसके साथ एक समझौता हुआ जिसकी पुष्टि बाद में जार और ब्रिटिश सरकार ने की। इस बात पर सहमति हुई कि जो सूबे दरअसल शेर अली के कब्जे में थे, उन्हें अफगानिस्तान का इलाका मान लिया जाये। यह भी तय हुआ कि ब्रिटेन अफगान अमीर पर अपना प्रभाव डाले और उसे बुखारा और अन्य मध्य एशियाई राज्यों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने से रोके। इसी प्रकार रूस की जिम्मेदारी बुखारा को रोके रखना और अपना सारा प्रभाव शांति के हित में इस्तेमाल करना था।

लेकिन शेर अली के अधिकार में वास्तव में कितना इलाका था, यह एक विवादस्पद सवाल था और किसी को भी, स्वयं अमीर को भी उसकी सम्बाई चौड़ाई का ज्ञान नहीं था। इसलिए यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष इसके बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव से दोनों पक्षा को समय मिल गया और व्यापक पैमाने पर झगड़े और समझौते की गुंजाइश पैदा हो गई। शीघ्र ही दोनों शक्तियों में १८६६ के समझौते के बारे में झगड़ा शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वह सारा इलाका, जो कभी शेर अली के पूर्ववर्ती अमीर दोस्त मोहम्मद के अधिकार में था, *ipso facto* अफगान गद्दी के वर्तमान पदग्राही के कब्जे में माना जायेगा। भारत के वाइसराय लार्ड मेयो का यह मत, जैसे भारत के लिए राज्यमंत्री डयूक आफ आगिल के नाम पत्र में व्यक्त किया गया था, रूसी सरकार के पास उसके लंदन स्थित राजदूत के जरिये पहुंचा लिया गया। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि कुछ खान शासित प्रदेश, जिनपर शास्त्र मोहम्मद प्रशासन करता था शेर अली के अधिकार में नहीं थे।

रूसी सरकार उन्हें नये अमीर शेर अली के कब्जे में मानना नहीं चाहती थी, जिसे वह अंग्रेजों का एजेंट समझती थी। १७ अक्टूबर, १८७२ का अल अलविल के लार्ड ताफ्ट्स के नाम एक लम्बे नोट में, जिसे उसने साम्राज्यी रूसी सरकार के लिए लिख कर दिया, शेर अली के अधिकार में अफगान इलाका की सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसमें ऐसा सुझाव पेश किया गया कि बदख़शान और बख़ान सूबे अफगानिस्तान का अंग हो जायें। रूसी सरकार ने ७ दिसम्बर, १८७२ के इस नोट के अपने जवाब



में अफगानिस्तान की सीमा अमू-दरिया पर बदख़शान और बख़ान के नीचे दराजा सालेह तक स्वीकार की। परन्तु उसने इन दो नूवा को अफगानिस्तान का अंग मानने से इनकार कर दिया। मगर आगे चलकर ज़ारशाही सरकार ने अपना मत बदल दिया और ३१ जनवरी, १८७३ को ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित रेखा को अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा मान लिया।

इस प्रकार अफगानिस्तान के मसल्ले में आंग्ल-रूसी वार्ता और पत्र व्यवहार, जो १८६६ में शुरू हुआ था, सम्पन्न हुआ। इस १८७३ का समझौता कहा जाता है और इसमें अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा निर्धारित कर दी गयी थी। ब्रिटेन ने इस समझौते के ज़रिये रूस से एकतरफ़ा रियायत हासिल कर ली और वह यह कि रूस ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर मानने का बार बार और पक्का विश्वास दिलाया। परन्तु जहाँ तक दाना शक्तियाँ के अधिकृत इलाक़ों के बीच "तटस्थ" या "मध्यस्थ" क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्न का सबल है, इस विचार को १८७३ में निश्चित रूप से त्याग दिया गया। ब्रिटिश, जो अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए नज़र गढ़ाये बैठे थे, दरमसल उम सुझाव के लिए तैयार नहीं थे। लाड भयों की सरकार शुरू ही से उसको स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी। लाड भयों ने लन्दन को लिखा था

‘सबसे अच्छा यह हो कि रूस और इंग्लैंड दोनों एक दूसरे के हितों में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दें, जिसकी पुष्टि किसी निश्चित संधि द्वारा नहीं की जाये।’\*

ज़ारशाही सरकार ने बदख़शान और बख़ान का अफगानिस्तान का अंग मानकर ब्रिटेन को रियायत दी, तो इसमें उसका अपना उद्देश्य था। वह चाहती थी कि ख़ीवा पर उसका अधिकार करने के प्रति ब्रिटेन का विरोध कमजोर पड़ जाय। ज़ार अलेक्सांडर द्वितीय की अध्यक्षता में असाधारण समिति की एक बैठक ने ४ दिसम्बर, १८७२ को ख़ीवा पर चढ़ाई करने का निणय किया था।\*\*

\* Quoted by D K Ghosh *England and Afghanistan* Calcutta 1960 p 165

\*\* 'कूटनीति का इतिहास', खण्ड २, पृष्ठ ६६।

जब रूस ने खीवा पर अधिकार कर लिया, तो कोई खास अंतर्राष्ट्रीय उलझनें नहीं पैदा हुईं। फिर भी ब्रिटिश अखबारा में इसका कुछ विरोध अवश्य हुआ। छह महीने से अधिक समय हो जाने पर ब्रिटिश विदेश मंत्री लार्ड ग्रेनविल ने सेट पीट्सवम में ब्रिटिश राजदूत के नाम एक पत्र भेजा और आदेश दिया कि वह उसकी नकल जारशाही सरकार को भी दे दे। इस चिट्ठी में बताया गया था कि अगर रूस भव की तरफ आगे बढ़े, तो हो सकता है कि तुकमान बंदीले अफगानिस्तान में शरण ले और इससे रूसी और अफगान सैनिकों में झड़पें हो सकती हैं। ब्रिटिश सरकार ने आशा प्रकट की कि रूसी सरकार ब्रिटिश इंडिया की सुरक्षा और एशिया में शांति की एक महत्वपूर्ण शक्त के रूप में अफगानिस्तान की "स्वतंत्रता" का सम्मान करेगी। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने खीवा पर रूस के बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। गोर्चाकोव ने अपने उत्तर में ब्रिटेन को विश्वास दिलाया कि रूस अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर मानता है। उसने सुझाव दिया कि अगर अफगान अमीर वास्तव में रूस से झगडा नहीं करना चाहता, तो उसे तुकमान सरदारों के लिए यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वे उसके समर्थन की आशा नहीं करें।

ब्रिटेन से आगे वार्तालाप के दौरान गोर्चाकोव ने २९ अप्रैल, १८७५ को अपने स्मरण पत्र में लिखा था कि दोनों शक्तियों में प्रतिद्वंद्विता उनके परस्पर हितों के लिए हानिकारक है। उसकी राय में यह वाछनीय था कि इस प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए दोनों के अधिकृत इलाकों के बीच में "मध्यवर्ती क्षेत्र" कायम किया जाये। अफगानिस्तान एक आदशमूलक मध्यवर्ती राज्य हो सकता है और इसके लिए दोनों पक्षा द्वारा उसकी स्वतंत्रता की मान्यता मात्र जरूरी है।

डिजरेली की कजर्वेंटिव सरकार ने १८७४ में ब्लैडस्टन की लिबरल सरकार को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। उसने सत्ता इस नारे के साथ सभाली थी कि वह ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करेगी। आठवें दशक में औपनिवेशिक विस्तार में ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। उपनिवेशों की ओर यह ध्यान विश्व मंडिया के लिए प्रतियोगिता तीव्र होने के साथ, खासकर जर्मनी की ओर

से, बढ़ने लगा था। इस नयी परिघटना का सबध पूजीवाद के साम्राज्यवादी अवस्था में सत्रमण के प्रारम्भ से था। डिजरेली की सरकार ने विश्व के भिन्न भिन्न इलाकों में—दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, तुर्की और मध्य एशिया—विस्तार और औपनिवेशिक बन्धों का माग अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने फारस और तुर्कमानिस्तान में अपने एजेंटों की कारवाइयां तेज कर दीं और वहां सैनिक तथा राजनीतिक जामूसी कराने लगी। उसने इस क्षेत्र के मुसलमान शासकों का संयुक्त मोरचा रूस के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। डिजरेली की सरकार अफगानिस्तान का भी अपने अधिन करने की तैयारी कर रही थी।

दोनों शक्तियां इस अवधि में मध्य एशिया के विभाजन के बारे में आपस में कोई समझौता कर सकती थीं। मई १८७५ में जर्मनी के विरुद्ध दोनों मिल गईं और कुछ समय तक दोनों शक्तियों के सबध सुधरते मालूम पड़ रहे थे। लाइ डरबी ने लंदन स्थित रूसी राजदूत के सामने घोषणा की कि रूस और इंग्लैंड को एशिया में समझौता करने से कोई चीज रोक नहीं सकती क्योंकि दोनों के लिए काफी जगह है।\* परन्तु ब्रिटिश सरकार ने रूस से वाता के आधार के रूप में मध्यपूर्वी राज्य के विचार को अस्वीकार कर दिया। वह अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की संयुक्त पुष्टि के लिए रूसी सुझाव से सहमत नहीं हुई। अक्टूबर १८७५ में ब्रिटिश कैबिनेट ने घोषणा की कि अफगानिस्तान के सबध में कारवाई करना या उसे पूरा अधिकार है। इसका उत्तर गोर्बाकोव ने फरवरी १८७६ में दिया और रूस के इस पुराने मन की पुनः पुष्टि की कि अफगानिस्तान को वह अपने प्रभावक्षेत्र से बाहर मानता है। उसने यह भी घोषणा कर दी कि रूसी सरकार के मतानुसार मध्यस्थ क्षेत्र के सबध में वार्तालाप समाप्त हो चुका है। दोनों शक्तियों को इस इलाके के देशों के प्रति अपनी कारवाई की स्वतंत्रता पूरी तरह कायम रखते हुए भी एक दूसरे के हितों का उचित ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के इलाकों में सीधा सम्पर्क नहीं होने देना चाहिए।

\* “कूटनीति का इतिहास”, खण्ड २, पृष्ठ ६८।

रूस ने तुरत इस "कारवाई की स्वतंत्रता" का प्रयोग किया, जिसकी घोषणा पहले ब्रिटेन ने की थी। १७ फरवरी, १८७६ को ज़ारशाही सरकार ने एक आज्ञा जारी की, जिसके अनुसार कोकान खान-शासित प्रदेश को रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत का वाइसराय लाड मेयो और उसका उत्तराधिकारी नायब्रुक अफगानिस्तान पर तुरत कब्ज़ा करने के विरोधी थे। वे "धैर्य" और "प्रतीक्षा" की नीति के समर्थक थे। इस नीति पर "अग्रिम नीति" के समयको ने आक्षेप किया, जिनमें रालिंसन था। डिजरेली ने सत्ता सभालने पर इसी नीति पर अमल किया। भारत सरकार को आदेश दिया गया था कि वह अफगान अमीर से हेरात और कन्दहार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की आज्ञा की मांग करे। लाड नायब्रुक को, जो इस नयी नीति का विरोधी था, त्यागपत्र देने पर मजबूर किया गया। अप्रैल १८७६ में उसके स्थान पर लाड लिटन वाइसराय बनकर आया। मई १८७६ में लिटन ने मांग की कि शेर अली काबुल में ब्रिटिश मिशन से मिले। इस प्रश्न पर वाइसराय के पत्रों का अध्ययन करने से मन की व्यग्रता और हठधर्मी की झलक मिलती है। चौथे दशक का कहानी दूसरे अफगान युद्ध में पुनर्दोहराई गई, और फिर यह सब हम व आनामक इरादा के मुकाबले में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के नाम पर किया गया। इस सिलसिले में यह बात उल्लेखनीय है कि वाइसराय का भारत की सुरक्षा की तो बड़ी चिन्ता थी, मगर उस महान अकाल व प्रति वह बिल्कुल उदासीन रहा जिसमें ५० लाख व्यक्ति मौत के घाट उतर गये। ब्रिटिश राजमुकुट की महिमा प्रदर्शित करने के लिए उसने निल्ली में शानदार दरबार ऐसे समय रचाया, जब करोड़ों भारतवासी दश व हर शहर और हर गांव में प्लेग और भूख से मर रहे थे।

तुक्मानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों ने रूस के विरुद्ध स्थानीय सरदारों का उभारा। ज़ारशाही रूस को ईरान और अफगानिस्तान से, जहाँ ब्रिटिश प्रभाव बढ़ रहा था, तुक्मानिस्तान के लिए ब्रिटिश खतरे का इहसास था। १९वीं सदी के आठवें दशक में खुरासान मध्य एशिया में ब्रिटिश सैनिक विस्तार का अड्डा बन गया। १८७३ में कनल बेकर, कैंप्टन ब्लैटन और लेफ्टिनेंट गिल अतरेक नदी क्षेत्र का अध्ययन करने भेजे गये। बेकर

ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की जिसमें तुर्कमाना के लड़ाकू गुणों की प्रशंसा की गई थी। उसकी राय में १२० हजार ब्रिटीश तुर्कमान घुड़सवार यूरोपीय अफसरों की बर्मान में एक बड़े इलाके की रक्षा कर सकते हैं।\* बेकर ने इस इलाके के सैनिक भूगोल के संबंध में लखनऊ में लेख भी प्रकाशित किये। १८७४ में नेपियर को वहां यह अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि हम के विरुद्ध ब्रिटेन के संधि में "मुद्बलि" के रूप में तुर्कमान कबीलेवालों का प्रयोग करने की क्या सम्भावनाएँ हैं। वह ब्रिटेन के अनुयायी घानों से मिला, उनमें हथियार बाँटे, सबकों का नक्शा तैयार किया और कास्पियन सागर में जहाजरानी के संबंध में सूचना इकट्ठा की। वापस आने पर उसने सरकार से आग्रह किया कि वह ईरान तुर्कमानिस्तान की सीमा पर होनेवाली घटनाओं में अधिक सैन्य हस्तक्षेप करे।

१८७४ में कर्नल मकग्रेगर मशहद से मव खाना हुआ। उसने तुर्कमान सरदारों का रिश्तत दी ताकि मव पहुँचने में वे उसकी सहायता करें। वह मव तक नहीं जा सका क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसे आगे बढने से मना कर दिया। उसे रूसी सरकार के प्रतिरोध का डर था। लेकिन वह तेज़ेन नदी पार करके मव की ओर २० मील तक गया। बाग़ में कप्तान बर्नाबी को खोवा से मव जाने का काम सौंपा गया। परन्तु वह भी इसे पूरा नहीं कर सका। रूसी अधिकारियों ने उसे मव जाने नहीं दिया और मध्य एशिया से चले जाने पर मजबूर किया। १८७६ के अंत में नेपियर एक बार फिर तुर्कमाना में अपना विध्वंसक काम करने मशहद पहुँचा।

१८७७ में कैप्टन बटलर ने जिसने चीन में तार्त्तारियन विद्रोह को कुचलने में भाग लिया था, अतरेक नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उसे अखाल और मव के नखलिस्तान के तुर्कमानों को रूसियों के विरुद्ध संगठित करने का व्यक्तिगत आदेश भारत के वाइसराय लार्ड लिटन से मिला।

---

\* V Baker, *Clouds in the East Travels and Adventures on the Perso Turkmen Frontier* London, 1876 pp 341—342

परन्तु रूसी अधिकारियों को उसके मिशन की सूचना मिल गई और उनके प्रतिरोध के कारण उसे वापस बुलाना पड़ा। बाद में जब लाड लिटन ने तुर्कमानिस्तान में हुआ उसका खच भ्रदा करने से इनकार किया, तो उसने अपने मिशन का कच्चा चिट्ठा अफवाग में छपवा दिया और लाड लिटन को विध्वंसक कारवाइयाँ के संगठनकर्त्ता के रूप में बेनबाव किया। २५ जनवरी, १८८१ को "ग्लोब" में प्रकाशित अपने लेख में उसने बताया कि कस उसने आधुनिकतम यूरोपीय तकनीक के अनुसार गैम्रोव-सैपे की किलाबलिया के पुनर्निर्माण में भाग लिया। अंग्रेजी पत्रपार चाल्स भाविन ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि यदि बेंकर, मक्ग्रेगर, नेपियर और बत्लर फारस के उत्तर-पूर्वी सीमा पर न पहुँच गये होते, तो रूस को अनेक लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।\* १८७३ से लेकर १८८१ तक शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता हुआ जब तुर्कमानो में उपद्रव फलाने के लिए ब्रिटिश एजेंट न भेजे जाते हों। लाड लिटन ने मक् पर अधिकार करने की एक योजना बनाई थी। १८७८ में ही, जब अंग्रेज अफगानिस्तान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, लाड लिटन ने भारत के लिए राज्य मंत्री को अपना सुझाव लिख भेजा कि एक अलग पश्चिमी अफगान राजतन्त्र स्थापित किया जाये जिसमें मक्, मैसेना, बल्ख, कन्हार और हेरात शामिल हों, उसका शासक अंग्रेजों की पसंद का बादमी हो और कि यह राजतन्त्र अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटेन के समर्थन पर निर्भर हो।\*\* यह था उस "मक् पीडा" का असल कारण, जिसने मक् पर रूसी कब्जे के समय भारत सरकार को दबोच लिया था। चारशाही सरकार ने तुर्कमानिस्तान पर कब्जा करने में जल्दी की ताकि अंग्रेज अफगानिस्तान से आगे उत्तर में न जायें। ब्रिटिश सरकार

\* C Marvin *Reconnoitring Central Asia* London 1886, pp 246-249, न० अ० खालफिन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३३८-३३९।

\*\* B Balfour, *The History of Lord Lytton's Indian Administration* London, 1899, p 247

ने रूस से १८८० की संधि के आधार पर अफगानिस्तान के सामा निधारण का सवाल उठाया। सीमा निर्धारण के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग के अंग्रेज सन्ध्या ने रूस के विरुद्ध अंग्रेज अब्दुरहमान का भड़काया। ब्रिटिश सरकार अवश्य ही यह नहा चाहती थी कि रूस और अफगानिस्तान में अच्छे पड़ोसी के संबंध कायम हों। १८८४ में अंग्रेजों के उकसावे पर अफगानों ने अपनी सेना पंजदेह के नखलिस्तान में भेज दी जिसमें सराउ कबीले के तुक्मान बसे हुए थे। रूसों पलस्वान रूसियों से जबरदस्त झड़प हो गई जिसमें अफगानिया को हार खाकर पीछे हटना पड़ा। इस झगड़े के पीछे अंग्रेजों का हाथ था, यह बात अफगानों के नाइब सालार के वक्तव्य से जाहिर है

“मुझे प्यारी है कि पंजदेह में हम रूसिया से लड़े, क्योंकि अब हम मालूम हो गया कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु। कम से कम व, जिहान हमें लड़ने पर आमादा किया और मरण के लिए छाड़ दिया हमारे सच्चे दोस्त नहीं है।”\*

इस लड़ाई का दोष रूस पर नहीं लगाया जा सकता। वह सामा निर्धारण सीमावर्ती इलाके की भौगोलिक और जातीय स्थितियों के अनुसार करना चाहता था। ब्रिटेन ने रूस के पक्ष किये हुए जातीय आधार को सीधे अस्वीकार कर दिया।

परंतु ब्रिटिश उकसावों के बावजूद अफगानी अमीर न सीमा के झगड़े में संतुलन से काम लिया। वह रूस से लड़ाई में नहीं फसना चाहता था। अंग्रेजों ने पंजदेह नखलिस्तान को रूस का अधिकृत इलाका मान लिया। इसके बदले में रूस अफगानिस्तान को जुलफिस्तान क्षेत्र दत्त पर राजा हो गया। लंदन में १० सितम्बर, १८८४ को एक राजीनामे पर हस्ताक्षर करके यह समझौता कर लिया गया। १८८६-१८८८ में इस इलाके में सीमा रेखा रूसी अफगान आयोग ने नहीं, बल्कि अंग्रेज रूसी आयोग ने खींची।

\* Quoted by D K Ghosh *India and Afghanistan*  
pp 196—197

१६ वीं सदी में आंग्ल-रूसी संबंधों की अंतिम जटिल समस्या पामीर का प्रश्न था। नव दशक के अंत और दसवें दशक के प्रारम्भ में आंग्ल-रूसी प्रतिद्वंद्विता का केंद्र "संसार के शिखर" पर पहुंच गया। जारशाही सरकार

कोकान खान प्रशासन के उत्तराधिकारी की हैसियत से पूर्वी पामीर पर अपने अधिकारों का दावा करती थी। जहां तक पश्चिमी पामीर के देव शासनो का संबंध था, ब्रिटेन के साथ १८७३ के समझौते के अनुसार वही रूस के प्रभाव-क्षेत्र में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे आमू-दरिया के उत्तर में थे। यह क्षेत्र अंग्रेजों के उसकावा का क्षेत्र बन गया क्योंकि

जोरशाही रूस तुर्कमान कारवाइया में उलझा रहा था। रूस कोकान को पराजित करने के बाद पामीर पर भी अधिकार कर ले सकता था लेकिन यह दरिद्रता भरा वीरान इलाका उस समय उसे किसी आयिक महत्व का नहीं जान पड़ा। परंतु उसने पामीर पर अपने अधिकारों को कभी त्यागा नहीं। १८७६ के आलाई अभियान में पामीर पर अधिकार जमान की उसकी इच्छा पहली बार व्यक्त हुई।

रूसी भौगोलिक सत्या पामीर के वैज्ञानिक अध्ययन में दिलचस्पी लेने लगी थी। अंत १८८२ में उसने अ० रेगेल को वहां भेजा। शुगनान के शासक युसूफ अली ने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। रेगेल ने बदख़शान भी जाना चाहा, मगर अफगानी अधिकारियों ने उसकी आज्ञा नहीं दी। १८८३ में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुरहमान ने शुगनान और रूशन पर कब्ज़ा करने के लिए सना भेजी। शुरू में रूसी अधिकारियों ने इसपर कोई ज़ारदार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। परंतु जब रूसी अख़बारा ने सवाल उठाया, तो दिसम्बर १८८३ में ब्रिटिश सरकार के पास एक नोट भजा गया था। वहां गया था कि अफगान कब्ज़ा १८७३ के समझौते की प्रत्यक्ष अवहेलना है। पांच महीनों तक अंग्रेज खामोश रहे और जब फिर स्मरण पत्र भेजा गया, तब उन्होंने उत्तर दिया कि अफगानिस्तान शुगनान और रूशन को बदख़शान का भाग मानता है जो उसे १८७३ के समझौते के अनुसार दे दिया गया था। रूसी सरकार उस समय तुर्कमानिस्तान में पूरी तरह व्यस्त थी इसलिए वह इस मामले पर और अधिक ध्यान नहीं दे सकी। इस बीच शुगनान के लागा में असतोप वदता





निधिमंडल भेजे। मगर ज़ारशाही सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के मामले में दखल देने से बराबर इनकार किया।\*  
 वजत इलाके पर १८६१ में अंग्रेजों के कब्जे से सेट पीटसवग में छतरे का इस्तेमाल पड़ा हुआ। १२ जनवरी, १८६२ को साम्राज्यी परिषद की एक बैठक में एक गुप्तचर अभियान पामीर भेजने का निश्चय किया गया। इसमें यह भी विचारिश की गई कि पामीर इलाके के सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटेन और चीन से बातचीत की जाये। पामीर समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल १८६२ में बुलायी गयी एक और बैठक में युद्ध मंत्री प्रतिकारिया ने सावधानी की नीति पर जोर दिया। निणय किया गया कि हिंदूकुश के दरों की ओर न बढ़ा जाये और १८७३ के समझौते के आधार पर सीमा निर्धारण के लिए बातलाप किया जाये।\*\*  
 अप्रैल १८६४ में रूस और चीन पामीर इलाके में वर्तमान अवस्था का कायम रखने और एक दूसरे की स्थिति का परस्पर सम्मान करने पर राजी हो गये। तब रूसी सरकार ने अंग्रेजों से बातचीत करने का आग्रह किया। ११ मार्च १८६५ को ब्रिटिश विदेश मंत्री अल आफ किम्बरले और लंदन स्थित रूसी राजदूत म० दे स्टाल के बीच पत्रों के आदान प्रदान का स्वरूप एक समझौता हुआ। अफगानिस्तान ने शुगनान और कश्गार क्षेत्रों को रूस के हवाले कर दिया। बाद में रूस ने उन्हें बुखारा को दे दिया। बुखारा ने अमु-दरिया के बायें तट पर स्थित दरवाजा का एक भाग अफगानिस्तान को दे दिया। विक्टोरिया झील के पूर्व ब्रिटेन और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों को एक रेखा से विभाजित करना था, जो उस झील के पूर्वी तट पर एक बिंदु से शुरू होकर एक पहाड़ी रास्ते से होती हुई चीन की सीमा तक चली जायेगी। इस रेखा का निर्धारण एक संयुक्त तकनीकी आयोग द्वारा करना था। ब्रिटेन और रूस दोनों ने यह वादा किया कि पहला इस सीमा रेखा के उत्तर और दूसरा इस के दक्षिण कोई

\*वही, पृष्ठ ३६३।

\*\*वही, पृष्ठ ३६६।

गया। १८८८ में अफगानिस्तान की अदरूनी गडबड से फायदा उठाकर शुगनान के लोगो ने अपने भूतपूर्व शासक की सत्ता को बुखारा से वापस आने का निमन्त्रण दिया। उन्होंने जारशाही रुम से भी सहायता मागी। परन्तु अब्दुरहमान ने शीघ्र ही शुगनान के विद्रोह को बडाई से कुचल लिया।

अंग्रेजो ने पामीर के इलाके में अपनी कारवाइया तेज कर दी। १८८६ में कनल लाकाट ने हिंदूकुश से पामीर जानेवाले दरों का अध्ययन किया। गिलगित से अ० दूराट १८८८ और १८८९ में यह गुप्तचर काम करता रहा। मेजर कम्बरलैंड और लेफ्टिनेंट बावर ने १८८९ में तगदुम्बश पामीर की यात्रा की। शिकार के बहाने लिटलडेल भी उनके पीछे पीछे गया। १८९० में कैप्टन फ्रांसिस यगहस्वड के नेतृत्व में एक विशेष अभियान मडली पामीर भेजी गई। काशगर में रूसी कौन्सल न० पेत्रोव्स्की ने वैदेशिक मामला के मन्त्रानय का खबर दी कि अंग्रेज आधा पामीर अफगानिस्तान को दे देना चाहते हैं और गुप्त रूप से चीन से भी समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।\* यगहस्वड मडल के कारण जारशाही सरकार, जो कुछ समय से पामीर के मामले में "ठहरो और देखो" की नीति पर चल रही थी, सक्रिय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि तुकिस्तान के गवर्नर जनरल अ० वेस्की ने आलाई घाटी की यात्रा की। म० इयानोव को एक कज्जाक बटालियन के साथ पामीर भेजा गया। कनल व्योनोव ने कैप्टन यगहस्वड को बोजाई गुम्बज घाटी से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब यह था कि जारशाही रुम राजनयिक पत्र व्यवहार के बदले अब निणायक कारवाई पर उतर आया था। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पामीर में इस नयी जारनार नीति के बावजूद हिंदूकुश की दक्षिणी ढलान पर स्थित छोटे राज्यो हुआ और नगर पर अधिकार करने का जारशाही रुम का कोई इरादा नहीं था। इन राज्या के शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ रूस की सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रति

रूस द्वारा देशजय और आग्ल हसी प्रतिद्वंद्विता ७३

निधिमल भेजे। मगर जारशाही सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के मामलों में दखल देने से बराबर इनकार किया।\*

कजूत इलाके पर १८६१ में अंग्रेज़ों ने बम्बे से सट पीटसवग में खतरे का इहसास पैदा हुआ। १२ जनवरी, १८६२ को साम्राजी परिषद की एक बैठक में एक गुप्तचर अभियान पामीर भेजने का निश्चय किया गया। इसमें यह भी सिफारिश की गई कि पामीर इलाके के सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटेन और चीन से बातचीत की जाये। पामीर समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल १८६२ में बुलायी गयी एक और बैठक में युद्ध मंत्री ने प्रतिवादी दृष्टिकोण अपनाया, मगर वैदशिव मामला के मंत्रालय के अधिकारियों ने सावधानी की नीति पर जोर दिया। निणय किया गया था कि हिंदूकुश के दरों की ओर न बढ़ा जाये और १८७३ के समझौते के आधार पर सीमा निर्धारण के लिए बातलाप किया जाये।\*\*

अप्रैल १८६४ में रूस और चीन पामीर इलाके में वर्तमान अवस्था को कायम रखने और एक दूसरे की स्थिति का परस्पर सम्मान करने पर राजी हा गय। तब रूसी सरकार ने अंग्रेज़ों से बातचीत करने का आग्रह किया। ११ मार्च १८६५ को ब्रिटिश विदेश मंत्री अल आफ बिम्बरले और लन्डन स्थित रूसी राजदूत म० दे स्ताल के बीच पत्रा के आदान प्रदान के फलस्वरूप एक समझौता हुआ। अफगानिस्तान ने शुगनान और रुशान क्षेत्रों को रूस के हवाले कर दिया। बाद में रूस ने उन्हें बुखारा को दे दिया। बुखारा ने आमू-दरिया के बायें तट पर स्थित दरवाज का एक भाग अफगानिस्तान को दे दिया। विनटोरिया झील के पू्व ब्रिटेन और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों को एक रेखा से विभाजित करना था, जो उस झील के पूर्वी सिरे पर एक बिंदु से शुरू होकर एक पहाड़ी रास्ते से होती हुई चीन की सीमा तक चली जायेगी। इस रेखा का निर्धारण एक संयुक्त तकनीकी आयोग द्वारा करना था। ब्रिटेन और रूस दोनों ने यह वादा किया कि पहला इस सीमा रेखा के उत्तर और दूसरा इस के दक्षिण कोर्ड

\* वही, पृष्ठ ३६३।

\*\* वही, पृष्ठ ३६६।

राजनीतिक प्रभाव या नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने जाहिर किया कि ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र और हिंदूकुश तथा विक्टोरिया झील के पूर्वी सिरे से चीनी सीमा तक की रेखा के बीच का इलाका अफगानिस्तान के अमीर के इलाके का हिस्सा होगा और ब्रिटेन उस पर कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वह इस घटनाके मे किसी सैनिक चौकी या किले का निर्माण नहीं करेगी।

पामीर क्षेत्र मे सयुक्त आयोग ने वास्तविक सीमा निर्धारण का काम आसानी से पूरा कर लिया। इस ने भारत और रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप मे आठ मील चौड़ी "अफगानिस्तान की लम्बी पतली बाहु, जो अपनी उगलिया की नोक से चीन को छ रही थी", निमित्त की। १८६५ का पामीर समझौता "घटनाओं की महत्वपूर्ण शृंखला की एक कड़ी था"। उस दशक मे व्यापक अविश्वास के बावजूद एक और दोस्ताना समझौता हो गया था। मध्य एशिया की घटनाएं आखिरकार उस मैत्री-संधि के लिए रास्ता साफ कर रही थी, जो १९०७ मे सम्पन्न हुई।

पामीर समझौते के बाद के वर्षों मे आग्ल रूसी तनाव धीरे धीरे कम होता गया। १८८५ से १८९५ तक के समझौते के बाद अफगान सीमाओं के बारे मे और किसी झगड़े की गुंजाइश कम ही रह गई थी। शताब्दी के मोड़ पर दोनों शक्तियों के संबंध फिर से बिगड़े हुए थे। लाड कजन ने फिर "अग्रिम नीति" को अपनाया। रूस से प्रतिद्वंद्विता मचूरिया से फारस तक फैल गई और यहा तक कि तिब्बती पठार भी उसमे शामिल हो गया। रूसी-जापानी युद्ध से आग्ल रूसी संबंधो मे दबाव और तनाव का नया दौर शुरू हो गया। जब रूसी समुद्री बेड़े न लाल सागर मे ब्रिटिश जहाज "मत्ताक्का" पकड़ लिया और मछेरों की नौकाओं के संबंध मे डगर टट झगड़ा हुआ, तो पुरानी शत्रुता पुन जाग उठी।

परन्तु रूसी-जापानी युद्ध आग्ल रूसी संबंधो मे एक मोड़ बिंदु साबित हुआ, क्योंकि इससे रूसी साम्राज्य का चौखलापन ब्रिटेन के लिए स्पष्ट हो गया। ब्रिटेन का ध्यान अब एक नये और ज्यादा बड़े खतर की ओर आवृष्ट हुआ। यह खतरा धीरे धीरे उभरते हुए अधिक शक्तिशाली और जोरदार साम्राज्यवादी जर्मनी की ओर से था, जो अपनी *Flottenpolitik*

Weltpolitik और Drang nach Osten नीति के कारण ब्रिटेन के लिए एक दबंग प्रतिद्वंद्वी हुआ जा रहा था। बोस्निय युद्ध के दिना में उसका खतरनाक रस हो गया था और बल्तिन-बगदाद रेलवे बनाने की उसकी योजना पूरा में ब्रिटेन के प्रभुत्व की जोखिम में डाल रही थी। इसलिए एडमंड ग्रे का विश्वास था कि रूस से सम्बन्धों का बिल्कुल जरूरी है। इससे मोरक्का सक्क से, जिसके फलस्वरूप अलजेसिरास सम्मेलन आयोजित हुआ, प्रोत्साहन मिला। रूस फ्रांस का मित्र था, जिससे ब्रिटेन अपने सारे औपनिवेशिक झगड़े निपटा चुका था। फरवरी १९०७ में ब्रिटिश राजनयिक निक्सन ने रूस के विदेश मंत्री डजवोल्स्की के सामने ब्रिटिश सरकार के विचार की रूपरेखा पेश की। अनेक मसविदों के आदान प्रदान के बाद दोनों शक्तियां ने ३१ अगस्त, १९०७ को सेट पीटसबर्ग में एक इकरारनामा (अग्रीमेंशन) पर हस्ताक्षर किये। यह "फारस, अफगानिस्तान और तिब्बत के संबंध में इकरारनामा" के नाम से प्रसिद्ध है। १९०७ का संधि ने "दो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच झगड़े के कारणों को" दूर किया था।

१९०७ के इकरारनाम में तीन समझौते थे। इनमें पहला फारस के बारे में था। भूमिका में दोनों शक्तियों के बीच "फारस की अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करने", "सुख्यवस्था बनाये रखने" तथा "अपने सभी राष्ट्रों के लिए व्यापार के समान अवसर प्रदान करने" की बाबत समझौते की बात की गई थी। इन आठम्बरपूरा सिद्धांतों के बावजूद ब्रिटेन और रूस फारस को तीन भागों में बांटने पर सहमत हो गये थे। उत्तरी और दक्षिणी भाग क्रमशः रूस और ब्रिटेन के पास प्रभाव-क्षेत्र मान लिए गये थे और बीच का क्षेत्र तटस्थ छोड़ दिया गया था। दूसरा समझौता अफगानिस्तान के बारे में था। रूसी सरकार ने घोषणा की कि अफगानिस्तान रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बाहर है और इस बात पर सहमत हो गई कि उस देश में सारा राजनीतिक सम्पर्क ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता के जरिये रखेगी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी धार में घोषणा की कि अफगानिस्तान की राजनीतिक हैसियत का बदलने या उससे अदरुनी प्रशासन में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ब्रिटिश और रूसी सरकारों

ने इस बात की पुष्टि की कि अफगानिस्तान में वे व्यापार के समान अवसर के मिद्धात का पालन करती है। तीसरा समझौता तिब्बत के बारे में था। ब्रिटेन और रूस दोनों ने तिब्बत में चीन के अधिराजकीय अधिकारों का माना और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वादा किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि इसके अदरुनी प्रशासन में कोई दखल नहीं देगे और चीनी सरकार की मध्यस्थता के बिना तिब्बत से वार्तालाप नहीं करेंगे।

१९०७ के इकरारनामे से दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के सद्भावनापूर्ण सवधा के युग का श्रीगणेश हुआ,\* मगर फारस और अफगानिस्तान के लागा में हमसे नाराजी फैली, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था से उनकी प्रभुसत्ता प्रतिबद्धित और सीमित होती थी। तिब्बत में लामा शासन ने लोगों को अधविश्वास और अज्ञान की कालकोठरी में बंद कर रखा था। उनमें इतनी चेतना नहीं थी कि प्रतिराध करते। और लामा, जो पहले अंग्रेजों की चोट सहते रहते थे, इससे प्रसन्न हो गए कि दो महान यूरोपीय शक्तियों ने तिब्बत पर चीन के अधिराज की पुष्टि कर दी। लेकिन अब जबकि चीनियों ने उनपर अपनी पकड़ और कड़ी कर दी है, उन्होंने भारतीय हिमालय में अपन प्रवास से उस समझौते की निंदा की है और कहा है कि वह साम्राज्यवादी था। अफगानिस्तान में अमीर हवीबुल्लाह ने १९०७ के इकरारनामे को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति-सम्मेलन से अपने देश की स्वतंत्रता की मान्यता की मांग की। उनके उत्तराधिकारी अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया। इंग्लैंड के साथ वास्तविक समानता के आधार पर नय संधि सवधा के लिए अपने संधप में उस रूस की नयी सोवियत सरकार की नीति से प्रोत्साहन मिला। २७ मार्च, १९१९ को सोवियत सरकार ने

---

\* सच कहा जाये तो १९०७ के इकरारनामे से आगत रूसी प्रतिद्विद्धिता केवल कुछ समय के लिए दूर हो सकी थी। दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच पूर्व में अपना प्रभाव स्थापित करने का संधप खत्म नहीं हुआ, पासवर, ब्रिटेन इस संधप में सक्रिय रहा।—स०





है”।\* १८९५ में कांग्रेस के ग्यारहवें अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में चित्राल पर कब्जा करने की बड़ी आलोचना की। उन्हें विश्वास नहीं था कि रूस भारत पर हमला करेगा। इसी प्रकार १८९७ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपना गहरा और गम्भीर विश्वास प्रकट किया कि सरकार की सीमा-नीति से देश के मूल हिता को हानि पहुँचती है और इसको त्यागने का आग्रह किया।\*\* कांग्रेस के १८९८, १९०३ और १९०४ के अधिवेशनों में भी “अग्रिम नीति” का विरोध किया गया।

अग्रेष्ठ १९०७ के आग्ल रूसी इकरारनामे के बाद भी भारत में रूसी हीए की रट लगाते रहे। पंडित नहरू ने १९२८ में लिखा था

‘हम रूस के प्रति शत्रुता की परम्परा में बड़े हुए हैं जिसे अग्रेजों ने बहुत ध्यानपूर्वक सीखा। कितने ही बरसातों से हमारे सामने रूस के आक्रमण का हौआ खड़ा किया जाता रहा है और इसे हमारा शस्त्रास्त्र पर विशाल खर्च का बहाना बनाया गया है। ज़ारों के जमाने में हम से कहा जाता था कि रूस का साम्राज्य सदा दक्षिण की ओर बढ़ता आ रहा है, समुद्र के रास्ते या स्वयं भारत की लालसा से अधीर हो रहा है। ज़ार जा चुका, मगर इंग्लैंड और रूस की प्रतिद्वंद्विता जारी है और अब हम से कहा जाता है कि भारत को सोवियत सरकार से खतरा है।’\*\*\*

स्वतंत्र भारत ने इस “परम्परा” से नाता तोड़ लिया है।

\* *Report of the Seventh Indian National Congress* pp 28—36

\* विमल प्रसाद, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४३-४४।

\*\* J Nehru *Soviet Russia* Allahabad 1928 p 191

### सामाजिक आर्थिक ढांचा

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ज़ारशाही रूस में बोकान के घान प्रांतिन प्रदेश को पराजित और उसपर कब्ज़ा कर लिया तथा दो और घान प्रांतिन प्रदेश—बुखारा और खीवा—के क्षेत्रफल को कम कर दिया, जो अधीन राज्या के रूप में साम्राज्य के दायरे में शामिल कर लिये गये थे। मध्य एशिया और दक्षिण कज़ाख़स्तान में अधिवृत्त इलाक़े को गवर्नर-जनरल द्वारा प्रशासित तुर्किस्तान नामक क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया। १९१६ में रूसी तुर्किस्तान की जनसंख्या ७४,६८,१००, बुखारा का २०,३६,८३० और खीवा की ६,४०,००० थी।\*

तुर्किस्तान भी बुखारा और खीवा के घान प्रांतिन राज्यों की तरह बहुजातीय था। उनमें उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमन, कज़ाख़, त्रिभिन्ज, कराकल्पाक तथा अन्य जातियाँ थीं। खीवा और बुखारा का अपने अधीन बनाने के बाद ज़ारशाही रूसी सरकार ने उन्हें नान ओंग अधीर की गद्दी की रक्षा अपनी सेना द्वारा की और इन राज्यों में शासन करने में सहायता की।

\* अ० अ० गार्दियेका, "रूसी तुर्किस्तान में सामाजिक परिवर्तन की स्थापना", मास्को, १९३६, पृष्ठ १३। (रूसी संस्करण)

औपनिवेशिक काल में तुकिस्तान, बुखारा और खीवा कृषिप्रधान क्षेत्र थे। १९१३ में कुल १९ फी सदी आबादी शहरो और शहरी वस्तिया में रहा करती थी।\* १९१७ की अखिलरूसी कृषि जनगणना के अनुसार तुकिस्तान में कृषिक घघा में काम करनेवाला की संख्या ५३,७५,५३८ थी, जिनमें ३५,८१,८७३ खेती करते थे और बाकी खानाबदोश पशुपालक थे। तुकिस्तान में और उससे कहीं अधिक खीवा और बुखारा में सामंती सामाजिक संबंधों का प्रभुत्व था। कुछ इलाका में, जैसे तुकिस्तान के कज़ाख़ किगिज़ इलाको और खीवा और बुखारा के तुकमान इलाका में अभी भी खानाबदोश लोगो में पितृसत्तात्मक बर्दाश्ती जीवन पद्धति के अनेक अवशेष दिखाई देते थे।

तुकिस्तान, लेनिन के शब्दों में, सीधा उपनिवेश था।\*\* बुखारा और खीवा के खान शासित प्रदेशों का अस्तित्व यद्यपि “स्वतंत्र” रूप में था, वास्तव में वे तुकिस्तान से बहुत कम भिन्न थे और “उपनिवेशों की ही तरह बंधे”।\*\*\* मध्य एशिया में पूँजीवादी विकास की प्रक्रिया बहुत धीरे और असमान रूप से चल रही थी, क्योंकि ज़ारशाही तथा बुखारा और खीवा के सामंती शासन जान-बूझकर सामंती और पितृसत्तात्मक संबंधों को बनाये रखने के प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए यह इलाका अक्टूबर क्रांति तक ज़ारशाही रूस का अत्यंत पिछड़ा हुआ कृषिक उपनिवेश था। यह उन पिछड़े हुए देशों में से था, जहाँ “पूँजीवाद-पूर्व संबंध”\*\*\*\* अभी प्रधान थे।

यह सही है कि ज़ारशाही सरकार ने तुकिस्तान में कुछ भूमि-सुधार किये थे, जिनसे मध्य एशिया के गाँवों में पूँजीवादी संबंधों का विकास का रास्ता खुल गया था। परन्तु इन सुधारों ने श्रमजीवी किसानों को उनकी सामंती अधीनता और गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाई। बड़े जमींदार

\* १९६३ में मध्य एशिया का अथर्न , सांख्यिकीय सर्वेक्षण” ताशकंद, १९६४, पृष्ठ ८। (रूसी संस्करण)

\*\* V I Lenin Collected Works, vol 22, p 338

\*\*\* वही, खण्ड २५, पृष्ठ २७।

\*\*\*\* वही, खण्ड ३१, पृष्ठ २४२।





बटाईदारों का शोषण करते रहे। सबसे प्रचलित रूप चैरीकारी था, जिसका मतलब यह था कि किसान को पंदावार व चार भाग में से सिर्फ एक भाग मिलता था। चूंकि अधिकांश किसानों के पास खेती के लिए अपने जानवर कृषि के औजार और बीज आदि नहीं होते थे, वे जमींदारों और माहूवाग व शिकजों में पड़ जाया करते थे। सिचाई के क्षेत्र में औपनिवेशिक काल में बहुत कम प्रगति हुई थी। १९१० में पूरे मध्य एशिया में केवल ४७५८०००० हेक्टेयर (१ हेक्टेयर = १०९ हैक्टर) जमीन पर सिचाई होती थी जो पूरे इलाके का केवल २६ प्रतिशत था। तुर्किस्तान व पांच ओब्लास्तों (प्रान्तों) में सिंचित भूमि का पूरा क्षेत्रफल २८०८०००० और यकारा में १६००,००० हेक्टेयर था।\* टासकास्पियन ओब्लास्त में और ताशकन्द के दक्षिण-पश्चिम वजर स्तपी में कुछ सिचाई का काम शुरू किया गया था। रिचर्ड ग्र० पियस सिचाई के क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए लिखता है

‘मध्य एशिया में सम्पन्न की जा सका—एक वजर स्तेपी में और दूसरी मरगि में। इनमें से किसी में भी उनका डिजाइन बनानेवाला की प्रारम्भिक जमींदार या उन लोगों की महान आशाएँ पूरी नहीं की, जिनका हम पूरे इलाके में वही विशाल उपलब्धियों की योजना १८७४ में गवर्नर वजर स्तेपी में व्यापक नहर निर्माण की योजना १८७४ में गवर्नर जनरल फान काउफमन व आदमानुसार शुरू की गई, मगर अंत में १८७६ उस त्याग देना पड़ा। स्थानीय लोग इस तगुज आरीक या ‘सुधर की नहर’ कहा करते थे। १९१२ में ग्र० व० त्रिनाशईन ने एक भारी भ्रमक योजना रखी जिसमें नयी सिंचित भूमि पर १५००००० हेक्टेयर किसानों को बसाने की योजना भी शामिल थी। इसपर अभी अमल नहीं हुआ।

\*५० इ० त्याश्चको “सोवियत संघ के अद्यतन का इतिहास” मास्को १९४८, खण्ड २ पृष्ठ ५४३।  
 \*\* R A Pierce *Russian Central Asia 1867—1917* Berkeley and Los Angeles 1960 p 181

तुर्किस्तान में और उससे ज्यादा खीवा और बुखारा में कृषि और पशुपालन दोनों ही पुराने जमाने के थे। कृषि में प्रयुक्त औजार आदिकालीन थे जिससे श्रम उत्पादनता और भूमि की पैदावार बहुत कम थी। किसानों का कृषि-तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने पशु-चिकित्सा विज्ञान का नाम भी नहीं सुना था। भूमि, जल और पशु जमींदारों और कुत्तों के हाथों में सकेन्द्रित थे। तुर्किस्तान के कुल किसान परिवारों में ६५ प्रतिशत भूमिहीन किसान थे।\* खीवा और बुखारा में सामंती प्रभुत्व की प्रधानता थी। खीवा में खानों तथा अन्य सामंती जमींदारों की निजी जमीन कुल सिंचित और उपजाऊ जमीन का दो तिहाई थी, सातवा भाग राज्य की तथा बक्फ जमीन थी और किसानों के स्वामित्व में केवल दसवा भाग जमीन थी।\*\* बुखारा में कुल खेती योग्य जमीन का ६५ प्रतिशत जमींदारों की और २४ प्रतिशत बक्फ जमीन थी।\*\*\* करो का बड़ा बाँझ किसानों के ऊपर था। खीवा में किसानों का २५ किस्म के और बुखारा में ५५ किस्म के कर देने पड़ते थे। किसानों को नहरों के निर्माण और मरम्मत का काम करना पड़ता था और इस प्रकार के श्रम का प्रयोग सामंती वर्ग अक्सर अपने निजी फायदे के लिए करत थे। खीवा में दास प्रथा भी थी। जे० व्हीलर ने जर्मन श्रवण-रिफ्लेक्स के कुछ अचिंतित वाक्यों तथा बरतोल्ड के अप्रासंगिक उद्धरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का जो प्रयास किया है कि बुखारा में जीवन "समृद्ध" था, बिल्कुल विश्वासप्रद नहीं है।\*\*\*\* यह कह देना जरूरी है कि बरतोल्ड ने भी शतर की राय का उल्लेख किया है कि बुखारा के समीर मुजफ्फर

\* अ० अ० गादियेंको उपराक्त पुस्तक पृष्ठ २३।

\*\* म० य० यूल्गाशेव, "प्राच्यविदों के पहले अखिल सघीय वैज्ञानिक सम्मेलन की लेख-सामग्री", ताशकन्द, १९५३, पृष्ठ २०५। (रूसी संस्करण)

\*\*\* म० हिक्मानोव, 'जरफशान प्रदेश में भूमि सुधार तथा सिंचाई व्यवस्था', ताशकन्द, १९५३ पृष्ठ ३-४। (रूसी संस्करण)

\*\*\*\* G. Wheeler *The Modern History of Soviet Central Asia* London 1964 p 85

से लोग "घणा करते थे क्योंकि वह अन्यायी और अत्याचारी था" बरतोल्द लिखते हैं कि उसने शासन काल में 'जबरदस्ती वसूली की व्यवस्था थी जिससे लोग तबाह हो जाते थे'।\* वह बताता है कि रूसी अखबारों में अमीर की लम्बी चौड़ी प्रशंसा का जो विरोध किया गया है, वह न्यायपूर्ण है।\*\*

मध्य एशिया पर कब्जा होने के बाद उसको प्रधान देश के उद्योगों के लिए कच्चा सामान सप्लाई करने का स्रोत बना दिया गया। जारशाही प्रशासन कपास की खेती पर बहुत ध्यान देता था और गेहूँ तथा कृषि की अन्य पैदावार के बदले उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करता था। तुकिस्तान में भूमि प्रशासन के निदेशक ने १९१३ में लिखा था तुकिस्तान के हर पूव (१ पूव = १६३८ किलोग्राम) गेहूँ का मतलब है रूसी और साइबेरियाई गेहूँ से प्रतियोगिता, हर पूव कपास का मतलब है अमरीकी कपास से प्रतियोगिता। इसलिए यह कहीं अच्छा है कि इस इलाक़ में खाद्यान्न का आयात किया जाय और वहाँ की सिंचित ज़मीन को कपास की खेती के लिए छोड़ दिया जाये।\*\*\* बाहर से मगवाये हुए कपास पर अधिक चुगी लगी होने के कारण अदरुनी मंडी में प्रशासन ऊँचा दाम बसूल करता था, तथा कपास की खेती तथा अन्य कम लाभदायक खाद्यान्न के लिए प्रयुक्त भूमि पर समान मर लगाने की नीति से कपास की खेती को बढ़ावा मिला जिससे वह कृषि की मुख्य नकदी फसल हो गई। इसके अलावा प्रशासन ने अनेक कृषि-संबंधी कदम उठाये जिनसे कपास की खेती के विकास में सहायता मिली। १८६२ में ३० लाख पूव अमरीकी किम्म का कपास तुकिस्तान से रूस में निर्यात किया गया। कपास का निर्यात १८८० में ८७३००० पूव से बढ़कर १९०० में ४६६०००० पूव और १९१३ में १,३६६७,००० पूव हो गया। उन्नेको की धरती मध्य एशिया

\* व० व० बरतोल्द रचनाएँ, खण्ड २, भाग १, मास्को, १९६३, पृष्ठ ४२०-४२१। (रूसी संस्करण)

\*\* वही पृष्ठ ४२४।

\*\*\* 'उज़बेकिस्तान के जनगणना इतिहास', ताशकन्द, १९५०, खण्ड २, पृष्ठ २६१। (रूसी संस्करण)



के कपास-क्षेत्र का केन्द्र बन गयी, यद्यपि कपास की खेती दक्षिणी किर्गिजस्तान तथा आधुनिक तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाकों में भी होती थी।

परन्तु कपास की खेती के विकास से देहकानों ( किसानों ) की भौतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब प्रधान दशिय पूँजी स्थानीय फर्मों के जरिये कपास की खेती के लिए वित्त प्रदान करने लगी तो एक नया शोषक सामन्य आ गया। कपास का खरीदार, जो उद्योगपति और कपास उत्पादक के बीच एक प्रकार के मध्यजन का काम करता, उनका शोषण करता था। देहकानों को जो ऋण लिया जाता था, उसके सूद की दर इन मध्यजनों के माते बहुत ऊँची होती थी। मध्यजन निजी बका और कपास फर्मों से ८-९ प्रतिशत दर पर ऋण लेते और उसे कपास उत्पादकों को ४०-६० प्रतिशत सूद पर शिया करते थे।\* अविकाश छोटे किसानों पर कज का इतना बोझ हो गया था कि यह जीवन भर अदा नहीं किया जा सकता था। अपना कज चुकाने के लिए उन्हें अक्सर बाई के हाथ अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी।

१९१४ में सरकारी आकड़ा न अनुसार फरगाना क्षेत्र में कुल किसान परिवारों में २५ प्रतिशत अपनी जमीन की बिनी या बंधक रखने के कारण भूमिहीन हो गये थे।\*\* समरकन्द प्रदेश में कुल किसान परिवारों में ३५७ प्रतिशत और फरगाना में ५४५ प्रतिशत के पास अक्तूबर क्रांति से पहले केवल एक देसियातीना जमीन थी। कपास की खेती के विकास के साथ कृषिक अत्यन्त की विनियता बनी, जिससे गावों में प्रारम्भिक पूँजीवादी संघर्षों का दखन हुआ परन्तु उत्तरती श्रम का प्रयोग करनेवाले कपास के बड़े पूँजीवादी बागानों की उत्पत्ति नहीं हुई। मध्य एशिया में घटाई की व्यवस्था ही प्रधान व्यवस्था बनी रही।

\* अ० व० विबोर्गेन '१९१२ में तुर्कमान क्षेत्र की यात्रा का विवरण, पृष्ठ १८। (रूसी संस्करण)

\*\* १० नोमनिन, "उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, ताशकन्द १९६० पृष्ठ ४०। (रूसी संस्करण)

तुल्यमान, किंगिज और न्याय खानाबदोश तथा कराबन्पाको और भीतरी इलाके की पहाड़ियां में रहनेवाले ताजिका की सामाजिक संरचना की ध्यानपूर्वक खानबीन करने की आवश्यकता है। इन खानाबदोश लोगों में पितृसत्तात्मक वंशायली सामाजिक संस्थाओं का अवशेष काफी प्रबल था। उनमें जटिल कबीला-कुल व्यवस्था का अस्तित्व से कुछ लेखकों को यह कहने का आधार मिल गया कि वंशायली व्यवस्था २० वीं सदी के प्रारम्भ तक कायम थी। परन्तु वास्तव में इन लोगों में वंशायली व्यवस्था कई सदी पहले नष्ट हो चुकी थी और १८ वीं और १९ वीं सन्तियों में उसकी सामाजिक संरचना में केवल उसकी परम्पराएँ रह गई थी। उनके खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश पशुपालन अथवा के कारण पितृसत्तात्मक परम्पराओं के अवशेष बहुत दिना तक बने रहे। तुल्यमानों में खान और बैक, किंगिजों में मानप\* और बी और कुलक बाई जैसे शोषक वर्ग की प्रबल इच्छा थी कि पितृसत्तात्मक-वंशायली परम्पराओं को कायम रख ताकि उनके द्वारा गरीबों के शोषण पर परदा पड़ा रहे। ऐसे समाज में जहाँ अधिक असमानता बहुत हो, चरागाहों भूमि और जल के समान स्वामित्व का कोई अर्थ नहीं हो सकता था। गरीब खानाबदोशों के शोषण का रूप यद्यपि पितृसत्तात्मक था मगर उसका सार फिर भी सामंती था। तुल्यमानों में कृषि योग्य भूमि और पानी का बंटवारा ग्रामीण समुदाय द्वारा हर साल होता था। उस रिवाज को सनानशिक कहा जाता था और इसका आधार था भूमि और पानी का समान वंशायली स्वामित्व का 'यायिक' भ्रम। कबीले के सदस्य नहरों की सफाई और युद्ध में अपने आउल (गाव) की रक्षा करते थे। इसलिए भूमि और पानी का बंटवारा बड़ी आयु के लोगों में किया जाता था जो नहरों साफ करने और खोदने के योग्य हों और हथियार उठा सकें। प्रागे चलकर यह परम्परा बदल गई और भूमि और पानी में हिस्सा केवल कबीले के विवाहित सदस्यों को दिया जाता था। धनी खान बैक और बाई लोग अपने छोटे बच्चों का भी विवाह कर देते थे और इस प्रकार उन्हें भूमि अपने हाथों में सन्तुष्ट करने का अवसर

\* मानप - कृषि योग्य भूमि तथा चरागाहों के धनी स्वामी।

मिल गया। इसके विपरीत गरीब तोग वध का ऊँचा दाम होने के कारण विवाह नहीं कर सकते थे, अधिकतर भूमिहीन होने जाते थे। चरागाहों का उपयोग कबायली परम्परा के अनुसार कबीले के सभी सदस्य कर सकते थे परन्तु कुआँ और कुड जिनके बिना पशुपालन नहीं हो सकता था, धनी लोगों के कब्जे में थे।

इसी प्रकार किगिज शायक वग भी अपने दरअसल सामंती शोषण पर परदा डालने के लिए कबायली पितृसत्तात्मक परम्पराओं का प्रयोग करते थे। चरागाह यद्यपि कबीले की सम्पत्ति थी मगर वास्तव में उनपर भी धार मानपों ने अधिकार जमा रखा था, जो लोगों का सामंती शोषण किया करते थे। पशुधन बहुत थोड़े हाथों में केंद्रित हो गया था। इसकी पुष्टि एक छानबीन के नतीजे से भी होती है, जो पिश्पक उयेन्द (जिला) में १९१२-१९१३ में की गई थी। कुल परिवारों में ५ ५२ प्रतिशत उच्च वग के मानपों, बी और बाई लोगों के परिवार थे जिनके पास ३३ ५१ प्रतिशत पशु थे, जबकि ४९ २२ प्रतिशत परिवारों के पास केवल ११-१२ प्रतिशत पशु थे।\* ४७ ७५ प्रतिशत परिवारों के पास खेती के औजार नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि किगिज ग्रामीण समाज में वग भेद किस हद तक बढ़ चुका था। चरागाहों के समान प्रयोग तथा भूमि पर समान कबायली स्वामित्व के अनेक परम्परागत अधिकारों के बावजूद य भेद कम नहीं थे।

तुर्किस्तान का प्रशासन गृह मन्त्रालय के नहीं, बल्कि युद्ध मन्त्रालय के अधीन था। जार द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उस क्षेत्र का सारा सैनिक और नागरिक प्रशासन उसने हाथों में केंद्रित था। बुखारा और खीवा के मामले में भी उसे बड़ा अधिकार था। स्थानीय अभिजात वग तथा सैनिक अफसरों में से वह ओब्लास्त और उयेन्द के अधिकारियों को नियुक्त किया करता था।

\* "मध्य एशिया और कजाखस्तान के जनगण" भाग २, मास्का, १९६३, पृष्ठ १७८। (रूसी संस्करण)

ओब्लास्त प्रशासन का प्रधान सैनिक गवर्नर था, जिसके हाथों न सभी सैनिक और नागरिक मामले, यहाँ तक कि न्याय प्रशासन भी केंद्रित था। उयेस्द और नगर प्रशासन के प्रधान साधारणतः सैनिक अफमरो में से नियुक्त किये जाते थे। ओब्लास्त और उयेस्द स्तर पर सैनिक प्रशासन के अलावा ज़ारशाही सरकार ने तथ्यावधित जननिर्वाचित ग्राम प्रशासन का भी उपयोग किया। बोलोस्त (चन्द गावों की निम्नतम प्रशासकीय इकाई) शासक तथा ग्राम अधिकारियों—स्तारशोना, आकसकल और क्लावी की नियुक्ति चुनाव के जरिये होती थी। परन्तु इन नियुक्तियों की मजूरी ओब्लास्त के सैनिक प्रशासक से लेनी पड़ती थी। ये नियुक्त किये गये अधिकारी उयेस्द शासकों के नियंत्रण में काम करते थे। अपने धन और प्रभाव का, क्योंकि केवल धनी लोग ही चुने जा सकते थे। अपने धन और प्रभाव की बदौलत बाई और सामन्ती ज़मींदार हमेशा इन पदों पर कब्ज़ा किये रहते थे। इन चुनावों में रिफवत का भी बड़ा हाथ था, इसे काउंट पलेन ने तुकिस्तान की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में स्वीकार किया है।\* इसने अलावा सैनिक गवर्नर को अधिकार था कि चुनाव के नतीजे बदल दे या चाहे तो बोलोस्त प्रशासक ग्राम स्तारशोना (प्रधान) और क्लावी को बिना किसी चुनाव के स्वयं नियुक्त कर दे। चूँकि इन निर्वाचित अधिकारियों तथा औपनिवेशिक प्रशासन का वगैरह एक ही था, यानी गरीबों का शोषण करना इसलिए उन्होंने एक दूसरे से अच्छी तरह सहयोग किया। निर्वाचित स्थानीय अधिकारी अपनी महत्तक जनता के खिलाफ रूसी उपनिवेशवादियों से मिल जाते थे। उससे तरह-तरह की बलपूर्वक वसूलिया तथा उसके विरुद्ध अधिकार का दुरुपयोग रोजमर्रा की बात थी। प्रार० पियस लिखता है कि अधिकार उयेस्द अधिकारी "स्थानीय लोगों से अतिरिक्त कर वसूल करते थे जिससे न केवल सामान्य धन ही पूरा होता था, बल्कि व आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे"।\*\* यूरोपीय

\* व० क० पलेन "तुकिस्तान क्षेत्र की निरीक्षण रिपोर्ट। ग्रामीण शासन", सेट पीटसवग १९१० पृष्ठ ६७-१०३। (रूसी संस्करण)

\*\* प्रार० पियस, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०।

रूस का सैनिक प्रशासन अपन सबसे खराब अफमरो से मुक्ति पान क  
लिए साधारणत उह तुकिस्तान भेज दिया करता था।”

खीवा और बुखारा के खान प्रशासन सामती निरकुश बादशाही का  
नमूना थे। खान और अमीर को अपनी प्रजा पर जीवनमरण का पूरा  
अधिकार था। वे जमींदार अभिजात वग तथा मुल्लाओं को सन्धिय सहायता  
स उनपर शासन करते थे। खीवा का खान शासित प्रदेश २२ बेकदारियों  
में बंटा हुआ था और बुखारा का २६ हाकिमदारियों में। बेकदारों का  
प्रधान बेक होता था और हाकिमदारों का प्रधान हाकिम, जिनको खान  
और अमीर नियुक्त करते थे। यह अधिकारी मनमान ढंग से अनेक छा  
अधिकारियों की सहायता से शासन करते थे।

अगरचे जारशाही जान-बूझकर मध्य एशिया को अपना कृषिक कच्चा  
सामान का स्रोत बनाये रखना चाहती थी पर अपन सैनिक और रणनीतिक  
हितो और रूसी पूजीपति वग के सक्ती हितो से मजबूर हाकर उसे ३,३७७  
किलामीटर रेलव लाइन और १४ रेलवे मरम्मत वकशाप और टिपा बनाने  
पड़े, जिनमें सब मिलाकर लगभग २४,००० मजदूर काम करते थे। मध्य  
एशिया में रेलवे का निर्माण पिछली सदी के नव दशक के मध्य में शुरू  
हुआ। १८८८ में समरकंद का रेल द्वारा त्रास्नोवोदस्क से १८९८ में  
अन्दीजान से और एक साल बाद ताशकंद से जोड़ दिया गया था। १९०६  
में ताशकंद को एक शाखा लाइन के जरिये आरेनवुग से मिला दिया गया  
था। रेलवे के निर्माण से मध्य एशिया के भीतर विभिन्न इलाकों के आर्थिक  
अलगाव का और पूर मध्य एशिया के अलगाव का भां अत हाने लगा।  
परंतु विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्नी एकत्रीकरण पर रेलवे का प्रभाव अभी  
नगण्य था। फिर भी यह एक नयी परिघटना थी जिससे इस क्षेत्र के  
भविष्य के लिए नयी सम्भावनाएँ उत्पन्न हो गई।

रूसी पूजीपति वग का डम इलाकों में कच्चा माल की तयारी का उद्योग  
विकसित करना पड़ा। यह उसके अपन हित के अनुसार था और उसे  
उससे प्रतियोगिता का कार्द खतरा नहीं था। कपास आटाई, तल, साबन,



वग की उत्पत्ति घनी बाई लोगो, साहूकारो और व्यापारियो से हो रही थी, परन्तु अभी वह कमजोर था और अपने बड़े उद्योग नहीं स्थापित कर सकता था। इसलिए उसने रूसी पूँजीपति वग पर अपनी निर्भरता का स्वीकार कर लिया। मध्य एशिया की जातियो मे केवल उज्बेक और कजाख मे राष्ट्रीय पूँजीपति वग की उत्पत्ति हो चुकी थी, किगिज़, ताजिक और तुक्मान मे इसका कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। औद्योगिक सवहारा भी सख्या की दृष्टि से कम था। उज्बेको मे भी जहा इसका सख्या दूसरी जातियो की तुलना में अधिक थी, पूरी आबादी मे यह नगण्य था। तात्ति से पहले केवल १२,७०२ उज्बेक औद्योगिक मजदूर थे।\* जहा तक तुक्मानो किगिज़ा और ताजिको का सवाल है, उनके पूँजीवाद विकास का स्तर और कम था। किगिज़स्तान मे कोई उल्लेखनीय राष्ट्रीय पूँजीपति वग नहीं था और सभी खनन उद्योग रूसी और तातार पूँजीपतियो के हाथ मे थे। किगिज़ मजदूरों की सख्या १९१३ मे केवल ११४४ था।\*\* तुक्मानिस्तान में औद्योगिक विकास केवल ट्रांसकास्पियन इलाके तक सीमित था और तुक्मान मजदूरों की सख्या कम थी। १९१६ मे केवल २४२ तुक्मान औद्योगिक मजदूर थे जिनमे निपुण केवल सात थे।\*\*\* ताजिकिस्तान मे कोई आधुनिक उद्योग नहीं था और वर्तमान लेनिनाबाद इलाके के उत्तर मे कपास शोधन और तेल और कायला खनन के जो छह छोटे उद्यम थे, उनमे केवल २०६ ताजिक औद्योगिक मजदूर काम करते थे।\*\*\*\*

अतः तात्ति से पहले मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसपर सामंती उत्पादन-संबन्धों का प्रभुत्व था। लेनिन ने कहा कि तुकिस्तान उन दशों में था, जो पूँजीवादी विकास के रास्ते पर उन्नति नहीं कर सके थे और जहा "औद्योगिक सवहारा" किसी महत्व का नहीं

\* म० बहावोव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४५।

\*\* "सावियत संघ मे समाजवादी जातियो का निर्माण", मास्को, १९६२ पृष्ठ ४९९। (रूसी संस्करण)

\*\*\* वही, पृष्ठ ५९७।

\*\*\*\* अ० अ० गोदियेका, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ २४।

था। लेकिन हमारा मतलब यह नहीं कि स्त्री-शिक्षण मध्य एशिया में पूजावादी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ था। बल्कि यह था कि यह इलाका पूजावादी विचारों की पूरी शक्ति से लैस हुआ था और भी वह रेख तथा कृषि बच्चे मानव के प्रारम्भिक प्राणिक चरणों की उत्पत्ति का बोधना पूजावादी चिन्तन के द्वारा कर सका था।

भारत का जनविकास के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें अपने  
 को लोगो का स्वास्थ्य तथा की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।  
 विकास की। तुलनात्मक म केवल २५० करोड़ रुपया के अर्थव्यवस्था में  
 सब शहरों में काम करने दें। - को न केवल के लिए ही नहीं  
 सुविधा देना है। बल्कि हमें अपने अर्थव्यवस्था में भी विकास के लिए  
 सेवा का कोई प्रयत्न ही नहीं है। हमें अपने अर्थव्यवस्था में विकास के लिए  
 नीमट्रीमें और पाणों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।

पिता व क्षेत्र में स्थिति का उल्लेख नहीं है। १९११ में परिवार  
 के राज्य-बजट का बेटा ० ३ अर्थात् बजट की पिता का बजट  
 किया गया था और ० ३ अर्थात् बजट, बजट का १९११ में  
 प्रभावशील बजट के लिए अर्थात् १९११ में १९११ में १९११ में  
 १९११ राजकाय पिता अर्थात् १९११ में १९११ में १९११ में  
 १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अर्थात् बजट, १९११ में १९११ में १९११ में  
 और खाता में अर्थात् बजट का बजट १९११ में १९११ में १९११ में  
 में खाता में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 की मन्ता ४० अर्थात् १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 सुमानों में ० ३ अर्थात् बजट १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 बजट-बजट में ० ३ अर्थात् १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 और खाता में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 और बजट में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में  
 सुमानों का बजट १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में १९११ में



## सांस्कृतिक विकास

औपनिवेशिक काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता है, यद्यपि आम तौर पर यह सांस्कृतिक पिछड़ेपन का काल था। तुर्किस्तान में लौकिक स्कूला तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थानों का खुलना बहुत महत्वपूर्ण था। पहला रूसी स्कूल समरकन्द में १८७० में खुला।\* तत्कालीन गवर्नर-जनरल काउफमन ने इस बात का बहुत महत्व दिया कि स्थानीय लोग अपने बच्चा को रूसी स्कूल में भेजे, जहाँ लौकिक तथा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु रूसी स्कूलों में बहुत कम स्थानीय विद्यार्थी गए। ज्यादा-ज्यादा बचें बीतते गये उनकी लोकप्रियता और कम होती गई। इसका कारण यह था कि हमी छात्रों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, परन्तु मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था।\*\*

स्थानीय छात्रों का स्कूलों में आकर्षित करने के लिए एक और तरीका मिश्रित रूसी-स्थानीय स्कूलों की स्थापना था। ऐसा एक स्कूल ताशकन्द में दिसम्बर १८८४ में एक धनी उज्बेक सैन्य गनी की पहलकदमी पर स्थापित किया गया।\*\*\* १९११ तक १०५ ऐसे स्कूल काममें हो चुके थे। स्कूल का पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा था, यानी रूसी भाषा और गणित शास्त्र आदि, जो रूसी शिक्षक पढ़ाता था, और मुस्लिम धार्मिक शिक्षा मुफ्त दी जाकरा था।\*\*\*\*

स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन में ये नयी गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। रूसी संस्कृति के प्रभाव में पुराने स्कूलों के सुधार का ह्याल पैदा हुआ, ताकि उन्हें जीवन की नयी स्थितियों के अनुकूल बनाया जाय। नये स्कूलों को नयी प्रणाली के स्कूल कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अध्ययन की धार्मिक प्रणाली अपनायी थी। इस उसूल एजदोद (नये उसूल)

\* व० व० बरतोव, रचनाएँ, खण्ड २ भाग १, पृष्ठ २६६।

\* वही पृष्ठ ३०२।

\*\* वही पृष्ठ ३०५।

\*\*\* 'उज्बेकिस्तान के जनगणना का इतिहास' खण्ड २, पृष्ठ ३२६।



भूगोलविद, भूविज्ञ तथा जीवविज्ञानी आये, जसे उदाहरण के लिए, प० प० सेम्योनोव तियानशानस्की नि० अ० सेवेत्सोव, अ० प० फेचनको, इ० व० मुष्वेतोव, ग० द० रोमानोव्स्की वगैरह। व० व० बरतोल्द और न० इ० वेसेलाव्स्की ने मध्य एशिया के इतिहास और सस्कृति के बारे में बहुमूल्य सामग्री जमा की तथा उसका अध्ययन करने में अग्रणी भूमिका अदा की। ताशकन्द में १८७० में एक सावजनिक पुस्तकालय खोला गया जिसके लिए सेट पीटसबग और मास्को की विभिन्न सांस्कृतिक सस्थाओं ने तथा अनेक रूसी विद्वानों ने पुस्तकें दान की। अ० प० फेचनको की पहलकदमी पर १८७१ में ताशकन्द में एक संग्रहालय आयोजित किया गया था। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का मुद्रण भी उस इलाक के जीवन में एक महत्वपूर्ण नयी घटना थी। रूसी वैज्ञानिकों की पहलकदमी पर भूगोल मानव विज्ञान पुराविद्या, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक वैज्ञानिक सस्थाएँ संगठित की गई। इन सब बातों से मध्य एशिया के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में अवश्य ही योगदान मिला।

इन गतिविधियों का स्थानीय बुद्धिजीवियों पर प्रबल असर पड़ा और स्थानीय लोगों में बौद्धिक जागरण तेजी से फैला। प्रगतिशील रूसी सस्कृति के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क से उनमें नये लौकिक ज्ञान की आकांक्षाओं की प्रोत्साहन मिला और इसके अध्ययन के लिए उनमें शीघ्र ही एक आन्दोलन चल पड़ा। नयी सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए इस आन्दोलन को अक्सर भ्रामक रूप में जदोदियत से जोड़ दिया जाता है। जदोदियत का यह मूल्यांकन कि वह स्थानीय बुद्धिजीवियों का प्रगतिशील आन्दोलन था इस ऐतिहासिक गलतफहमी का नतीजा है कि २० वीं सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया में ज्ञान प्रसार का जनवादी आन्दोलन लुप्त हो चुका था और उसका स्थान जदोदियत ने ले लिया था। इसके अलावा कुछ अनुसंधानकर्ता जदोदियत को प्रगतिशील आन्दोलन के रूप में इसलिए भी समझन लगे हैं कि अनेक देशों में जिन्होंने हाल ही में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त की है, राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय



था। कुछ भूदत्त में एक विचारधारात्मक तथा राजनीतिक आन्दोलन की रचना हुई, जिसमें ऐतिहासिक साहित्य में जदीदियत का नाम पाया। प्रसिद्ध सोवियत उज्बेक इतिहासकार म० ग० वहावाव के शब्दों में 'जदीदियत औपनिवेशिक' मध्य एशिया के स्थानीय पूजोपति वर्ग का राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में उत्पन्न हुई।' उनके अनुसार "इस विचारधारा की उत्पत्ति मजदूरों के नातिकारी आन्दोलन तथा जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के दौर में हुई, जब स्थानीय पूजोपति वर्ग ने आम जनता से नाता तोड़ लिया और जारशाही तथा रूसी पूजोपति वर्ग का समर्थन करने लगा।"\*

मध्य एशिया की पूजोपति राजनीतिक विचारधारा का जिस चौड़ा ने एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों की राजनीतिक विचारधारा से अलग किया वह मध्य एशिया की विशेष औपनिवेशिक परिस्थिति था। एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में पूजोपति राजनीतिक विचारधारा का विकास ऐसी स्थिति में हुआ, जब मजदूर आन्दोलन कमजोर था, परन्तु मध्य एशिया में जो जारशाही रूसी साम्राज्य का अंग था, स्थानीय और रूसी दोनों ही पूजोपति वर्ग रूसी मजदूर वर्ग के शक्तिशाली आन्दोलन से भयभीत थे। इसमें अलावा मध्य एशिया में राष्ट्रीय पूजोपति वर्ग इतना निबल था कि कोई स्वतन्त्र भूमिका नहीं अदा कर सकता था। वह कबल साम्राज्यवादी रूसी पूजोपति वर्ग के एजेंट का काम करता था।

१९०४-१९०७ की तारीखों के वर्षों में जदीदियों का कायकलाप व्यापक रूप से फैला हुआ था। १९०६ में १९०६ तक उन्होंने कई पत्र प्रकाशित किये जिनमें 'तरक्की', "खुरशेद" "शोहरत" और 'एशिया'। जदीदी अखबारों ने सन-तुक्लाद तथा सब इस्लामवाद का प्रचार किया और प्रभावशाली व्यापारियों और बाईं लोगों को इस्तेमाल करके जनगण की

\* म० वहावाव जदीनियत का प्रतिस्पर्धावादी चरित्र तथा जन विरोधी भूमिका - महान अकतूबर समाजवादी तारीख में पूरे तथा उसके दौरान में जातीय प्रश्न (सांख्यिक विज्ञान अकादमी की वित्तिक समिति की बैठक के लिए लेख-सामग्री), पहला भाग मास्को, १९६४ पृष्ठ ५०-५३। (रूसी संस्करण)

इस प्रकार तले इकट्ठा करने का प्रयास किया। जदीदी अखबार जनगण का मुसीबतों, श्रमजीवी किसानों और कारीगरों की बढ़ती हुई दरिद्रता, बाई लोगों तथा साहूकारों द्वारा उनके शोषण तथा औपनिवेशिक प्रशासन का मनमानी धांधली के बारे में कुछ नहीं लिखा करते थे। परन्तु लोगों को तो ठीक यही सवाल विचलित कर रहे थे। इस लिए कोई आश्चर्य नहीं कि जदीदी अखबारों का जनगण में कोई प्रभाव नहीं था। १९१६ के विद्रोह के समय जदीदियों ने जनगण का विरोध किया, ज़ारशाही सरकार के लामबन्दी अभियान का समयन किया। उन्होंने जनता को अपना विरोधी बना दिया, जो उनकी प्रतिक्रियावादी भूमिका को समझने लगी थी।

यह सही है कि धार्मिक तथा सामंती तत्वों के मुकाबले में जदीदियत में कुछ उदारवादी प्रवृत्तियाँ थीं। जदीदी नई युरोपीय संस्कृति का समर्थन तथा पुरानी सामंती प्रणाली का विरोध करते थे। यह बात उनमें और अन्य प्रबुद्ध जनवादियों में समान रूप से पायी जाती थी। परन्तु इन दूसरों के विपरीत वे नमस्त जनता के हितों की रक्षा नहीं करते थे। वे अपने वग-पूजीपति वग के हितों—का समर्थन करते थे। धार्मिक तत्वों के विरुद्ध समय में भी वे दृढ़ सैद्धांतिक स्थिति पर जमे नहीं रहे। बल्कि वे इस्लाम के उसूलों का राष्ट्रीय पूजीपति वग के हितों के अनुकूल बनाना चाहते थे।

जदीदियों को राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्ति का बौद्धिक अप्रदूत कहना गलत होगा। उनका उदारवाद भी ऐसी अवस्था से संबन्ध रखता था, जिसमें मध्य एशिया के लोग आगे बढ़ चुके थे। वे अब सबहारा प्राप्ति के द्वार पर खड़े थे। औपनिवेशिक भारत में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आंदोलन से, जो सामाजिक सुधार और नागरिक पुनरुद्धार का आन्दोलन था, जदीदियों की तुलना करना बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि भारत और मध्य एशिया का ऐतिहासिक विकास भिन्न था। राजा राम मोहन राय प्रगतिशील समाज-सुधारक और प्रबुद्ध जनवादी थे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक उदारवादी विचारों का प्रचार-प्रसार किया, जब समाज के नागरिकी स्थापना की शक्तियाँ भारतीय राजनीति के मंच पर नहीं आयी थी। परन्तु जब वेच बुद्धी ने मुसलमानों से अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने और सामाजिक

के विरुद्ध वैधानिक सम्राटवादियों का समर्थन करने की अपील की, ता वह मात्र सुधारक तथा शिक्षा प्रचारक नहीं रहा, बल्कि सक्रिय प्रतिक्रियावादी हो गया। जदीदी नेताओं ने मेहनतकश जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि "मुस्लिम कौम" यानी सारे मुसलमान एक हैं और उनके विभिन्न वर्गों में कोई भेद नहीं है। यह वे ऐसे समय कर रहे थे, जब वर्गीय विरोध दिनोदिन तीव्र होते जा रहे थे और क्रांतिकारी परिस्थिति तेजी से विकसित हो रही थी। यह नई क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिस्थिति और इसमें उनकी प्रतिक्रियावादी भूमिका मध्य एशिया के जदीदियों को भारतीय समाज-सुधारकों से जुदा करती है।

मध्य एशिया की जातियाँ के सामाजिक और वर्गीय ढाँचे तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास स्तर के बारे में ऊपर की बहस का खुलासा करते हुए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बावजूद इसके कि औपनिवेशिक काल में उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये थे, जैसे उदाहरण के लिए, नये शहरों का जन्म, रेलवे का निर्माण, कृषि में पूँजीवादी संघर्षों की उत्पत्ति, हल्के पूँजीवादी उद्योगों की उत्पत्ति और एक आम बौद्धिक जागरण। फिर भी पूँजीवाद पूर्व संघर्षों का प्रभुत्व, सांस्कृतिक पिछड़ापन और अनानता तथा इसलाम का प्रभुत्व रह गया था। परन्तु सामंतवादियों, मुल्ताओं और नवजात राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से जनता का विलगाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। यह विशेष रूप से १९०५-१९०७ में मजदूरों के क्रांतिकारी आन्दोलन के समय और आगे चलकर १९१६ में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के सक्रिय दौर में और बाद के वर्षों में स्पष्ट हो गया था। १९१७ का फरवरी आति के बाद के दौर में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया।

### राष्ट्रवादी तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन

औपनिवेशिक काल में जारशाही शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोह और वगावत हुए। परन्तु उन सभी को राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन कहना सही नहीं होगा। इन संघर्षों में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक शासन के प्रारम्भिक वर्षों में लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में

अनेक प्रगतिशील परिवर्तन हुए। खान-दुशामन की निरकुशता और घुली बूट घमाट के तारीख दिना के बाद जनगण जारशाही शासन की लाई हुई नई तब्दीलिया को पसन्द किय बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए जब मामती और धार्मिक नेताग्रा ने ग़सबात या धार्मिक युद्ध के प्रतिनियामादी नारे के तहत खान प्रशासन को बहाल करने का धार्मिक-राष्ट्रवादी आन्दोलन खड़ा किया, तो जनगण ने उनका साथ नहीं दिया।

१६वीं सदी के आठवें और नव दशकों में फरगाना घाटी में "नवली खाना" ने ऐसे विद्रोहों को भड़काने का प्रयत्न किया। इन विद्रोहों का समयन केवल कुछ अधिकारप्राप्त सामंतवादिया और मुत्ताग्रा न किया, जिनके विशेषाधिकारों पर जारशाही प्रशासन की कुछ बारबाइया से चोट पड़ती थी। १८८५ में दरवेश खान तियुरा ने खान शासन की बहाली के लिए आन्दोलन चलाया। उसके साथ मोमिनबाई आ मिला, जिसने फरगाना क्षेत्र में एक सफ़र सन्तान संगठित किया। जारशाही सेना ने इस विद्रोह को आसानी से कुचल दिया। दरवेश खान भागकर काशगर चला गया और मोमिनबाई गिरफ्तार हो गया।

दरवेश खान के विद्रोह को जन-समयन नहीं प्राप्त था। इसी तरह मदाली ईशान का विद्रोह या तथाकथित अदीजान बगावत भी जनप्रिय आन्दोलन नहीं था। मदाली ईशान बुखारा का रहनेवाला था जहाँ उसने अध्ययन किया और कुछ दिन अमीर की चाकरी की। आठवें दशक के प्रारम्भ में वह अदीजान आया और यहाँ उसने जैसे-तैसे करके बहुत धन अर्जन कर लिया और अपने मुरीबों या चेनों के जग्ये कुछ स्थानीय प्रभाव भी हासिल कर लिया। ईशान मिंग-तेपे गांव में बस गया, जहाँ उसने एक धार्मिक समुदाय की स्थापना की। परन्तु साधारण लोगों से उसका दूर का भी संबंध नहीं था और उसके चेले अधिकतर सामंती क्षेत्र के लोग थे। रूसियों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध का जो नारा उसने १७ मई, १८६८ का दिया, उसका लोगों ने समयन नहीं किया और जब उसने अदीजान पर घावा किया, तो वह मात्र १००० आदमिया से अधिक को साथ नहीं ला सका। उसने विद्रोह का बिना किसी कठिनाई के कुचल दिया गया और वह पहाड़ों में भाग गया। औपनिवेशिक प्रशासन ने इसके



बाद बड़ा अत्याचार किया। वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन से लोगों का भयभीत करके अपना ताबेदार बनाना चाहता था। तोपा की मालाबारा से मिग-तेपे को मटियामट कर दिया गया और मदाली ईशान के २०५ अनुयाइयों को मार डाला गया।

जारशाही शासन के विरुद्ध इन प्रारम्भिक विद्रोहों का वास्तविक स्वरूप सोवियत ऐतिहासिक लेखों में बड़े बाद विवाद का विषय बना रहा है। “उज्बेकिस्तान के जनगण का इतिहास” के लेखकों ने मदाली ईशान के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की सजा दी है।\* “इज्वस्तिया” अखबार ने इस पुस्तक की समीक्षा की और मसलमान धर्मगुरुओं द्वारा निवेशित और साम्राज्यवादी शक्तियों के दलालों द्वारा उकसाय गये सामान्य राष्ट्रवादी विद्रोहों को जन नातिकारी आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत करने की कड़ी आलोचना की।

ऐतिहासिक घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन सप्ताह के सभी देशों में ऐसी प्रक्रिया है, जो बराबर जारी रहती है। यह बात उन घटनाओं और आन्दोलनों के बारे में खामखोर सही है जिनको हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है। सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण समय गुजरने पर ही होता है। यह सवथा नियमित प्रक्रिया है और सावियत इतिहास-लेखन कोई अपवाद नहीं है।

निस्सन्देह एक समय ऐसा था, जब सोवियत इतिहासकार (उज्बेक और रूसी दोनों ही) रूस के साथ मध्य एशिया के विनयन के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील महत्व का कुछ कम करके आकते थे। यह कुछ हद तक अक्षुण्ण नाति के तुरत बाद के दौर का अनिवार्य नतीजा था, जब उस हर चीज की अवहेतना और निंदा की जाती थी, जिसका नातिपूर्व अतात से संवध था। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक सोवियत लेखकों ने जारशाही शासन के विरुद्ध औपनिवेशिक काल के सभी आन्दोलन का स्वाधीनता का नातिकारी जन-संघर्ष बना कर पेश किया। तीसरे और चौथे दशकों के कई सावियत लेखकों की वृत्तियाँ का हवाला दिया जा सकता है, जिनमें यह

\* “उज्बेकिस्तान के जनगण का इतिहास”, ताशकन्द, १९६७, पृष्ठ १, पृष्ठ ३६८।

दृष्टिकाय अपनाया है। यू० पयोदोरोव ने अपनी पुस्तक\* में श्रीपनिवेशिब काल के सभी आन्दोलनों को, उनका भी, जिनका नेतृत्व मुस्लिम धार्मिक गुरु कर रहे थे और जिनको कोई जन-समर्थन प्राप्त नहीं था, एक ही शीर्षक "राष्ट्रीय धार्मिक मुक्ति आन्दोलन" के अन्तर्गत जमा कर दिया है। उहान १८६८ के अन्दोजान विद्रोह को भी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन बताया है। ५० ग० गलुजो ने अपनी पुस्तक\*\* में ज़ारशाही शासन के प्रति हर विरोध का भाव बंद करके राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष माना है, जिसमें उन्होंने १८ शताब्दी के चौथे दशक में सुलतान बेनिस्सारी के विद्रोह, १८६८ में समरकन्द में विद्रोह, शहरिमन्ज बेंकशाही के विद्रोह, १८७५ और १८७६ काकान में विद्रोह, ताशकन्द में १८६२ में हैजा उपद्रव, १८६८ में मदाली रेशान के विद्रोह से लेकर १९१६ के विद्रोह तक को जोड़ लिया है।

यह दृष्टिकोण उस समय सोवियत इतिहास लेखन में आम था और इसका कोई संघर्ष कुछ उल्लेख लेखकों के "पूजोवादी राष्ट्रवादी भटकाव" से नहीं था, क्योंकि पयोदोरोव और गलुजो उल्लेख नहीं हैं। यह ऐसे दौर की पैदावार था, जब अतीत की संपूर्ण निंदा करने की प्रवृत्ति हावी थी। "उज़बेकिस्तान के जनगण का इतिहास" ने इस परम्परा का ऐसे दौर में जारी रखा, जहाँ सोवियत इतिहासकारों ने अतीत की घटनाओं के अधिन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की आशा की जाने लगी थी और इसी लिए "इज़बेस्निया" ने सही ही इसकी आलोचना की। यहाँ यह बता दिया जाये कि इस दृष्टिकोण की आलोचना उस प्रारम्भिक दौर में भी की जा रही थी, जब उसे अधिकृत दृष्टिकोण माना जाता था।\*\*\*

\* यू० पयोदोरोव, "मध्य एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का विवरण", ताशकन्द, १९२५, पृष्ठ १४-१८। (रूसी संस्करण)

\*\* ५० ग० गलुजो, "उज़बेकिस्तान-उपनिवेश", ताशकन्द, १९३५। (रूसी संस्करण)

\*\*\* दे० ५० अतोपाव, "मध्य एशिया के प्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास और पाठिकाय के बारे में क्या और किस तरह पढ़ना है", समरकन्द-ताशकन्द, १९२६, पृष्ठ ३०। (रूसी संस्करण), ग० तुकिनासकी द्वारा संपादित 'काम्मुनिस्तीचेस्काया भीस्न' में, १९२७ अंक ३, पृष्ठ १६०-२२२। (रूसी संस्करण)

जारशाही के विरुद्ध आंदोलन का वर्तमान सोवियत मूल्यांकन "महान रूसी गणराष्ट्रवादी भटकाव" का नतीजा नहीं है, जैसा कि रिवर पाप्स और सीटन वॉट्सन हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। पाइप्स ने मध्य एशिया पर रूसी कब्जे की प्रगतिशील भूमिका पर हाल में जोर देने का "सोवियत उपनिवेशवाद" विषयक गोपनीय मध्य एशियाई जातियों के "रूसीकरण" का "इतिहास लेखन सबसे पहला" घोषित किया है। सीटन वॉट्सन ने सोवियत इतिहासकारों के तर्कों के बारे में कहा है कि यह "गार आन्नी के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का नकली मार्क्सवादी रूप है, जिसे किपलिंग समझ लेता"।\* लेकिन इन दावा में रस्ती भर सच्चाई नहीं है। मध्य एशिया पर जारशाही के कब्जे के प्रगतिशील चरित्र के बारे में सोवियत इतिहासकारों का हाल का विचार अच्छी तरह सोचा-समझा हुआ विचार है, जो कुछ अतिशयास्तियों के बावजूद तथ्यों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित है।

वह दृष्टिकोण, जो जारशाही के विरुद्ध सभी आंदोलनों को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में मानता है, सही नहीं है, क्योंकि वह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि इन सभी आंदोलनों में से कुछ को छोड़कर, जैसे १८६२ में ताशकन्द में हैजा उपद्रव और १९१६ का विद्रोह, किसी में भी जनता ने भाग नहीं लिया। सुलतान केनिस्सारी के विद्रोह का कजाखों का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि शुरू में केनिस्सारी ने अनेक कजाख खानाबदोशों को इकट्ठा कर लिया था, परंतु उसका सामंती चरित्र समझ लेने के बाद वे उससे अलग हो गए और वह अंत में जार के रूसी सैनिकों से नहीं, बल्कि किगिजा से लड़ने हुए मारा गया। बुखारा की राजगद्दी के लिए शहरिमन्त के बेका के पड़ोसियों का तथा जारशाही शासन के विरुद्ध धार्मिक युद्ध के नारे व तटन लोगो का उभारने के लिए मुस्लिम मुत्ताघा और रईसा के नाकाम प्रयत्न को जसा कि उन्होंने १८७५ और १८७६ में कोकान में, १८८५

म फरगाना में और १८६८ में अदीजान में किया था, राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन कहना ऐतिहासिक तथ्यों को बिगुल ताड़-भराड़ कर पेश करना है।

मध्य एशिया में औपनिवेशिक बाल में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के जाने में कुछ सामान्य टिप्पणियों से शायद उस आन्दोलन को ज्यादा भ्रन्टी तह समझना आसान हो जायेगा। खान प्रशासन बाल में मध्य एशिया के लोग आपस के विनाशकारी युद्धों से ऊब गये थे। इसलिए प्रारम्भ में उन्होंने जारशाही द्वारा ऐसे शासन की स्थापना का स्वागत किया, जिनमें अदरुनी मुख्यवस्था और व्यक्ति की सुरक्षा कायम की। ताशकन्द पर, यह याद रहे, दो हजार रूसिया ने दखल किया था। लेकिन तुक्मान बवाता ने जारशाही बच्चे का घोर विरोध किया था।

मध्य एशिया पर जारशाही का अधिकार ब्रिटेन के साथ तीव्र प्रतिद्विधा के वातावरण में हुआ जिससे मजबूर होकर जारशाही को मध्य एशिया की जातियों के प्रति मावधानीपूर्ण नीति अपनानी पड़ी। यहाँ जारशाही ने इमलाम के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया। मध्य एशिया के मुसलमानों में काम करने में ईसाई मिशनरियाँ को रखा गया। परन्तु १९वीं सदी के अंत में जब आगल रुमी प्रतिद्विधा की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने लगी, तो परिस्थिति बदली और जारशाही की नीति का दमनकारी दौर शुरू हुआ। परन्तु सदी के अंत में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का उभार उठी हूँ तब मध्य एशिया में पूँजीवादी सबघाँ का उत्पत्ति के कारण हुआ जिससे अमजीवी जनगण की दरिद्रता बढ़ गई और उनकी राष्ट्रीय चेतना जग गयी। अब आधिक दृष्टि में तबाह दैक्कान और गरीब कारीगरों ने राजनीति में क्रियाकलाप के क्षेत्र में प्रवेश किया। ताशकन्द में हैजा उपद्रव और पूरे तुकिस्तान में १९१५ का विद्रोह इसी दौर से संबंध रखते हैं।

इन दोनों आंदोलनों को पूरा औचित्य के साथ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनगण का मुक्ति-संग्राम कहा जा सकता है। हाल की सभी भावियत ऐतिहासिक श्रुतियाँ में इन्हें इस रूप में स्वीकार किया गया है। इस मूल्यांकन में धर्म के प्रति विराध का कोई हाथ नहीं रहा है। सभी

सोवियत लेखकों ने ताश्कन्द में हैजा उपद्रवों को धार्मिक तत्वों के शरक होने के बावजूद जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है। मार्क्सवाद ने हमेशा यह स्वीकार किया है कि किसानों पर धार्मिक अत्याचार करने से धार्मिक नारों के तहत मुक्ति संघर्ष शरू हो जा सकता है। इस संबंध में यह याद रहे कि मार्क्स ने हुस्साइट युद्धों को “धार्मिक झंडे तले चेक किसानों का राष्ट्रीय युद्ध”<sup>\*</sup> कहा था। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया था, जारशाही ने तुकिस्तान में धार्मिक अत्याचार की नीति नहीं अपनाई थी। इसलिए मध्य एशिया की जातियों की राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम में धर्म ने कोई भूमिका अदा नहीं की।

१९वीं सदी के अंत में मध्य एशिया के किसानों ने जारशाही के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी राजनीतिक कारवाही शुरू की। उस क्षेत्र के ग्रामीण अर्थतंत्र में पूँजीवाद के प्रवेश के कारण देहकानों की स्थिति बिगड़ गयी थी। दरिद्र किसानों ने औपनिवेशिक शासन के तहत अपना दयनीय स्थिति के प्रतिरोध के रूप में धनी लोगों और औपनिवेशिक अधिकारियों पर छापा मारना शुरू किया। फरगाना, समरकन्द और सिर-दरिया के तीन ओग्लास्तो में, जहाँ औपनिवेशिक शोषण सबसे अधिक तीव्र था, कपास उत्पादक किसानों द्वारा ऐसे छापे की सच्चा प्रतिक्रिया बढ़ती गई। १८८७ और १८९८ के बीच ६६८ ऐसे छापे मारे गये। फरगाना में, जहाँ किसानों की आर्थिक तबाही की प्रक्रिया सबसे तेज़ थी, किसान छापे की सच्चा ४२९ थी। इस अवधि में समरकन्द में १८२ और सिर-दरिया क्षेत्र में ५७ छापे मारने की रिपोर्ट मिली।<sup>\*\*</sup>

किसान आंदोलन न पशासन के साथ मुठभेड़ का रूप भी लिया। १८८७ और १८९८ के बीच इस प्रकार की २५ मुठभेड़ों की सूचना मिली जिसमें ३४ अधिकारी उलझे हुए थे और इनके पन्ध्रस्वरूप २० हताहत हुए। सदी के अंत तक अधिराधिन देहकान और खानाबदोश राजान स्वधीनता तथा वग-संघर्ष में भाग लेने लगे। स्थानीय पशुपालक खानाबदोश

\* १० मार्स और फ्रे० एंगेल्स, पुगलेख-संग्रह १९३९ खण्ड ८ पृष्ठ ३-४। (रूसी संस्करण)

\* १० १० मसुजा “तुकिस्तान-उपनिवेश”, पृष्ठ ६०।

भी कुत्तों और कज्जाक बसनेवालों के विरुद्ध सघष के मैदान में उतर आये और उनके भवेशी पकड़ कर ले जाने लगे।

किसानों ने इस प्रकार का राष्ट्रीय सघष २० वीं सदी के प्रथम दशक में जारी रखा। किसानों के छापो को\* जिनकी संख्या १९०५ तक धीरे-धीरे ही बढ़ी थी, १९०५ की नातिकारी उथल-पुथल से प्रोत्साहन मिला। १९०५ से १९०८ तक उनकी संख्या में ८३ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९०५ की नाति इस दृष्टि से मोड़-पिंडु साबित हुई। उसने देहकानों के राजनातिक सघष को सक्रिय बना दिया, जो उसके बाद खुले आम जारशाही औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। परंतु उनके आंदोलन का स्वरूप असंगठित और स्वतः स्फूर्त रहा। १९०५-१९०७ की नाति में स्थानीय सबहारा ने भी, यद्यपि उसकी संख्या कम थी, बड़ी राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की। १९०६ में जब हड़ताली रूसी मजदूरों की जगह स्थानीय जातियों के मजदूर भरती किये जाने लगे, तो वे भी स्वतः स्फूर्त ढंग से हड़ताल में शामिल हो गये। स्थानीय मजदूरों ने भी रूसी मजदूरों के साथ सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया। मास्को के दिसम्बर विद्रोह के असफल होने पर पूरे तुकिस्तान में घेराव की स्थिति घोषित कर दी गई और इस घोर दमन के दौरान में सामाजिक जनवादी संगठनों का बंद कर दिया गया। जन नातिकारी आंदोलन की नई लहर, जो रूस में १९१२ में शुरू हुई, तुकिस्तान के सैनिकों और मजदूरों को प्रभावित किये बिना नहीं रह सका। जुलाई १९१२ में ताशकंद में सैनिकों का शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोह हुआ। परन्तु इसे भी औपनिवेशिक प्रशासन ने कड़ाई से कुचल दिया।

जारशाही के विरुद्ध मध्य एशिया की जातियों का एक जन राष्ट्रीय

\* पृ. १० गलुजो ने ३० जुलाई, १९२८ में 'प्रायदा वोस्ताका' के पृ. १७२ (१९६६) में प्रकाशित अपने लेख में तथा अपनी पुस्तक "तुकिस्तान-उपनिवेश" में घनी लोपा पर विमान छापो का उल्लेख किया था, मगर वह कभी भी 'रुमियो पर छापा' के बारे में बात नहीं करता था, जसा कि अपनी मर्जी पर २० वें दशक में किया था। ( R V dyanath The Formation of the Soviet Central Asian

मुक्ति विद्रोह १९१६ में हुआ। इसमें मध्य एशिया की सभी जातियां न भाग लीं। साम्राज्यवादी युद्ध के फलस्वरूप मध्य एशिया का औपनिवेशिक शोषण और लूट अधिक तेज हो गई थी। जारशाही प्रशासन न पक्ष जब्त करवाया और अतिरिक्त कर लगाये, जिसके कारण लोग की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। रूस से रोटी का आयात कम हो गया और इसलिए उसका दाम बढ़ गया। फसल नहीं होने से हालत और खराब हो गई और देश में अकाल फैल गया।

जारशाही के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन का अवसर २५ जन, १९१६ की आज़ाप्ति के जरिये मिल गया। यह आज़ाप्ति मोरचे के पीछे काम के लिए स्थानीय पुरुषों की लामबंदी के सबंध में थी। इससे जनगण में आन्दोलन फैल गया। इसका कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आज़ाप्ति पर अमल करने का ढग था। धनी बाई लोग और समाज के अग्र समूह तत्तन रिश्तत देकर या अपने बदले किसी को रखकर सेवा से बच जाते थे। आज़ाप्ति का बड़ा याव सारा का सारा गरीबों पर पड़ता था।

मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में बेहकानों और शहर के गरीबों का विद्रोह स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरू होन लगा। नृद्ध लोगों की भीड़ ने बोलोस्त प्रशासन कार्यालयों पर धावा बोल दिया और मोरचे के पीछे सेवा के लिए भरती किये जानेवाले की सूचिया फाड़कर फेंक दी, कई अधिकारियों की हत्या भी की। आंदोलन आम तौर पर असंगठित था और उसका कोई समान नियंत्रण या आदेश-केन्द्र नहीं था। अधिकांश जिला में यह आंदोलन मनमाने जारशाही प्रशासन, औपनिवेशिक अधिकारियों और साथ ही स्थानीय बाई लोग तथा मामती तत्वा के विरुद्ध था। बनी हद तक इसका राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष का प्रगतिशील स्वरूप था। परंतु कुछ जिला में सामन्ती और धार्मिक तत्व जमन और तुर्कों के एजेण्टों से मिलकर इसे रंग विरोधी रंग देने में सफल हुए। जिसके उयेन्द, तंजेन और गिउरगेन में आन्दोलन न यही रंग लिया।

१९१६ के विद्रोह का जारशाही न शस्त्र बल में बड़ी क्रूरता का माय युक्त लिया। विभिन्न साम्राज्यवादी के विरुद्ध दमन विशेष रूप से पड़ा था। उनमें से कई तीन लाख जेलीखुज से चीन भाग गया। उनकी

जमीनें जब्त कर ली गई और रुमी बसनेवाला को दे दी गई। १९१६ के विद्रोह ने अपनी असफलता के बावजूद औपनिवेशिक क्षेत्र की जातियां के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन से सामतवाद विरोधी आन्दोलन में परिवर्तित हो गया। लामबंदी के विरुद्ध स्वतः स्फूर्त प्रदर्शनों से शुरू होकर उसने सशस्त्र संघर्ष का रूप धारण कर लिया। उसका उद्देश्य रूस से अलग होना नहीं था, बल्कि केवल राष्ट्रीय औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त करना था। आन्दोलन की शक्ति और उमकी व्यापकता मध्य एशिया में आतंककारी परिस्थिति की परिपक्वता साबित कर रही थी। भरती हुए मजदूर और बेहकान, जिन्होंने रूस में रहकर काम किया, इसी बोतशेविका के प्रभाव से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गये और तुकिस्तान में वापस आकर फरवरी और अक्टूबर आति के बीच के दौर में स्थानीय जनता के हिराबल दमने बन गये। उन्होंने मेहनतकश मुसलमानों की सोवियत संगठित करने में अग्रिम भूमिका अदा की।

१९१६ का विद्रोह विफल हुआ, मगर उसने मध्य एशिया के जनगण का आतंककारी संघर्ष का बड़ा सबक दिया। इसने उन्हें विश्वास दिला दिया कि केवल रूसी सवहारा की सहायता से और केवल समाजवादी आति के जरिये वे राष्ट्रीय और औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पूजीपति बग और पूजीवादी बुद्धिजीवियों के विश्वासघात ने, जो उस समय जारशाही साम्राज्यवाद की चाटुकारी कर रहे थे, जनता की आखें खोल दी।

समाजवादी आति के लिए सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक पूर्वस्थितियों का परिपक्व होना

मध्य एशिया में समाजवादी आति सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक पूर्वस्थितियों की उपस्थिति के कारण फट पड़ी। कुछ लेखकों का कहना है कि मध्य एशिया में उत्पादक शक्तियां के अविक्सित होने तथा वहां की जातियों के निम्न सांस्कृतिक स्तर के कारण ऐसी पूर्वस्थितियां नहीं थी।



वे यह रट लगाये जाते हैं कि स्थानीय लोगों में औद्योगिक सहकारिता का कोई बड़ी मध्या नहीं थी, जिसके बिना समाजवादी नीति की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सभी तर्कों का सार उनका यह दावा है कि मध्य एशिया में समाजवादी नीति की अपनी जड़ें नहीं थी और उसे रूसी बोलशेविक रूस से लेकर आये।\* रूस से समाजवादी नीति के "प्रसार" के अवधि में अपने ऐतिहासिक रूप से भ्रामक नतीजे पर पहुँचने में पश्चिमी लेखकों का सफ़ारोव जैसे विगत सोवियत लेखकों से बहुत समय मिला, जिन्हें एक समय पार्टी और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था।"

परन्तु यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक वास्तविकता के विपरीत है। साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी नीति के लिए आवश्यक शर्तों का मौजदगी के सवाल पर विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के सदन में ही विचार किया जा सकता है, और सामंतविरोधी तथा राष्ट्रीय मुक्ति नीतियों का समाजवादी नीतियों में विकास की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

तुर्किस्तान के अवधि में सही दृष्टिकोण केवल इस विलगित दूरदर्शी

---

\* A G Park *Bolshevism in Turkestan* New York 1957  
R Pipes *The Formation of the Soviet Union*, Cambridge Mass 1954  
W Kolarz *Communism and Colonialism*, London New York, 1964  
H Seton Watson *The New Imperialism* London, 1964, Brian Kroeber *Neo Colonialism* London 1964

\*\*सफ़ारोव के अभिनत तथा अवस्तुनिष्ठ विचारों के लिए देखिये उनकी पुस्तक "औपनिवेशिक नीति-तुर्किस्तान का अनुभव", मास्को-लेनिनग्राद १९२१ (रूसी संस्करण)। इस लेखक की राय में फरवरी नीति से पहले तुर्किस्तान में 'तनिक' की फ़र्क़ हुआ नीतिवादी आंदोलन" नहीं था (पृष्ठ ५३)। उनकी राय में फरवरी नीति 'तार के जरिये' तुर्किस्तान पहुँची (पृष्ठ २४)। उनका दावा था कि तुर्किस्तान में रूसी मजदूरों में 'नीतिवादी विचारधारा' कोई नीतिवादी परम्परा नहीं थी" और कि उनमें और स्थानीय लोगों में कोई समान नहीं था। उनका कहना था कि तुर्किस्तान में सभी रूसी मजदूरों और वहाँ राजकारण के अधिपति का 'युग औपनिवेशिक रूप' था (पृष्ठ ७१) पश्चिमी दशा में सफ़ारोव का हवाला यापन तौर पर दिया जाना है।

सत्र म समाजवादी नाति की आवश्यक शर्तों के विश्लेषण तक ही सीमित रहा रह सकता, बल्कि उसे पूरे देश के सदम में देखना होगा। जारशाही उपनिवेशवाद व विद्रुध मध्य एशियाई जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति सघष को ध्यान म रखना होगा, जो हर साल रूस में मजदूरों के नातिकारी आंदोलन व प्रत्यक्ष अनुपात म और मुख्यत उसके प्रभाव के तहत तीव्र और व्यापक हा रहा था। फिर, वस्तुनिष्ठ सामाजिक आर्थिक तत्वा के अलावा आत्मनिष्ठ तत्व की भूमिका का भी ध्यान रखना होगा।

रूस व साथ मध्य एशिया के विलयन की बदौलत यह सम्भव हुआ कि समाजवादा नाति की सामाजिक आर्थिक पूर्वस्थितियों का विकास तेजी में हो। औपनिवेशिक काल म पूजीवादी सबधों की उत्पत्ति से बग विरोध और तीव्र हुए। इसके फलस्वरूप मध्य एशिया म अत में समाजवादी नाति की विजय हुई। तुकिस्तान म नाति से पहले की स्थिति का मूल्यांकन करने व लिए उत्पादक शक्तियों के विकास को ही नहीं बल्कि बग-सघष की परिस्थितियों को राष्ट्रीय उत्पीड़न की तीव्रता आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। समाजवादी नाति के लिए यह कोई जरूरी नहीं कि किसी देश की आर्थिक और राजनीतिक परिपक्वता में प्रत्यक्ष सानुपातिक सबध हो। जसा कि लेनिन ने कहा है यह कहना कठिन है कि "इसकी शुरुआत कौन करेगा और अत कौन"।\* समाजवादी नाति के दृष्टिकोण से तुकिस्तान के अपरिपक्व होने की सारी दलीलों का मतलब है रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील परिणामों और उस विनयन के फलस्वरूप हुए राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन से इनकार करना। रूस म मिल जान के कारण तुकिस्तान म आर्थिक विषमता बढ गई। उत्पादन-साधनों के प्रति विभिन्न वर्गों के सबध बदल गये और वृष्टि तथा उद्योग म वर्गीय विभेदीकरण की प्रक्रिया और गहरी हो गई। यह मानना, जैसा कि हयात और मुस्तफा चाबायेव कहते हैं, कि मध्य एशिया के मुसलमानों म बग भेद नहीं था और कि उन्होंने एक मनुन मुस्लिम राष्ट्र बनाय के जा बग-सघष की धारणा से भी अपरिचित

ये वस्तुस्थिति के विपरीत है। यह सही है कि तुर्किस्तान में औद्योगिक  
सवहारा की सख्या बहुत कम थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि रमका  
आवादी में सवहारा तत्वा का अधिकत्व नहीं था। कृषिक सवहारा और  
अद्ध सवहारा मिलकर आवादी का खासा बहुमत बन गये थे। यहाँ यह उल्लेख  
कर दिया जाये कि लेनिन ने “शहरी सवहारा” और “ग्रामीण सवहारा”  
की बात कही है और कुलको तथा किमान पूजीपतियों के विरुद्ध उनका  
एक हाने की चर्चा की है।\* उन्होंने “गरीब किसानों” का अद्ध-सवहारा  
कहा है।\*\* अपनी “सोवियत सत्ता के सबंध में दस प्रस्थापनाएँ” नामक  
कृति में लेनिन ने बताया कि सवहारा तथा गरीब किसानों (अद्ध सवहारा)  
का अधिनायकत्व कायम करना सोवियत सत्ता के उद्देश्य में से एक है।\*\*\*

मध्य एशिया के इतिहास का कोई गम्भीर अध्ययनकर्ता इस बात से  
इनकार नहीं कर सकता कि तुर्किस्तानी गावों की आवादी का अधिकांश  
भाग सवहारा और अद्ध-सवहारा था। १९१७ की अप्रिल वृत्ती कृषि  
जनगणना के अनुसार कृषि में काम करनेवाले उजरती मजदूरों की सख्या  
फरगाना ओब्लास्त के बस हुए हिस्सों में २२,२१७, समरकन्द ओब्लास्त  
में २३,०२७ और सिरदरिया ओब्लास्त में (आमू दरिया विभाग को  
छोड़ कर) १५,०६७ थी।\*\*\*\* दूसरे प्रदेशों के सबंध में बाई आकड़े हासिल  
नहीं किये जा सके। इन सब उपलब्ध आकड़ों से भी पता चलता है कि  
ग्रामीण समाज में वर्गीय विभेदीकरण कितना बढ़ गया था। भूमिहीन किसानों  
की यह विशाल सेना ही कृषिक सवहारा का आधार बन गयी। फिर गरीब  
किसानों—चारिकेरो और भरदिबेरो की बड़ी सख्या थी। इनका बाड़ा  
जमीन पर स्वामित्व था। वे बाई लोगों की जमीन पर बटाईदारी का  
आधार और ऐसी शर्तों पर रेंती करते थे, जो उनके लिए प्रतिकूल और  
घटित थी। तुर्किस्तान की दस्तकारी में १,०८,३२४ आदमी काम करने

\* वही, पृष्ठ २८ पृष्ठ ३६२ और खण्ड ३३, पृष्ठ ४६५।

\* वही, पृष्ठ ३१, पृष्ठ ३८५ और खण्ड २८, पृष्ठ ४६।

\* वही, पृष्ठ २७, पृष्ठ १५३-१५४।

\*\* \*ग० त० सुमनोब, “मध्य एशिया और कजाखस्तान में १९१६ का  
विद्रोह”, ताशकन्द, १९६२ पृष्ठ १००। (रमा संस्करण)

ये।\* आवादी के इस क्षेत्र की सामाजिक वनावट १६०८-१६०९ में यह थी कि उसमें ४० प्रतिशत गरीब दस्तकार, २५ प्रतिशत माध्यमिक दस्तकार और २४ प्रतिशत उजरत पर काम करनेवाले मजदूर और धावी समूह दस्तकार थे।\*\* यही जनता समाजवादी क्रांति और नये जीवन का स्रष्टा थी।

रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के पहले दिनांक ही श्रमजीवी जनता का सम्पर्क "दो रूसों" से हुआ—एक उत्पीड़ित और शोषित, रोमानोव और स्तोलीपिन का रूस, जो एशिया की जातियाँ और रूसी लोग दोनों का शोषण और उत्पीड़न करता था और दूसरा क्रांतिकारियों का रूस जो सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ता था। मध्य एशिया के लोग का जारशाही उपनिवेशवादियों, रूसी कुलकों और व्यापारियों से ही नहीं, बल्कि रूसी किसानों और औद्योगिक मजदूरों, वनानिका, शिल्पियों, लघुकारों और क्रांतिकारियों से भी सम्पर्क होता था।

महान रूसी जनगण के साथ मध्य एशिया के श्रमजीवियों के इस लड़ने का प्रगतिशील चरित्र और अधिक स्पष्ट तब हुआ, जब रूस विश्व क्रांतिकारी आन्दोलन का केन्द्र बन गया और रूसी मजदूर वर्ग अपनी जमीन क्रांतिकारी पार्टियों का निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आन्दोलन का हिस्सा बन गया। रूस में क्रांति की उभरती लहर ने भी मध्य एशिया का प्रभावित किया। मध्य एशिया की प्रगतिशील शक्तियों ने रूसी सवहारा के साथ मिलकर सामंती और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया। यह समझकर कि रूस के श्रमजीवी जनगण उन्हें पूँजीपतियों और जमींदारों के उत्पीड़न का शिकार थे, मध्य एशिया की जनता ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि उनकी समान नियति रूसी सवहारा के साथ सम्बद्ध है।

मध्य एशिया की समाजवादी क्रांति में रूसी सवहारा ने निस्सन्देह अग्रिम भूमिका अदा की। उसने स्थानीय मजदूरों की वर्ग चेतना को जागृत

\* वहाँ, पृष्ठ ७२।

\*\* म० वहाँवाले "उत्प्रेक्ष्य समाजवादी क्रांति का निर्माण", पृष्ठ १७३।

करने तथा देहकानो स एकता कायम करने मे एक यत्न का काम किया। ये देहकान धीरे धीरे सामतवादियो और धामिक नेताओ के प्रभाव से अपन आपका उबारने का प्रयास कर रहे थे, और १९वीं सदी के अंत स व राजनीतिक सघष के क्षेत्र मे प्रवेश करने लगे थे, यद्यपि स्वत स्भूत और असंगठित ढंग से।

मध्य एशिया पर रूसी औपनिवेशिक कब्जे मे एक नया तत्व मौजू था, जो नय यूरोपीय शक्तिया के औपनिवेशिक कब्जा मे नही था। वह था रूसी साम्राज्य की औपनिवेशिक प्रजा और साधारण रूसी जनगण मे प्रत्यक्ष सम्पक। रूस के उपनिवेश क्षेत्रीय दष्टि से इससे मिले हुए थे और रूसी उनमे आकर बसते थे।

यह चीज रूसी उपनिवेशा मे समाजवादी ऋति के लिए आवश्यक पूर्वस्थितियो के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी आर ब्रिटिश सवहारा अनेक कारणा से, जिनमे उपनिवेशा से भौगोलिक दूरी भी एक थी, उपनिवेशा मे समाजवादी ऋति के मामले मे पहलकदमी नही कर सका। ब्रिटिश सवहारा उपनिवेशो (जैसे भारत) मे वही प्रगतिशील भूमिका नही अदा कर सका क्योंकि वह बडी हद तक धर्मिक रईसशाही के प्रभाव मे था। याद रहे कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने अनेक मौना पर भारत के लिए स्वायत्त शासन का विरोध किया था। परन्तु अगर ब्रिटिश मजदूर वग धर्मिक रईसशाही के प्रभाव मे नही होता, तब भी भौगोलिक दूरी ऐसी चीज थी जा बाधा बनी रहता। भारत मे शायद ही कोई ब्रिटिश मजदूर रहा हा, जबकि हजारो रूसी मजदूर मध्य एशिया की रेलवे तथा अन्य औद्योगिक उद्यमा मे काम करने थे। ब्रिटिश पूजी न अवश्य ही भारत के कच्चे सामान के साधना का अधिक पर्याप्त शापण करने के लिए भारत मे रेलवे का निमाण किया। इन निर्माण प्रायोजनाओ मे एक भी ब्रिटिश मजदूर न काम नही किया। रूसी मजदूरो के धलावा मध्य एशिया मे खासी बडी सख्या मे रूसी विमान भी आकर बस गये थे। इन मे से बहुतरे कुलरु नही थे और इनका और देहकानों का सम्मान हित था।

कुछ लेखका न यह निधान का प्रयाग किया है कि मध्य एशिया मे

एक रूसी बसनेवाला तथा देशी जागण के हिता में स्यायी विरोध था, जिससे दोना में महामोग की सम्भावना नहीं थी। सफ़ारोव का कहना कि तुकिस्तान में एक तिहाई से आधे तक रूसी भाषावादी "मुफतपार" थी, कस्तुरियन की घोर विकृति है।\* वह इस "मुफतपार" वग में बिना किसी भदभाव के सभी रूसी शहरी वासिन्दा को शामिल करते हैं। अगर हम जनगण सहमत हों, तो सभी रूसी साहित्यकार और वक्ताओं जिन में १०० प्रसवात्स्वी, १०० १०० सम्मोनोंय तिमनशान्स्की आदि उपनिवेशवादी हों जाने हैं, और सभी मजदूर अधिकांश प्राप्त श्रमिक रईसगाही के सदस्य।

तुकिस्तान की कुल रूसी भाषावादी ५४०,६७४ थी।\*\* इसमें से १,८५,३०३ शहरों में रहते थे और ३,३०,४६९ गांवों में, १६६४८ शहरी वस्तिमा में और ८,२५८ रेलवे स्टेशन के निवट स्टेशनों में रहते थे। रूसी नगरनिवासियों में कोई २६,००० औद्योगिक मजदूर थे, जिनमें २०,००० रेलवे मजदूर थे।\*\*\* मजदूरों जैसे मजदूरों के सम्बन्धों से पता चलता है कि रूसी रेलवे मजदूरों को कोई विशेष सुविधाएँ नहीं प्राप्त थीं। उन्हें वही कानून मिलता था, जो उनके जैसे मजदूरों को रूस में मिलता था। निपुण रूसी मजदूरों और अनिपुण स्थानीय मजदूरों के वतन में फर्क से यह नतीजा निष्पन्न कि मध्य एशिया में सुविधाप्राप्त रूसी श्रमिक रईसगाही थी, श्रमिक रईसगाही की धारणा के बारे में अज्ञानता प्रकट करना है। अगर मध्य एशिया के रूसी मजदूर श्रमिक रईसगाही से सवध रखते थे, तो उनमें असंतोष किस कारण था जिससे बड़ी-बड़ी हड़तालें और प्रदर्शन होते थे? मालिक दश के पूँजीपति वग के औपनिवेशिक अतिरिक्त मुनाफे द्वारा खरीदी हुई श्रमिक रईसगाही औपनिवेशिक शोषण का एक

\* ग. सफ़ारोव, "औपनिवेशिक शासन—तुकिस्तान का अनुभव", पृष्ठ ५२।

\*\* 'सांख्यिकीय वापिकी, १९१७-१९२४', ताशकन्द, १९२४, खण्ड १, भाग ३, पृष्ठ ४२-४४। (रूसी संस्करण)

\*\*\* "उन्केकिस्तान के मजदूर वग का इतिहास", खण्ड १, पृष्ठ ३१-३२।

लचीला यत्न होता। भारत की रेलवे में काम करनेवाले अंग्रेजा की हठताल और प्रदर्शन कभी सुनने में नहीं आये।

यह कहना भी सही नहीं है कि गावों में बस हुए सभी रूसी कुलक थे। जेतीसुव रूसी प्रवासी बस्तिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहां क आबडा से पता चलता है कि रूसी प्रवासियों में भी वर्गीय विभेदाकरण की प्रक्रिया जारी थी। जेतीसुव की पुरानी रूसी बस्तियों में ११,६५६ परिवार थे जिनकी आबादी ७८,५६१ थी। इनमें १०,५३१ रूसी परिवार थे जिनमें ७२,११७ व्यक्ति थे और १,४२८ गैर रूसी परिवार जिनमें ६,४७४ व्यक्ति थे। ३,३२२ (१६.५ प्रतिशत) परिवार भूमिहीन थे (जिनमें २,२०४ यानी कोई ७० प्रतिशत रूसी थे और १,११८, यानी ३० प्रतिशत गैर रूसी)। भूमिहीन परिवार और ५ देसियातीन की छोटी भूमिदारी के परिवार ओब्लास्त के कुल परिवारों का ५० प्रतिशत थे। ६८ प्रतिशत परिवार कृषि के अलावा अनुपूरक काम करते थे, २,६६० व्यक्ति खेतिहर मजदूर थे ३७७ उद्योगों में काम करते थे और २०८२ कारीगर और दस्तकार थे।\* सिरदरिया ओब्लास्त के विमकद उमेख में बसे हुए रूसी किसानों में कोई ३५ प्रतिशत परिवार खेतिहर मजदूर थे और ३४ प्रतिशत औद्योगिक मजदूर थे।\*\* ट्रांसकास्पियन ओब्लास्त के प्रशासक न रूसी प्रवासियों की भौतिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था कि यह 'मध्यम स्तर के लोगों से घराब' है।\*\*\* बरतोन्द का कहना है कि रूसी किसानों की बड़ी सख्या भी जो बरजाका से लगान पर जमीन लती थी, सरकार के विरोध के बावजूद चली आयी थी।\*\*\*\*

भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। १९३१ की जनगणना के अनुसार देश में ६०,६०८ यूरोपीय पुरुष थे जिनमें ५६,६६२ सना और पुलिस में काम करते थे, ३,६७२ सरकारी प्रशासन में ३,५०७ व्यापार में, ६७५८ परिवहन में, ४,०८० उद्योग में, १,४३४ खनन में, ३,०६६ पशुपालन

\* प० त० तुमोव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १३०-१३१।

\*\* वही पृष्ठ १३२।

\* वही।

\* \* \* य० बरतोन्द, रचनाएं पृष्ठ २, भाग १ पृष्ठ ३२२।

और कृषि में और ८,०१२ बौद्धिक पेशों तथा करता में\* यद्यपि जनगणना की तालिकाओं में वही स्पष्ट नहीं कहा गया है, यह सभी जानते हैं कि उद्योग धनन और परिवहन में काम करनेवाले यूरोपीय अधिगतर उच्च प्रशासनिक पदों पर काम करते थे और जहाँ तब पशुपालन और कृषि का सबध है वे फार्मों और बगानों के मालिक थे। अतः साधारण मजदूर बहुत कम थे। इसी प्रकार भारत में ८३१३ यूरोपीय स्त्रियाँ में, ५,०८६ बौद्धिक पेशों और कला में काम करती थी।

मध्य एशिया में नाति कहा की व्याप्त पूजीवाद पूर्व सबधा की अनुठी परिस्थिति में समाजवादी नाति थी। वह महान अक्तूबर समाजवादी नाति का एक अभिन्न अंग थी, उन घटनाओं का सिलसिला और विकास जो पेन्नाफ्राद और मास्को में अक्तूबर १९१७ में शुरू हुई थी। इस के केन्द्र में अक्तूबर नाति की विजय और हमी सबहारा द्वारा दी गई सहायता ने मध्य एशिया में नाति की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नाति का नतत्व निश्चित ही हमी सबहारा के हाथों में था, जिसे तुकिस्तान की व्यापक जनता का पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त था।

मध्य एशिया में नाति समाजवादी हम की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मध्य एशिया पर नाति हमी मजदूरों के ऊपर से लादी थी। मध्य एशिया के महनतवशा ने नाति का अभिनन्दन किया मानो यह उनका अपना मामला हो और इसका लाने और इसकी रक्षा करने में सक्रिय भाग लिया।

इतिहास हम सिद्धांता है कि किसी नाति की जड़ अगर व्यापक जनता में गहरी नहीं हो और उस ऊपर दस्ती ऊपर से लादा जाय तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। ऐसी नाति अगर इतिहास की आकस्मिक चोट के रूप में जीत भी जाये तो वह अदरुनी और बाहरी अनेक शक्तिशाली शक्तियों का सफल मुकाबला नहीं कर सकती थी। मध्य एशिया के लोगों ने स्वयं नाति का रास्ता चुना इस पूरा किया और इसकी उपलब्धियों की रक्षा की।

\* J H Hutton *Census of India*, vol I pt II 1931, pp 420-421



२० वीं शती के प्रारम्भ से रूसी सवहारा और देशी मजदूरों और देहकानों की तेजी से विकसित होती हुई एकता के विरुद्ध जारशाही और देशी बाई लोग और मुल्लाओं में एकता स्थापित होने लगी। राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग से स्थायी जनता के बिलगाव की प्रक्रिया, जो १९०५-१९०७ के दौर में ही शुरू हो गई थी, १९१६ के विद्रोह के समय पूरा हो चुकी थी। मध्य एशिया का राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग रूसी साम्राज्यवादी पूजीपति वर्ग की सेवा कर रहा था। उसने जनता के हितों का विश्वासघात किया। फरवरी क्रांति की विजय ने औपनिवेशिक तुर्किस्तान में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये। तुर्किस्तान के श्रमजीवी जनगण को तब तक यह विश्वास हो चुका था कि वे रूसी सवहारा की सहायता से ही राष्ट्रीय और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने राजनीतिक कायकलाप संगठित करना शुरू किया। फरवरी क्रांति के बाद उनके अनेक वर्गीय संगठन कायम हुए—स्थानीय श्रमजीवी जनगण की सोवियतें, समितियाँ और यूनियनें। मई १९१७ के अंत और जून के प्रारम्भ में स्थानीय मेहनतकशों की सावित बनने लगी। सामाजिक रूप में भी रूसी मजदूर वर्ग ने बड़ी सहायता की। देशी मजदूरों ने मोरचे के पीछे सेवा-न्दाय से घर वापसी पर इन संगठनों के निर्माण में अग्रिम भाग लिया। मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतों ने शुरू ही से देशी शोषकों के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष किया। शापक तत्त्वा ने भी अपने आपको “शूरा ए इस्लामिया” और “उलमा” जस संगठना में संगठित किया। यह सही है कि शुरू में देशी जनता ने अपने सांस्कृतिक पिछड़ेपन और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण इन प्रतिश्रियावादी संगठनों में कुछ विश्वास प्रकट किया। परन्तु वर्ग विरोध तीव्र होत गये और इसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता या इन प्रतिश्रियावादी संगठनों में जो भी विश्वास था वह जाना रहा। मजदूर क्रांति के समय वर्गीय शक्तियों के विभेदोत्तरण की प्रक्रिया पूरा हो चुकी थी। क्रांतिकारी परिस्थिति पूरी तरह विकसित और सन्नत पूरा तरह परिपक्व हो चुका था। इन सब का अनिवार्य परिणाम यह था कि मध्य एशिया में समाजवादी क्रांति शुरू हो गई।

## साम्राज्यवाद या भारत की सुरक्षा?

भारत और मध्य एशिया के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कई सदी पुराना है। मध्य एशिया के ही इलाके से यात्री और व्यापारी चीन से भारत और भारत से चीन आते और जाते थे। इसी तरह पश्चिम और पूव के व्यापार का रास्ता भी यहीं से होकर जाता था। समुद्री रास्तों की खोज से पहले यह क्षेत्र सम्यता और व्यापार का महत्वपूर्ण चतुष्पथ था। स्ट्राबोन ने आक्सस नदी, कास्पियन सागर, ट्रांसकानेशिया और इसके आगे पश्चिम में काले सागर तट से भारतीय सामान के जाने की चर्चा की है। आधुनिक सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के इलाके तथा चीन के सिक्कांग क्षेत्र में जो पुरातन स्मारक मिले हैं, उनसे भी दोना जातियों के घनिष्ठ संबंधों का पता चलता है।

य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मध्य युग में बन रहे। ख्वारज़्मी विद्वान अबू रैहान अल बेरूनी तथा अब्दुरज्जाक समरकंदी की दास्ताना यात्राएँ इन सम्पर्कों के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय हैं। बाबर द्वारा स्थापित राजवंश के तीन सौ वर्षों के शासन काल में दोना जातियों का यह संबंध और विकसित हुआ।

१९वीं सदी में उत्तराद्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत का महत्व काफी बढ़ गया था। भारत अपने विशाल क्षेत्र, अत्यधिक भौतिक

साधनो और आवादी सहित पूरे एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता की "चौकी और बुज" बन गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने और अधिक उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए अट्टे के रूप में भारत को इस्तेमाल किया। वे सूडान, मिस्र, अवीसीनिया, अफगानिस्तान, बर्मा और चीन में आक्रामक युद्ध भारतीय सैनिकों का प्रयोग करके लड़ और इन युद्धों का खर्च भारत के सर मठा। लंदन में इंडिया आफिस, चान में तथा लाल सागर की अर्थ बंदरगाहों में औपनिवेशिक सस्यानों, चान में कौनसलखाना और फारस में दूतावास का खर्च भारत के लोगों को देना पड़ता था।

ब्रिटिश लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास के आधुनिक युग के मित्या प्रदर्शन के सबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित होकर भारतीय विद्वानों को इस युग की पुनर्जागरण उससे अधिक आलोचनात्मक ढंग से करनी चाहिए जितनी अक्सर की जाती है। नेहरू ने लिखा है

"भारत के इतिहास और खासकर जिसे ब्रिटिश युग कहते हैं, उनके ब्रिटिश विवरण को बहुत बुरा माना जाता है सच्चाई अक्सर सबत गहरे कूप की तरह में छिपी होती है, और झूठ नग्न और निलज्ज सर्वोपरि होता है।"\*

ब्रिटेन की साम्राज्यवादी कारवाइया भारत के पड़ोसी देशों सिंधिया अफगानिस्तान, ऊपरी बर्मा और तिब्बत तक फैली हुई थी। ब्रिटेन की औद्योगिक पैदावार के लिए मछी और बच्चे सामानों के स्रोत के रूप में इन देशों का महत्व नगण्य था। परन्तु विश्व के अंतिम विभाजन के साम्राज्यवादी सपने के युग में सामरिक दृष्टि से उनका महत्व बढ़ गया, क्योंकि वे चीन और मध्य एशिया के द्वार पर स्थित थे।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की वैदेशिक नीति हमेशा आक्रामक रही। उसकी मुनिसादी दिशा सबसे प्रथम ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से निर्धारित होती थी। १९वां शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का केन्द्र बिंदु "पूर्वी प्रश्न" यानी पननशील तुर्की साम्राज्य की

विरासत सभालने के सपप म निहित था। निक्ट और मध्य पूव मे हस मुख्य शत्रु था। इसी तय्य स ब्रिटिश विस्तार वा विवास भारत की सीमा पर, पासकर उत्तर और पश्चिमोत्तर दिशाआ म काशगर, अफगानिस्तान और तुवमानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रा म निर्धारित होता था। ब्रिटिश उपनिवेशवादी इन क्षेत्रा को मध्य एशिया म हन के विरुद्ध सपप वा भड्डा मानते थे।

ब्रिटेन की सीमा-नीति की आक्रामकता म भारत के अन्दर की स्थिति म उतार-चढ़ाव के अनुसार हेरफेर होता रहता था। सीमा-नीति के सबध म दो दष्टिकाण उत्पन्न हुए। भारत की सीमाआ पर "अग्रिम नीति" का पक्ष जो प्रतिरक्षा-व्यवस्था म उत्तर-पश्चिमी सीमाआ की दुयलता की रट लगाया करता था भारत क प्रतिरक्षा प्रबध को उसकी प्राकृतिक सीमाओं के बाहर सबल बनाने वा आवाहन करता था। इस नीति क समर्थका वा कहना था कि मध्य एशिया पर रुस का कब्जा ब्रिटिश भारत क लिए बड़ा खतरा है। दूसरा पक्ष इस खतरे से इनकार करता था और "बंद सीमा-नीति" का समर्थन करता, और भारत की सीमाआ के बाहर सक्रिय रूप म आगे बढ़ने वा विरोधी था। इसका उद्देश्य उपनिवेश की भीतरी स्थिति को सुदृढ बनाना था। उस जमाने की ऐतिहासिक परिस्थितिया के कारण "बंद सीमा-नीति" १८५७ से १८७५ तक हावी रही। १८५७ के जन विद्रोह के बाद अदरुनी पेचीदगिया के कारण सक्रिय रूप म आगे बढ़ना फठिन हो गया था। परन्तु अस्थायी रूप म "अग्रिम नीति" को त्यागने वा मतलब यह नहीं था कि पड़ोसी इलाकों म घुसपैठ की नीति को वित्कुल छोड दिया गया। कूटनीति का चतुराई से प्रयोग करके अग्रज अपने प्रभाव-क्षेत्र को बराबर बढ़ाते रहे व ऐसी परिस्थितिया तैयार करने मे सलग्न रहे, जो सक्रिय आक्रमण के अनुकूल हो सके। काशगर और अफगानिस्तान म ब्रिटिश नीति इसका स्पष्ट प्रमाण है। लारेस ने अफगानिस्तान के प्रति "निष्पक्षता" और 'हस्तक्षेप नहीं करने' की जो नीति घोषित की थी, उसका कारण भी अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय अखंडता वा सच्चा सम्मान नहीं था। कजर्वेटिव पार्टी के कत्ती जनवान ने लारेस को लिखा "विरोधी पक्षो ने -

सतवक्तापूर्ण रखैया ही एकमात्र ब्रिटिश हितों के अनुकूल है। भारतीय साधना की आवश्यकता इस समय के विस्तार के अलावा और काम के लिए है" (जोर-दे० वी० का)।\* वास्तव में त्रैनबोन को अफगानिस्तान से अधिक दिलचस्पी ऊपरी बर्मा में थी। लारेस को उस समय तक अफगान शासकों से घनिष्ठ संबंध बनाने की कोई आवश्यकता या उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया था। वाइसरॉय ने लिखा कि "ऐसा निश्चित हो सकता है, जब ऐसा करना बुद्धिमानी होगी (जैसा बाद में लिटन ने किया), परन्तु वह दिन अभी नहीं आया है"।\*\*

उस जमाने में काशगर में ब्रिटिश अपनी विस्तारवादी कारवाइयों पर परदा डालने के लिए व्यापार की आड़ ले रहे थे। ग० ज० ऐलंडर ने स्पष्ट स्वीकार किया

"पूर्वी तुर्किस्तान में ब्रिटिश नीति में उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक के बाद हमेशा ही व्यापारिक साधनों और राजनीतिक उद्देश्यों की मिलावट रही है। व्यापार एक यंत्र मात्र था। उस युग के सभी वाइसरॉय इस बात से भली भाँति अवगत थे कि व्यापार 'राजनीतिक प्रभाव का एक बड़ा यंत्र' है। लारेस और रिपन भारत की राजनीतिक जिम्मेदारियाँ का भारतीय सीमा के अंदर सीमित रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काशगर से व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं किया। और सवा न इसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे ब्रिटिश प्रभाव को फलाना चाहते थे।"\*\*\*

ब्रिटिश लेखकों की यह राय सही है। परन्तु उसकी यह सफाई कि अंग्रेज काशगर में अपना प्रभाव "भारतीय सुरक्षा के लिए उमने विशेष महत्व" के कारण फैलाना चाहते थे, सत्य से बहुत दूर है। भारत को

\* द० S Gopal *British Policies in India* Cambridge, 1965 p 43 अंग्रेजों के लिए "घनिष्ठ संबंध" का एक ही मतलब था अफगानिस्तान का अधीन राष्ट्र में बदलना।

\* वही, पृष्ठ ४१।

\*\*\* G J Alder *British India's Northern Frontier 1865* 95 London 1963 p 98

रूसी खतरे का हौआ अंग्रेजों ने भारत की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के परे अपने सम्भावनी आक्रमण पर परदा डालने के लिए खड़ा किया था। ऐलंडर स्वयं अपना खटन करता है, जब वह उसी पुस्तक में एक और स्थान पर कहता है

“रूस द्वारा सिक्किम पर कब्जा करने की काउफमन की योजना १८८० में इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि उससे उसमें लगनेवाले समय और खर्च के मुकाबले में नगण्य लाभ होगा। इस बात के ठोस राजनीतिक तथा सैनिक कारण थे कि रूस बहुत अच्छी प्राकृतिक सीमा को छोड़ना नहीं चाहेगा और कहीं ज्यादा कष्ट देनेवाली एशियाई मुस्लिम प्रजा की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेगा। एक ब्रिटिश सैनिक रिपोर्ट ने काशगर पर रूसी हमले की सम्भावना को प्रमाणित रूप में अस्वीकार किया।”\*

इससे स्पष्ट है कि काशगर की ओर से रूसी हमले से भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की चिन्ता और “कश्मीर जैसे देशी राज के साथ, जिसकी बफादारी अनिश्चित है और जो अघ अगम्य है, रूस जैसे शक्तिशाली यूरोपीय राज्य के समसीमायुक्त होने” का खतरा झूठा बहाना था। दुख की बात है कि ब्रिटिश इतिहास लेखकों द्वारा दिये गये इन परम्परागत कारणों को इस विषय के कुछ प्रमुख भारतीय लेखक आख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। श्री विशेश्वर प्रसाद लिखते हैं

“फिर भी इस बात पर बल देना होगा कि इस युग में सीमावर्ती राज्यों की अखंडता और स्वतंत्रता तथा भारत की अपनी सुरक्षा का न केवल गहरा संबंध, बल्कि दोनों की अनुरता सामने आयी। अदन, फारस की खाड़ी, बलात, अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा—सभी उसकी रक्षा के दुग थे और उनको गैरों के हस्तक्षेप से बचाने में ही भारत की सुरक्षा भी थी। भारत की वैदेशिक नीति की नींव तब पड़ी और मैत्री के संबंधों और हिता की व्यवस्था विकसित हुई जिससे भारत को सुरक्षा प्राप्त हुई।”\*\*

इसी प्रकार डी० पी० सिंगल कहते हैं

\* वही, पृष्ठ ६६ ६७।

\*\* Bisheshwar Prasad, *The Foundations of India's Foreign Policy* vol I Bombay Calcutta, Madras 1955 p 263

“भारत का हित ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था और यूरोपीय शक्तियाँ के प्रभाव के विरुद्ध भारत की सीमाओं को सबल बनाने की समस्या उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में साम्राज्यवादी नीति का एक प्रभावशाली तत्व बन गई।”\*

इस तरह की धारणा भारत में अंग्रेजी राज के मूलतः साम्राज्यवादी उद्देश्यों का नेतृत्व करती है, जिसका वे० एम० पनिकर ने सही मूल्यांकन किया है

“निस्सन्देह एक महान एशियाई शक्ति के रूप में ब्रिटेन की ताकत भारत पर आधारित थी, जिसने उसको इस योग्य बनाया कि चीन के द्वार खोल सके, यास्से पाटी में यूरोपीय प्रभुत्व स्थापित कर सके, महान मछू मर्यादा की शक्ति को हीन बना सके और शेष एशिया का यूरोप के अधीन बनाने में सहयोग कर सके।”\*\*

अभी हाल में एक और भारतीय लेखक ने भी “मध्य एशिया और फारस में हम के आगे बग्न के पक्ष” को “उत्तरी क्षेत्र में” ब्रिटेन की दिलचस्पी का कारण बताया है। परन्तु उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह यह स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश नीति “मध्य एशिया पर दीर्घकालीन प्रभुत्व” स्थापित करने के उद्देश्य से “निरूपित” की गई थी। परन्तु उनका ध्यान है कि हमी खतरा न अंग्रेजों का “पुर्जाश बारबादिया” पर “आक्रामक” कर दिया। (P N K Bamzai *Kashmir from Lake Success to Tashkent*, Delhi 1966 pp 28 33 40 46) आर० ऐच० मजुमदार के अनुसार अंग्रेजों के अधिनार के तहत भारत की बदलिनी नीति का “प्रधान लक्ष्य” “शुरू से अन्त तक उत्तरपश्चिम और उत्तर-पूर्व में क्षेत्रीय विस्तार या अथवा उपाय से भारत की प्राकृतिक सीमाओं का सुरक्षा करना था (*British Paramountcy and Indian Renaissance The History and Culture of the Indian People* pt I 1963 pp 1039 1041)।

\* D P Singhal, *India and Afghanistan 1876—1907* Melbourne 1963 p xi

\* K M Panikkar *Asia and the Western Dominance* London 1951 p 95

एशिया में ब्रिटिश विस्तार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरित्र का स्वाभाविक नतीजा था, न कि भारत की सुरक्षा की तथाकथित चिंता का। ब्रिटेन के शासक वर्ग इज्जतदारी-पूर्व के पंजीवाद से साम्राज्यवाद में संक्रमण काल में अधिकतम औपनिवेशिक विस्तार चाहते थे। जैसा कि पहले कहा गया था, भारत की सुरक्षा को “रूसी खतरा” ऐसी मनगढ़ंत बात थी जिससे वे मध्य एशिया में अपने आक्रमण का औचित्य पेश करना चाहते थे। यह सचमुच दुख का विषय है कि भारतीय लेखकों ने, उत्तर और पश्चिम में भारत के सीमावर्ती राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति का यह कहकर समर्थन किया कि वह भारतीय सुरक्षा के हितों द्वारा निर्धारित होती थी। इन लेखकों ने यह छानबीन करने का कष्ट नहीं किया कि यह “रूसी खतरा” रूस की सैनिक और राजनीतिक स्थिति तथा उसकी आर्थिक और वातावरण सम्भावनाओं की दृष्टि से कहा तक वास्तविक था।\*

### मध्य एशिया से संबंध

मध्य एशिया में बड़ी भारतीय बस्तियाँ का उल्लेख १७वीं शती के स्थानीय साहित्य में मिलता है। उदाहरण के लिए, मोहम्मद यूसुफ मुशी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति में इसकी चर्चा है। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी अधिवासियों की बस्तियाँ अक्तूबर क्रांति के समय तक कायम रही। सावित्र विद्वान ग० ल० द्मीत्रियेव ने मध्य एशिया में हिंदुस्तानी अधिवासियों की सरगमियों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। उनके मतानुसार छह से आठ हजार हिंदुस्तानी १९वीं शती के मध्य और २०वीं शती के प्रारम्भ में वहाँ रहते थे। वे मुख्यतया सिंध के शिकारपुर इलाके और पंजाब के पेशावर, लाहौर, मुल्तान, लुधियाना और अमृतसर के रहनेवाले

---

\* K S Menon, *The “Russian Bogey and British Aggression in India and Beyond Calcutta 1957* ब्रिटिश नीतियों के आलोचनात्मक अध्ययन का भारत में यह शायद पहला प्रयास है।



थे। उनमें कश्मीर, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई तथा अन्य नगरों के लोग भी थे।

हिंदुस्तान से आकर बसनेवालों में हिंदु, मुस्लिम, सिख—सभी प्रकार के लोग थे। वे अधिकतर अमीर-बुखारा के प्रशासन क्षेत्र में, फरगाना घाटी, समरकन्द, तुर्किस्तान के सिर-दरिया इलाके में बसे हुए थे। कुछ हिंदुस्तानी जैतीमुख और ट्रांसकास्पियन क्षेत्रों में भी आबाद थे। चीन के खान प्रशासन क्षेत्र में शायद कोई हिंदुस्तानी बस्तियां नहीं थीं, यद्यपि हिंदुस्तानी व्यापारी दो या तीन महीनों के लिए वहां जाया करते थे। मध्य एशिया में रहनेवाले अधिकांश हिंदुस्तानी व्यापारी और साहूकार थे (सिंध के भाटिये राजस्थान के मारवाड़ी, पंजाब के खत्री तथा पश्चिमी भारत के खोजा और बोहरा)। मगर उनमें कुछ किसान, दस्तकार तथा मेहनतकशा के अल्प प्रतिनिधि भी थे। ताशकंद में १८७१ में जा १८८६ हिंदुस्तानी रहते थे, उनमें ३६ धनी भारतीय व्यापारियों के गौबर-चाकर और पांच भिखारी थे। उज्जैन सोवियत समाजवादी जनतंत्र के पुरालेख संग्रहालय की कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ हिंदुस्तानियों के अलावा, जो खेतीपारी का काम करते थे, सोनार, जिल्दकार, बुनकर नानवाई और हलवाई भी थे।

बहुत कम हिंदुस्तानी ऐसे थे, जिन्होंने मध्य एशिया में स्थायी आवास ग्रहण कर लिया था। ज्यादातर लोग अग्रिम से अग्रिम १० या १५ वर्ष रहा करते और उसने बाढ़ दफ्न सौट जाते थे। बहुत कम ऐसा होता कि स्त्री और बच्चे उनके साथ आते हों। भारतीय अधिवासी माघारणनया पारवान-भराया में साथ मिलकर रहा करते थे। ताशकंद, बुखारा और समरकंद जैसे बड़े शहरों में कई-कई हिंदुस्तानी कारखाने-सरायें हानी थीं। नमनगान और मंगिता जैसे छोटे शहरों में ग़ाम हिंदुस्तानी मुन्ले होते थे। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी समुदायों के अपने मुखिया हान थे, जो प्रशासन के सम्मुख उनका प्रतिनिधित्व किया करते थे तथा निराशा संबंधी तथा अन्य शिकायतों का निपटारा करना में गहायता करता थे।

मध्य एशिया पर जारगाही रूस का बन्दा हान में पहर भारत स र्ग इताई का व्यापार भाषा जारा पर था। भारत में जारगाही रूस का

सबध ( जिसका स्वरूप कुछ अस्थायी और अनियमित था ) मध्य एशिया के जरिये ही हुआ करता था। जब जारशाही रूसी साम्राज्य में कोकान का घान शासित क्षेत्र, बुखारा और खीवा का वह भाग मिल गया, जो तुकिस्तान का जारशाही प्रांत बना तो बुखारा भारत से व्यापार और व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना रहा। १९वीं शती के सातवें दशक के अंत में वहां की स्थानीय आवादी को भारतीय सामान मुहैया करने में हिन्दुस्तानी व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका भेदा की। वे चाय, नील, मलमल, मसाले तथा अन्य प्रकार का भारतीय और अंग्रेजी तयार माल मध्य एशिया लाया करते। ५४,७५००० रूबल का भारतीय सामान जिसका वजन एक लाख पौंद होता, सालाना बुखारा निर्यात किया जाता था। इसके बदले में बुखारा से २१०० पौंद वजन का सामान भारत भेजा जाता था। बुखारा से भारतीय सामान रूसी तुकिस्तान तथा रूसी साम्राज्य के अन्य व्यापार-बंदों को भेजा जाता था। भारतीय माल, खासकर चाय, के निर्यात का तुकिस्तान में उसकी फुटकर वित्री सिध और पंजाब के हिंदु व्यापारी किया करते थे। बुखारा में छह हिन्दुस्तानी कारवान-सरायें थीं, जो चाय के व्यापार से संबंधित थीं। अन्दुरशीद की सराय में हर साल ३००० ऊट हिन्दुस्तानी चाय लादकर आया करते थे जिर्जा गुलिया की सराय में १५०० ऊट और बहुहीन की सराय में १२०० ऊट।

जारशाही सरकार ने रूसी तुकिस्तान में हिन्दुस्तानी अंग्रेजी माल का आयात रोकने के लिए अनेक कारवाइया कीं। इन कारवाइया के फलस्वरूप पिछली शती के आठवें और नौवें दशका में भारतीय सामान का निर्यात कुछ दिना के लिए रुक गया। १८८५ में बुखारा में रूसी राजनीतिक एजेंसी स्थापित की गयी और चाय, मलमल और नील को छोड़कर बाकी आगल भारतीय सामानों के प्रवेश पर निरोध लग दिया गया। भारतीय चाय के आयात पर ५० प्रतिशत चुगी लगा दी गयी। इतने ऊँचे आयात-करों के कारण भारतीय व्यापारी परिवहन के खर्चों में क़िफायत करने का उपाय ढूँढने लगे। पहले उन्होंने मध्य एशिया में अपना सामान फारस के रास्ते लाना शुरू किया और अफगानिस्तान का खतरनाक

रास्ता छोड़ दिया। दसवीं दशाब्दी के शुरू में वे बम्बई-बतूम का समुद्री रास्ता अग्निधार करने लगे और वहाँ से वे ट्रांसकास्पियन रेलवे पर जाते, जो उन्हीं दिनों खुली थी। बतूम से भारतीय माल काकेशियाई रेलवे के जरिये कास्पियन तट तक जाता और तब कास्पियन के रास्ते ताम्नावादस्क पहुँचाया जाता। इस रास्ते भारतीय सामान के आन से जारशाही खजाने का भी नफा था, इसलिए १८६४ में इस रास्ते सामान लाने-ले जाने की आज्ञा दे दी गयी।

मध्य एशिया से व्यापार के इस सस्ते रास्ते के खुल जाने का इस क्षेत्र से भारत के व्यापार पर लाभदायक असर पड़ा, यद्यपि चुगी पर ऊँचा था। बम्बई-बतूम रास्ता खुल जाने के साथ भारतीय व्यापारियों ने तुर्किस्तान की मंडी में, घामकर जहाँ तक चाय के व्यापार का सवाल था अपनी पुर्गानी हैमियत पुनः स्थापित कर ली। सोवियत इतिहासज्ञ ग० ल० दमीत्रियेव के अनुसार ताशकन्द के पुरालेख-संग्रहालय में जो दस्तावेजें उपलब्ध हैं, उनसे पता नहीं चलता कि १८८१-१८९२ की अवधि में कौन हिन्दुस्तानी व्यापारी चाय का व्यापार करता था। परन्तु १८९६ की दस्तावेज़ों में छह हिन्दुस्तानी व्यापारियों का उल्लेख है, जिनमें उम माल चाय का व्यापार किया। समुद्री रास्ते के खुल जाने से बुधारा के साथ भी भारतीय चाय का व्यापार को फायदा पहुँचा। गत शताब्दी के आठवें तथा नव दशक में बुधारा में भारतीय चाय के व्यापारियों की संख्या ८-१० थी और बीसवीं शती के प्रारम्भ में यह बढ़कर ७० के लगभग हो गयी। बुधारा के चाय के व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने प्रायः अपना एकाधिकार कायम रखा और धीरे-धीरे वे तुर्किस्तान की मंडी पर भी हावी हो गये। समरकन्द में, जो चाय का व्यापार का एक मुख्य केन्द्र बन गया था १९१० में चाय की पैकिंग के जो १० उद्यम थे, इनमें से तीन के मालिक भारतीय व्यापारी थे।

जमा कि ऊपर उल्लेख किया गया था भारत में मध्य एशिया का नियंत्रण की जानकारी मुख्य वस्तु चाय, मसूर, नाल, कश्मीरी शाल और घग्नेदी औद्योगिक जाड़े थे। उल्लेख इतिहासकार श्रीमती रमलदास का कहना है कि हर साल काद मान चाय पूर भारतिय चाय, १८ हदर

पूठ नील, मलमल की १४०० गांठ, काई ५०० कश्मीरी शाल और ३०० टुकड़े विमछाव का आयात मध्य एशिया में होता था। भारतीय व्यापारी मध्य एशिया से अफगानिस्तान, बासगर और अक्सर हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में कच्चे रेशम, रूसी चीनी के बतन तथा अन्य औद्योगिक सामान का आयात करते थे। वे रूसी तुर्किस्तान तथा मध्य एशिया के खान-प्रशासित क्षेत्रों के परस्पर व्यापार में भी भाग लिया करते थे। इस प्रकार वे कोकान से ताशानन्द कपास हाथ का बुना कपड़ा, कालीन, गाउन और रंग लात और रूसी सोटा ताबा इत्यादि, चीनी तथा अन्य सामान कोकान लाया करते थे। भारतीय सामानों का अलावा वे रूसी तुर्किस्तान में १९१७ की अवतूर तक मध्य एशियाई तथा रूसी सामानों का भी व्यापार किया करते थे और अक्सर फेरीवाला की तरह गावों गावों घूमकर फुटवर माल भी बचा करते थे।

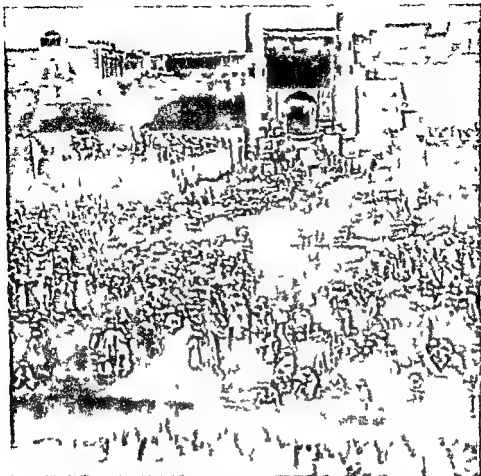
१९वीं शती के अंत और २०वीं शती के प्रारम्भ तक कपास ऊन कर तथा छाद्यान् की खरीद भारतीय व्यापारियों के कारोबारी कामकाज में बड़ा स्थान ग्रहण कर चुकी थी। समय बीतने के साथ वे केन्द्रीय रूसी कर्मों से भी कारोबार करने लगे, उनसे सामान मगवाते और नीज्जी नौबगोरोद के व्यापारी मेला में भाग लिया करते। कुछ हिंदुस्तानी प्रवासियों ने पजीवादी उद्यमों में पूजी भी लगायी। १८८७ में एक बार्ड वालागुलेव\* को सोना तथा घनिष्ठ पदार्थों का खनन करने का अनुमति मिली। वालागुलेव रूसियों के शराब के कारखाना में अगर सप्लाई किया करता था। एक और हिंदुस्तानी परामान लागूरिनोव का भी उल्लेख किया गया है कि वह भी कोई कारोबार करता था। हिंदुस्तानियों की चाय पेकिंग फैक्ट्रियां में अनेक स्थानीय मजदूर काम किया करते थे। उदाहरण के लिए एक पेशावरी फैब्रिक अहमदोव की फैक्टरी में १९०६ में ३० मजदूर काम किया करते थे। १८९६ में बार्ड गुलाएव ने नमनगान जिले के मशहद नामक

\* अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों में दज हिंदुस्तानी नामों पर स्पष्टतः उल्लेख और रूसी प्रभाव है।

गाव में हसी अ० येपीफानोव के साझे में कपास साफ करने की फैक्टरी स्थापित की। एव और हिन्दुस्तानी याकूब शेख नूरखानोव न, जो पेशावर का रहनेवाला था, १६०६ में अन्दीजान में एक और कपास साफ करने की फैक्टरी खोली।

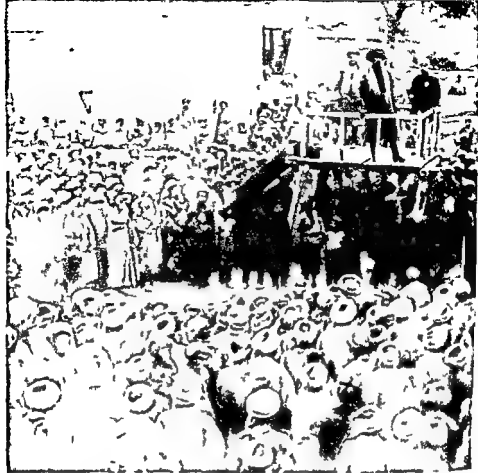
मध्य एशिया में हिन्दुस्तानी प्रवासियों की खासी बड़ी सख्या साहूकारी भी करती थी। गत शती के आठवें दशक में हिन्दुस्तानी साहूकारों का बारोबार हसी तुर्किस्तान में ज़ोरो पर चला हुआ था। उनकी शापणकारी कारवाइया की ओर प्रशासन का ध्यान १८७१ में ही आकृष्ट हुआ था, जब ज़रफशान प्रदेश के सनिक गवनर ने उनके विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करने की मिफारिश की थी। परन्तु १८७७ तक इनकी सरगमियां पर राक लगान के लिए कुछ नहीं किया गया। उस साल एक कानून लागू करके हिन्दुस्तानियों द्वारा अचल सम्पत्ति की खरीदारी पर निषेध लगा दिया गया। इसके बाद तुर्किस्तान के हिन्दुस्तानी प्रवासी धीरे-धीरे व्यापार की ओर ध्यान देने लगे। बुधारा में बीसवीं शती के शुरू तक भारतीय समुदाय में अधिकांश साहूकार थे।

यद्यपि आग्नेय अफ़ग़ानिस्तान के कारण भारत तथा मध्य एशिया के परस्पर व्यापार का कुछ धक्का लगा, उनका सांस्कृतिक सम्पर्क निरन्तर बना रहा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बदल १८६७ में उठाया गया, जब अशरफ़ाबाद और ताशकन्द में तुर्किस्तान सैनिक कमान के अफ़ग़रों के लिए हिन्दुस्तानी भाषा का दो वर्ष का पाठ्यक्रम जारी किया गया। अशरफ़ाबाद हिन्दुस्तानी पाठ्यक्रम का १६०० में ताशकन्द पाठ्यक्रम में मिला दिया गया, जो आगे बढ़कर प्राच्य विद्याभ्यास का स्कूल बन गया। अशरफ़ाबाद में हिन्दुस्तानी पाठ्यक्रम का प्रारम्भ काल यागेतलो न और ताशकन्द में सेपिटनेंट-वनल विगानित्स्की ने किया था। वनल यागेतलो ने प्राच्य भाषाभ्यास के परिस स्तून में शिक्षा प्राप्त की थी और सेपिटनेंट-वनल विगानित्स्की ने बुधारा में भारतीय भाषा के साथ रहकर हिन्दुस्तानी सीखी थी। विगानित्स्की ने भारत की यात्रा भी की और यहाँ एक मान र्ण था। बर्नन यागेतलो ने हिन्दुस्तानी भाषा में व्यापार किया था, जो १६०२ में प्रकाशित हुआ। उन्होंने मुग़लान तथा

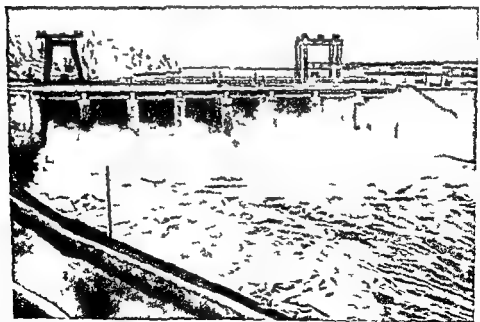


बुखारा में जन विद्रोह की विजय,  
सितम्बर १९२०। विद्रोही जनता  
भूमि के किले के सामने

एक गरीब किसान को भूमि और  
मवेशी का दानपत्र दिया  
गया है १९२५

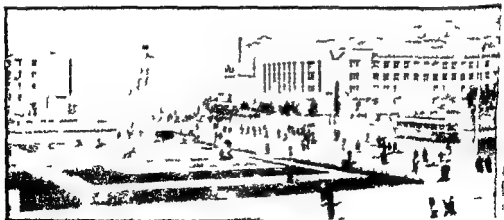
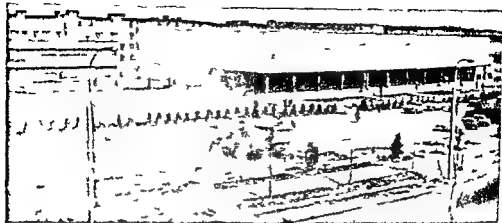


भूमि और जन-मुधार व शानून  
 की तामीन पर विचार करने क  
 लिए एक मभा। प्रयत्ना है  
 उम्मेद गा० म० जनता का  
 राष्ट्रीय कार्यवाहिनी समिति क  
 अध्यक्षता क अध्यक्ष  
 म० अमर नारायण १९२०



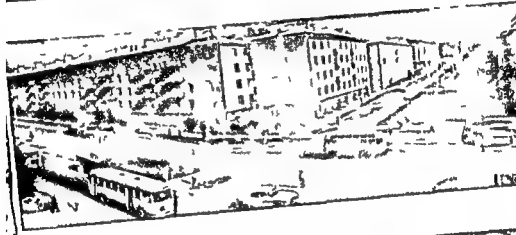
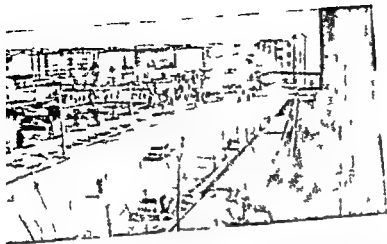
सामूहिक विमान फरहाद फरहाद पनविजलीघर का बाध,  
पनविजलीघर व निर्माण से १९५८



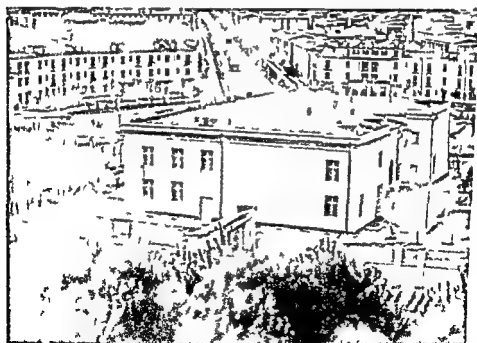
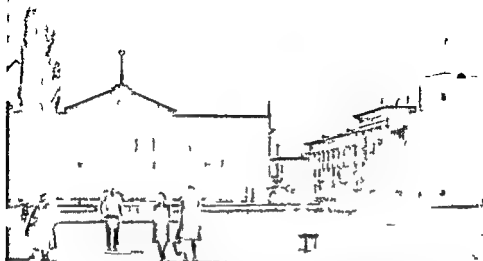


उत्तरी मा० म० जनता की  
राजधानी ताशान्त का चिह्नान  
सार मुन्ना

बहाण मा० म० जनता की  
राजधानी धमाधमा का प्राण  
प्रॉपस

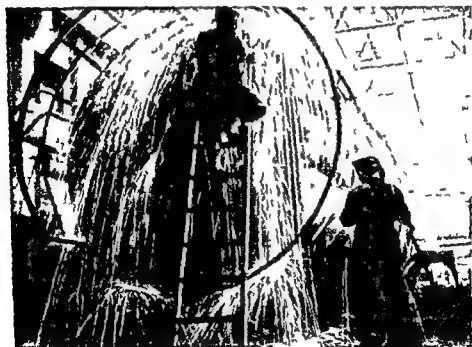
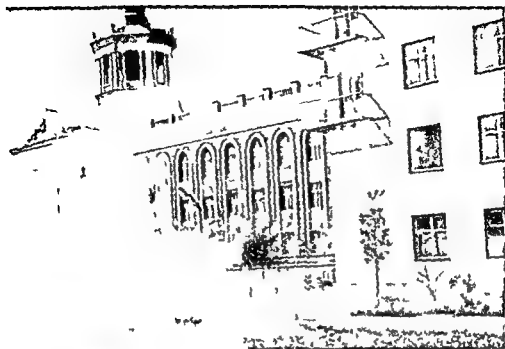


ताजिब सा० स० जनतंत्र की  
राजधानी दशवे का लेनिन

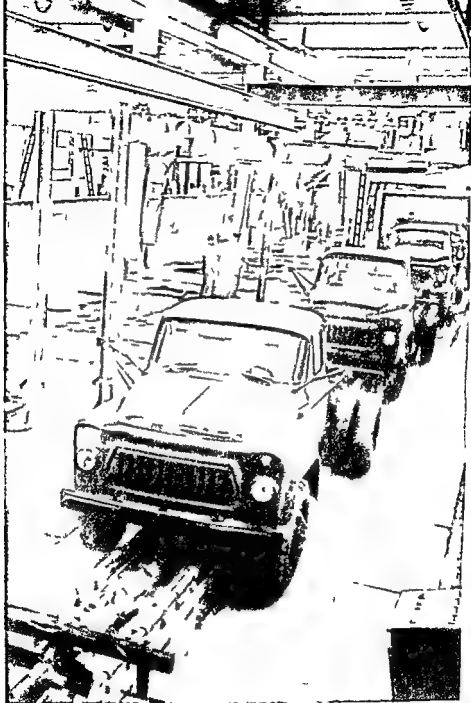


पुरमा मा० म० जनन रा  
सकथान धारागा

सिपिज मा० म० जनन रा  
सकथानि फत्र रा गारगारा  
भगा



चिरचिक्क उज्जेक् सा० म०  
जनतन्त्र, मे रासायनिक उद्योग  
के लिए यन्त्रों का निमाण



पद विविध सा० म० ज्ञान  
 म एव मात्र वाग्यता

चित्राल की बोलियों का व्याकरण तैयार करने में भी सहायता की। अप्रैल १९०१ में प्राच्य विद्याओं की रूसी संस्था की एक शाखा अ० ग० सेरे-ब्रेनिकोव, अ० ई० स्नेगारेव, म० व० ग्रुलेव तथा अन्य प्रसिद्ध प्राच्य विदा की पहलकदमी पर ताशकन्द में स्थापित की गयी। ताशकन्द में दो महत्वपूर्ण अखबारों—रूसी में “तुकिस्तानस्कीये वेदामास्ती” तथा उज्बेक में “तुकिस्तान विलायतिनिग गजेती” ने हिंदुस्तानी मामला में काफी दिलचस्पी ली। इस दूसरे अखबार ने उज्बेक कवि फुवत तथा यात्री सैयद अली खाजा की भारत यात्रा के सबंध में मूल्यवान सूचनाएँ प्रकाशित की। रूसी प्राच्यविदों के साथ उज्बेक विद्वानों ने भी भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी ली। इस सबंध में सैयद रसूल खोजा, सैयद अजीज़ खोजायेव, ताहिरखेव कियाशवेकोव और खलिलुद्दीन अहमद के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ उज्बेक विशेषज्ञ भारतीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने भारत भेजे गये।

बहुतेरे हिंदुस्तानिया न मध्य एशिया में अपने लम्बे निवासकाल में वहाँ की स्थानीय भाषाएँ सीखीं। कुछ ने रूसी भी सीखी। कुछ हिंदुस्तानिया की उज्बेक और ताजिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था जिसका दस्तावेजी सबूत ताशकन्द के पुरालेख-संग्रहालय के कागजात में मौजूद है। बबीरशाह मुस्ताफीन, जो कश्मीर से आये थे और ताशकन्द जिले के बेकाबाद गाँव में अपने परिवार सहित पिछली सदी के दसवें दशक में रहते थे, ताशकन्द के रहनेवाले किर्यामल और सुयमल, जो मिर्घ के शिकारपुर से आये थे, तथा अन्य हिंदुस्तानी जैसे साधुमल खिमनमलीयेव, खासा खुदायेव, गुलाममल खिमनमलीयेव और मुश्कीमल खिमनमलीयेव उज्बेक भाषा से भली भाँति परिचित थे। ज़ारशाही रूस में मध्य एशिया के विलयन के बाद हिंदुस्तानियों को रूसी व्यापारियों, कारोबारियों तथा प्रशासकों से काम पड़ने लगा। कुछ दिनों में अनेक हिंदुस्तानिया न रूसी बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। १९वीं शती के आठवें दशक में सरकारी कामों में एक भारतीय नुका बूता का उल्लेख है जिसके बारे में कहा गया है कि वह रूसी का अच्छा ज्ञान रखनेवाला विदेशी था। हमें १९०४ में ताशकन्द में कम से कम एक हिंदुस्तानी का पता मिलता

है, जिसका काम अपन स्वदेशियों के लिए रूसी में अनुवाद करना था। उसका नाम था पीरदास शबीलदासोव। अधिकांश हिंदुस्तानी नामों के अंत में "ओव" प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसमें रूसी प्रभाव प्रकट होता है। सरकारी दस्तावेजों में यह सूचना भी है कि समरकंद में रहनेवाले एक ३२ वर्षीय हिंदुस्तानी तथा एक १६ साल के लड़के ने रूसी भाषा सीखने के लिए रूसी स्कूल में नाम लिखाया था। १८२६ की जनगणना में मध्य एशिया के क्षेत्र में रहनेवाले ३७ हिंदुस्तानियों का उल्लेख है। ये सब माबियत सघ के नागरिक बन गये थे। उनमें से पांच न रूसी पोर् और एक ने उद्देश्य को अपनी मुख्य भाषा लिखवाया था।

मध्य एशिया के जारशाही साम्राज्य में विलयन के बाद उस इलाके में अनेक हिंदुस्तानियों की उपस्थिति से कई रूसी प्राच्यविदा में दिलचस्पी पैदा हुई। १८६७ में ही ५० ई० पचीसों ने "कश्मीरिया की ज़बानी कश्मीर की कहानी" प्रकाशित की। रूसी में यह उस राज्य का पहला यणन है, जो ताशकन्द में रहनेवाले कश्मीरियों के माध्यम से समाचार पर आधारित है। कुछ भारतीयों ने, जिनमें रामचंद्र बालाजी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध १८५७ के विद्रोह के महान नेता नाना साहेब का भतीजा थे, मध्य एशिया के अध्ययन के लिए रूसी वैज्ञानिक यात्रा-यात्रा में भाग लिया। १८८७ की गणना में रामचंद्र ने समरकंद वैज्ञानिक यात्रा-यात्रा के सदस्य की हैमियत से मध्य एशिया का विस्तारपूर्वक दौरा किया और घामू-रिया की एक शाखा की प्राचीन धारा के अध्ययन में योगदान दिया। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी प्रवासियों का अंतरावाद और ताशकन्द में रूसी अफगानों के लिए हिंदुस्तानी के पाठ्यक्रम संगठित करना भी गणनीय था। विमानिकता तथा मिलफेदिन जंग रूसी अफगानों का हिंदुस्तानी बान्धन का व्यावहारिक अभ्यास अफगानों में हिंदुस्तानी प्रवासियों के बीच में हुआ था। भारतीय व्यापारों द्वारा माध्यम से सन्ध्या में लीपापोत में छपा पुस्तक मध्य एशिया लाये थे। १८९३ में शास्त्र के एक ताजिन व्यापारों ने रूसी, बम्बई, लखनऊ, राहौर, पानपुर तथा अन्य हिंदुस्तानी शहरों में प्रकाशित २००० पुस्तकें छापा

की थी। उस व्यापारी ने बाद में बम्बई में अपना निजी छापाखाना भी वायम किया।

मध्य एशिया पर रूसी कब्जे का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर भी पड़ा। एंगेल्स ने लिखा था “ जब एक प्रथम श्रेणी की यूरोपीय मजदूर शक्ति तुर्किस्तान में अपने कदम जमाती है, बल प्रयोग तथा चापनूमी दोनों से काम लेकर फारस और अफगानिस्तान को अपना अधीन बनाने का प्रयास करती है, और धीरे-धीरे मगर दृढतापूर्वक हिंदूकुश तथा सुलैमान पर्वतमाला की ओर बढ़ती है — तो वहाँ एक सवधा भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंग्रेजी प्रशासन कोई अनिवार्य नियति नहीं रह जाता, और स्थानीय लोगों के सामने एक नयी सम्भावना उत्पन्न होती है। शक्ति द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, शक्ति ही उसे छिन्न भिन्न भी कर सकती है ”\*।

मध्य एशिया पर रूसी कब्जे से ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के वृद्ध से भगोडो ने १८५७ के विद्रोह की असफलता के बाद बुधारा और कोकान में शरण लिया था। मध्य एशिया में रूसी आगमन से भारतीय जनगण का आशा बघी कि वे अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक अत्याचार का जूझा उतार फेंकेगे। अवश्य ही यह आशा प्रारम्भ में केवल कुछ देशी रजवाड़ों के शासकों तक ही सीमित थी जिनकी जनप्रिय आकांक्षाएँ उही थी और जो केवल दो औपनिवेशिक शक्तियों के अंतर्विरोध से फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे।

सोवियत इतिहासकार नि० अ० खालकिन, ग० ल० द्मीत्रियेव और प० व० रसूलजादे ने विभिन्न दूत मंडलियों का उल्लेख किया है, जिन्हें भारतीय राजा महाराजा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता मागने के लिए तुर्किस्तान में रूसी अधिकारियों के पास भेजा था। कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह ने चार व्यक्तियों का मंडल भेजा था। इनमें से मंडल के नेता सहित दो व्यक्ति रास्ते में मार डाले गये और महाराजा का पत्र

\* व० माक्स, फ्रे० एंगेल्स, रचनाएँ, खंड २२, पृष्ठ ४५। (रूसी संस्करण)



भी उनके साथ खो गया। बाकी दो—अन्दुरहमान खान और सरफराज खान—नवम्बर १८६५ में ताशकन्द पहुँचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनसे भेंट की, जिसके समक्ष उन्होंने मंत्री की घोषणा की और पूछा कि रूसिया से क्या आशा की जा सकती है। इस दूत-मंडल को कोई सफलता नहीं मिली। जारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय को प्रोत्साहित करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी केवल अपने औपनिवेशिक विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिक साधनों के अभाव के कारण उस समय उसकी अभिरुचि नहीं थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से किसी प्रकार झगड़े में पड़े।

१८६६ में इंदौर के शामका न भी इसी तरह के उद्देश्य से एक दूत मंडल ताशकन्द भेजा। दूत ने अपने को इंदौर के मुख्य मंत्री का सुपुत्र बताया। उन्होंने अनवर रजवाड़ा, जसे हैदराबाद, त्रिवानेर, जोधपुर और जयपुर के नाम पर सहायता की याचना की। लेकिन सम्भव है कि उन दूत ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के विचार से ही इतने सारे नाम ले दिए हों, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन हिंदुस्तानी राज्यों ने अग्रजों का निवाल भगाने के लिए कभी कोई एका किया हो। इस दूत मंडल का भी कोई परिणाम नहीं निवाला।

कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह का एक दूसरा दूत मंडल जून १८७० में ताशकन्द पहुँचा। इसका नेता थे बालिया नाम प्रताप। परन्तु इस बार भी जारशाही हम ने कोई सान्नीतिक या सैन्य सहायता नहीं की। हिंदुस्तानी साम्राज्य और जागण के लिए जरा कही से हा सान समथता पाने का प्रयास करता स्वाभाविक ही था। मगर यह बात गन्तव्य है कि उपनिवेशवादी जारशाही हम का सहायता अगर मिल भी जाती, तो इस देश आजाद हो सता था। जारशाही हम "यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का जनक" और जातिया का कारागार" था, और उतम यह आशा थी कि जो सताही थी कि हिस्सा सहायता करे।

भारत के सामाजी राजाभा द्वारा भेजे गये हा दूत-मंडल में कदा कदा महत्त्वपूर्ण गुरु चरण सिंह का दूत-मंडल था, जो १८७८ में ताशकन्द पहुँचा। इस दूत-मंडल का जाग्रित दूत-मंडल कदा भी सता है।

इसका भारत के सामंती राजाओं से कोई संबंध नहीं था। इसे पंजाब के नामधारी सिखा ने भेजा था, जो उस प्रांत का अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना चाहते थे। गुरु चरण सिंह ने जब यह कठिन यात्रा की, तो उनकी आयु ७० वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्होंने इसी अधिकारिया को यह समझाने की चेष्टा की कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में भारतवासियों की सहायता करना क्या आवश्यक है। यह अपने माय बालिया राम सिंह का पत्र ले गये थे जिनमें गुरु गोविंद सिंह की भविष्यवाणिया के आधार पर बताया गया था कि भारत का हकियारा के धर्म पर अंग्रेजी जूट से मुक्ति मिलेगी। गुरु चरण सिंह के संबंध में लिखते हुए जेफरसन प्रांत के गवर्नर न० अ० इवानोव ने इस बात पर बल दिया कि "यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी के एक भाग ने वैदिक जूट से मुक्ति दिलाने के लिए हमसे सहायता मांगी है"। उन्होंने यह भी नोट किया कि "गुरु चरण सिंह से बातें करने से हमें कम की शक्ति में ऐसे विश्वास का, ब्रिटेन के धर्म शासन से भारतीय जनता की मुक्ति दिलाने की हमारी नियति में ऐसी धारणा का पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव में सदेह करना असम्भव हो जाता है"।\* लेकिन जारशाही सरकार ने हिन्दुस्तानी देशभक्तियों की प्रार्थना को फिर सुना मनसुना कर दिया। तुकिस्तान के जारशाही गवर्नर-जनरल वाइफमन ने किसी प्रकार वचनबद्ध हुए बिना वास्ताना उत्तर दे दिया।

ग्वालियर और जयपुर के महाराजाओं ने भी १८७६ और १८८० में तुकिस्तान में इसी अधिकारिया के पास दूत भेज दिए थे। ग्वालियर के शासक के ब्राह्मण दूत हीरालाल से जेफरसन के गवर्नर न० अ० इवानोव ने समरवद में भेंट की। इवानोव ने शाहजादे इब्राहीम शाह से भी भेंट की, जो जयपुर के महाराजा का पत्र लाये थे। सोवियत

\*उद्धेक सो० स० जनतंत्र का राष्ट्रीय अभिलेखागार, फाइल १। मिशन के बारे में पढ़िये पी० सी० राय द्वारा लेख, 'प्राब्लेमी वोस्तोकोवेनेनिया', १९५६, अंक ४, पृष्ठ ७७-८१। (इसी संस्करण)

भी उनके साथ खो गया। बाकी दो—अब्दुरहमान खान और सरफराज खान—नवम्बर १८६५ में ताशकन्द पहुँचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनसे भेट की, जिसके समक्ष उन्होंने मैत्री की घोषणा की और पूछा कि रूसिया से क्या आशा की जा सकती है। इस दूत मंडल को कोई सफलता नहीं मिली। ज़ारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय का प्रोत्साहित करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी केवल अपने औपनिवेशिक विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिक साधना के अभाव के कारण उस समय उसकी अभिरुचि नहीं थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से किसी प्रकार झगड़े में पड़े।

१८६६ में इंदौर के शासकान भी इसी तरह के उद्देश्य से एक दूत मंडल ताशकन्द भेजा। दूत ने अपने को इंदौर के मुख्य मंत्री का सुपुत्र बताया। उन्होंने अनेक रजवाड़ों, जैसे हैदराबाद, बिजानेर, जोधपुर और जयपुर के नाम पर सहायता की याचना की। लेकिन सम्भव है कि उक्त दूत ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के विचार से ही इतने सारे नाम ले दिये हों, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन हिन्दुस्तानी राज्यों ने अंग्रेजों को निकाल भगाने के लिए कभी कोई एका किया हो। इस दूत मंडल का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह का एक दूसरा दूत मंडल जून १८७० में ताशकन्द पहुँचा। इसके नेता थे बालिया त्रय प्रकाश। परंतु इस बार भी ज़ारशाही रूस ने कोई राजनीतिक या सैनिक सहायता नहीं की। हिन्दुस्तानी राजाग्रा और जनगण के लिए जहाँ कहीं से हो सके समर्थन पाने का प्रयास करना स्वाभाविक ही था। मगर यह बात सन्देहजनक है कि उपनिवेशवादी ज़ारशाही रूस की सहायता अगर मिल भी जाती, तो इससे देश आजाद हो सकता था। ज़ारशाही रूस 'यूरोपीय प्रतिक्रिया का जनडाम' और "जातिया का बारागार" था, और उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि निस्स्वार्थ सहायता करे।

भारत के सामंती राजाग्रा द्वारा भेजे गये इन दूत मंडलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु चरण सिंह का दूत-मंडल था, जो १८७६ में ताशकन्द पहुँचा। इस दूत मंडल को जनप्रिय दूत मंडल कहा जा सकता है।

इसका भारत के सामंती राजाओं से कोई संबंध नहीं था। इसे पंजाब के नामधारी सिखों ने भेजा था, जो उस प्रांत का अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना चाहते थे। गुरु चरण सिंह ने जब यह कठिन यात्रा की, तो उनकी आयु ७० वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्होंने रूसी अधिवासियों को यह समझाने की चेष्टा की कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के सपने में भारतवासियों की सहायता करना क्यों आवश्यक है। वह अपने साथ बालिया राम सिंह का पत्र ले गये थे जिसमें गुरु गोविंद सिंह की भविष्यवाणियों के आधार पर बताया गया था कि भारत की रूसियों के आने पर अंग्रेजी जूए से मुक्ति मिलेगी। गुरु चरण सिंह के संबंध में लिखते हुए ज़रफ़शान प्रांत के गवर्नर न० अ० इवानोव ने इस बात पर बल दिया कि "यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश इंडिया की आबादी के एक भाग ने वैदशिव जूए से मुक्ति दिलाने के लिए हमसे सहायता मांगी है"। उन्होंने यह भी नोट किया कि "गुरु चरण सिंह से बातें करने से हमें रूस की शक्ति में ऐसे विश्वास का, ब्रिटेन के धुनित शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने की हमारी नियति में ऐसी आस्था का पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया की आबादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव में मंदेह करना असंभव हो जाता है"।\* लेकिन ज़ारशाही सरकार ने हिंदुस्तानी देशभक्तियों की प्रार्थना को फिर सुना-अनसुना कर दिया। तुर्किस्तान के ज़ारशाही गवर्नर-जनरल वाउफ़मन ने किसी प्रकार वचनबद्ध हुए बिना दोस्ताना उत्तर दे दिया।

खालियर और जयपुर के महाराजाओं ने भी १८७६ और १८८० में तुर्किस्तान में रूसी अधिवासियों के पास दूत भेज दिये थे। खालियर के शासक के ब्राह्मण दूत हीरासाह से ज़रफ़शान के गवर्नर न० अ० व्ना नोव ने समरखंद में भेंट की। इवानोव ने शाहजादे इम्राहीम शाह से भी भेंट की, जो जयपुर के महाराजा का पत्र लाय थे। सोवियत

\*उत्खेक सो० स० जनतंत्र का राजकीय अभिलेखागार, पाइल १। मिशा के बारे में पढ़िये पी० सी० राय द्वारा लेख, 'प्रान्तेमी वोस्तोकोवेदेनिया', १९५६, भाग ८ पृष्ठ ७७-८१। (रूसी संस्करण)

इतिहासकार इ० अ० रुस्तामोव ने १८६१ में हुज़ा के शासक के दूत मडल की यात्रा का उल्लेख किया है। १६०३ में बम्बई में रूसी कौन्सल य० ओ० क्लेम ने रूसी विदेश मन्त्रालय को सूचना दी कि उनके पास गुमनाम चिट्ठियाँ आ रही हैं जिनमें अंग्रेज़ों के प्रति घणा तथा यह आशा व्यक्त की जाती है कि रूस शीघ्र ही भारत की धरती पर प्रकट होगा।

अंग्रेज़ों को इन सम्पर्कों का पता चल गया था। इसलिए उन्होंने रूसी अधिकारियों से मिलने मध्य एशिया जानवाले भारतीय प्रतिनिधियों का पीछा करने का पक्का प्रबंध किया। इस काम में उन्हें गुलाब खान नामक एक हिन्दुस्तानी से सहायता मिली। उसने भारत तक गुरु चरण सिंह का पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। गुलाब खान अपनी पत्नी सहित कत्ता कुर्गन में बस गया था, जहाँ उसने दवा की दुकान खोल ली थी। उसे ब्रिटिश इंडियन सेना के एक भगाड़े सैन्य खान से, जो जरफशान के रूसी गवर्नर का सहायक बन गया था, और दो यहूदियाँ रिउवेन तथा इसहाक से, जो नमशा पुलिस अधिकारी और जरफशान के गवर्नर का दुभाषिया थे, सूचना मिली थी। गुलाब खान ने अपने एजेंटों ताजिक मुल्ला इनाम और गुलाम मुहिउद्दीन के जरिये भारत में अंग्रेज अधिकारियों को सवाद भेजा। ये दोनों कत्ता-कुर्गन के रहनेवाले थे। गुलाब खान की भेजी हुई सूचना भारत के राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय में मौजूद है और उससे कश्मीर के महाराजा तथा नामधारी सिखों के भावी सम्पर्कों पर दिलचस्प प्रकाश पड़ता है। इन सम्पर्कों के बारे में उल्लिखित रूसी स्रोतों से कुछ पता नहीं चलता। राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रहालय में गुलाब खान के जा पत्र हैं, उनसे हमें ज्ञात होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के गुप्तचर विभाग के प्रधान अफसर सिंह ने १८७० में कम प्रकाश के दूत मडल के तुरंत बाद एक और व्यक्ति गया रास टागरा का महाराजा का सदेश देकर भेजा। गुलाब खान की सूचना के अनुसार गया रास समरकंद में चार साल तक रहा और रूसी स्वतंत्र में पढ़कर अच्छी रूसी सीख ली। जम्मू लौटने के बाद उस तत्समन्तार बना दिया गया। गुलाब खान ने एक और कश्मीरी अधिकारी शेर सिंह का भी उल्लेख किया है जिसे कश्मीर के शासक ने १८७२ में तुर्किस्तान भेजा था।

ब्रिटिश एजेंट की सूचना के अनुसार वह ताशकन्द में जनरल काउफमन से मिला। गुलाब खान ने लिखा है कि रूसियों ने १८८० में युमुफजर्द के एक व्यक्ति अब्दुल को कश्मीर भेजा, जो एक और कश्मीरी प्रणिधि जीवन मान डोगरा को साथ लेकर ताशकन्द लौटा। अब नामधारी प्रणिधिया में गुलाब खान ने परियाता के एक ब्राह्मण जस राम और इलाही कश्मीरासी का उल्लेख किया है, जिन्होंने समरकन्द के रूसी गवर्नर के समक्ष अपने आप को पेश किया। कहा जाना है कि उसने उन्हें अपने सहायक सैयद खान के पास भेज दिया, जिसने उनके बागडर फाड़कर उन्हें निवाल दिया। गुलाब खान ने गुरु चरण सिंह के बारे में भी लिखा है (जा उस समय बंद थे) कि उन्होंने शिकारपुर के निवासी शाम्भू के जरिये बुखारा से रूसी गवर्नर के नाम एक पत्र जनवरी १८८२ में डाक में डनवाया। इस पत्र के मिलने पर गवर्नर अज़ामोव ने जस राम को दूढ़ने का आदेश दिया। वह बुखारा में मिला और वहां से लाया गया। गुलाब खान की सूचना के अनुसार जनवरी १८८२ में जस राम का गुलाम रसूल के साथ, जिसे वह रूसी एजेंट कहता है, मेट-उपहार देकर जम्मू में भेजा गया। उनको जा पत्र दिया गया था, वह एक कश्मीरी यवक मसूख की सहायता से डोहरी में लिखवाया गया था। मसूख कत्ता-कुर्गान में रहना और रूसी पद रहा था।

रूसी अधिकारियों के पास इन दूत-मंडलों के भेजन से भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को कोई लाभ नहीं हुआ। परन्तु इनसे इतना अवश्य प्रकट हुआ कि भारतीय जनगण को अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने समय में रूसी सहायता की बड़ी आशा थी। १८७६ में बम्बई में रूसी मुद्र-भोता के आने के समाचार पाकर लोग शहर की ओर यह देखने को दौड़ पड़े कि वे सचमुच वहां आये हैं। रूसी सहायता के संबंध में भारतीय देशभक्तों की आशाओं का एक उल्लेखनीय परिचय इस बात से मिलता है कि तिलक न बम्बई स्थित रूसी कौनमला बेकिन तथा क्लेम से वार्तालाप किया था। उनसे उन्होंने रूसी फर्मों से परिचय कराने का अनुरोध किया ताकि भारत में फैक्टरिया की स्थापना के लिए मशीनरी खरीदी जाय, और सैनिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय नवयुवकों को रूस भेजन में सहायता

मागी। ज़ारशाही रूसी सरकार हिन्दुस्तानी जनगण को सहायता देने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। इस तथ्य से "भारत को रूसी छतरे" के मिथ्या प्रचार का भाड़ा फट जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह खतरा अंग्रेज़ों की मनगढ़त था, जिससे वे मध्य एशिया में अपने निदिष्ट आक्रमण पर परदा डालना चाहते थे।

१९१७ की महान् अक्टूबर समाजवादी क्रांति द्वारा मध्य एशिया के आज़ाद होने के बाद यह इलाका भारतीय स्वाधीनता के अनेक सेनानियों के लिए आश्रयण का केंद्र बन गया, जिन्होंने ताशकन्द को अपनी क्रांतिकारी सरगमियों का एक मरकज बनाया। पश्चिम में लंदन, पेरिस, बर्लिन, स्टॉकहोम, 'यूयाव', सान फ्रांसिस्को और बेलीफानिया में तथा पूर्व में टोकियो में भारतीय क्रांतिकारियों के कायकलाप से लोग भली भाँति परिचित हैं, परन्तु महान् अक्टूबर क्रांति के तुरन्त बाद के दौर में सोवियत एशिया में उनकी सरगमियों का ज्ञान कम लोगों को है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अनेक राष्ट्रीय क्रांतिकारी ब्रिटेन की विरोधी वैदेशिक शक्तियों से सहायता मागने के लिए भारत से विदेश चले गये थे। चूँकि ज़ारशाही रूस ब्रिटेन का मित्र था, इसलिए उससे सहायता मिलान का कोई सवाल ही नहीं था। १९१५ में बर्लिन स्थित भारतीय क्रांतिकारी समिति ने हेटिंग मिशन में राजा महेन्द्र प्रताप और बकतुल्लाह को शामिल कराया। यह मिशन ब्रिटेन के विरुद्ध अमीर को अपने साथ मिलान के लिए साम्राज्यवादी जर्मनी द्वारा अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा था। काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप ने "भारत की अस्थायी सरकार" की स्थापना की, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष बन, और बकतुल्लाह का प्रधान मंत्री तथा उयैदुल्लाह सिद्दी को गृह मंत्री बनाया। अपने जर्मन सलाहकार हेटिंग की सलाह के बावजूद राजा महेन्द्र प्रताप ने ज़ारशाही रूस से भी सहायता मागन का प्रयत्न किया। उन्हें इस क्षेत्र में आग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता के कारण कुछ आशा थी। मगर गीघ्र ही उन्हें निराश होना पड़ा। ताशकन्द में ज़ारशाही रूस के अधिकारियों ने ज़ार के नाम उनको 'स्वर्ण ध्यान पत्र' का कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी बार उन्होंने जिन दो दूतों को

ताशकन्द भगा, उधे गिरफ्तार कर लिया गया और ईरान में अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। अंग्रेजों ने उधे गोली मार दी।

परन्तु जारशाही रूस ने भारतीय जातिकारियों द्वारा सम्पक स्थापित करने के सभी प्रयासों को अंगर अस्वीकार कर दिया, ता सोवियत सरकार ने उन लोगों का स्वागत किया, जा भारत की स्वाधीनता के लिए काम करना चाहते थे। उसने खुल्लमखुल्ला पूव की सभी दलित जातियों के लक्ष्य का समर्थन किया। भारतीय सर्वधानिक सुधारों के सबध में माटेगु-चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट (१९१८) ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि रूस की क्रांति से "भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रेरणा मिली है"। मध्य एशिया के विभिन्न नगरों में कई हजार हिंदुस्तानी बसे हुए थे, जा भारत के एक निकटवर्ती इलाके से ब्रिटिश विरोधी कायकलाप के लिए अच्छे आधार का काम द रहे थे। दूसरे, सुनसान पहाड़ी दर्रा में होकर इस इलाके में भाग आना समुद्र के रास्ते यूरोप जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित था। इसलिए अक्सूधर समाजवादी क्रांति के पीछे पीछे सोवियत एशिया में भारतीय देशभक्तों का स्थायी धारा-सी बहने लगी।

१९१८ में १९२० तक हिंदुस्तानियों के कई दल भारत की स्वाधीनता के लिए सोवियत सहायता की आशा में मध्य एशिया पहुँचे। फरवरी १९१८ में महेन्द्र प्रताप तुर्किस्तान सोवियत अधिकांशियों ने निमंत्रण पर ताशकन्द आये और वहाँ से पेत्रोग्राद के लिए रवाना हुए जहाँ उच्च सरकारी नेताओं ने उनसे भेंट की। पेत्रोग्राद से महेन्द्र प्रताप बलिन गये। उनके बाद "भारत की अस्थायी सरकार" के कई प्रतिनिधि कावन से सोवियत सघ आये। ताशकन्द और बुखारा के मध्य एशियाई नगरों के अलावा वे मास्को और कज़ान में भी रहते और काम करते थे और अफगानिस्तान से सम्पक स्थापित करने में उन्होंने नवजात सोवियत राज्य की विशेष सहायता की।

अमानुल्लाह खान के अमीर बनने के बाद मार्च १९१९ में दक्खिनाह ताशकन्द के रास्ते मास्को पहुँचे। नये अमीर ने उधे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि सोवियत रूस में स्थायी राजनयिक सत्रघ स्थापित करे। ७ मई, १९१९ का वे लेनिन से मिले। महेन्द्र प्रताप उस समय जमनी में



थे। ब्रिटेन और अफगानिस्तान की लड़ाई का समाचार पाते ही उन्होंने मास्का होते हुए अफगानिस्तान लौटने का निश्चय किया। सावियत इतिहासकार म० अ० पेसित्स के अनुसार महेन्द्र प्रताप जुलाई १९१६ में मास्का लौटे। उनके साथ अब्दुरब और प्रतिवादी आचाय भी थे। वहाँ उनसे बकतुल्लाह मिले। महेन्द्र प्रताप के आने के शीघ्र ही बाद उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें बकतुल्लाह, अब्दुरब प्रतिवादी आचाय, दलीप सिंह गिल और पंजाब का एक किसान इब्राहीम भी था, लेनिन से भेट की। सोवियत वैदेशिक कमिसारियत से अपने वार्तानाम में महेन्द्र प्रताप ने माग की कि सोवियत सरकार काबुल स्थित उनका "भारत की अस्थायी सरकार" को भारत की आतंककारी शक्तियों के एकमात्र बैटन के रूप में मान्यता प्रदान करे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए सोवियत अफगान सैनिक कारवाई की भी योजना पेश की।

काबुल स्थित "भारत की अस्थायी सरकार" का एक विशेष मंडल, जिसमें मोहम्मद अली और शफीक अहमद थे, ३१ मार्च, १९२० को ताशकन्द पहुँचा। बाद में इब्राहीम और अब्दुल मजीद भी उनमें आ मिले। इन लोगों ने बकतुल्लाह से मिलकर "अस्थायी सरकार" का दल स्थापित किया। इस दल ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए वैदेशिक सैनिक अभियान पर जोर दिया, यद्यपि वह राष्ट्रीय सेना संगठित करने की बात भी करता था। बकतुल्लाह ने तुर्की युद्ध-बहिदियाँ तथा बोलगा क्षेत्र और मध्य एशिया के मुसलमानों में सोवियत सत्ता के समर्थन में प्रचार किया और अनेक पुस्तिकाएँ लिखी, जिनमें बाल्योविसम का इस्लाम का मित्र साबित किया गया था और दोनों के सामाजिक आदर्शों और मित्रता की समानता को पेश किया गया था। बकतुल्लाह दल के विचारशील लोगों का विकास वामपंथी तथा समाजवादी विचारों की दिशा में हुआ और उसके कई सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय पंचार की सोवियत के लिए सक्रिय रूप में काम करने लगे, जिसकी स्थापना वैश्वीय कार्यवाहिनी समिति के तुर्की आयोग द्वारा दिसम्बर १९१६ में ताशकन्द में हुई थी। इस संगठन का काम सोवियत तुर्किस्तान में काम करनेवाले अनेक आतंककारी

संगठना को पड़ोसी देशों में काम करनेवाले संगठनों से एकताबद्ध करना था। "सोवियन्तर्प्राप" (अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की सोवियत) के भारतीय विभाग ने कुछ हिन्दुस्तानिया को ब्रिटिश इंडियन सेना व सिपाहियों में काम करने वाबू और ईरान भेजा और सीमावर्ती कबोला में काम करने पामीर भेजा। इसमें अनेक पैफलेट और पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित कीं। इससे साप्ताहिक पत्र "जमींदार" का एक अब ताशकन्द से प्रकाशित हुआ।

संगठित भारतीय राष्ट्रीय आतिवारिया का एक नया और बड़ा दल २ जुलाई १९२० का काबुल में ताशकन्द पहुँचा। इससे नेता अब्दुरख के और इससे सदस्यों की संख्या २८ थी। उन्होंने काबुल में ही भारतीय आतिवारी संस्था के रूप में अपने को संगठित कर लिया था। संस्था ने काबुल से लेनिन के नाम पर अभिनंदन संवाद भेजा था, जिसका उन्होंने बड़ा उत्साहवर्धक उत्तर भेजा था। ताशकन्द में डा लोगा के सम्मान में एक सार्वजनिक सभा की गयी, जिसमें व० व० यूइविशेव तथा म० व० फूजे जैसे प्रमुख सोवियत नेता भी उपस्थित थे। भारतीय आतिवारी संस्था के सदस्यों में १०-१२ ब्रिटिश सेना के भागे हुए लोग भी थे। अब्दुरख के साथ जा लोग ताशकन्द आये उनमें दो नसीर खान भाई भी थे जो स्वतंत्र बलूच कबोला के नेता थे जिन्होंने १९१७-१९१८ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रतिवादी आचार्य भी इस दल के साथ थे। भारतीय आतिवारी संस्था के सात सदस्य उन १४ भारतीय प्रतिनिधियों में थे, जिन्होंने सितम्बर १९२० में पूब की जातियों की वाबू कांग्रेस में भाग लिया था। संस्था के सदस्यों की धारणा थी कि स्वतंत्र कजाखली सीमावर्ती लोगो के समयन से भारत को सोवियत रूस द्वारा स्वाधीन कराया जाय। अवश्य ही सोवियत पक्ष इस प्रकार के दुस्साहसिकतावादी सैनिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता था। फिर भारतीय आतिवारी संस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की सोवियत के भारतीय विभाग में तीव्र अनद्वंद्व पदा हो गया और इसमें भी ताशकन्द में भारत की स्वाधीनता के आतिवारी काम की प्रगति में बाधा हुई।

सितम्बर अक्टूबर १९२० में हिन्दुस्तानी मुहाजिरीन का एक दल कठिन यात्रा के बाद ताशकन्द पहुँचा। ये लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता

आन्दोलन के मुस्लिम अंग के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलन के दौरान खिलाफत की बहाली की खातिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश को त्याग किया था। अफगान सरकार ने सोवियत मध्य एशिया से होकर उनके तुर्की जाने का विरोध किया। उस विरोध को दूर करने के बाद हिंदुस्तानी मुहाजिरीन दो जत्था में तेरमीज की ओर रवाना हुए। हर जत्थे में ८० आदमी थे। पहले जत्थे के नेता थे मोहम्मद अकबर खान। इसमें अनेक शिक्षित नौजवान मुसलमान थे। इसको तुक्मान आतिविरोधियों ने पकड़ लिया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। लाल सेना ने उन्हें हाथा भारे जाने से बचा लिया। बाद में इस जत्थे के कुछ लोगो ने किरकी बिले पर आतिविरोधियों के हमले का परास्त करने में सोवियत सेना की सशस्त्र सहायता भी की। अतः इन मुस्लिम नौजवानों के दिल में तुर्की जाने का इरादा छोड़ दिया और ताशकंद जाने पर राजी हो गया। जो बहुतेरे तुर्की गये, वहाँ में ताशकंद लौट आये, क्योंकि कमालपाशा का तुर्की अब उन्हें लेना नहीं चाहता था। वे जिस खिलाफत की रक्षा करने निकले थे, उसे तुर्की में मिटा दिया था। नवम्बर १९२० तक ताशकंद में अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ कोई १०० हिंदुस्तानी सेनानी जमा हो गये थे। दिसम्बर १९२० तक उनकी सख्या लगभग २०० हो गयी। कोमिटन के तुक-ब्यूरो ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को अधिकाधिक खिलाफती मुहाजिरों के आने की सूचना दी। बुधवार में १९२० के अंत तथा १९२१ के प्रारम्भ में अनेक हिंदुस्तानी मुहाजिर आये जिनमें कोई २० बंगाली भी थे।

एम० एन० राय और अबनि मुखर्जी अक्टूबर १९२० में ताशकंद पहुँचे। वे खिलाफती मुहाजिरीन के बड़ी सख्या में आने की खबर सुनकर मध्य एशिया पहुँचे थे। उन्होंने सोचा कि यह स्वाधीनता सेना का केन्द्रीय दस्ता बनाने का अच्छा अवसर है। इस सेना का संगठन अफगानिस्तान में भारत के सीमावर्ती कवायतियों का लेकर करना था, जिनमें ब्रिटिश विराधी भावना लगी थी। ताशकंद आने से पहले राय मास्को में ही अखिल भारतीय अस्थायी केन्द्रीय आतिकारी समिति की स्थापना कर चुके थे, जिसमें कोमिटन की दूसरी कांग्रेस में भाग लेनेवाले हिंदुस्तानी शामिल थे। यद्यपि

राय साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का मयुक्त मोरचा बनाने की लेनिनवादी ग्राह्य को, जिसे दूसरी कांग्रेस में स्वीकार किया गया था, मानने का दावा करते थे, परन्तु उन्हीं ने न केवल राष्ट्रीय एकीपति का, बल्कि राष्ट्रीय आतिवारी संगठन से भी सहयोग के प्रति अपना नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं छिपाया था। उनकी आतिवारी समिति का तुरन्त ही भारतीय आतिवारी समिति से, जिसके नेता अहमद और आचाय थे, बगडा हो गया। दिसम्बर के शुरू में अहमद को, जिन्हें आतिवारी समिति का सदस्य बना लिया गया था, संगठन से निकाल दिया गया। राय और अहमद के मतभेद इतने तेज हो गये कि सुल्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के तुल्य-व्यूरों ने ३१ दिसम्बर, १९२० का एक संयुक्त बैठक में उसके समाधान के लिए उन्हें मास्को जान की मलाह दी।

ताशकंद में अपने संक्षिप्त निवासकाल में राय को पूव में कम्युनिस्ट आन्दोलन संगठित करने की व्यावहारिक कठिनायियों का सामना करना पड़ा। उस समय तब उन्हें इन समस्याओं का कोई परिचय नहीं था। वे समझते थे कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के राष्ट्रीय संघर्ष पर सवहार का अधिनायकत्व स्थापित करना यायाधिक काम है। परन्तु वह खिलाफती मुहाजिरीन की बड़ी संख्या को ताशकंद में राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रशिक्षण पाने पर राजी नहीं कर सके। इससे उन्हें एक सबक मिला। सैनिक प्रशिक्षण के आकषण से भी उन्हें अपने अनुयायी बनाने में सफलता नहीं हुई। ताशकंद के सैनिक स्कूल में १९२० के अंत तक केवल २५ हिंदुस्तानी मुहाजिरीन शामिल हुए और उनकी अधिक से अधिक संख्या मार्च १९२१ में ३६ तक पहुँची और उसके बाद घटने लगी। मई १९२१ में यह स्कूल बंद कर दिया गया और उसमें प्रशिक्षण पानेवाले भारतीयों को पूव के कमजोरियों के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए मास्को भेज दिया गया। बाद में भारत लौटने पर अंग्रेजों ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया। उनपर पेशावर साजिश मुकदमा चलाया गया और विभिन्न अवधि के लिए सजाएँ दी गयीं। ताशकंद में भारतीय मुक्ति सेना संगठित करने की योजना को धक्का इस बात से भी लगा कि अफगान सरकार ने इसे अपने इलाके से होकर भारत जाने

की आज्ञा देने से इनकार कर दिया। वैसे भी भारत में मुख्यतया बाहरी सैनिक अभियान के जरिये सामाजिक राजनीतिक क्रांति करने की योजना अत्यंत अव्यावहारिक थी। इससे निम्न पूँजीवादी क्रांतिवाद की व आती थी। इसमें सन्देह नहीं कि गह्युद्ध में लाल सेना की शानदार विजय के कारण बहुतेरे भारतीय देशभक्तों के मन में क्रांतिकारी सघर्ष के सैनिक उपायों की श्रेष्ठता का सिक्का जम गया था। परन्तु वे यह भ्रमने लगे थे कि लाल सेना को क्रांतिकारी जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस जनता को बोल्शेविकों ने संगठनात्मक तथा विचारधारात्मक रूप से अच्छी तरह तैयार किया था।

### सिक्किम में अंग्रेजों की साजिशें

काशगर को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अंग्रेजों का प्रयास १९वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में ही शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अस्तित्व का अधीक्षक विलियम मरनापट १८२१ में लेह गया जहाँ उसने लद्दाख से होकर चीनी और उसके कुछ व्यापारियों के आने जाने के बारे में एक समझौता किया। उसने चीनी अधिकारियों से काशगर जाने की आज्ञा भी माँगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। मरनापट ने काशगर के रास्ते रुसी हमले का हौआ उस समय खड़ा किया, जबकि रुस ने अभी बज्राय स्टेपी पर भी कब्जा नहीं किया था। आगा मेहदी नामक एक रुसी एजेंट के लद्दाख के शासक तथा रणजीत सिंह से भट करन आने के अवसर पर जो अफवाह फैली हुई थी, मरनापट को उनपर विश्वास था। लद्दाख में उसने रणजीत सिंह के विरुद्ध पड़यत्न में भाग लिया।\*

मरनापट ने बाद में यूरोपीय "खोज-यात्री", जैसे गेराड विरादरान, हेडरसन, फालक्नर और विगने लद्दाख, कश्मीर और

\*दे० ग० ज० ऐलडर, 'उपगन्त पुस्तक', पृष्ठ १८।

वलूचिस्तान में सक्रिय रहे।\* अंग्रेजों की सहमति से ही गुलाब सिंह ने, जो रणजीत सिंह का जामीनदार था, १८३४ में लद्दाख पर अधिकार कर लिया। सिंध की पराजय के बाद अंग्रेजों ने गुलाब सिंह का कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का महाराजा बना दिया। उसे आदेश था कि सीमा में कोई हेरफेर करने से पहले अंग्रेजों की अनुमति ले और पड़ोसिया से सारे झगड़े निवटाने के लिए अंग्रेजों के पास ले जाये। १८४९ में रहा-सहा सिंध राज्य भी समाप्त हो गया और ब्रिटिश भारत की सीमाएँ गुलाब सिंह के इलाके से और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सिक्खों से आ मिली।

सिक्खों में अब अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जून १८६१ में सिक्खों से व्यापार के बारे में एक छपी हुई प्रश्नावली पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा पंजाब के अधिकारियों के पास भेजी गई। इस प्रश्नावली में आधार पर पंजाब की सरकार के सचिव २० ह० डेवीस ने एक विस्तारित रिपोर्ट तैयार की। डेवीस इस नतीजे पर पहुँचा था कि मध्य एशिया की भूमिका में भारतीय व्यापार इसी व्यापार का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है।\*\*

पंजाब के उत्साही अधिकारियों के लिए भारत और सिक्खों के बीच बारबानी रास्ते की भौतिक कठिनाइयाँ व्यापार में उतनी बाधक नहीं थी जितना हुआ बताया गया के हमले, राजनीतिक अव्यवस्था और चीनी अधिकारियों की उदासीनता। उन्होंने कश्मीरी अधिकारियों की अनुरोध व्यापार-नीति का भी कुछ दोष ठहराया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर राबर्ट माटगोमरी ने हिमालय पार के व्यापार के विकास में बड़ी दिलचस्पी ली। १८६४ में कश्मीर के महाराजा को आयात और परिवहन कर में कमी करने पर राजी कर लिया गया।

\* इन खोज-यात्राओं के सवध में द० S A Hedin, *Southern Tibet*, Chapter VII—*History of Exploration in the Kara Koran Mountains*, Stockholm 1922 ईश्वरी प्रसाद झा "खोज-यात्रियाँ" को "साम्राज्यवाद के माग शोधक" कहते हैं (*History of Modern India* 1951, p 1671)

\*\* National Archives F D S P, Aug 1874, Nos 205 07

सिक्खों की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई, जब १८६६ में बोकान के याकूब बेग न सत्ता समाली। याकूब बेग ने व्यापारिक सबंध कायम करने के लिए पंजाबी अधिकारियों के उत्साह का प्रतिदान किया और अपने शासन के प्रथम वर्ष में एक व्यापारमंडल कश्मीर भेजा।\* उसने रिंगिज और हज्जा सुटेरो का चाय के वाग्वान लटने से राकन का और लेह के व्यापार के रास्तों की रक्षा करने का वायदा किया। सिक्खों से चीनियों के निकाले जाने से भारतीयों को सुनहरा भवसर मिल गया। कागडा के चाय के नये वागानों को, जो कुतू के रास्तों पर थे, इसमें बहुत लाभ होने की आशा थी।

डा० केली न, जो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर थे, काशगर के रास्ते को बेहतर बनाने के बड़े प्रयत्न किये और यारकंद के व्यापारियों का भारत से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। चांग चे मो भाग की खोज करने का श्रेय उही को दिया जाता है। शो और हवड ने बाद में यही रास्ता लिया। डा० केली ने याकूब बेग से मंत्री-सद्वि करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल काशगर भेजने का प्रस्ताव रखा। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन प्रस्ताव का समर्थन किया।\*\* लेह में व्यापारियों के जरिये जो सूचनाएं मिल रही थी, उससे डा० केली ने यह अनुमान लगाया कि अमीर अंग्रेजों से दोस्ती रखना चाहता है। इसकी पुष्टि शो की रिपोर्ट से भी हुई, जो १८६८ में व्यक्तिगत रूप से यारकंद गया था। याकूब बेग के राज में मैत्रीपूर्ण सबंधों की शुरुआत उस समय हुई, जब १८६८ की गमिया के प्रारम्भ में उसके प्रतिनिधि माहम्मद मजोर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भेंट की। शा ने इस प्रतिनिधि से अपनी काशगर जान की इच्छा प्रकट की और प्रतिनिधि ने इस विचार का स्वागत किया। दिसम्बर १८६८ में शो काशगर खाना हुआ जहां उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट हवड का भी देश में आने की आना दी गई। शा ने अमीर से 'तुर्की के सुलतान मुसलमानों के खलीफा के प्रति

\* *Letters from India and Madras* vol I, p 845

\*\* National Archives F D S P Aug 1871 Nos 205 07

इंग्लैंड की दोस्ती" की चर्चा की।\* उसने यारकंद के रास्ते के सबध में "स्मृति पत्र" लिखा, जिसमें उसने मध्य एशिया के इलाकों तक अबाध व्यापारिक रास्ते के लिए कश्मीर से वातचीत का सुझाव दिया। उसने कराकुरम के बदले चांग-चे-मो के रास्ते को ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इसमें दरें और नदिया कम पार करनी होती थी और घास, दूधन, सामान आदि आसानी से मिल जाता था। सदाय के लिए वह कागडा, कश्मीर के रास्ते के मुकाबले में कुल साहूल रास्ते को ज्यादा पसंद करता था।\*\* भगले दस वर्ष तक दोनों व्यापारिक रास्ता पर वाद-विवाद जारी रहा। १८७४ में लेह के ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर फ्रान्स ६० मोलोय ने कुलू रास्ते के मुकाबले में कश्मीर रास्ते का ज्यादा पसंद किया, 'क्योंकि वह ३५ मील कम था और कम से कम साल के नौ महीने चाल रह सकता था, जबकि कुलू का रास्ता छह महीने बन्द रहता था।' मोलोय ने थोड़ा के बजाय ऊँचा के हस्तेमाल की सिफारिश की, क्योंकि इसी भी यही कर रहे हैं और यातायात के खर्च में कमी कर रहे हैं। उसने यह भी शिकायत की कि अंग्रेजी सामान तुर्कों की पसंद का नहीं होता, जबकि इसी सामान "अपनी कम-दमक" और भड़कीले रंगों और बहुत मजबूत होने की वजह से" पसंद किये जाते हैं।\*\*\* मोलोय काशगर के लिए कुगियार के रास्ते को तरजीह देता था, जबकि जलधर डिवीजन के कमिश्नर फोरसाइथ की राय में चांग-चे-मो का रास्ता ज्यादा अच्छा था। शो में भारत और सिबिया के बीच व्यापार की बड़ी रंगीन तस्वीर खींची है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यारकंद ट्रेडिंग कम्पनी की स्थापना की गई।

\* National Archives Pol A, July 1870, Nos 73 76  
D C Boulger, *The Life of Yakoob Beg* London, 1878, pp 214—215

\*\* National Archives Memorandum by Shaw Foreign Department, Sec, July 1876 No 30

\*\*\* National Archives, Pol A May 1874, Nos 37 39, E Molloy to the Secretary, Punjab Government



सिकयाग से व्यापार के लिए उत्साह की यह लहर अनेक "पयवेभणो" का नतीजा थी, जिसका प्रारम्भ १८५५ में हुआ था। छह वर्षों के दौरान भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के सर्वेक्षकों ने अपना काम लदाख और कश्मीर तक फैला दिया था। १८६८ तक इस इलाके के नये नक्शे तैयार कर लिए गये। काशगर में सारेस द्वारा अपनाया गई "अहस्तक्षेप" की सावधानीपूर्ण नीति के बारे में बहुत बात का बताई बनाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कराकुरम के उत्तर की भूमि के बारे में अंग्रेजों का ज्ञान उस समय तक अस्पष्ट था। एकमात्र यूरोपीय जिसके बारे में मालूम था कि उसने कराकुरम को पार किया है, अलेक्सांद्र गाडनर था। उसने इस पहाड़ के रास्ते लदाख में प्रवेश किया था। तीन ग्लाइडवैट बिरादर नं १८५४ और १८५८ के बीच कम्पनी की ओर से इस इलाके की छानबीन की। यारकन्द में अबुल्फ ग्लाइडवैट की हत्या से इस क्षेत्र में प्रवेश करने का यूरोपीय उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। मगर काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ और देशी एजेंटों के हवाले कर दिया गया। देशी एजेंटों का प्रयोग कोई नया नहीं था। मरनाफ्ट ने अपने कर्मचारी भीर इब्जतुल्लाह को १८९२ में काशगर भेजा था।\* १८५२ में अहमद शाह नक्शबंदी और १८५८ में मोहम्मद अमीन को वहां भेजा गया था। जब फत्तान माटगामरी कश्मीर का सर्वेक्षण कर रहा था, तो उसने इस इलाके के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए देशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था। ऐलंडर लिखता है

‘१८६३ से असाधारण व्यक्तियों का ताता लगा हुआ था, जो मिथ्या या सक्षिप्त नाम रखकर, बेस बदलकर और खोखले प्राथना चक्र या दशम की जपमाला लेकर ताकि चरणा की गिनती आसानी से की जा सके, पूरे उत्तर पश्चिम सीमा-क्षेत्र में फैल गये थे।’\*\*

\* *Calcutta Quarterly Oriental Magazine and Register*, III and IV (1825)

\*\* ग० ज० ऐलंडर उपराक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१। देशी "सर्वेक्षकों" के बारे में द० K Mason *Abode of Snow* London 1955



एक आदमी से सरकार"। और अंत में उसने लिखा "और यह बहुत जरूरी कील कुएन लुएन पवतमाला के उस पार आसानी से मिल सकती है।"\*

फोरसाइथ, शो और हेवड ने काशगर से रूसी आक्रमण का होआ खड़ा किया। फोरसाइथ को जब यह अंदाजा हुआ कि पहाड़ी रेगिस्तानी भूमि पर कुछ सौ घोड़सवारों को भी रखना कितना कठिन है, तो उसने अपना विचार बदल दिया। मगर शो और हेवड यह बूढ़ा डर फलाते रहे।

लाड मेयो काशगर को ब्रिटेन के उचित प्रभाव क्षेत्र का भाग मानता था। वह ब्रिटेन के राजनीतिक प्रभुत्व में एक "दरमियानी" राज्य का निर्माण करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था। उसने व्यापार के विकास को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। मेयो ने कश्मीर के प्रति दबदबा रख अपनाया। एक विशेष प्रतिनिधि कप्तान ग्रे को महाराजा से समझौते की बातचीत करने वहाँ भेजा गया। फोरसाइथ ने बाद में (१८७० में) ग्रे की खींची हुई सीमा रेखाओं के अनुसार एक संधि सपन्न की। संधि में तमाम रास्ता का सर्वेक्षण करने की बात थी जिसके बाद उनमें से एक को सभी यात्रियों और व्यापारियों के लिए 'हमेशा के लिए खुला मार्ग' घोषित कर दिया जायेगा। इस मार्ग की देखभाल करने और झगड़े चुकाने के लिए दो जॉइंट कमिश्नर होंगे, हर पक्ष से एक। महाराजा ने यह मान लिया कि कश्मीर होकर जानेवाले सामान पर वह कोई परिवहन कर नहीं लगायेगा। डा० केली को लेह में पहला ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर नियुक्त किया गया।

शो की प्रथम गैरसरकारी काशगर यात्रा के फलस्वरूप याकूब बेग ने १८६६-१८७० के जाड़ों में अपने प्रतिनिधि मिर्जा शादी को भारत भेजा। फोरसाइथ और दल इसी प्रतिनिधि के साथ काशगर गया।\*\* मेयो ने इस दल में किसी सैनिक को शामिल नहीं किया और इस बात से इनकार

\* National Archives Foreign Department, Nov 1868 Pol A, Nos 1-3

\*\* National Archives Sec July 1876 No 30

किया कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है। परन्तु फोरसाइथ को पड़ोसी देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया गया। उसे यह भी कहा गया कि अमीर को अपनी उत्तरी सीमाओं पर आक्रामक कारवाइयाँ करने से मना करें। ब्रिटिश जानते थे कि ऐसा किया गया, तो रूसी काशगर की इट से इट बजा देंगे और इसी के साथ उसपर एक दिन अपना प्रभुत्व कायम करने का अंग्रेजों का स्वप्न भी चूर चूर हो जायेगा। फोरसाइथ की पहली यात्रा असफल रही और उसे अतालीक याने याकूब बेग से मिले बिना ही लौट आना पड़ा। दो सी जानवर, जो उसके दत्त के साथ थे, रास्ते में मर गये।\*

१८७० की फोरसाइथ की यात्रा ने रूसियों को चौकन्ना कर दिया और उन्होंने मुज्जभात दर्रे पर दखल कर लिया। यह देखकर कि याकूब बेग ईली घाटी पर अधिकार करना चाहता है, रूसिया ने १८७१ में उसपर रुकड़ा कर लिया, ताकि वह अंग्रेजों का अधीन राज्य न बनने पाय।

१८७१-१८७२ के जाडों में काशगर का एक और प्रतिनिधि अहरार घान नियुरा भारत आया। वह केवल बाइसराय ही नहीं, महारानी विक्टोरिया के नाम भी पत्र लाया था। १८७२ में रूसी राजनयज्ञ वाउलवास काशगर पहुँचा और उसने बहुत ही लाभदायक व्यापारिक संधि कर ली। १८७३ में सैयद याकूब घान कुस्तुनतुनिया जाते हुए भारत आया। इस बीच लाड मेयो की हत्या हो चुकी थी और उसके म्यान पर लाड नाथब्रुक आ गया था। उसने इसका प्रवचन किया कि सैयद याकूब घान के तुर्की से लौटने पर एक ब्रिटिश मदन उसके साथ जायेगा। कुस्तुनतुनिया में काशगर के प्रतिनिधि ने काशगर्गिया के नये राजतन्त्र को खलीफा के अधिराजत्व में दे दिया। अंग्रेजों ने सब इस्लायवाद और सब तुल्यवाद का प्रयोग अपने रूसी प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध बड़ी चतुराई से किया। उन्होंने अमीर याकूब बेग को तुर्की के सुलतान से गहरा सवध स्थापित करने पर प्रोत्साहित किया। बाद में लाड लिटन के समय, जब निक्ट पूव में त्रिटन और रूस में टक्कर होने की सम्भावना थी, ब्रिटिश कूटनीति

\* National Archives Foreign Department, July 1875, No 30

ने मध्य एशिया में रूस के विरुद्ध इस "मुस्लिम सघ" का प्रयाग करने की तत्परता दिखाई। परन्तु १८७५ में जब काशगर के प्रतिनिधि न फोरसाइथ और ब्रिटिश विदेश मंत्री से मेट के दौरान अफगानिस्तान से मंत्रीपूर्ण सवध स्थापित का सवाल उठाया, तो उसे चेताया गया कि ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि इससे रूस नाराज हो जायेगा।\* परन्तु दरअसल अंग्रेजों का इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय मोरचे के नतीजा का डर था, क्योंकि उनके अपने साम्राज्य में मुसलमान प्रजा की बड़ी सख्या थी।

फोरसाइथ के नेतृत्व में एक मडल १८७३ में काशगर भेजा गया और उसे १८७२ की रूसी सधि, के समरूप व्यापार सधि करने का आदेश दिया गया। सदा की तरह इस दूसरे फोरसाइथ मडल का प्रत्यक्ष उद्देश्य व्यापार था, मगर असल में वह इससे व्यापक था। याकूब बेग के रात को ब्रिटिश नीति की परिधि में ले आना था और उसे रूस और चान के विरुद्ध ब्रिटिश आक्रमण का झुंड बनाना था। अंग्रेजों को कोकान की अव्यवस्था का ज्ञान था और वे इस बात से कि याकूब बेग कोकान का रहनवाला था, फायदा उठाना और उसको कठपुतली बनाकर उस इलाक में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मडल में जिस तरह के लोग रखे गये, उनका उसके घोषित उद्देश्य—व्यापारिक सवधों को प्रोत्साहित करने से कोई लगाव नहीं था। इसमें गुप्तचर अधिकारी और स्थलरूपरेखीय विभाग के छिपे एजेंट थे। इस मडल के सदस्या में सेना के कप्तान बिडडुर्फ, कप्तान चैपमैन, कप्तान ट्राटर और लेफ्टिनेंट कनल गाडन थे। एक वैज्ञानिक डा० स्टोलिच्का और एक चिकित्सक डा० बेलो और इनके अलावा अनेक दली अधिकारी और चाकर थे। सब मिलाकर ३०० व्यक्ति और ४०० जानवर थे। यह छोटी-सी सेना लगती थी। ब्रिटिश मडल के सदस्या का काशगर के अमीर ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया और तीन महीने से अधिक उनका अतिथि सत्कार किया। २ फरवरी, १८७४ को अमीर के साथ एक सधि सम्पन्न की गई, जो अंग्रेजों के लिए उतनी ही लाभदायक थी जितनी १८७२ की सधि रूस के लिए थी। इसके अनुसार

ब्रिटिश प्रजा को अपरदेशीय अधिकार मिल गये और अंग्रेजों को अमीर के दरबार में एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। इस मंडल ने सिक्काग तथा पड़ोसी देशों की स्थिति, साधन, इतिहास, भूगोल और व्यापार के संबंध में बहुत बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा की। लेफ्टिनेंट-कमल गाडन ने तियान शान पठार की यात्रा की, कप्तान टाटर और डा० स्टालिच्का ने तक्ले रेबात दर्रे के रास्ते का और रूसी इलाके में गदुर-कल झील का सर्वेक्षण किया। काउफमन ने रूसी युद्ध मंत्री मित्यूतिन को फोरसाइथ मंडल के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में लिखा। ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे पता चलता है कि १८७३ में कोकान पर रूसी कब्जे का कारण काशगर आधारित ब्रिटिश षडयंत्र का भय था। कोकान पर रूसियों का कब्जा हो जाने से सैनिक दृष्टि से काशगर रूस का आश्रित हो गया।

फोरसाइथ का दल जो सूचना लाया, उससे सिक्काग का व्यापारिक महत्व सन्देहजनक हो गया। मंडल ने पामीर के पार और सुगम दरों के रास्ते हुआ, यासिन और चित्तल तक रूस के बंद आने के खतरे की ओर सचेत किया। पामीर के बारे में गाडन की रिपोर्ट ने काशगर को एक नई सामारिक रोशनी में पेश किया कि वह "और अधिक पश्चिमी बड़ाव के बाज में समुद्र सप्लाई-केन्द्र है"।

फोरसाइथ को भारत से "काशगर राज की राजनीतिक सीमाएं निश्चित करने" का आदेश दिया गया था, मगर उसने पाया कि "यह कोई आसान काम नहीं है", क्योंकि स्वयं अमीर को भी इन सीमाओं का पता नहीं था। फोरसाइथ ने अपनी रिपोर्ट में उनका निर्धारण इस तरह किया

"दक्षिण-पूर्वी कोने से शुरू होने पर इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि कुएन लुएन पर्वतमाला यारकन्द का इलाका है और हमेशा रहा है, और चकि निचली कराकाश घाटी में नेफाइट की खान में चीनी गत १५० वर्षों से बाम करते आये हैं, इसलिए मान लिया जा सकता है कि घाटी ही सीमा है जहां तक मैं स्वयं यारकन्दियों से पता लगा सका, कराकाश नदी के दक्षिण में किसी इलाके पर दावा नहीं किया जाता, और यारकन्द

नदी पर वे कूफीलोग से आगे नहीं जाते। परन्तु सुविधा के लिए मैं सामा को आक-तांग पर निर्धारित करूंगा। और अपना सामान ले जाने में मन व्यवहार में उसी को अपना अंतिम बिंदु बनाया। तो रेखा कुएन लैन के पूर्वी कोने (भोगाश ८१) से नीचे, कराकाश नदी तक (भोगाश लगभग ७८ ५, अक्षांश ३५ ५६) जायेगी, वहां से यारकंद नदी के रास्ते कुजुत तक। कुजुत यारकंद के इलाके से बाहर है।”\*

१८७६ में साइ नाथशुक की जगह साइ लिटन को वाइसरॉय नियुक्त किया गया। नाथशुक के शासन काल में “काशगर में ब्रिटिश प्रभाव उच्चतम शिखर” पर पहुंच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ की संधि है। परन्तु लिटन इससे सतुष्ट नहीं था। सितम्बर १८७६ में उसने अपनी नई काशगर नीति रेखांकित की। जब मैयद याकूब खान दूसरी बार भारत आया, तो लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह से मधोपुर में एक समझौते के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके अनुसार उसे अपने इलाके को यासिन तक विस्तारित करना और गिलगित में एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति का अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिन्हें फोरसाइथ मंडल के सदस्यों ने “सुगम” बताया था, ब्रिटिश नियंत्रण विस्तारित करने की अपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान बिड्डुल्फ ने इन दरों के सुगम होने के बारे में अपनी पहली राय बदल दी थी। जब लिटन को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमें से एक तयार्कथित सुगम दर्रा बंद हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निराशा” हुई। ऐलंडर ने कहा “आश्चर्यजनक प्रतिन्या है, अगर उन दर्रा तक कश्मीर के और इसलिए ब्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षात्मक था”\*\* १८७७ के प्रारम्भ में लिटन ने निजी रूप से सुझाव दिया कि रूस से कहा जाये कि “वह पलूचिस्तान और

\* National Archives Confidential Report Yarkand Mission Aug 1875 Sec, No 68

\*\* ग० ज० ऐलंडर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६१।

भारत और मध्य एशिया १४३

काशगर और अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप या हम से प्रतियोगिता नहीं करे”।

ब्रिटिश प्रतिनिधि भेजने के फैसले को औपचारिक अनुमति अप्रैल १८७७ तक नहीं मिली। इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से शो चुना गया जो जुलाई में भारत जाने की तैयारी कर रहा था। इस निश्चय को अनुमति देने में हिचकिचाहट का कारण किसी हद तक यह था कि शो १८७४ की संधि का अनुसमयन प्राप्त करने में असफल रहा था। याकूब बेग १८७४ की संधि की धारा ६ को, जिसका सबंध स्थायी प्रतिनिधि से था उस समय तक अमली रूप नहीं देना चाहता था जब तक तुर्की के सुलतान की अनुमति न मिल जाये। वह इस को नाराज करना नहीं चाहता था और डरता था कि वह भी अपने लिए ऐसी मांग करेगा। जब जुलाई १८७४ में शो को वापस लौटने का आदेश मिला, तो वह अपने साथ एक पत्र लाया जिसपर अमीर की मोहर थी। मगर शो जिस कागज को अनुसमयन की दस्तावेज समझ रहा था, वह वाइसराय के नाम केवल धमकाव का पत्र निकला।

अंग्रेजों को विश्वास था कि काशगर में याकूब बेग का शासन स्थायी रहगा। उन्हें विश्वास था कि चीनियों की यह स्थिति नहीं कि सिक्किम पर पुन अधिकार कर सकें। केवल १८७६ में ही पेकिंग स्थित ब्रिटिश मंत्री को विश्वास हुआ कि चीनी वास्तव में सिक्किम को अपने अधिकार में लाने की बात गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। सेट पीट्सबर्ग में अंग्रेज और रूसी मिलकर लांड भागस्टस लाफटस की राय थी कि अंग्रेज और रूसी मिलकर मध्यस्थता का प्रयास करें। परन्तु पेकिंग में टामस वेड ने इसका विरोध किया। उसने अकेले यह पहलकदमी ली। अंग्रेज मचू सन्नाटो को ऋण देने के बावजूद याकूब बेग की सत्ता को बचाये रखना चाहते थे, जो उनके प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उस और मच सरकार में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया।

१८७६ में फोरसाइथ पेकिंग गया और काशगर और चीन में मध्यस्थता कराने में भाग लिया। टामस वेड पहले ही से पेकिंग में चीनियों के साथ यह सवाल उठा रहा था। उसके प्रयत्न से ली-टुंग चांग और फोरसाइथ



नदी पर वे कफीलोग से आगे नहीं जाते। परन्तु सुविधा के लिए मैं सीमा को आक-ताग पर निर्धारित करूँगा। और अपना सामान ले जाने में मन व्यवहार में उसी को अपना अंतिम बिन्दु बनाया। तो रेखा कुएन-लुएन के पूर्वी कोने (भोगाश ८१) से नीचे, कराकाश नदी तक (भोगाश लगभग ७८ ५, अक्षांश ३५ ५६) जायेगी, वहाँ से यारकंद नदी के रास्ते कुजुत तक। कुजुत यारकंद के इलाके से बाहर है।”\*

१८७६ में लाड नाथबुक् की जगह लाड लिटन को वाइसराय नियुक्त किया गया। नाथबुक् के शासन काल में “काशगढ़ में ब्रिटिश प्रभाव उच्चतम शिखर” पर पहुँच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ की संधि है। परन्तु लिटन इससे सतुष्ट नहीं था। सितम्बर १८७६ में उसने अपनी नई काशगढ़ नीति रेखांकित की। जब सैयद याकूब खान दूसरी बार भारत आया, तो लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह से मधोपुर में एक समझौते के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके अनुसार उसे अपने इलाके को यासिन तक विस्तारित करना और गिलगित में एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति की अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिन्हें फोरसाइथ मन्त्र के सदस्यों ने “सुगम” बताया था, ब्रिटिश नियंत्रण विस्तारित करने की अपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान विडहुल्फ ने इन दरों के सुगम होने के बारे में अपनी पहली राय बदल दी थी। जब लिटन को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमें से एक तथाकथित सुगम दरें बंद हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निराशा” हुई। ऐलंडर ने कहा “आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है, अगर उन दरों तक कश्मीर के और इसलिए ब्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षात्मक था”\*\* १८७७ के प्रारम्भ में लिटन ने निजी रूप से सुझाव दिया कि रूस से कहा जाये कि ‘वह बलूचिस्तान और

\* National Archives Confidential Report, Yarkand Mission, Aug 1875, Sec No 68

\*\* ग० ज० ऐलंडर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ६१।

काशगर और अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप या हम से प्रतियोगिता नहीं करे"।

ब्रिटिश प्रतिनिधि भेजने के फैसले को औपचारिक अनुमति अग्रैल १८७७ तक नहीं मिली। इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से शो चुना गया, जो जुलाई में भारत जान की तैयारी कर रहा था। इस निश्चय को अनुमति देने में हिचकिचाहट का कारण किसी हद तक यह था कि शो १८७४ की संधि का अनुसमर्थन प्राप्त करने में असफल रहा था। याकूब १८७४ की संधि की धारा ६ को, जिसका सबंध स्थायी प्रतिनिधि से उस समय तक झगली रूप नहीं देना चाहता था जब तक तुर्की के उत्तान की अनुमति न मिल जाये। वह इस को नाराज करना नहीं चाहता था और डरता था कि वह भी अपने लिए ऐसी भाग करेगा। जब जुलाई १८७५ में शो को वापस लौटने का आदेश मिला, तो वह अपने साथ एक पत्र लाया जिसपर अमीर की मोहर थी। मगर शो जिस कारण को अनुसमर्थन की दस्तावेज समझ रहा था, वह वाइसराय के नाम केवल धन्यवाद का पत्र निकला।

अंग्रेजों को विश्वास था कि काशगर में याकूब बेग का शासन स्थायी रहेगा। उन्हें विश्वास था कि चीनिया की यह स्थिति नहीं कि सिक्किम पर पुन अधिकार कर सक। केवल १८७६ में ही पेकिंग स्थित ब्रिटिश मंत्री को विश्वास हुआ कि चीनी वास्तव में सिक्किम को अपने अधिकार में लाने की बात गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। सट पीटसबग में ब्रिटिश राजदूत लार्ड प्रागस्टस लाफटस की राय थी कि अंग्रेज और रूसी मिलकर मध्यस्थता का प्रयास करें। परन्तु पेकिंग में टामस वेड ने इसका विरोध किया। उसने अकेले यह पहलकदमी की। अंग्रेज मचू सभ्राटों को श्रृण्व देने के बावजूद याकूब बेग की सत्ता को बचाये रखना चाहते थे जो उनके प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उस और मचू सरकार में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया।

१८७६ में फोरसाइथ पेकिंग गया और काशगर और चीन में मध्यस्थता करने में भाग लिया। टामस वेड पहले ही से पेकिंग में चीनियों के साथ यह मवाल उठा रहा था। उसके प्रयत्न से ली-टुंग चांग और फारसाइथ

तथा मेयस का सम्मेलन आयोजित किया गया। ली-हुग चांग ने यात्रा वेग द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण और चीनियों की अधीनता स्वीकार करने पर जोर दिया। यह पूछे जाने पर कि काशगर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि का स्वागत पेकिंग में किस प्रकार किया जायेगा, ली-हुग चांग ने उत्तर दिया कि काशगर के मामले का सारा प्रबंध जनरल त्सो-त्सुंग तांग के जिम्मे कर दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे भारत के सारे मामले वाइसराय के जिम्मे हैं, और याकूब बेग को जनरल त्सो से बात करना चाहिए।\*

परंतु याकूब बेग और चीनियों में सफलतापूर्वक निवटारे का आशा फिर जाग उठी जब पेकिंग में ब्रिटिश अस्थायी कायदूत ने सर्वोच्च समिति में काशगरिया के विरुद्ध सैनिक कारवाइयों पर विचार विमर्श में मनमानी की रिपोर्ट भेजी।\*\* १८७७ के पूरे साल पेकिंग में ब्रिटिश अस्थायी कायदूत काशगर के मुकाबले में चीनिया के कदम पीछे हटाने की बात लिखता रहा। कैनटन के वाइसराय से सर ब्रूक राबटसन की बातचीत के स्मृतिपत्र से पता चलता था कि ली-हुग चांग ने फौरनसाइथ से अपनी बातों में याकूब बेग द्वारा अधीनता स्वीकार करने की जा मांग की थी, उसे भ्रम बना दिया गया है। नया प्रस्ताव यह था कि काशगर का चीन से संबंध बढ़ी होना चाहिए, जो नेपाल और बर्मा का है।\*\*\* यह सुनने पर वाइसराय लार्ड लिटन ने भारत के लिए सेनेटरी आफ स्टेट लार्ड सोरसबेरी को १६ जुलाई, १८७७ को लिखा

“अगर कैनटन के गवर्नर द्वारा काशगरिया के बारे में सर बी० राबटसन से प्रकट किये गये विचार किसी प्रकार भी चीनी सरकार के विचारों का प्रतिबिम्बित करते हैं, तो हमारी राय है कि वे पूर्व में ब्रिटिश हितों के अनुकूल हैं और हमें विश्वास है कि इंग्लैंड में यारकंद के प्रतिनिधि

---

\* National Archives Foreign Department Sec, Jan 1877  
No 120

\*\* वही, अक्टूबर १८७७ अथ १९३।

\*\*\* वही, अथ १९५ १९७।

- की उपस्थिति से हर मजिस्टी की सरकार को उस समझौते को प्रोत्साहित करने का मौका मिल सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप में चीनी सरकार को लाभ दे
- से करना चाहती है।\*\*

लाड सोल्सबेरी ने सैयद याकूब खान से भेंट की, जो उन दिनों लंदन में था। अब कारवाई का क्षेत्र पेकिंग से लंदन आ गया और लाड डरवी, लाड सोल्सबेरी और टामस वेड ने चीनी राजदूत की सेवाय सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया। वे इसमें सफल हुए और जुलाई १८७७ को टामस वेड के घर पर चीनी राजदूत और अमीर के विशेष प्रतिनिधि में भेंट का प्रबंध किया गया। मगर उसी दिन काशगर के अमीर याकूब बेग के मरने का समाचार आया और काशगर और चीन में समझौता कराने के इन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकला।\*\* चीनियों ने दिसम्बर १८७७ में काशगर पर कब्जा कर लिया।

मजबूर होकर भारत सरकार को शो की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इस बीच नये शासक बेग कुली बेग ने ब्रिटिश प्रतिनिधि के आग्रह की इच्छा प्रकट की। लेह में ब्रिटिश जाइंट कमिशनर ने इलियास ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश प्रतिनिधि काशगर भेजा जाये ताकि चीनिया से सम्मानपूर्ण समझौता करने में नये शासक को ब्रिटिश नैतिक समर्थन प्राप्त हो।

लाड लिटन ने इस सुझाव को स्वीकार करने का समय दिया। स्थायी प्रतिनिधि के लिए लंदन की अनुमति प्राप्त करने से पहले उसने इलियास को काशगर जाने की आज्ञा दे दी। इलियास काशगर के लिए रवाना हुआ, मगर वह वहाँ पहुँचा नहीं क्योंकि बेग कुली बेग राज छोड़कर भाग चुका था। चीनिया के लीड आने के बाद कुछ दिनों तक शक्ति-संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में रहा। ईली घाटी को वापस लेने का सवाल उठ गया था जिसपर

\*वही अंक १६७।

\*\*वही, अंक २१६-२२५।

रूसिया ने १८७१ में इस शर्त पर कब्जा किया था कि उस इलाक में स्थिति सामान्य हो जाने के बाद उसे लौटा दिया जायेगा। आठ महीने की कड़ी सौदेबाजी के बाद लिवादिया में जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए, उसे चीनी वैदेशिक कार्यालय ने अस्वीकार कर दिया और चीनी रूसी सबंध, जिनमें पहले ही तनाव पैदा हो चुका था, बहुत खराब हो गये। लगता था कि युद्ध होनेवाला है, मगर फरवरी १८८१ में सेंट पीटर्सबर्ग की संधि की बदौलत वह टल गया और संकट का अंत हो गया।

१८७८-१८८१ की अवधि में, जब चीनी रूसी सबंध खराब हो गये थे, अंग्रेजों ने इससे फायदा उठाकर सिक्यांग में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। सिक्यांग से उनका व्यापार १८७६-१८८० में बराबर बहाल होता गया और १८८१ में वह १८७६ के उच्च स्तर पर पहुंच गया था।\* भारतीय चाम पर चीनियों का प्रतिवध कारगर नहीं था। एक अंग्रेज व्यापारी एंड्रस डालगीश ने काफी मुनाफा कमाया। इसके विपरीत चीनी रूसी व्यापार का दोनों शक्तियों के तनाव से बड़ा धक्का पहुंचा। इलियास जिस १८८० में यारकंद में वापस भेज दिया गया था, यारकंद के गवर्नर से मिला और ऐसी "व्यवस्था" पर जोर दिया जिसमें "ब्रिटिश और चानिया के बीच रूसिया के कायबत्ताप के बारे में गुप्त सूचना का आदान प्रदान किया जा सके"।\*\* पेकिंग में चीनी वैदेशिक कार्यालय ने काशगर में अंग्रेजी उपदूतावास खोलने तथा व्यापार का नियंत्रण करने के लिए करारनामे क ब्रिटिश अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। परन्तु उसने ब्रिटिश एजेंटों को सिक्यांग में यात्रा करने की आज्ञा दे दी। यात्रा की इन सुविधायों से फायदा उठाकर डालगीश सिक्यांग के अपने व्यापक धौरे पर खाना हुआ। परन्तु स्थानीय चीनी अधिकारियों की धार से उसे बहुतरी बाधाओं का सामना करना पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग की संधि से भारतीय व्यापार को, जो कुछ दिना से बढ़ गया था, १८८१

\* ग० ज० ऐलडर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ७७।

\*\* वही।



मे, जो १८८४ मे तैयार की गई थी, यह प्रबन्ध था कि मध्य एशिया के खान प्रशासित प्रदेशों और तुर्कमानिस्तान में गड़बड़ कराने के लिए ग्रामों भेजे जायें। यह बात दिलचस्प है कि इस योजना में "चीन से तुल्य पुनर्मात्री" करने पर जोर दिया गया था।\* रिपन को आन्तर्गत वार्षिक नीति के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करना वास्तविक तथ्यों पर परदा डालना है। अफगानिस्तान में उसने जो समझौता कराया, वह इस मान में "रूढ़िवादी समझौता" था कि वह गडामक संधि के "बहुत निकट" था। यह भी रिपन ही के शासन काल की बात थी कि अफगान सरकार ने अंग्रेजों के दबाव से १८८३ में रुशान और शुगनान पर कब्जा कर लिया और यह बात अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के संबंध में ब्रिटिश और रूस के १८७३ के समझौते के विपरीत थी।

लाड डफरिन (१८८४-१८८८) ने एक व्यापारिक करारनामा और सिक्याग में उपद्रुतावास खुलवाने का निश्चय किया। उसने काशगर में एक मंडल भेजने का निणय किया। चीनी वैदेशिक कार्यालय ने इलियास से बातचीत करने अपना प्रतिनिधि भेजने से यह कहकर इनकार कर दिया कि ब्रिटिश भारत व्यापार कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि इसके लिए विशेष व्यापार करारनामा किया जाय। चीनिया ने इलियास से अनमनीपूर्ण व्यवहार किया और उसने इस असफलता के लिए पेकिंग में ब्रिटिश अस्थायी वायदूत आर्कोनोर पर दोष मढ़ा। भारत से एक व्यापार उपसंधि का मसवदा आर्कोनोर के पास भेजा गया था। परंतु पेकिंग में चीनी अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और चीन के साथ संबंधों में अनेक उलझन पैदा होते रहे जैसे तिब्बत का व्यापार, बर्मा का झगड़ा, सिक्किम का वार्तालाप, आदि। ओरानार ने सिययाग के शहरों में टियेंटसिन की संधि की सबसे अनुगृहीत राष्ट्र की

\*मनमगर, "भारत की सुरक्षा", भाग १- 'एशिया विषयक भौगोलिक, स्थलरूपपरणीय तथा सांख्यिकीय सामग्रिया का संग्रह', अं ४३, सेंट पीटर्सबर्ग, १८९१, पृष्ठ २०७, खालफिन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३६७।

धारा के आधार पर अंग्रेजों के लिए उपद्रुतावासीय अधिकारों की मांग की। परन्तु चीनियों को इससे पहले काशगर में रूसी उपद्रुत का बहुत कटु अनुभव हो चुका था (रूसी उपद्रुत पेत्रोव्स्की ने उससे अधिक राजनीतिक प्रभाव कायम कर लिया था जितना चीनी देना चाहते थे)। अतः अब वे कोई और उपद्रुत नहीं चाहते थे। उपद्रुतीय प्रतिनिधि की अंग्रेजों की मांग को बदलकर राजनीतिक एजेंसी की मांग कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश भारत व्यापार बहुत कम हो गया था। ब्रिटिश भारत सरकार पेकिंग में वालशम को कुरेदनी रही कि वह इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय पर दबाव डाले, परन्तु चीनियों के हठ के कारण इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

१८६१ में ब्रिटिश भारत सरकार ने मकाटनी को सिक्क्यांग में अनिश्चित काल तक रखने का निश्चय किया, अगरचे चीनियों द्वारा उसे कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसने अंग्रेजों की अच्छी सेवा की। चीनियों से वह उनका "सम्पर्क" कायम रखनेवाला व्यक्ति भी था और रूसिया पर निगाह रखनेवाला उनका गुप्तचर एजेंट भी। १८६१ में हुआ पर अंग्रेजों के कब्जे से चीनी नाराज हो गये। उनका दावा था कि उसके शासक उन्हें नजराना दिया करते थे और इसलिए उसपर उनका कभी का अस्पष्ट अधिराजत्व का अधिकार था।

१८६३-१८६५ की अवधि में लद्दन चीनिया की मैत्री बनाये रखना चाहता था ताकि पामीर के विरुद्ध आक्रामक कारवाइया कर सके। भारत को रूस के "खतरे" का पुराना बहाना बनाकर अंग्रेज इस इलाके सैन्य घुसपैठ की नीति पर अमल कर रहे थे। इसलिए अब वे काशगर उपद्रुतावास की मांग पर जोर देना नहीं चाहते थे। अधिक व्यापक साम्राज्यवादी नीति के हित में अंग्रेजों ने १८६३ में चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनायी। इसका उद्देश्य यह था कि वे चीनी सागर तट पर तथा प्रधान भूमि के कुछ इलाका में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे जिन्हें उन्होंने चीन के मजबूत शासकों के साथ अनमन संधियां करके अर्द्ध-औपनिवेशिक पराधीनता की स्थिति में पहुँचा दिया था। जनवरी १८६३ में भारत सरकार ने इंग्लैंड में अपनी सरकार को सूचना दी कि चीनी



अधिकारियों ने कराकुरम दर्रे पर सीमा चिह्न लगा दिए हैं।\* पेकिंग में आ'कोनोर ने इस मामले में चीनी रवैये पर किसी आपत्ति का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उसका समयन किया। विदेश मंत्री लाड किम्बरलाने सुझाव दिया

“पेकिंग में चीनी सरकार को उन रिपोर्टों के सारतत्व की सूचना दे देनी चाहिए, जो हर मैजिस्ट्री की सरकार को प्राप्त हुई है और वह बता देना चाहिए कि कश्मीर राज्य की ओर से भारतीय अधिकार काशगरिया में चीनी अधिकारियों के साथ तोह से काशगर तक की सड़क पर सीमा निर्धारण करने में सहप सहयोग करेंगे। परंतु इस सड़क पर काशगरी अधिकारियों द्वारा लदाख राज्य के सीमा निर्धारण का कोई प्रयास हर मैजिस्ट्री की सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया, तो वह एना नहीं करने देगी।”\*\*

आ'कोनोर को पता लगा कि पेकिंग के सरकारी क्षेत्रों में “पानीर में रूस की आनामक नीति” के कारण लांग “खीजे” हुए हैं और इसलिए उसने कराकुरम में चीनियों द्वारा चिह्न लगाने का विरोध नहीं करने का सलाह दी।

यद्यपि वर्तमान पेकिंग शासक भारत को दोष देते नहीं थकते कि उनका ब्रिटिश साम्राज्यवादिया द्वारा एकपक्षीय तौर पर स्थापित सीमाएं विरासत में मिली हैं, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि अंग्रेजा ने हमेशा ऐसा रख नहीं अपनाया, जो भारत के हिता के अनुकूल हो। इसकी एक मिसाल अन्नामई चीन के मामले में अंग्रेजा की गड़बड़ है। काशगर में ब्रिटिश प्रतिनिधि मजादती ने दिसम्बर १८६५ में चीनी प्रांतीय गवर्नर को कुछ पुस्तक और गणितीय यंत्र भेंट किए। गवर्नर ने काशगर के ताम्रो-साई से आग्रह किया कि वह उसकी ओर से इन चीजा के लिए धन्यवाद दे दे। इन पुस्तक

\* National Archives Foreign Department, K W Sec F, April 1888 Nos 282—283

\*\* National Archives Foreign Department, Enclosures to 1894, Aug, Sec F Nos 26—33



## सोवियत सत्ता की स्थापना

### प्रारम्भिक सोवियत आजाप्तियाँ

सोवियत सभ ने अपनी प्राथमिक आजाप्तियों में से एक—“शांति के बारे में आजाप्ति” में अपनी वैदेशिक नीति के एक मौलिक सिद्धान्त के रूप में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की। आगे चलकर इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति रूसी सभ तथा अन्य सोवियत जनतवा की आय अनेक आजाप्तियाँ (‘रूस की जनताओं के अधिकारों का घोषणापत्र’, “मेहनतकश और शोषित जनता के अधिकारों का घोषणापत्र”, “रूस और पूर्व के मेहनतकश मुसलमानों के नाम जन कमिसार परिषद की अपील”, अनेक राजनयिक नोट, वक्तव्य आदि) में हुई।

“शांति के बारे में आजाप्ति”, जो लेनिन द्वारा लिखी गई थी, महान अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक असाधारण दस्तावेज़ है। इसने समस्त जातियों और राष्ट्रों के अधिकारों की समानता के आधार पर “यायोचित और जनवादी शांति की स्थापना की भाग की। इसने वैदेशिक भूमि पर सभी कब्जों की निंदा की। आजाप्ति ने न केवल राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का निरूपण किया बल्कि इस बात की विस्तारपूर्वक व्याख्या भी की कि कब्जा करना क्या होता है। आजाप्ति में कहा गया “जब भी कोई छोटा या कमजोर राष्ट्र उस राष्ट्र की सुस्पष्ट शब्दों में, साफ-साफ तथा स्वेच्छापूर्वक व्यक्त की गयी अनुमति या इच्छा के बिना किसी बड़े

या शक्तिशाली राज्य में शामिल कर लिया जाता है, ता इस बात का कोई लिहाज बिये बगैर कि इस प्रकार बलात कब्जा किस समय किया गया या इस बात का कोई लिहाज किये बगैर कि वह राष्ट्र, जिसे किमा हमारे राज्य में बलात शामिल कर लिया गया है या जिसे जबरदस्ती किमा दूसरे राज्य की सीमाओं के भीतर रखा जा रहा है, कितना उन्नत या पिछड़ा हुआ है और अतः में इस बात का कोई लिहाज किये बगैर कि वह राष्ट्र, जिस पर अधिकार किया गया है, यूरोप में है या समुद्र-पार का कोई सुदूर देश है, यह सरकार उसे आम तौर से पूरे जनवाद और खास तौर से मेहनतकश जनता की 'यायमावा' के अनुरूप सजाजन या कब्जा समझती है। '•

आज्ञप्ति के इस भाग में आत्मनिर्णय के सिद्धांत के सार, अतः और काय-क्षेत्र की व्याख्या की गई है। आज्ञप्ति ने घोषणा की कि यह मित्रान न केवल श्रमजीवी जनगण के 'याय-बोध' के, बल्कि "आम तौर पर जनवादिया के 'याय-बाध' के अनुकूल है। वास्तव में आत्मनिर्णय का नारा पूजीवादी-जनवादी कायन्म का अंग था। आज्ञप्ति से यह भी नतीजा निकलता था कि किसी राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना बनाकर उसे अपने मामलों का प्रबंध करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज्ञप्ति ने उपनिवेशवादिया के इन दावा पर निर्णायक प्रहार किया कि उन्होंने अथ राष्ट्रों का अपनी गुलामी में इसलिए लिया है कि उनमें अपना प्रशासन स्थापित करने की क्षमता नहीं थी।

"शांति के बारे में आज्ञप्ति" न जहाँ राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की घोषणा मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में की बल्कि हमका "मेहनतकश और शोषित जनता के अधिकारों का घोषणापत्र" में सावियन राज्य के राष्ट्रीय विकास के सिद्धांत के रूप में किया गया। "इस का जनताओं के अधिकारों के घोषणापत्र" में कहा गया था कि सावियन

1 वाग्रेस से सम्बोधन किया, "उलेमा" की वाग्रेस थी जिसे मुसलमान मेहनतकशा के नाम पर बालन का कोई अधिभार नहीं।\* रहीमनायेव ने घोषणा की कि मुसलमान मजदूर रूसी मजदूरों का साथ दोगे। कई दिना की लम्बी बहस के बाद सोवियतों की तीसरी वाग्रेस न पूजीपतियों और पूजीवादी राष्ट्रवादियों के साथ सत्ता में शरीक हान के लिए मजबूत कर दिया। बोल्शेविकों और "परवाग्राहकों" द्वारा प्रस्तावित अस्थायी कर दिया। बोल्शेविकों और "परवाग्राहकों" द्वारा प्रस्तावित घापणापत्र ने तुकिस्तान में सोवियत सत्ता की विजय का एलान किया और यतमान केन्द्रीय सत्ता और उससे सगठन के रूपों को स्वीकार किया। उसने स्पष्टतः "मुसलमानों" (यानी पूजीवादी राष्ट्रवादियों और प्रतिस्पर्धावादी धर्मविलम्बियों) और समवातावादी रूसियों के साथ सत्ता में शरीक होने से इनकार कर दिया जो अस्थायी सरकार का समर्थन करते, प्राप्ति के विरुद्ध लड़ते तथा प्रातिकारी जनवाद से विश्वासघात करते थे।\*\*

इस प्रकार सोवियतों की तीसरी क्षेत्रीय वाग्रेस ने तुकिस्तान में सत्ता के सगठन के महत्वपूर्ण सवाल को प्रातिकारी ढंग से हल किया। इसकी अवसर यह आलोचना की गई है कि उसने स्वायत्त शासन की समस्या को नजरअन्दाज किया और सत्ता की उच्चतर सत्ताओं में मुसलमानों की शिरकत के बारे में नकारात्मक खयाल अपनाया। परन्तु वाग्रेस की कारवाई की अगर पूरी छानबीन की जाये, तो इस आलोचना का कोई आधार नहीं रह जाता।

जब १५-२२ नवम्बर, १९१७ की वाग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस समय तुकिस्तान के क्षेत्र का केवल एक छोटा भाग सोवियत नियन्त्रण में था। ताशकन्द के अलावा यह फरगाना और समरकन्द इलाकों के केवल बड़े शहरों तक सीमित था। जेतीसुव और अधिकांश ट्रांसकास्पियन इलाका

\* "नाशा गजेता"

तुकिस्तानस्कीये बन्नेमोस्ती" अथ १३३, २३ नवम्बर, १९१७ और

\*\* नाशा गजता, अथ १३३, २३ नवम्बर, १९१७।

अभी तक अस्थायी सरकार की सस्थाओं तथा पूजीवादी राष्ट्रवादी समितियों के हाथों में था। ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः समाजवादी क्रांति तथा सत्ता के क्रांतिकारी संगठन के सवाल को कांग्रेस की कार्य-सूची में स्वायत्त शासन के सवाल के मुकाबले में प्राथमिकता प्राप्त थी।

तीसरी कांग्रेस में बोल्शेविकों और "पराकाष्ठावादियों" के घोषणापत्र की तीव्र आलोचना इसलिए भी की गई है कि उसने मुसलमानों को क्रांतिकारी सत्ता की उच्चतम सस्थाओं से अलग रखा। मुसलमानों को अलग रखने तथा सोवियत सत्ता के प्रति उनके रवैये की अनिश्चितता का उल्लेख किसी हद तक भ्रामक है। इतना तो मानना ही पड़गा कि घोषणापत्र के इस भाग की शब्दावली ठीक नहीं है और इसमें आलोचना की अनेक गलतियाँ हैं। परन्तु अगर घोषणापत्र को उसकी पूर्णता में लिया जाये और उसे पूजीवादी राष्ट्रवादियों की इस भाग के प्रसंग में पढ़ा जाय कि मजदूर महान कुर्बानियों के बाद हासिल की हुई सत्ता का छाड़ दें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि "मुसलमान" शब्द वर्गीय अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। घोषणापत्र ने सत्ता की सस्थाओं से मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि रूसी समूह के उन प्रतिनिधियों को भी अलग रखा, जो क्रांति के विरुद्ध लड़े थे। अगर घोषणापत्र को पूरा पढ़ा जाये, तो उसका लेखक का आशय साफ हो जाता है। उसमें जोर दिया गया था कि "सक्रिय सार्वजनिक काम में हिस्सा लेने से व्यापक जनता को अलग नहीं रखना है और स्थानीय प्रतिनिधियों को लेकर जिसस मुसलमान अलग नहीं किये जायेंगे, सोवियतों की कांग्रेस" आयोजित की जायेंगी, ताकि अथनत्र और राजकीय ढाँचे के सवाल पर विचार किया जाये।\* इस अंतिम शब्द से ये

"इस प्रकार न तो स्थानीय आजादी और न स्थानीय बुद्धिजातियों का इस क्षेत्र के जीवन के सुधार के लिए सक्रिय काम करने के अवसर से वंचित किया जाता है। इसके विपरीत इस काम के लिए उनका बल स्वागत किया जाता है।" \*\*

\* पूरा या पूरा घोषणापत्र 'गंगा गङ्गा' में २३ नवम्बर, १९१७ में प्रकाशित किया गया था।

\*\* वही।

सोवियतों की तीसरी कांग्रेस ने तुर्किस्तान की सरकार की उच्च सत्ता के रूप में १८ सदस्यों की जन-समिति परियोजना स्थापित की। सोवियत कृतियाँ में भी इस बात की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि कांग्रेस ने जन-समिति परियोजना में तीन स्थान मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित कर दिये थे। 'नाशा गजेता' के २३ नवम्बर, १९१७ के अंक में जन-समिति परियोजना में मुसलमान मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का स्पष्ट उल्लेख है।\* इसकी पुष्टि हमें पुनः २५ जनवरी, १९१८ की सोवियतों की चौथी क्षेत्रीय कांग्रेस में बोल्शेविक दल के नेता तोलोत्किन के भाषण में मिलती है।\*\* तातोल्किन ने कहा था कि जन-समिति परियोजना में १८ सदस्य होंगे। १५ सदस्यों का निर्वाचन सोवियतों की तीसरी कांग्रेस कर चुकी है और तीन स्थान मुसलमान मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए खाली छोड़ दिये गये हैं। सोवियतों की चौथी क्षेत्रीय कांग्रेस ने बोल्शेविकों के आग्रह पर इस सुझाव का समर्थन किया।

जन-समिति परियोजना के निर्देशन के लिए सोवियतों की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत आदेश से कोई संदेह नहीं रह जाता कि सोवियत सत्ता की उच्च सत्ताओं में मुसलमानों की शिरकात के खिलाफ कहीं कोई भावना नहीं थी। आदेश की धारा ३ में मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जन-समिति परियोजना की रचना में मुस्लिम सहयोग और श्रमजीवी जनगण के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा और उन्हें " (सानुपातिक रूप से) उचित स्थान दिये जायेंगे"।\*

\* 'स्वोयोदनी समरकन्द' (रूसी संस्करण) जिस गैर-बोल्शेविक अखबार ने भी (अंक १२७, २६ नवम्बर, १९१७) इसकी पुष्टि की थी।

\*\* 'नाशा गजेता', अंक २२, २७ जनवरी, १९१८।

\*\*\* 'नाशा गजेता', अंक १३३, २३ नवम्बर, १९१७। "सानुपातिक" शब्द आदेश के मूलपाठ से किसी तरह निकल गया था, जब वह "तुर्किस्तान में महान् अवतार समाजवादी क्रांति की विजय, दस्तावेज संग्रह" में (ताशकन्द, १९४७, पृष्ठ ६३-६५, रूसी संस्करण) प्रकाशित किया गया था और कुछ समय बाद "उज़्बेकिस्तान में अवतार क्रांति की विजय" नामक दस्तावेज-संग्रह में (ताशकन्द, १९६३, पृष्ठ ५७२-५७३, रूसी संस्करण) प्रकाशित हुआ।

आदेश की धारा ४ ने जन कमिसार परिषद का केवल तुकिस्तान के मजदूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के सामने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम गवहारा तथा मेहनतकश जन संगठनों के सामने भी जवाबदेह बनाया।

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि तुकिस्तान के प्रारम्भिक बोशेविकों का मुस्लिम जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासन में भाग लेने से बल्लु करने का कोई इरादा नहीं था। घोषणापत्र में अवश्य आलेखन का कुछ गलतियाँ थीं। परन्तु इसी कारण इसके लेखकों पर स्थानीय मुसलमानों के प्रति शत्रुता की भावना का दोष नहीं मढ़ा जा सकता। निम्न पूजीवादी अखबार तुकिस्तान के बोशेविकों का मजाक उड़ाया करते थे कि वे सभाओं की विज्ञप्तियाँ आदि भी ठीक से नहीं लिख पाते। 'स्वाबोल्नी समरबन्द' अखबार ने तिरस्कारपूर्वक इस बात का उल्लेख किया है कि तुकिस्तान का जन कमिसार परिषद में बलक, कम्पाज़ीटर तथा चिकनाई करनेवाले मजदूर हैं। उसने वित्त-कमिसार द्वारा लिखी हुई एक नोटिस की नकल भी यह दिखाने के लिए छापी कि साक्षरता का स्तर कितना नीचा है।\*

सोवियतों की तीसरी कांग्रेस ने स्थानीय सत्ता-संगठन पर भी एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। स्थानीय क्षेत्रों में सारी सत्ता मजदूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथ में होगी। स्थानीय साविमता से आग्रह किया गया था कि जहाँ कहीं मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों की सावियतें नहीं हैं, वहाँ वे उनका संगठन करें। जहाँ ऐसी सोवियतें हैं, वहाँ उन्हें आत्मशासित रहने दिया जाय।\*\*

नवम्बर १९१७ के अंत में पूजीवादी राष्ट्रवादियों ने सोवियत सत्ता का घुलेग्राम विरोध किया। तीसरी कांग्रेस द्वारा सत्ता उनके हवाले करने के साफ़ इनकार के फलस्वरूप २७ नवम्बर को काकाव में तथाकथित क्षेत्रीय मुस्लिम कांग्रेस बुलाई गयी थी। कोकान कांग्रेस में उजवेव, कज़ाख,

\* 'स्वाबोल्नी समरबन्द', अंक १२७, २९ नवम्बर, १९१७।

\*\* 'तुकिस्तान में महान् अग्नूर समाजवादी आति की विजय',



ताजिक और निर्गुज पूजीवादी राष्ट्रवादियों ने भाग लिया, जो "शूरा-ए-इस्लामिया", उलेमा" और "आलश आरदा" जैसी राजनीतिक पार्टियाँ में संगठित थे। मुस्लिम मेहनतकशा के कम ही प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने दाँव सवाल पर विचार किया, एक था तुर्किस्तान के "दक्षिण पूर्व सघ" में जिसका प्रधान प्रतिनातिकारी नेता दूतोव था, शामिल होने का सवाल और तुर्किस्तान की स्वायत्तता का सवाल। पहला सवाल उसने तुर्किस्तान की भावी सरकार के लिए छोड़ दिया और तुर्किस्तान की क्षेत्रीय स्वायत्तता की घोषणा कर दी। उसने तुर्किस्तान की अस्थायी परिषद का निर्वाचन किया, जिसके ५४ सदस्य थे जिनमें से एक तिहाई रूसी पूजीपतियों के प्रतिनिधि थे। कोवान की तयारपित स्वायत्त सरकार का प्रधान पहले बजाख सब-नुकवादी मोहम्मदजन तिनिशवायेव था, जिसका स्थान जल्दी ही "शूरा ए-इस्लामिया" के मुस्तफा चौवायेव ने ले लिया। स्वायत्तवादियों का घनिष्ठ संबंध दूतोव से काशगर में ब्रिटिश कौन्सल से तथा मगोविक और समाजवादी नातिकारी सगठनों से था। उन्होंने स्वायत्तता का नारा केवल अपने प्रतिनातिकारी उद्देश्य पर परदा डालने के लिए दिया था।

कोवान स्वायत्तता रूसिया के विरुद्ध मुसलमानों का कोई राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं था, जैसा कि कुछ लेखकों का कहना है। वास्तव में यह बग-सघप था, जिसमें एक और मुस्लिम सम्पत्तिवान बग थे जो रूसी पूजीपति बग और वैदशिक साम्राज्यवादियों से मिले हुए थे, और दूसरी ओर रूसी सघारा था, जिस मुस्लिम मेहनतकशा जनता का समर्थन प्राप्त था। वास्तव में यह तुर्किस्तान में प्रतिनातिकारी तथा नातिकारी शक्तियों का सघप था। अ० सटिमोर ने खुलासा करते हुए सही कहा है कि "नाति ज्या ज्यो गहरी होकर राजनीतिक सघप से बग-सघप का रूप धारण करती गई, विभाजन की रेखाओं ने अधिकाधिक सम्पत्तिवान रूसिया और गैर रूसिया को एक ओर कर दिया, जो इसलिए लड़ रहे थे कि पुरानी व्यवस्था में से जो कुछ हो सके उसे बचायें, और सम्पत्तिहीन

रूसियों और गैर-रूसियों को दूसरी ओर, जो नई व्यवस्था को पूर्ण अपन हाथों में लेना चाहते थे।”\*

कुछ लेखकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि बाल्शेविक स्वयत्तता के बट्टर विरोधी थे और पूँजीवादी राष्ट्रवादी इसके पक्के समर्थक। यह कहना वस्तुस्थिति के विपरीत है। पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्त्व, जो सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद स्वायत्तता के ध्येय के समर्थन में गला पाव फाड़ कर चीखने लगे, अस्थायी सरकार तथा उसकी तुर्किस्तान समिति के प्रति अपनी अटूट वफादारी जतलाने में एक दूसरे पर बाजी लड़ने का प्रयत्न करते थे, हालाँकि उन सबको मालूम था कि वह स्वायत्तता की धारणा का विरोधी है। अस्थायी सरकार चाहती थी कि तुर्किस्तान को ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के नमूने पर स्वशासन की शिक्षा दी जायकिसित करे और वह स्वायत्तता की समयक नहीं थी।

जातीय संघर्ष के संघर्ष में पूँजीवादी राष्ट्रवादियों का कोई सुसंगत कार्यक्रम नहीं था। उनकी स्वायत्तता की धारणा बेहद उलझी हुई, अतर्विरोधी और बड़ी हद तक धम से प्रभावित थी। कुछ लेखकों ने उन्हें “राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता” की वैज्ञानिक धारणा का ध्येय देने का प्रयत्न किया है।\*\* पर यह भ्रामक है। पूँजीवादी राष्ट्रवादियों में कई प्रकार की राय थी। एक तो सब इस्लामवादी थे, जिनके विचारों से रूस के सभी मुसलमान एक कौम थे और उन्हें उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए था। वे मुगलमानों में कोई बग भेद नहीं देखते थे और सबों के हितों का एक और समान मानते थे। सब-तुर्कवादी तातारों, आज़रबैजानियों, उज़्बेकों, बज़ार्गों, तुर्कमानों और किर्गिज़ों का मिलाकर कृत्रिम रूप से एक कौम का निर्माण करना चाहते थे। वे तातार पूँजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनका इच्छा थी कि वे तुर्की भाषा-बोलनेवालों में से सबसे अग्रगण्य वर्ग के सभी मुसलमानों पर अपना वर्गीय नेतृत्व स्थापित करें।

\* O Lattimore *Pivot of Asia* Boston 1950 p 204

S A Zenkovsky *Pan-Turkism and Islam in Russia* Cambridge Mass 1960 pp 147-149

मध्य एशिया के जदीदी भिन गिरोहा का पचमल थे, वे अभी तक-  
 इमलामवागिया की ओर झुकते और अभी तक-तुक्वादिया की ओर और  
 - अभी स्वयं अपने पूजीवादी राष्ट्रीयतावाद की ओर। तथाकथित अखिल-  
 रूसी मुस्लिम कांग्रेस में पूजीवादी राष्ट्रवादिया की यह उत्पन्न और  
 सिद्धांतहीनता पूरी तरह चलवती है। पहली अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस  
 मास्को में मई १९१७ में हुई। इसने "एक सघीय आधार पर संगठित  
 जनवादी जनतंत्र" के भीतर "राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता" का प्रस्ताव  
 स्वीकार किया।\* परन्तु दूसरी अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस की कार्यसूची  
 में जो बजान में जुलाई १९१७ में हुई, "राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता"  
 का सवाल निहित था।\*\* दूसरी अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस के साथ-साथ  
 बजान में मुस्लिम मुस्ताफ़ी और सनिका की कांग्रेस भी हुई। तीनों कांग्रेसों  
 के एक संयुक्त अधिवेशन में रूस की सभी तुक्-सातार कौमा की  
 सांस्कृतिक स्वायत्तता का" कार्यकथित करने का निश्चय किया गया।\*\*\*  
 पूजीवादी राष्ट्रवादिया ने इस अंतर्विरोधी मत की रोशनी में प्रथम  
 अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस के प्रस्ताव में उल्लिखित "राष्ट्रीय क्षेत्रीय  
 स्वायत्तता" को कोई महत्त्व नहीं दिया जा सकता। इससे यह नतीजा  
 निकालना कि पूजीवादी राष्ट्रवादिया का कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता  
 की स्पष्ट मांग थी, बात का वतगड बनाना है। इस प्रसंग में यह कहा  
 जा सकता है कि प्रथम अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस ने भूमि-मुद्धार पर  
 प्रतिनातिकारी प्रस्ताव स्वीकार किया था। उसने मांग की थी कि  
 सभी प्रकार की ज़मीनें "समस्त जनगण की सम्पत्ति" घोषित कर दी  
 जायें और "भूमि के हर प्रकार के निजी स्वामित्व को बिल्कुल मिटा दिया  
 जाये"। किसानों को बिना उजरती के भूमि का प्रयोग किये भूमि को इस्तेमाल  
 करने का अधिकार प्रदान करना था। मुस्लिम कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव  
 ने संविधान सभा द्वारा समस्या के समाधान की प्रतीक्षा किये बिना तुरत

\* 'उलुग तुकिस्तान', अंक ५, १३ मई, १९१७ और 'नाशा गज़ेता',  
 अंक १८, १६ मई, १९१७।  
 \*\* 'उलुग तुकिस्तान', अंक २०, ४ अगस्त, १९१७।  
 \*\*\* वही, अंक १८, २७ जुलाई, १९१७।

भूमि-मुधार की मांग की थी।\* यह देखा जा सकता है कि प्रथम क्रिस्ती मुस्लिम कांग्रेस का भूमि वायनम भूमि के संवर्धन में बाल्शेविक वायन की प्रतिध्वनि माल था। यहां तक कि उसने भूमि के राष्ट्रीयकरण में लेनिनवादी आज्ञाप्ति का भी प्रस्तुत कर लिया था। परन्तु इसके आधार पर कोई यह कह सकता है कि पूंजीवादी राष्ट्रवादी वायन में भूमि की समस्या का क्रान्तिकारी समाधान चाहते थे? जाहिर है कि बहुत सी बातें जनता को भ्रमान के लिए कही गई थी। वे जानते थे कि बाल्शेविकों द्वारा प्रचारित राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण का विचार मुस्लिम भूमिजीवी जनता में बहुत जनप्रिय हो रहा था। इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों से अपनी अनुमति जल्दी ही प्रकट की।

यह सही है कि कभी-कभी पूंजीवादी राष्ट्रवादियों ने धर्म के प्रभाव से निक्लन तथा अपनी अलहदा राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। परन्तु वे अपने आप को उसके प्रभाव से पूर्ण तरह मुक्त नहीं कर सके। उनके लिए इस्लाम और राष्ट्र मूलतः एक ही चीज थी। सितम्बर १९१७ में हुई दूसरी असाधारण क्षेत्रीय मुस्लिम कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि स्वायत्त तुर्किस्तान जनतंत्र का संसद द्विसदनी होना चाहिए, जिसकी उच्च सभा धर्मावलम्बियों की सिनेट हो। उसका वायन यह देखना होगा कि संसद द्वारा स्वीकृत सभी कानून शरीअत व अनुमत हों। धर्मावलम्बियों की इस सिनेट को सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करना था।\*\* इन सब बातों से यही स्पष्ट होता है कि स्वायत्तता का उनकी धारणा ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक थी, राष्ट्रीय क्षेत्रीय नहीं। जेकोविया ने (यह बात जेकोव्स्की भी स्वीकार करता है) मध्य एशिया की स्वायत्तता को वायरूप देने के लिए कोई कन्म नहीं उठाया।\*\*\* व "उलेमा" की प्रतिष्ठा से बहुत डर हुए थे जिनके आगे उन्होंने धार-धार घुटन टेक दिए। उलेमा का न स्वायत्तता से कोई दिलचस्पी थी और

\* 'नाशा गजेता', धन २०, १७ मई, १९१७।

\* तुर्किस्तान सोवियेट, धन २६३, ११ नवम्बर, १९१७। (रूसी मस्करण)

\*\*\* ग० जेकोव्स्की, उपरान्त पुस्तक, पृष्ठ २२६-२२६।

न स्वतंत्रता से। वह केवल मध्य एशिया के मुसलमानों पर धर्मावैतन्व्य का प्रभाव डालना चाहती थी।

अन्य पश्चिमी लेखकों ने तुर्किस्तान के पहले बाल्शेविकों का स्वायत्तता के कट्टर शत्रु के रूप में वर्णन किया।\* कुछ सोवियत लेखकों ने भी उन्हें अप्रैल १९१८ में सावियता की पांचवीं क्षेत्रीय कांग्रेस से पहले तक स्वायत्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का दावा ठहराया है। परन्तु इस विचार से सहमत होना कठिन है। स्थानीय बाल्शेविकों पर तुर्किस्तान की स्वायत्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का आरोप लगाना का कोई उचित आधार नहीं है।

ताशकन्द के पुराने शहर में १३ दिसम्बर, १९१७ का स्वायत्तता की भाग के पक्ष में प्रदर्शन की तयारी के संबंध में एक सभा हुई, जिसमें ताशकन्द नगर सावियत का एक प्रतिनिधि उपस्थित था।\*\* इस प्रदर्शन में जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष कालेसोव तथा अन्य कमिसार उपस्थित थे। कालेसोव ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष भाषण दिया और तुर्किस्तान की स्वायत्तता का समर्थन किया।\*\*\* प्रतिश्रियावादी रूसियों ने उसको टोकना चाहा, मगर मुस्लिम प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे उसकी बातें सुनते रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो जाता, अगर कुछ प्रतिश्रियावादी रूसिया ने मुसलमानों को हिंसा पर न उकसाया होता और दोरेर जस प्रति क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ा न लिया होता। अतः कुछ प्रतिश्रियावादी रूसियों के उकसाव का नतीजा था कि प्रदर्शन पर गोली चलायी गई और कुछ निरपराध लोग मार गये।

‘नाशा गजेता’ ने, जो ताशकन्द सोवियत का मुखपत्र था, १३ दिसम्बर के सम्पादकीय में लिखा कि बाल्शेविक “स्वायत्तता के सिद्धांत” विरोधी नहीं हैं, मगर वे अवश्य “एक छोटे समूह द्वारा स्वायत्तता के नाम पर पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता का शोषण करने और उसको गुलाम

\* R Pipes *The Formation of the Soviet Union* p 179, A G Park, *Bolshevism in Turkestan*, pp 14—21

\*\* ‘नाशा गजेता’, अंक १४६, ६ दिसम्बर, १९१७।

\*\*\* वही, अंक १५२, १५ दिसम्बर, १९१७।

बनाने के प्रयत्नो" के विरोधी है। ऐसी झूठी स्वायत्तता के विरोधी सच्ची वास्तविक स्वायत्तता के पक्षपाती थे जिसकी घोषणा सावधान रूप से निवाचित संविधान सभा (अर्थात् सावियतो की कांग्रेस) द्वारा की जाय।

सोवियतो की चौथी कांग्रेस न, जो ताशकंद में १९ से २६ जनवर १९१८ तक हुई, ताति के बाद के पहले कुछ महीना में सोवियत म के निर्माण तथा सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे में तातिकारी परिवर्तन में हुई प्रगति पर जोर दिया। स्वायत्तता के सवाल पर भी विचार किया गया। इस अवधि में वास्तविक नेता तोवोलिन का भाषण, जिसपर अफगानिस्तान की स्वायत्तता का विरोध करने का आरोप लगाया जाता है इस के योग्य है कि उसका लम्बा उद्धरण दिया जाये। तोवोलिन ने चौथी कांग्रेस में घोषणा की

"इस देश के असली मालिक, जिसकी स्वायत्तता की हम बात कर रहे हैं, हमारे अनुसार इस देश के जनगण हैं। हम आत्मनिर्णय की केवल बात नहीं करते, बल्कि इस विचार को हर तरह कार्यान्वित भी करते हैं। हम हथियार लेकर प्रतिताति के विरुद्ध लड़ते हैं चाहे उसका स्रोत भी हो, देशी पजीपति या हसी। इसी के साथ हम न केवल हमारे लोगों का स्वायत्तता का अधिकार स्वीकार करते, बल्कि उनके अधिकार की भी रक्षा करते हैं कि अगर वे चाहें तो निराला अलग हो जायें। हम कहते हैं कि तुकिस्तान के इलाके पर बलपूर्वक कब्जा किया गया था और बलपूर्वक रखा गया था और अगर आम मतानुसार इस व्यक्त जनमत इस से अलग होना चाहे तो हम अलग होने के इस अधिकार की रक्षा करेंगे।"

परंतु तोवोलिन का विचार था कि यकायक और तुरंत स्वायत्तता को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि ताति की उपलब्धियाँ प्रतिताति से खतरा था और देश में युद्ध की स्थिति थी। मगर तोवोलिन की राय में स्वायत्तता या आत्मनिर्णय के लिए भी तयारी का काम चल रहा था। उन्होंने विश्वास दिलाया



ग्रीर कहा कि सामाजिक जनवादियों को पार्टी उम क्षेत्र के लिए सहयोग स्थापित करने का प्रयास करेगी।\*

ऊपर उद्धृत प्रस्ताव से स्पष्ट है कि बोल्शेविक स्वायत्तता के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि केवल पूँजीवादी स्वायत्तता के विरोधी थे। उन्होंने मने ही पूँजीवादी स्वायत्तता के मुकाबले में सहयोग स्थापित करने को पेश किया। यह आगे पढ़ने का कोई आधार नहीं है कि उनमें स्थानीय मनमान जनता के प्रति शत्रुता की भावना थी। उन्होंने सोवियत प्रशासन में धर्मजात मुसलमान जनता की शिक्षण का स्वागत किया और सोवियतकाम (जो कमिसार परिषद) में उनके लिए तीन स्थान रिक्त रखे।

परंतु इस सबके बावजूद पहले बोल्शेविक ऐसी जातीय स्वायत्तता का निर्माण करने में असफल रहे। जहाँ उनकी पूँजीवादी स्वायत्तता के विपरीत सहयोग स्थापित करने की मांग बिल्कुल सही थी, वहाँ शुरू में अपने सहयोग स्थापित करने में उनकी असफलता के कई कारण थे। पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने इस स्थिति से पूरा फायदा उठाया, जिन्होंने जातीय स्वायत्तता के रूप में अपनी पूँजीवादी स्वायत्तता के विचार को जनता में धालना शुरू किया। परंतु सोवियत की तीसरी और चौथी कांग्रेस के समय सोवियतकाम में मुसलमान प्रतिनिधियों के नहीं होने की जिम्मेवारी बोल्शेविकों की केवल आशिक है, क्योंकि उसमें १५ स्थान थे। उन्हें केवल ४ स्थान प्राप्त थे ("पराकाष्ठावादियों" को २ तथा सामान्य मजदूरवादी श्रमिकों को ८)।

जनवरी १९१८ के अंत में सोवियत मता में जाइलम और बर्जास की प्रतिनिधित्व शक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने उससे बग़ावत कर दी थी, सैनिक बग़ावत शुरू की। कोकान स्वायत्ततावादी और दूतों के जाइलम से मिले हुए थे। ताशकन्त के लाल गाँव ने जाइलम के १८ फरवरी १९१८ का ममरान्द के निकट पराजित कर दिया। समरकन्त में निर्यात सफल बग़ावत का शिविर दल के बाद बोल्शेविकों ने बग़ावत स्वायत्ततावादी के विरुद्ध अपना गाँवजनिक प्रचार आंदोलन और तैयार किया।



जनवरी ही में शहरा और ग्रामी के गरीबा की गमायें संगठित की गई थी, जिनमें सावियत सत्ता के समयम म प्रस्ताव पास किये गये। इन सभाया म बोल्शेविका १ बारान स्वायत्ततावादियों के वास्तविक द्वारा का बेनकाब किया। ताशकन्द के पुराने भाग में एक बड़ी सावजनिक सभा म म्यानीय श्रमजीवी जनता न कोमान के मिथ्या स्वायत्ततावादिया के विरुद्ध अपना मन प्रकट किया। फरगाना और समरकन्द प्रदेशो ने श्रमजीवी जनगण न अनव सभाए की और तुकिम्यान की जन-मिसार परिषद का प्रतिनिधित्व किया। अन्दीजान उयेखद (जिले) के श्रमजीवी जनगण न ५ जनवरी, १९१८ को एक सभा म जिनमें १५ हजार मजदूर उपस्थित थे, एक प्रस्ताव स्वीकार करके सावियत सरकार में अपना विश्वास प्रकट किया।\*

३०-३१ जनवरी की रात, १९१८ को बारान स्वायत्ततावादियो ने सावियत सत्ता की नगर-सत्था के विरुद्ध सनिक बारवाई शुरू की। उन्होंने कोमान जिले को घेर लिया। इनमें मजदूरन सावियत सरकार को उनके विरुद्ध खारदार सनिक बंदम उठाना पडा। समरकन्द के निषट सफेद बन्धकों की शिक्स्त के बाद लाल भाड वाल कोमान की तरफ बढ गये। फरगाना और अन्दीजान में लाल गाड वाले भी बारान की ओर बढे। उनकी पकिया में बहुत से देशी सोग भी थे। सनिक बारवाई १९ फरवरी, १९१८ को शुरू हुई और २२ फरवरी, १९१८ तक जारी रही। कोमान के पूजीवादी स्वायत्ततावादिया के विरुद्ध लडाई में स्थानीय बेह्कानो और गरीबा ने प्रमुख भाग लिया। कोमान सरकार द्वारा लामबन्दी का आदेश मानन से उन्होंने इनकार कर दिया। २२ फरवरी, १९१८ का कोमान सरकार नष्ट कर दी गई। प्रतिनातिकारी स्वायत्ततावादियो का एक हिस्सा भाग कर मुखारा चला गया, जहा के अमीर में मिलकर सोवियत सत्ता के विरुद्ध पडपन्न करते रहे। कोमान सरकार के विघटन के बाद पूजीवादी राष्ट्रवादी फरगाना घाटी में आसमची\*\* गिरोह संगठित करने लगे।

\* "उयेख सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का इतिहास", ताशकन्द, १९५७, खण्ड २, पृष्ठ ६१। (इसी संस्करण)

\*\* सोवियत सत्ता के प्रथम वर्षों म मध्य एशिया में आतिविरोधी फारवाइया करनेवाले सशस्त्र दलों के सदस्यों को आसमची कहते थे। - अनु०।

मार्च १९१८ को सोवियत सरकार का असाधारण कमिन्तर त्वा  
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति का प्रतिनिधि बोरोस  
ताशकन्द पहुँचा। उसे सोवियत सत्ता को सबल बनाने और तुकिस्तान  
स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना करने में पार्टी को  
सोवियत सत्ता की स्थानीय संस्थाओं की व्यावहारिक सहायता करने के  
लिए भेजा गया था। अप्रैल १९१८ में तुकिस्तान के मजदूरों, किसानों,  
सैनिकों तथा मुस्लिम बेहकानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की पांचवीं  
क्षेत्रीय कांग्रेस हुई। पांचवीं कांग्रेस के प्रतिनिधियों में काफी बड़ा हिस्सा  
देशी आवादी के प्रतिनिधियों का था। प्रतिनिधियों के भाषणा का अनुवाद  
उज्बेक भाषा में किया जाता था। २२ अप्रैल को कांग्रेस के नाम सन्ति  
और स्तालिन का तार आया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि  
सोवियतकोम सोवियत के आधार पर क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करेगा।  
३० अप्रैल, १९१८ को पांचवीं कांग्रेस ने "रूसी संघ के तुकिस्तान सोवियत  
जनतन्त्र की संविधि" का अनुमोदन किया। संविधि की धारा १ और २  
में जनतन्त्र के राजकीय ढाँचे, इसकी क्षेत्रीय सीमाओं तथा रूसी सोवियत  
संघात्मक समाजवादी जनतन्त्र से पारस्परिक वैधानिक संबंधों की व्याख्या  
की गई थी। तुकिस्तान सोवियत संघात्मक जनतन्त्र को स्वायत्ततापूर्ण  
स्वशासित घोषित किया गया। परन्तु उसने केन्द्रीय सत्ता को स्वीकार किया  
और उसके साथ संबंध स्थापित किया। कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक आयोग  
केन्द्र के साथ पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने मास्को भेजा गया।

पांचवीं कांग्रेस द्वारा स्वायत्तता की घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी का  
लेनिनवादी जातीय नीति के मौलिक सिद्धांतों की विजय का परिचायक था।  
इसका तुकिस्तान में सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ  
पता कीं। कांग्रेस ने तुकिस्तान सोवियत जनतन्त्र की उच्च संस्थाओं—स्तान  
(केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति) और सोवियतकोम (जन-समितार परिषद)  
का निर्माण किया। स्थानीय स्तरों के प्रतिनिधि राज्य की सर्वोच्च संस्थाओं  
में चुने गये। नयी जन-समितार परिषद में नयी आवाजों के तार प्रतिनिधि  
थे। पांचवाँ कांग्रेस ने तुकिस्तान इलाके की स्वायत्तता की घोषणा कर  
एक बड़ा ऐतिहासिक काम पूरा किया। तुकिस्तान की सोवियत स्वायत्तता

सोवियत सत्ता की स्थापना १८५

- मध्य एशिया में राष्ट्रीय सोवियत जनतन्त्रों के निर्माण की दिशा में
- महत्वपूर्ण कदम था।

१९१८ में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जून में तुकिस्तान के बोल्शेविक सगठनों की, जिन्होंने संयुक्त होकर हसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के अभिन्न भ्रम के रूप में तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, पहली कांग्रेस हुई। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में राज्य के प्रशासन में स्थानीय श्रमजीवी जनगण की व्यापक शिरकत, पार्टी प्रसारण को सफल बनाने, सभी ओब्लास्तों, उपेखों और स्थानीय सोवियतों में राष्ट्रीय मामलों की कमिसारियत स्थापित करने, दली भाषाओं में कांग्रेस की दस्तावेजों प्रकाशित करने, आदि की जरूरत पर ज़ार दिया गया।\*  
तुकिस्तान में सभी जातियों के श्रमजीवी जनगण सोवियत निर्माणकार्यों में व्यापक पैमाने पर शरीक होने लगे। तुर्क के दली कार्यकारिणी समिति के ११ जुलाई, १९१८ के निर्णय के अनुसार मध्य एशिया की जातियाँ भी भाषाओं को हसी के साथ समान स्तर पर राजकीय भाषाएँ घोषित किया गया।\*\*

ताशकन्द में २१ अप्रैल, १९१८ को तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।\*\*\* जुलाई १९१८ में उपवेक भाषा में "इस्तराकिज़न" (कम्युनिस्ट) अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ।

अक्टूबर १९१८ में सोवियतों की छठी कांग्रेस ने तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के प्रथम संविधान का अनुमोदन किया। तुकिस्तान के लिए सोवियत स्वायत्तता की घोषणा और संविधान की स्वीकृति के साथ पार्टी की लेनिनवादी नीति को कार्यान्वित करने के संघर्ष की पहली मजिल पूरी हो गई। स्वायत्त तुकिस्तान एक बहुजातीय जनतन्त्र था, जिसके भीतर सभी जातियों के समान अधिकारों की रक्षा की गई थी। राजनीतिक अधिकारों की समानता के सुरक्षित होने के बाद अब

\* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव और निर्णय", ताशकन्द, १९५८। (रूसी संस्करण)  
\*\* नाशा गज़ेता अंक १४४, १७ जुलाई, १९१८।  
\*\*\* नाशा गज़ेता, २३ अप्रैल, १९१८।

समाजवादी विकास तथा समाजवादी जनतन्त्रों के निर्माण की तयारी का काम रह गया था।

तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना के सम्पूर्ण सहयोग के वातावरण में हुई। किसी भी अवस्था में केंद्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों में उनके अपने-अपने अधिकारों के सवाल पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ पश्चिमी लेखकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों में इस सवाल पर फूट थी। उनके लिखने का आशय यह होता है मानो तुकिस्तानी प्राधिकारी ज्यादा अधिकार चाहते थे और केंद्र उन्हें देना नहीं चाहता था। इसके सबत में वे कहते हैं कि तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र के निर्माण की आज्ञाप्ति जारी करने में केंद्र ने "असाधारण" तौर पर बड़ी देर की। यह आज्ञाप्ति, उनका कहना है, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ११ अप्रैल, १९२१ में जारी की गई। उनका कहना है कि यह तभी किया गया, जब तागोब "अवकाशी" नहीं रहा और सितम्बर १९२० में सोवियतों की क्षत्रप कांग्रेस में नया संविधान स्वीकार करके, जो "अभरत मास्को में स्वायत्तता की धारणा के अनुकूल था" पर्याप्त मात्रा में मास्को का आनाकारी बन गया।\*

परन्तु इस विचार में तनिक भी सत्य नहीं है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि अस्तूअर १९१८ तक मास्को और ताशकेंड परस्पर मजदूरी का सवाल तय हो चुका था और केंद्र ने तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र का पूरा स्वीकार कर लिया था। अगर इस सब में कोई आज्ञाप्ति जारी नहीं की गई तो इसका कारण यह था कि तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र के संविधान का अनुमोदन करने में कुछ दिनों की आज्ञाप्ति की ज़रूरत नहीं थी। नया सोवियत राज्य, रु० सो० स० में जनतन्त्र का स्वच्छापूर्ण रूप था जिसका निर्माण हमें शामिल मानवाने स्वायत्त जनतन्त्र के धार्मिकता के जरिये हुआ था। जुलाई १९१८ में मास्को की पाठ्य अभियन्त्री कांग्रेस द्वारा स्थापित रु० सो० स० स०

जनतन्त्र के संविधान में इसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि इसमें शामिल होने वाले स्वायत्त जनतन्त्रों के संविधान का अनुमोदन केन्द्र द्वारा किया जाये, न ही संविधान ने इसका अधिकार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को दिया था।\*

हम यह भी जानते हैं कि तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का प्रतिनिधि मंडल जिम्मम त्राईत्सकी, युसूपोव, तेम्रोदोरोविच तथा दो और व्यक्ति थे, पारस्परिक संबंधों पर वार्तालाप करने भास्का गया था। प्रतिनिधि मंडल लेनिन और स्वेदलोव से मिला और इसके सदस्यों ने तुकिस्तान स्वा० सो० सं० जनतन्त्र के प्रतिनिधियों की हैसियत से सोवियतों की पाचवीं अखिल रूसी कांग्रेस में भाग लिया। पारस्परिक संबंधों के सवाल पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति स्वेदलोव ने एक आयोग नियुक्त किया जिसमें रोजेनगोल्स, यनुकीद्जे, डमेलनोत्स्की तथा दो और थे। कई बैठकों के दौरान में, जो जुलाई १९१८ में केन्द्रीय आयोग और तुकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई, बड़ी प्रगति हासिल की गयी थी और तुकिस्तान स्वा० सो० सं० जनतन्त्र की सीमाओं, इसकी सत्ता-संस्थाओं तथा प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों आदि के संबंध में कुछ सवालों पर स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण के सवालों को सतोपजनक रूप में हल कर दिया गया। केन्द्र और तुकिस्तान के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक की कारवाई की जो रिपोर्ट ४ अक्टूबर, १९१८ के "नाशा गजेता" में छपी, उससे यह लग सकता है कि बातचीत सरल ढंग से नहीं चल रही थी। उसमें संकेत है कि तुकिस्तान की कार्यकारिणी संस्था के लिए सोवन्तारबोम का नाम संवसम्मति से नहीं स्वीकार किया गया और कार्यकारिणी समिति संगठित करने का सवाल अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के हवाले कर दिया गया। यह भी खबर थी कि तुकिस्तान की "असाधारण घटनाओं" के कारण चौथी बैठक स्थगित कर दी गई और आयोग का काम वहां सामान्य स्थिति लौट आने तक के लिए रोक दिया गया। यह भी कहा गया कि तुकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल वापस लौट रहा है।

---

\* "सोवियतों की कांग्रेसों की दस्तावेजें १९१७-१९२६", मास्को, १९५६, खण्ड १, पृष्ठ ७७-७८। (रूसी संस्करण)

परन्तु प्रतिनिधि मंडल तुकिस्तान वापस नहीं गया। यह भी "नाग गजेता" के उमी अक से मालूम हो जाता है। अक्टूबर में वह अभा भाग में ही था और २ अक्टूबर, १९१८ को त्रोईत्स्की और मुसूपोव न क और तुकिस्तान के परस्पर संबंधों को तय करने के सवाल पर हई प्रती के बारे में एक सदेश केन्द्र से भेजा था। उन्होंने इस सदेश पर तुकिस्तान के पूर्णाधिकारी दूतों की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे। ऐसा लगता है कि शुरू की बैठकों में, जो जुलाई १९१८ में हुई थी, मतभेद कुछ तत्काली बातों पर हुआ था। जनवरी १९१८ में स्वीकृत ६० सौ० स० स० जनतंत्र के संविधान में स्वायत्त जनतंत्रों के निर्माण की बात नहीं साची गई थी। इसमें केवल "स्वायत्त ओब्लास्त सभा" की गुंजाइश रखी गई थी। परन्तु जीवन में तुकिस्तान के स्वायत्त जनतंत्र को जन्म दिया था और लेनिन तथा स्वेदलोव ने इसकी उत्पत्ति का स्वागत किया। तुकिस्तान के प्रतिनिधियों ने सकेत किया है कि उन्होंने लेनिन, स्वेदलोव तथा जन कमिसार परिषद के अन्य सदस्यों की ओर से तुकिस्तान जनतंत्र में पूर्ण विश्वास पाया। उन्होंने आशा प्रकट की कि जब आयोग अपना काम शुरू करेगा, तो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा सोवनार्रोम के अधिकारों तथा संगठन के संबंध में सब कुछ तय हो जायेगा। उन्होंने यह भी लिखा था कि "लेनिन से निजी बातचीत के अनुसार तुक काम कार्यकारिणी समिति को अधिनार था कि आपत्ति में कुछ बाना को बदल दे, जो उस क्षेत्र के लोगों की जीवन स्थितियों के बिल्कुल अनुरूप थी।" १०

अतः हमें कोई सन्देह नहीं कि अक्टूबर १९१८ में सावियता का एक क्षेत्रीय कांग्रेस में स्वीकृत तुकिस्तान २५० सौ० स० स० जनतंत्र के संविधान का चर्चा की पूरी मजूरी प्राप्त थी और उमम कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। ताना में इस सविधान में और सितम्बर १९२० में सावियता की ११वीं क्षेत्रीय कांग्रेस में स्वीकृत संविधान दोनों में बेशर्त समर्थ, प्रतिष्ठा,

१ 'सावियता की कांग्रेस की सारांश', पृष्ठ ७३।

२ 'नाग गजेता' अंक २०६, ६ अक्टूबर १९१८।

- वित्त रेलवे डाक-तार संपीय सरकार व हवाय कर दिया था।\* परन्तु १९१८ के संविधान में इन विषयों पर कुछ अधिकारक्षेत्रीय प्रतिबंध थे।
- जिनको १९२० के संविधान में हटा दिया गया। इन प्रतिबंधों की जरूरत तुकिस्तान में १९१८ की असाधारण स्थिति के कारण थी, जब वहाँ कोई स्थायी सम्भव नहीं था। परन्तु १९२० में यह स्थिति बदल चुकी थी।

तुकिस्तान जनतंत्र १९१८ में अपने जन्म के समय ही समाजवादी राज्य बन गया। १९१८ से १९२४ तक लगभग हर जगह ग्रामीण सोवियत और जन 'यायालय' स्थापित किए गये, जिनमें देशी भाषाओं, रीति रिवाज और परम्पराओं का गान रखनेवाले स्थानीय जातियों के लोग थे। अब प्रशासकीय संस्थाओं में बहुमत स्थानीय भाषावादी के प्रतिनिधियों का था। सोवियत सत्ता इस प्रकार सचमुच जनगण की अपनी सत्ता बन गई।

सरकार ने स्थानीय विशेषताओं का ध्यान रखा और कुछ हालतों में पुराने रिवाजों को रहन दिया। मिसाल के लिए सोवियत 'यायालयों' के साथ साथ जहाँ नये कानूनों के अनुसार 'याय' किया जाता था, पुरानी शाय जहाँ नये कानूनों के अनुसार 'याय' किया जाता था, पुरानी स्लिम अदालत भी थी जिनके लोग आदी थे और जिनमें बाकी लोग रोमत (धार्मिक कानून) के अनुसार 'याय' करते थे। अगर किसी व्यक्ति को काज़ी के फसले से सतीय नहीं होता, तो वह सोवियत 'यायालय' में जा सकता था। लोग थोड़े ही दिना में अपने अनुभव से सोवियत कानूनों की श्रेष्ठता के कायल हो गये, जो शापितों की सुरक्षा करते थे और काज़ी की अदालतों का काम धीरे धीरे पच फँसला करना हो गया और फिर वे विलुप्त लुप्त हो गये।

खीवा और बुखारा में सोवियत जनतंत्र का निर्माण

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खीवा के लोगों की आर्थिक स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगी। रूस से खाद्यान्न के आयात में बाधों से भी ज्यादा की

\*"सोवियतों की कायदा की दस्तावेज़ें", पृष्ठ २७६, ४५०।

कमी हो गई तथा अन्ध निमित्त सामानों के आयात में भी कमी हुई। इससे लोगों की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गईं। खाद्य पदार्थों का बड़ा अभाव हो गया। किसान करा के भारी बोझ में त्राहि त्राहि कर रहे थे, जो १९१८ और १९२० के बीच और बढ़ गया। उन दिनों खीरा पर खाने का प्रभुत्व था। खान के अधिकारी और डाकू दाना जनता का लूटते। खान शासित प्रदेश में अनेक जातियों के लोग थे, जिनमें उत्तर, तुर्कमान, कराकल्पाक और कजाख। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि उनमें आपस में शांति बनी रहती हो। अक्टूबर क्रांति से पहले के दश में राष्ट्रीय सवाल बहुत तीव्र हो उठा था। उन्नेक अभिजात वर्ग के लोग उन्नेक श्रमजीवियों का शोषण तो करते ही थे, वे तुर्कमानों और कराकल्पाकों का भी दमन करते थे।

पूँजीवादी अस्थायी सरकार ने जिसे फरवरी क्रांति के फलस्वरूप सत्ता मिली थी, उन्नेका, तुर्कमानों, कराकल्पाक देहकानों तथा शहरी ब्रह्मणों के विद्रोहों के विरुद्ध अपनी सेनाओं के जरिये खान के निरंकुश राज का समर्थन किया। खान राज में रहनेवाले किसान और कारीगर स्वतन्त्र ढंग से ही खान के अधिवासियों के निरंकुश शासन और सामंती बाई तांग और मुत्ताआ के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया करते। वे बाई और बक लागा की संपत्ति जला देते और उनके मवेशी और पशुधन लूट ल जाते। २० मई, १९१७ को खान राज की राजधानी यीबा के दक्षिण लोहा न घाटा और चानल लूट लिया। यीबा स्थित कश्गाक पलटन ने "अज के यनव" को बड़ाई से कुचन दिया।

मई-जून १९१७ में देहकानों ने कुनिया उरगेंच इलाके में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। आदालत इतना प्रबल हो उठा कि खान की अस्थायी सरकार की सहायता लानी पड़ी। उसने जाइल्मेव की बग़ल में कश्गाक टुकड़ा भेजा। उसने उन्नेक खान के अंतर्गत में कुत्तक और बाई फोजी टुकड़ों को सगठित करना में भी सहायता की। २० मितम्बर, १९१७ का आन्दोलन और जुलै खान के बीच एक सम्झौता हुआ कि वे आन्दोलन के अग्रनिर्वाह में आधिकारी आन्दोलन के विरुद्ध मिनरर सहाय करण।

अज और मुस्लिमान में अक्टूबर क्रांति की विजय यीबा के खान के



१. विरुद्ध जनता के शक्तिकारी सघप व भावी विरास व लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। खान शासित प्रदेश अथ उपनिवेश नहीं रहा और जनगण का अथ खान व निरबुध राज स भुक्ति प्राप्त करन व काम म नय प्रशासन की पूरी सहानुभूति और समय का विश्वास था। जुनैद खान व सैनिक और वज्जावा क आतक के बावजूद शहरो और क़िलाको (गावा) व थमजीवी जनगण निरबुध शासन और दमन व विरुद्ध उठ खड़े हुए। जन-सघप की इन स्थितियों म खीवा की कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, जिसने जनगण को खान प्रशासन की निरबुधता के विरुद्ध संगठित करना शुरू किया।

सोवियत सरकार ने प्रारम्भ म ही घोषित कर दिया कि वह खीवा की स्वाधीनता और प्रभुसत्ता का स्वीकार करती है। इसी सो० स० स० जनतंत्र तथा बुकिस्तान स्वा० सो० स० स० जनतंत्र न अपनी ओर स खीवा स अच्छे पड़ोसियों जैसे सबध विसित करन की इच्छा प्रकट की। परन्तु खीवा व प्रतिक्रियावादी शासक हल्ले सावियत सत्ता स अपनी अंगी घणा तथा खीवा के लोग पर उसके बहुत प्रभाव के डर व कारण, साम्राज्यवादी खेमे म जा मिल।

शुरू ही स खीवा मध्य एशिया म सावियत विरोधी प्रतिशक्तिकारी बद्र बन गया, जहा सफेद गार्ड वाले, मशेविक, समाजवाणी शक्तिकारी, पुर्जीमान् राष्‍ट्रवादी तथा अन्य प्रतिशक्तिकारी तत्व चारा आग स गया वर आन लग। यहा ब्रिटिश साम्राज्यवाद व एजट उनस आ मित्र और उनस मद्दयाग स सोवियत मध्य एशिया पर हमले की तयारी करन मग। उनस सावियत-विरोधी योजनाओं म जाहल्लेक की महत्वपूर्ण भूमिका गोंपो गई। जाहल्लेक कोकान स्वायत्ततावादियों तथा आन्तर्गत वज्जाव नवा दूताव से भेंट करने के बाद सावियत सत्ता व विरुद्ध प्रभावित आन्तमण म जुनैद खान का साथ देने पर राजी हो गया। उनकी याचना यह थी कि चरख पर बज्जा किया जाय और तब राज गार्ड व निवार काजान करे वद और जिज्जाव पर बज्जा करन क आग न ताउन्द करे कोकान स्वायत्ततावादियों की सलाह अन्य आ मित्रों। वजन करे स्वायत्त सो० स० स० जनतंत्र व आन्तर्गत के इनाजे म सन्दिग्ध म

तख्ता उलटने का काम भी जुनैद खान के सुपुद किया गया। खात्र प्रतिनातिकारियों का स्थायी सम्पर्क ताशकन्द के गुप्त सोवियत विराज सगठन से था, जिसे तुकिस्तान सैनिक सगठन कहा जाता था और बिना स्थापना अमरीकी कौसल, फासीसी एजेंट वस्ताये और अग्रज बन वेली की सक्रिय शिरकत से हुई थी। जुनैद खान की सेनाप्रा ने अज्ञाता में प्रतिनातिकारी उलट फेर सगठित करने में सक्रिय भाग लिया।\* १६ नवम्बर, १९१८ को जुनैद खान आमू दरिया क्षेत्र में सोवियत इलाक में घुस गया और लूटमार करने लगा। उसने किपचाक और बिम्बाई पर कब्जा कर लिया और तुतकुल (उस समय पेत्रो अलेक्साद्रोव्स्क) को पर लिया। तुतकुल के वीर रक्षकों ने जुनैद खान को भारी क्षति पहुंचाई और उसे विवश होकर अपना ११ दिन का असफल घेरा उठा लेना पड़ा। जनवरी १९१९ में जुनैद खान ने फिर सोवियत क्षेत्र पर आक्रमण किया, मगर फिर उसे शिक्स्त खानी पड़ी। अप्रैल १९१९ में उसने सोवियत सरकार से शांति का आग्रह किया। ६० सो० स० स० जनतंत्र तथा पारा के प्रतिनिधियों के बीच ६ अप्रैल, १९१९ का तखता किले में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसका अनुमोदन तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और खान सैयद अब्दुल्लाह ने मई १९१९ में किया। इस समझौते के अनुसार जुनैद खान को ६० सो० स० स० जनतंत्र के विरुद्ध कोई सशस्त्र कारवाई नहीं करना था। समझौते में स्पष्ट और जल मार्गों से व्यापार की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा राजनयिक प्रतिनिधिमंडल की अदला-बदली का भी प्रबंध था।\*\*

परन्तु पीवा ने इस समझौते का पालन कभी नहीं किया। सामान्य सरकार ने एक व्यापार संधि करने का कर्द बार आग्रह किया, मगर खान ने उस अस्वीकार कर लिया। जुनैद खान ने सामन्यत विरोधी हरकत बना रही छाड़ी। जून १९१९ में उसने कई सामान्यता का आदेश दिया और पानाव से सम्पर्क स्थापित किया। उसी महीने चीना और बुयारा के साथ

\* उन्नेत भागिया समाजवादी जनतंत्र का इतिहास", पृष्ठ १६१।

\*\* यही, पृष्ठ १६३-१६४।

## सोवियत सत्ता की स्थापना १९३

प्रतिनिधि मंडल का आदान प्रदान हुआ। अगस्त में उराल के कज़ाखों ने सोवियत सरकार व विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया और बाई लोग और कुलकों की सहायता से विम्बाई और नुकूस पर कब्ज़ा कर लिया। ग्राम-दरिया की सरकार की स्थापना की गई जिसका प्रधान एक कुलक फेलिचेव था। जुनैद खान ने इसे तुरंत मायता दे दी। द्रासवासियन इलाक में सफेद गाड़ का १९१९ के अंत में सफाया हो गया तो सभी समाजवादी नातिकारी और मशेविक अशकावाद से भागकर चीवा पहुँचे, जहाँ वे जुनैद खान के सलाहकार बन गये।

जब जुनैद खान इस प्रकार सोवियत सरकार व विरुद्ध पड़्यक्त कर रहा था, तो चीवा में देहकानों का नातिकारी आंदोलन बढ़ता जा रहा था। देहकानों और भूमिहीन किसानों के विद्रोही दस्ता ने तुतकुल को अपना केन्द्र बनाया। मूशे और कूइविशेव के नेतृत्व में तुक भाषायोग ने चीवा के कम्युनिस्टों रहमान प्रिम्यतोव, अहमेजान इब्राहीमोव, कूर्यान बकनियोजोव, अब्दुल्लायेव, न० सलापाव आदि की सहायता की कि वे चीवा के नातिकारी आंदोलन को संगठित कर। उन्होंने चीवा नौजवान संगठन के दक्षिणपंथियों का परदा न० सलापाव आदि की सहायता की कि वे चीवा के नातिकारी आंदोलन को संगठित कर। उन्होंने चीवा नौजवान संगठन के दक्षिणपंथियों का परदा फाश किया जो जुनैद खान की मदद करने लगे थे। वामपंथी नौजवान चीवाई जैसे पहलवान नियोज युसूपोव, नजीर शालिकारोव, इत्यादि स्थानीय बुद्धिजीवियों तथा पूँजीपतियों व मध्यम तबके के साथ-साथ सामंती उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। किसान और कारीगर नौजवान चीवाई इस आंदोलन से अलग होकर चीवा की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये।

चीवा व कम्युनिस्ट सशस्त्र नातिकारी स्वयंसेवकों का संगठित करने में सक्षम हो गये। उनके निदेशन में नवम्बर १९१९ में कूनगिरात, क्वाज़ली ईर्तिशलिस्क और दुनिया उरगच की ज़मींदारियों में सशस्त्र विद्रोह हुआ। सोवियत सरकार ने चीवा व लोगो के आग्रह पर सफेद गाड़ के विरुद्ध संघर्ष में सहायता करने का फैसला किया। २२ दिसम्बर, १९१९ को सोवियत सेना ने चीवा में प्रवेश किया। २ फरवरी १९२० को चीवा में नाति विजयी हुई। जुनैद खान की कठपुतली सैयद अब्दुल्लाह खान के प्रशासन का अंत कर दिया गया। २ फरवरी, १९२० को चीवा की

कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल सावजनिक सभा न खान के अत्याचार के अत तथा जन-सत्ता की स्थापना का अभिनन्दन किया। उन ने खीवा के जनगण को खान और ब्रिटिश साम्राज्यवाधियों के बुरा मुक्ति दिलाने में लाल सेना द्वारा दी गई सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकटी की। अस्थायी प्रातिवारी सरकार ने कुल्लुताई (जन प्रतिनिधियों के कांग्रेस) आयोजित करने की तैयारी की।

जन प्रतिनिधियों की प्रथम अखिल-स्वारज्य कुल्लुताई का अभिनय अप्रैल १९२० में हुआ और उसने भूतपूर्व खीवा खान प्रशासन को स्वतंत्र सोवियत जनवादी जनतन्त्र घोषित किया। कांग्रेस न केन्द्रीय कार्यकारी समिति का निर्वाचन किया और सरकार बनायी, जिसे ग्रामीण नादियों की परिषद कहते थे। जन प्रतिनिधियों की पहली कुल्लुताई ने स्वतंत्र सोवियत जनवादी जनतन्त्र के प्रथम संविधान का अनुमोदन किया, जिसे केन्द्रीय तथा स्थानीय क्षेत्रों में सारी सत्ता मेहनतकशों की सोवियत संसदों पर दी। कुल्लुताई सत्ता की सर्वोच्च संस्था थी। संविधान खीवा के जनगण के लिए भाषण, अखबार और समा इत्यादि की स्वतंत्रता की गारंटी दी। खान और उसके उच्चाधिकारियों की सम्पत्ति, जो प्राति के समय जब्त कर ली गई थी, सावजनिक सम्पत्ति घोषित कर दी गई। १८ वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों का वोट का अधिकार दिया गया। इससे बचित थे प्रातिवारी, खान और उसके स्थान पर भूतपूर्व खान प्रशासन के उच्चाधिकारी और बड़े जमींदार। स्वारज्य सोवियत जनवादी जनतन्त्र के संविधान न मभी जातियों के समान अधिकारों का भाषण की।

खीवा की प्राति की अपनी खास विशेषताएँ थी। औद्योगिक सहायता की संख्या बहुत कम थी और अधिकांश लोग देहात थे। इसलिए पहला अवस्था में प्राति समाजवादी नहीं, बल्कि जनवादी प्राति था। उन अवस्था में जनता का प्रातिवारी जनवादी अधिनायकत्व स्थापित किया। पहली अवस्था की प्राति को दूररी समाजवादी अवस्था में सन्नत का संसार करना था। पूँजीवादी-जनवादी प्राति का नायमार पूँजीपति वगैरे को नहीं बल्कि जनता के प्रातिवारी अधिनायक का पूरा करना था।

यह किसान जनता ने अपनी सोवियत सत्ता की सस्याओ के जरिये किया।

क्रांति के बाद खीवा में मुसूपोव के नेतृत्व में जो प्रथम सरकार बनी, उसपर भूतपूर्व नौजवान खीवाई तत्वों का कुछ रंग चढ़ा हुआ था, जो सोवियत सरकार के कायमारों के विरोधी थे। उसमें अनेक पूजीवादी राष्ट्रवादी थे, जो स्वार्थ को सोवियत रूस से अलग रखना और उसे अंग्रेज़ा का उपनिवेश बना देना चाहते थे। उन्होंने भूमि-सुधार में बाधाएं डालीं। पान की जल की हुई जमीनें आई लोग और साहकारों के हवाले कर दी गईं। वक्फ की जमीनें ज्यों की त्यों रहने दी गईं और देहकानों ने जब उनपर कब्ज़ा करना चाहा, तो उन्हें सज़ा दी गई। नई सरकार ने उज्वेका और तुक्माना में जातीय झगडा भी उठा दिया।

अतः खीवा की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने एक गम्भीर कायभार था। और वह था भूमि और पानी की समस्या तथा जातीय सबंधों की समस्या का क्रांतिकारी समाधान ढूँढने का कायभार। वह बैरी लोगो को निकाले बिना इस कायभार को पूरा नहीं कर सकती थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के तुक् ब्यूरो तथा तुक् आयोग की सहायता से इसका प्रयास शुरू हुआ। पार्टी में अधिकाधिक गरीब लोगो को शामिल किया गया और पूजीवादी राष्ट्रवाल्या के विरुद्ध सघन छेड़ दिया गया। ६ मार्च, १९२१ को खीवा में मेहनतकश लोगो की आम सभा की गई, जिसने बैरी लोगो को सरकार से निकालने की मांग की। दूसरी क्रुस्तलाई के अधिवेशन से पहले एक नई अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनायी गई।

मई १९२१ में दूसरी क्रुस्तलाई का अधिवेशन हुआ। कुल ३४० प्रतिनिधियों में बड़ा बहुमत गरीब और मध्यम देहकानों का था। उसने वक्फ की जमीन को राज्य से अलग किया और भूमि के स्वामित्व की हदबन्दी उठाने पर कर दी जितने पर स्वयं एक व्यक्ति काम कर सकता था। चौदह हजार तनाब भूमि देहकानों में वितरित की गई। दूसरी क्रुस्तलाई ने बड़े उत्साह के साथ रु० सो० स० स० जनतंत्र के साथ सैनिक और राजनीतिक समन्धों का अनुमोदन किया। रु० सो० स० स० जनतंत्र ने खीवा के अमजीवी जनगण के आर्थिक, राजनीतिक और

सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने में उनकी बड़ी सहायता की। रु० २० स० स० जनतंत्र ने खीवा जनतंत्र की स्वाधीनता और प्रभुसत्ता को स्वीकार किया और भूतपूर्व खान जासिन प्रदेश में पहले की रूसी सरकार की औपनिवेशिक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त थी, उन सब का त्याग कर घोषणा की। फिर उसने खीवा में अपनी सारी सम्पत्ति, कारखाने, स्कूल और जहाज आदि जनतंत्र की नई सरकार के हवाले कर दिया। तासिक सरकार ने जनगण का आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊँचा करने में खीवा सोवियत जनवादी जनतंत्र की बड़ी सहायता की। उसे सावियत सरकार ने ५० करोड़ रूबल की सहायता एकमुश्त मिली। इस से बड़ी सहायता प्रशिक्षक, इंजीनियर, डाक्टर और शिक्षक आदि भी वहाँ भेज गए थे।

खीवा की तरह बुखारा में भी सामंती निरंकुश राज था जो वह जारशाही रुस का संरक्षित राज्य था। फ़रगाना के बाद जारशाही रुस के लिए वह कपास का दूसरा बड़ा स्रोत था। रुस को इन कुल निर्यात में ४० प्रतिशत कपास था। अपनी कपास का ६० प्रतिशत वह रुस को भेज दिया करता था। बुखारा में पूँजीवादी ढंग का कोई बड़ा निमाण-उद्योग नहीं था। जो ५२ फैक्टरियाँ थी, उनमें २६ नई शोर्टन का काम करती थी। आवादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसान था दिनकी हाना दिनादिन बिगड़ती जा रही थी। बुखारा में मुस्लिम धार्मिक नेताओं का बड़ा प्रभाव था। मकतबा और मदरसा में कोई २० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे।

प्रथम रूसी प्राप्ति के विचारों के प्रभाव में बुखारा में जदीदियन का नाम से एक प्रगतिवादी पूँजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन का विकास हुआ। परन्तु जदीदियो का काम साम्यवादी तथा शैक्षणिक क्षेत्रों तक ही सीमित था। उन्होंने विद्यार्थी व्यवस्था के विनाश लटन का बौद्धिक काम ही उठाया। उन्हें अभीर तथा उनके धर्मभीरु वजीरों की गायबूद्धि और निवेदन का बड़ा भरोसा था। रूस की परवरी प्राप्ति के बाद ही जदीदियो ने, ज

नौजवान तुर्कों की देखा दखी अपन को नौजवान बुखारी बहने लगे थे, आशिक सुधारा की माग की। उनकी माग थी कि कर ठीक-ठीक तय कर दिय जायें और भजलिस (संसद) का आयोजन किया जाये। अमीर ने ७ अप्रैल, १९१७ को कुछ सुधारा का वादा करत हुए जा घायणपत्र जारी किया, उसे कभी पूरा नहीं किया। जदीदी जाति का नहीं, सुधारा का समयन करत थे।

अक्टूबर आति की विजय न बुखारा के लोगो को इसी औपनिवेशिक शाणन मे मुक्ति दिला दी। नवम्बर १९१७ मे बुखारा की सभी हमी वस्तिया-नया बुखारा, चारजूए, केरकी और तेरमीज-मे सत्ता सावियतो के हाथ मे आ गई। बुखारा की धरती पर सोवियता का जाल सा निछ गया, जो बुखारा म आतिकारी आदोलन के भावी विधास म बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

शुरू ही मे सोवियत सत्ता ने प्रति अमीर का रख शत्रुतापूर्ण था। नवम्बर १९१७ और मार्च १९१८ के बीच उसने तीन बार मेना के लिए लामबन्दी का आदेश दिया। उसने ओरेनबुर्ग कज़ाक के नेता दूताव से तथा कौकान के पजीवादी राष्ट्रवादी स्वायत्ततावादिया से भी सम्पर्क स्थापित किया। उधर ईरान मे अंग्रेजी सेना के कमाण्डर मैलेसन से भी उसका सवध था। अमीर की सेना मे कोई २,००० अफगान भाड़े के सिपाही अंग्रेज अफगरा की कमान मे काम करते थे। १९१८ के प्रारम्भ मे अमीर ने रेलवे लाइन के किनारे किनारे ३० हजार की सेना तैयार कर ली, जो तुकिस्तान म सोवियत सत्ता के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी। सावियत सरकार ने अमीर से सामान्य सवध म्यापित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया और इस उद्देश्य स दिसम्बर १९१७ मे एक राजाधिक मडत बुखारा भेजा। लेकिन अमीर ने उससे भेंट नहीं की।

६ दिसम्बर १९१७ को नौजवान बुखारिया का एक प्रतिनिधि मडल ताशान्द पट्टा और उसने सोवियत अधिकारिया का बुखारा म आति की तैयारिया की सूचना दी, जिसमे कोई ३० हजार सशस्त्र आदमियो के भाग लेने की आगा थी। बुखारा की जनता द्वारा आतिनारी पारवाई तमारी की इन आतिशयोक्तिपूर्ण सूचनाभा से गुमराह होकर ५

जन-कमिसार परिषद ने बुखारा के जनगण को असामयिक सहायता दान का गलत फैसला किया। २८ फरवरी, १९१८ को तुकिस्तान का जन कमिसार परिषद के अध्यक्ष कोलेसोव ५००-६०० ताल गां दाना लेकर बुखारा की ओर बढ़े। उन्होंने रूसी वस्तुओं में सोवियत सत्ता का मान्यता देने तथा नौजवान बुखारिया के प्रतिनिधियों को लेकर एक कायकारिणी समिति का निर्माण करने और इस तरह प्रशासन के जनवादीकरण की मांग की। अमीर ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद २ मार्च, १९१८ को कोलेसोव ने अपनी सैन्य कारवाई शुरू कर दी। उनकी कमान में कुल २,००० आदमी थे। प्रभात के समय लेने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव किया और इस बात पर की तैयारी की। उसने समरकन्द से रेलवे लाइन काट दी और वास्कर के विरुद्ध "जोराद" छेड़ दिया। कोलेसोव की समरकन्द की तरफ पला हटना पड़ा और तुकिस्तान से ताजी कुमक पहुंचने की वगैरह सबनास में बच गये। अमीर को किजिल-तेपे में २५ मार्च, १९१८ का समाचार पर हस्ताक्षर करने पड़े। वह सेना की सामवादी का बदलन, तमान रूसी प्रतिवातिकारियों का बुखारा के इलाके से निकालने, विनाश रेल लाइन की मरम्मत करने और बुखारा में एक सोवियत कमिसार रखने पर राजी हो गया। इस प्रकार अमीर के शासन का तल्ला उलटने का प्रथम प्रयास विफल हुआ। जनता ने नौजवान बुखारिया का साथ नहीं दिया। अभी वह बड़ी हद तक मुल्ताझा के प्रभाव में थी। लेकिन २ मार्च १९१८ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस में इसका पता पड़ा और पिछड़े हुए इलाका में वातिकारी परिवर्तन लागू करने में मायघाता में काम लेने पर जोर दिया।\*

किजिल-तेपे के समझौते से तुकिस्तान को आवश्यक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अमीर मार्च की घटनाओं के बाद अंग्रेज साम्राज्यवादी का और निकट हो गया। अगस्त और मई १९१९ में बर्द सो ऊटा पर तल्ला अंग्रेजी साम्राज्य अफगानिस्तान के राज्य बुखारा पट्टाया गये। अमीर



म अमीर को २० हजार राइफले मिली और भई म आठ हजार घीर।\* १९१६ के वसंत तक अमीर की सेना में अंग्रेज प्रशिक्षकों की संख्या ६०० तक पहुंच गई थी।\*\* १९१६ की गर्मियों में अमीर ने ट्रांसकास्पियन के सफेद गाड वालों से मिलकर और अंग्रेजों की प्रत्यक्ष शिरकत से वेरवी पर सशस्त्र घावा किया।

इस असफल अभियान का नेतृत्व तुकिस्तान का भूतपूर्व बोल्शेविक युद्ध मंत्री ओसिपोव और अंग्रेज वरनल लोमवाट कर रहे थे। अक्टूबर १९१६ में वरनल बेसी ताशकन्द से बुखारा पहुंचा और सोवियत तुकिस्तान के विद्रोह कारवाइ की योजना तैयार करने लगा। स्वयं अमीर ने लीग ऑफ नेशन्स के नाम एक स्मृतिपत्र में स्वीकार किया कि वह अफगानिस्तान, खीवा और अंग्रेजों से मिला हुआ है।\*\*\*

अमीर के आक्रमक इरादों के विपरीत तुकिस्तान के बोल्शेविक उसी प्रति शान्तिपूर्ण नीति पर अमल कर रहे थे। सोवियत सरकार ने हमेशा यही कोशिश की कि अमीर के बुखारा के साथ अच्छे पड़ानियाँ जैंगे संबंध स्थापित हो। तुकिस्तान की सोवियतता की पाचवी गारंटी ने बुखारा की स्वतंत्रता की घोषणा की और आगे चलकर बुखारा को काफी भीति सहायता भी दी गई। सोवियत सरकार ने अपनी अत्यंत पट्टाई के दिनों में भी १९१८ की पतझड़ में बुखारा का डेढ़ करोड़ रुबल गज देकर वित्तीय तबाही से बचा लिया।\*\*\*\* परन्तु अमीर ने सोवियत सरकार के प्रति अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। उसने ऊंची दर पर जारशाही मुद्रा खरीदी और उसे भारत की मही में इस्तेमाल किया। इसी कारण सोवियत मुद्रा का भाव गिर गया और इससे बुखारा और सोवियत तुकिस्तान के वित्तीय

\* "उत्तरे सोवियत समाजवादी जगत का इतिहास" पृष्ठ २ पृष्ठ १६६।

\*\* ब० ६० इसकदारोव, "सोवियत तुकिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए ब्रिटेन द्वारा बुखारा अड्डे की तैयारी", सोवियत विज्ञान प्रगति के ब्रायज़ान, १९५१, पृष्ठ ४३। (अती सरारण)

\*\*\* वही, पृष्ठ ४१, ४३।

\*\*\*\* वही, पृष्ठ ५०।

सबधो मे उलझन पैदा हुई। अमीर के शत्रुतापूर्ण रवैये की वजह से बखार और सोवियत तुर्किस्तान के बीच व्यापार बन्द हो गया। सोवियत सरकार ने बुखारा के कपास के बदले में कपास का तेल और चावल देने का प्रस्ताव किया, परन्तु बुखारा के शासक हल्की ने इसे अस्वीकार कर दिया ब्रिटेन तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियाँ सोवियत देश की आर्थिक नाकाम कर रही थी। इसमें उनकी सहायता करने के लिए अमीर ने सोवियत तुर्किस्तान से व्यापार करने से इनकार कर दिया और अपना माल, मुख्यतः कपास और ऊन ब्रिटेन और अफगानिस्तान के हाथ हथियारों के बंधे बेचा। अमीर के अधिकारियों ने बुखारा में सोवियत प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यकलाप में बाधा डाली। उन्होंने ट्रांसफास्फियन इलाके के सरगाड वालों को सभी आवश्यक रसद पहुँचाई और उनके विरुद्ध सैनिक कारवाहियों में बाधा डालने के लिए रेलवे लाइनें और तार के खम्भे उखाड़ फेंके और देहकानों को मना कर दिया कि वे सोवियत सैनिकों को खाना बेचने के लिए रेलवे लाइन के निकट नहीं आया कर।

युक्त आयोग ने ताशकन्द पहुँचकर बुखारा का मामला की ओर का ध्यान दिया। ७ जनवरी १९२० को आयोग के सदस्य बुखारा गये और अमीर सैयद अलीम खान से मिले। उन्होंने उसे सोवियत हम से प्रतिरोध सबध कायम करने की आवश्यकता समझाने की कोशिश की, जो एवमात्र बुखारा की पूर्ण स्वतंत्रता तथा आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सामान्य स्थितियों की जमानत दे सकता था। फिर १४ मार्च, १९२० को फ्रूड द्वारा आयोग के अन्य सदस्यों के संग बुखारा आया और अमीर से मिले। परन्तु अमीर ए-बुखारा का सही रास्ते पर लाने के ये सारे प्रयास निरर्थक हुए और सोवियत सरकार के सभी शान्तिपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गये। मुस्लिम मान्यता का वांछितता का विरुद्ध धर्मांधता का भावना उभारने की खुली हट दे दी गई। अमीर ने मशहद में अफ़ेन्डा से प्रतिरोध गन्धर्व म्यापिन किया और अफगानिस्तान से सैनिक संधि का। अगस्त १९२० में उसने १० हजार की मना तयार की और वापस आने का विरुद्ध जहाज का प्रत्यक्ष जारी दिया।

ऐसा स्थिति में बुखारा की घाम जाता का मामला यह था स्पष्ट हो



बहुत बढ़ गई। पार्टी की दूसरी कांग्रेस ताशकन्द में २६-२७ जून, १९१६ को हुई। इसने पार्टी का आह्वान किया कि जनता में अपने प्रचार आन्दोलन को और सबल बनाने और उसके दायरे में जनता के विभिन्न हिस्सों को खींच लाने के लिए ज्यादा मुस्तैदी से कदम उठाये जायें। न० हुसनोंवाली की केन्द्रीय समिति के नये अध्यक्ष चुने गये। तीसरी पार्टी कांग्रेस के एक सत्र, जो ताशकन्द में २६-२९ दिसम्बर, १९१६ को हुई, पार्टी की ३३ शाखाएँ काम कर रही थी, उनमें २४ देहकानों और कारीगरों में १३ सेना में।\* तीसरी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी प्रचार और आन्दोलन का तेज करने पर जोर दिया और इस उद्देश्य से "ताग" (सवेग) और "कुतुलूश" (आजादी) नामक की पत्रिकाएँ ताशकन्द और नये बजार से प्रकाशित की गईं। १९२० की गमियो तक बुखारा में प्रातिवार सत्र परिपक्व हो चुका था। बुखारा के मजदूर, विमान और कारीगर अन्तर्गत के घृणित तथा अत्याचारी शासन का तख्ता उलटने का तयार थे। उन समय तक ४३ पार्टी इकाइयाँ काम कर रही थी और पार्टी सन्ध्या की सख्या ५,००० तक पहुँच गई थी। पार्टी हमदर्दों की सन्ध्या २०,००० था। स्वयं पुराने बुखारा में २१ इकाइयाँ थी जिनमें १,५०० सदस्य थे।\*\* बजार के कम्युनिस्ट अमीर की सेना में भी सक्रिय थे। इरगाश मुसाबायेव ने बड़ी सुयोग्यता से सेना में पार्टी प्रचार किया। अमीर की सेना के भगोशों का लेकर समरखन्द में एक सैन्यदल संगठित किया गया। पार्टी की चौथी कांग्रेस चारजूएँ में १६ से १६ अगस्त, १९२० का हुई। उसने अमीर का सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र प्रातिनारी वाग्वार्ड करने का फैसला किया।

अभी तक नोजवान बुखारिया के साथ बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध की यादत कुछ नहीं कहा गया है। मार्च १९१८ की अगस्ताना के बाद नोजवान बुखारिया की पार्टी का मतार कुछ निम्न के लिए हो गया। परन्तु जनवरी १९२० में वह नुकिम्बान की भूमि पर फिर उभरा। इस में अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार की परिषद ने ६ फ़रवरी, १९२० को उत्तर

\* "उत्तरेक गावियत गमाजगदी जनतत का इतिहास", पृष्ठ १७०।

\*\* वही, पृष्ठ १७२।

कायकलाप को मजूर किया और तुकिस्तान आयोग ने इस मजूरी का अनु-  
मोदन किया। पूव में अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद की २५ मार्च, १९२०

की बैठक में बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान बुखारियों के सच-  
के सवाल पर भी विचार किया गया था। परिपद ने बुखारा के कम्युनिस्टों

के लिए यह आवश्यक कर दिया था कि वे अमीर के खिलाफ सच के  
नौजवान बुखारियों की सहमति से चलाए। परन्तु बुखारा की कम्युनिस्ट

पार्टी इस फसले से खुश नहीं थी। उसकी राय में नौजवान बुखारी पार्टी  
पूजोवादा राष्ट्रवादियों की पार्टी थी और उसका दृष्टिकोण सोवियत विरोधी

और सब इसलामवादी था। पूव में अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद और तुर्क  
आयोग के विदेशी मामला के विभाग का संयुक्त अधिवेशन १९ जून,

१९२० को आयोजित हुआ। उसने नौजवान बुखारी पार्टी के बारे में  
बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी के इस मूल्यांकन से सहमति प्रकट की। उसने

इस बात का समर्थन किया कि नौजवान बुखारी पार्टी में शामिल हो जायें।  
और उनके अधिक प्रगतिशील सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जायें।

उसने नौजवान बुखारियों को वित्तीय सहायता केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की  
परिपद के नियंत्रण में प्रचारकाय के लिए देने की स्वीकृति दी। तुर्क

आयोग की ३० जून, १९२० की बैठक में अमीर के अत्याचारी राज का  
खिला उलटने का फैसला किया गया। उसने नौजवान बुखारियों से सच

पूछने का नारा दिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद को आदेश  
दिया कि वह केवल बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करे। आयोग

न कहा कि नौजवान बुखारी परिवर्ती पार्टी हैं और बुखारा के  
कम्युनिस्ट अतृप्तवर्ग जाति की पार्टी हैं।\*

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद सभी प्रगतिशील और जायादी  
शक्तियाँ के व्यापक मोर्चे का समर्थन करे के पक्ष में थी। उसकी

राय में नौजवान बुखारियों की पूरी पार्टी में हाथ मिला बुखारा की  
जाति के लिए हानिकारक था। नौजवान बुखारी पार्टी के मंत्रीय वर्ग में  
सन्निध के नाम भी एक पत्र निम्नलिखित था जिसमें

\* वही, पृष्ठ १७१।

अनुरोध किया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) का सागठनिक ब्यूरो नतीजे पर पहुँचा कि नौजवान बुखारिया को उनके वर्तमान कार्यक्रम के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल करना सम्भव नहीं है, मगर उन अमीर की सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी सघष में उनसे सहयोग करने का सिफारिश की।

इस सिफारिश की राशनी में तुकिस्तान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रवा की परियद नौजवान बुखारियो तथा बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधिया की संयुक्त बैठक में दोनों पार्टियों के विलयन के मुद्दे पर विचार किया गया। नौजवान बुखारी पार्टी के प्रतिनिधिया ने इस बैठक में बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी पार्टी के कार्यक्रम का मतलब केवल कार्यानीतिक था, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों का भी, जो कम्युनिस्ट कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, अमीर के निरंकुश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी सघष में साथ ताना था। उनका कहना था कि बुखारा में क्रांति की विजय के बाद नौजवान बुखारी पार्टी वाला कम्युनिस्ट पार्टी का नाम और कार्यक्रम अपना लगे। इसी आधार पर तुक आयोग ने नौजवान बुखारियो के समयन का निष्कर्ष किया। उनसे कहा गया कि वे बुखारा के कम्युनिस्टों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाएँ, उनके विरुद्ध सघष करें और भविष्य में दोनों पार्टियों के विलयन की हर तरह तयारी करें। उनसे इन बातों की लिखित रूप में घोषणा करा जा रहा गया, जो उद्देश्य ६ अगस्त, १९२० का किया।\* इसपर बुखारा के कम्युनिस्टों का बोझ पार्टी का प्रेम न भी नौजवान बुखारी पार्टी वाला से अस्थायी एका की सम्भावना का स्वीकार किया। परंतु यहां यह कह देना चाहिए कि नौजवान बुखारी पार्टी वाला के मकसद में बुखारा के कम्युनिस्टों में जो सत्ता थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो गई।

१ अगस्त १९२० का प्रूजे ने लनिन का एक तार भेजकर बुखारा के गठन पर आग्रह मांगा। प्रूजे के मामला का ही गठन था अगस्त १९२०।

\* इसका मासिक गणनागानी जातक का अंकन, पृष्ठ १०६-१०७।

नातिकारी प्रक्रिया के विकास की आशा करना और इसकी प्रतीक्षा करना, या बाहरी सहायता से नाति संगठित करना। उनकी राय में पहला तरीका बहुत धीमा था और इसलिए वह इसके पक्ष में थे कि पहले को बढ़ावा न देकर हर उपाय करते हुए दूसरे पर अमल करना चाहिए। पोलिटब्यूरो ने इस तार पर विचार किया और निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई

- 1. "बुखारा में और बुखारा की सीमा पर इसी लोगों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कारवाई करना, बुखारा के इलाके और बुखारा की सभ्य शक्तियों पर हमला करने में अभी पहल नहीं करना, अग्रेज एजेंटों तथा इस प्रतिनातिवारियों की मिलीभगत से बुखारा द्वारा की जा रही प्रतिक्रातिकारी हरकतों के विरुद्ध मुसलमानों में व्यापक प्रचार करना जिसमें बुखारा के आन्दोलन के दौरान में एक देशी सेना तैयार करना जिसमें बुखारा के कम्युनिस्ट भी शामिल हों, और इन प्रतिरक्षात्मक कारवाइयों को आनामक रूप तथा देना, जब जनप्रिय नातिकारी केन्द्र बुखारा में बन जाये और महापता का अनुरोध कर।"

यह बता देना उचित होगा कि सोवियत सरकार और पार्टी में जिम्मेदार लोग खोवा या बुखारा में नाति का निर्यात करने के सदा विरोधी थे। परन्तु इसका समय नौजवान खोवाई और नौजवान बुखारी किया। परन्तु इनके बारे में सोवियत सरकार ने एक बार कहा था कि वे 'मध्य एशिया के दिसम्बरवादी हैं, जो इतिहास से कोई सबब नहीं सीखना चाहते।' उनके लिए जनता का नातिकारी बनाने का भाग बहुत लम्बा था। इसलिए खोवा और बुखारा के उत्पीड़ित लोगों को बाहर से तुकिस्तान की सैन्यीकृत सत्ता की सहायता के बिना "एशियाई दिसम्बरवादि" की आलाचना करनी पड़ी। इसलिए न इन "एशियाई दिसम्बरवादि" की शापित जनता अपनी अज्ञानता से 'मुक्ति' लानेवालों को वहीं वदेशिक हमलावर न समझ बैठे।

वहाँ, पृष्ठ १७८-१७९।

इरगितिया तुर्क लोका', ५ अगस्त, १९१९। (इसी संस्करण)

यह याद दिला दिया जाय कि तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी चौथी कांग्रेस ने भी, खीवा और बुखारा के लोगो पर बाहर से शोषण की धारणा का विरोध किया था। वर्तमान परिस्थिति के सामने प्रस्ताव में कहा गया था कि "हमें उस स्वाभाविक क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब खीवा और बुखारा के लोगो के भीतर स्वयं प्रेरित उथल-पुथल आये, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि तुकिस्तान सोवियत जनतंत्र के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य शक्ति द्वारा कार्रवाई का झूठा वन जायें।"\*

बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १९२० को चारजून के मुक्त करने बुखारा में क्रांति शुरू की। उसकी अपील पर फ्रेंच के नाम से सोवियत सेनाएँ जन मुक्ति संग्राम में सहायता करने आयीं। भारी लड़ाई के बाद सोवियत सेना ने ६ सितम्बर, १९२० को निरंकुश राज के विरुद्ध बुखारा पर अधिकार कर लिया। ५ अक्टूबर, १९२० को पहली क़ुहस्तानी बुखारा में आयोजित हुई। उसने बुखारा का सोवियत जनवादी जनतंत्र घोषित किया।\*\* ३ नवम्बर १९२० को इसी सो० सं० म० जनतंत्र का

\* 'तुकिस्तानस्वी कम्युनिस्ट', २० सितम्बर, १९१६। (रुसा म०)

\*\* अफगान अमीर ने खीवा और बुखारा को मायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था जिसपर भारत के लिए राज्य मंत्री और भारत के वादग्रस्त म० कुछ पत्र व्यवहार हुआ। भारत के लिए राज्य मंत्री ने अक्टूबर १० न० १७८४, दिनांकित ६ मई, १९२२ के तार में मायता नहीं प्रदान करवाया गया किया। "जब तक बहादुरी सहायता सरकार नहीं हो जाय जिसे मैजस्टी की सरकार किसी तरह भी खीवा और बुखारा का स्वाधीनता का मायता नहीं प्रदान कर सकती और फिर उम समय तक भी नहीं जब तक कि वह न मुसलमानों में उनकी स्वतंत्र हैसियत निर्दिष्ट हो जाय। तब तक तब तक की जिन्हीं से प्राप्त जा १६ तार रखा गया था कि वह न जमा था उसका मुसलमान अमीर बुखारा ने जान लिया। उसने कहा अफगान पंजी हुई था कि अमीर भारत आकर रहता था। १६। शुभ जीवन बुखारा एजेंट अमीर की परकी वर १९२३ में भारत में ५। मगर उम समय तक वह मायता मता मियर हो चुकी थी मन्त्रि-सद्वर १। हस्तोप करता उचित नहीं समझा।



## सोवियत सत्ता की स्थापना २०७

बुधारा जनतन्त्र के बीच एक सैनिक और राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर  
 हो गये। बुधारा के सोवियत जनवादी जनतन्त्र ने रु० सो० स० स० जनतन्त्र  
 के साथ एक आधिक्य संधि भी की जिसके अनुसार दोनों राज्या न अपनी  
 आधिक्य नीतिया और योजनाओं को समन्वित करने का फैसला किया।  
 रु० सो० स० स० जनतन्त्र ने बुधारा के जनतन्त्र को पांच अरब रूबल  
 असाध्यनीय ऋण दिया। रु० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ सहयोग की  
 बदौलत बुधारा का तेज़ी से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सम्भव हुआ।

यह याद दिला दिया जाय कि तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की योवाग्रेम न भी खीवा और बुखारा के लोग पर बाहर से शक्ति इन की धारणा का विराध किया था। वतमान परिस्थिति के सबध प्रस्ताव में कहा गया था कि "हम उस स्वाभाविक क्षण की प्रतीक्षा नहीं चाहिए जब खीवा और बुखारा के लोग के भीतर स्वयं शक्तिकारी लक्ष्य प्राप्त आय, तबिन इम बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वे अन्तर्गत सावियत जनतन्त्र के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य शक्ति द्वारा कारवाई भ्रष्टा बन जायें।"

बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १९२० को पारलूए का न करने बुखारा में शक्ति शुरू की। उसकी शक्ति पर फ्रूजे के नेतृत्व शक्तियुक्त मनाए जन मुक्ति संग्राम में सहायता करने आयी। भारी लड़ाई का सावियत गना ६ सितम्बर, १९२० को निरंकुश राज के विल गग पर अधिकार कर लिया। ५ अक्टूबर, १९२० को पहली कृषकताई गग में आयोजित हुई। उसने बुखारा को सोवियत जनवादी जनतन्त्र में लिया।\*\* २ नवम्बर १९२० को हमी सो० म० म० जनतन्त्र तथा

\* 'तुर्किस्तानम्भी कम्युनिम्न २० सितम्बर, १९१९। (रूसी म)  
अपमान अमीर १ खीवा और बुखारा का मायता प्रदान कर का गग रखा था तबपर भारत के लिए राज्य मंत्री और भारत के गराय में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। भारत के लिए राज्य मंत्री १ अप्रैल १० १७८८, शिनिनि ६ मई, १९२२ के तान में मायता नहीं प्रता १ का का लिया। "जब तब कहा म्यायी अदली सरकार नहा हा र हिन्दु भजेन्टी की सरकार किमी तरह भी खीवा और बुखारा की धीनाता का मायता रहा प्रदा कर मन्त्री और फिर उम समय तब तान, जब तब मग के मन्त्रालय में उनकी मन्त्र हैमियत निश्चित हा र'। सन्त म मगलून की विन्नी म प्राप्त जा १६ लाख म्याया म्मई गग म म मग था, उन्ना म्मलून अमीर म-बुखारा ने जान लिया। शिनि म्म अन्नाह फरी हुई था कि अमीर भारत आकर गगना चाना बुखारा गोजवा बुखारा एजट अमीर की परकी मग १९२३ में भारत आय मगर उम समय तब कहा मायता मता स्थिर म चुकी थी, म्मलून म १ म्मलून मग उन्ना नहीं मगमा।

बुखारा जनतन्त्र के बीच एक सैनिक और राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। बुखारा के सोवियत जनवादी जनतन्त्र ने रू० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ एक आर्थिक संधि भी की जिसके अनुसार दाना राज्या ने अपनी आर्थिक नीतियाँ और योजनाएँ को समर्थित करने का फैसला किया। रू० सो० स० स० जनतन्त्र ने बुखारा के जनतन्त्र को पाँच अरब रूबल अशासनीय ऋण दिया। रू० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ सहयोग की बदौलत बुखारा का तेजी से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सम्भव हुआ।

### प्रतिप्राप्ति तथा यदेनैव हस्तक्षेप के विरुद्ध सघष

१९१८ की गमिया में तुर्किस्तान में गृहयुद्ध और वैश्विक सत्ता हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। बागान "स्वायत्त" सरकार के विघटन में तुरन्त बाद ही परगाना में बासमधी आन्दोलन आरम्भ हुआ और तुर्किस्तान की हानत घिर हुए तिल की हो गई जिमारे चारा और मारना की माना गी बन गई थी। खीया का गान शाणित क्षेत्र और बुचारा का घमार नासित क्षत्र साखियन तुर्किस्तान पर हमला करा के अट्टे बन गये। दामनागिया इतारे में गफे गादों में गमाजवागी प्रातिनागिया तथा भोशिरा में लम्बे करके साखियन मत्ता में उनटन की कारनाई मगदित की। प्रतिप्राप्तिगरी अस्थायी दामनागिया सरकार की स्थापना का गई। नम कारनाई में हुआ ही त्रिटिग सत्ता हस्तक्षेप लम्बा। गफे जारन हूतान में आरातुग पर लम्बा कर लिया और तुर्किस्तान का मध्य हम में मध्य भाग में लिच्छ हो गया। जेरीमुन द्वात में प्रतिप्राप्तिगरी बुचरे और गफे करजाना में साखिया मत्ता में लिच्छ लम्बा उठा लिया। ताशत में लम्बा प्रतिप्राप्तिगरी लम्बी तुर्किस्तान सत्ता मगदित में लम्बा में दामनागी लम्बा में ताशतवा में स्थापित का गई। लम्बा घण्टा में लम्बा मगदित लिया, लिच्छो हवियार और घा लम्बा लम्बा बाग लिच्छ। लम्बा बागमधी प्रधान दरगाज घनार लम्बागरी और खीया में बुचरे लम्बा में मगदित स्थापित लिया।

सावियत तुकिस्तान के लोगों ने इस बठिन स्थिति का मुकाबला बड़े साहस के साथ किया और सोवियत सत्ता की प्रतिरक्षा में और अक्टूबर, १९१८ का तुकिस्तान की केन्द्रीय वायमारिणी समिति और सोवमारफोम तथा रनवे मजदूरों की वायमारिणी समिति ने एक संयुक्त बैठक में प्रसाधारण छानबीन आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया जिसका काम राजनीतिक स्थिति पर नज़र रखना और प्रतिश्रांतकारियों के विरुद्ध सघप करना था। इसी आयोग ने तुकिस्तान सैनिक संगठन के अस्तित्व का पता चलाया और अग्रजों से उसके सघप का परदाफाश किया। इस संगठन के एक भाग का कुचल दिया गया, परंतु शेष वामपक्षी समाजवादी-श्रांतिकारियों की सहायता से जो सत्ता में बाल्गेविका के माझेदार थे, और युद्ध कमिसार आसिपोव जैसे गद्दारा की सहायता से बच गये। १८-१९ जनवरी १९१९ की रात आसिपोव ने सावियत सत्ता के खिलाफ प्रतिश्रांतिकारी बगावत की। सरकार के सभी महत्वपूर्ण बाल्गेविक सदस्य तथा तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता गिरफ्तार किये गये और मार दिये गये। परंतु ताशकंद के मजदूर और सैनिक सावियत सत्ता के समर्थन में खड़े रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों में भी आसिपोव के विरुद्ध सशस्त्र सघप में भाग लिया। आसिपोव भागकर बासमच्चियों से जा मिला। जनगण ने सत्ता पर अधिकार करने के उसके प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया।

साम्राज्यवादियों ने फरगाना में बासमच्ची आन्दोलन से बड़ी उन्मीदें बांध रखी थीं। यह जनविरोधी आन्दोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान में मुल्तामा सामंतवादियों तथा पंजीवादी राष्ट्रवादी तत्वों का शासन स्थापित करना था। जूनि श्रमजीवी जनता में उसका कोई व्यापक आधार नहीं था, इसलिए उसे अधिकतर वैदेशिक साम्राज्यवादियों के समर्थन पर निर्भर करना पड़ता था। इसके अनुयायी मुख्यतः जारशाही प्रशासन के भूतपूर्व पदाधिकारी थे, जैसे आकसवाल, मोरख तथा बोलास्त प्रशासक तथा मुल्तामा में से थे। बासमच्चियों की पक्तियों में अगर स्पष्ट रूप से किसी की अनुपरिधि दिखाई देती थी, तो वे गरीब किसान और कारीगर

प्रतिप्राति तया यदनिष हस्तभय के विन्दु सपय

[illegible]

सोवियत तुकिस्तान ने लोगो ने इस कठिन स्थिति का मुकाबला बड़े साहस के साथ किया और सोवियत मत्ता की प्रतिरक्षा में और अदस्ती तथा बाहरी सभी शत्रुओं के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। ५ अक्तूबर, १९१८ को तुकिस्तान की नैट्रीय कायवारिणी समिति और सोवनारफोम तथा रेलवे मजदूरों की कायवारिणी समिति ने एक संयुक्त बैठक में असाधारण छानबीन आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया जिसका काम राजनीतिक स्थिति पर नज़र रखना और प्रतिभातिवारिया के विरुद्ध संघर्ष करना था। इसी आयोग ने तुकिस्तान सनिक संगठन के अस्तित्व का पता चलाया और अग्रजों से उसके संघ का परदाफाज किया। इस संगठन के एक भाग का बुचल दिया गया, परन्तु शेष वामपक्षी समाजवादी नातिकारिया की सहायता में जो सत्ता में बोल्शेविकों का साथेदार थे, और युद्ध कमिसार ओसिपोव जैसे गद्दारों की सहायता से बच गये। १८-१९ जनवरी, १९१९ की रात ओसिपोव ने सोवियत सत्ता के खिलाफ प्रतिभानिकारी बगावत की। मरकार के सभी महत्वपूर्ण बोल्शेविक सदस्य तथा तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता मिरफ्तार किये गये और मार दिये गये। परन्तु ताशकन्द के मजदूर और सैनिक सोवियत सत्ता के समर्थन में उठे रहे। उन्हीं स्वयंसेवकों ने भी ओसिपोव के विरुद्ध संशस्त्र संघर्ष में भाग लिया। आसिपोव भागकर बासमचियो से जा मिला। जनगण ने मत्ता पर अधिकार करने के उसके प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया।

साम्राज्यवादियों ने फरगाना में बासमचों आन्दोलन से बड़ी उम्मीद बाध रखी थी। यह जन विरोधी आन्दोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान में मुस्लाओ, सामतवादियों तथा पंजीवादी राष्ट्रीयवादी सत्ता का शासन स्थापित करना था। चूंकि अमजीवी जनता में उसका कोई व्यापक आधार नहीं था, इसलिए उसे अधिकतर वैदेशिक साम्राज्यवादियों के समर्थन पर निर्भर करना पड़ता था। इसके अनुयायी मुख्यतः ज़ारशाही प्रशासन के भूतपूर्व पदाधिकारी थे, जैसे आक्सकाल, मोरव तथा वोलोस्त प्रशासक तथा मुस्लाओ में से थे। बासमचियों की पकिया में अगर स्पष्ट रूप से किसी की अनुपस्थिति दिखाई देती थी, तो वे गरीब किसान और कारीगर

ये, सिवा चंद लोगो के, जो या तो अपने अत्यंत पिछड़ेपन के कारण या भय से कुछ दिनों के लिए उनके साथ हो गये थे। ऐसे अपराधी, जो बाई लोगो और धनी व्यक्तियों के सरक्षण में रहते थे और उनके इशारे पर हर तरह का पाप करते थे बड़े शौक से इस आंदोलन में शामिल हो गये जिसमें उनके लिए बड़ा मौका था। बासमच्चियों के अधिकार में जो इलाके थे, वहां स्थिति पुराने खान प्रशासन के दिनों से कुछ अधिक भिन्न नहीं थी।

बासमच्चियों ने सोवियत सरकार के विरुद्ध जेहाद का एलान कर दिया। प्रारम्भ में उन्हें कुछ सफलता मिली, क्योंकि फरगाना में किसानों का बहुमत शुरू में बासमच्चियों के विरुद्ध सघर्ष में तटस्थ था। फरगाना के किसानों की इस तटस्थता का कारण उनकी आर्थिक स्थिति का स्पष्टतः खराब होना था। यह खराबी प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों से शुरू हुई, जब निमित्त सामान और खाद्यान्न का दाम बहुत बढ़ गया था, जबकि फरगाना की मुख्य पैदावार—कपास का दाम कमोबेश स्थिर था।

यह स्थिति ओरेनबुर्ग की नाकाबंदी के कारण और बिगड़ गई। फिर यह बात भी थी कि तुकिस्तान आयोग के पहुंचने से पहले देहकानों में पार्टी ने बहुत कम प्रचारकाय किया था और उनके कुछ बुनियादी हितों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाया गया था। बाजार बिल्कुल बन्द थे तथा खाद्यान्न की बसूली के मामले में भेदात्मक वगैरह दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। कुछ स्थानीय बोलशेविका द्वारा पार्टी की जातीय नीति की विवृति भी बासमच्चियों और पंजीवादी राष्ट्रवादियों के काम आयी, जिन्होंने फरगाना में फैले हुए आर्थिक असंतोष से पूरा लाभ उठाया।

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि १९१८ से १९२० तक फरगाना में बासमच्चों आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। परन्तु वह कभी भी जनआंदोलन नहीं बन सका और स्थानीय किसानों में साक्षरता सत्ता के प्रति शत्रुता की भावना जगाने में सफल नहीं हो सका। फरगाना की २० लाख की आबादी में १० हजार बासमच्चों नगण्य अल्पमत थे। बासमच्चों की प्रारम्भिक सफलताएँ किसी व्यापक जन-समर्थन की वजह से नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध सघर्ष के बड़ी हद तक असंगठित होने की



वज्र से थी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ज्यों ज्यों किसानों को सोवियत सत्ता की धारणाओं और उद्देश्यों का ज्ञान होता गया, वे बासमचियों के विरुद्ध संघर्ष में अधिक सक्रिय होते गये।

रावान सरकार के पतन के बाद उसका सेनापति इरगाश बासमचियों का प्रधान बन गया। उगने बाबूरी को अपना बेदर बनाया और वहाँ से शहरा और गावा पर हमले किये। शीघ्र ही एक और बासमची दल मदामिन बेक के नेतृत्व में रायम हुआ जिसे पूजीवाणी राष्ट्रवादिया ने मंगिलान शहर की मिलिशिया का प्रधान नियुक्त किया था। इसी कुलक और आप्रवासी भी, जिनने हित सोवियत सत्ता से टकराते थे, बासमचियों के साथ हो गये। इसी कुलक मानस्त्राव के नेतृत्व में तथाकथित किसान मेना ने मोश पर कब्जा कर लिया और बासमचियों से जा मिली। मदामिन बेक ने इन सब भाति भाति के गिरोहों को एकत्रित किया और फरगाना की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। इस सरकार में ज़ारशाही जनरल, इसी कुलकों और कपास कर्षों के प्रतिनिधि, स्थानाय बाई और मुल्ला लोग थे। मार्च-अप्रैल १९१८ से १९१९ की पतझड़ तक बासमचियों ने फरगाना घाटी में बड़ा उत्पात मचाया। वे लूट मार करते, फँक्टरियों और खानों को नष्ट करते और जिस किसी पर सोवियत सत्ता के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह होता, उसपर पाश्विक अत्याचार करते।

यह स्थिति तब तक जारी रही जब तक कोल्चाक की पराजय के बाद फ्रूजे की कमान में तुकिस्तान मोरचा नहीं बन गया। लेनिन की पहलवदमी पर फ्रूजे, कूदविशेष तथा अन्य लोगों को लेकर तुकिस्तान आयोग कायम किया गया और उसे तुकिस्तान के श्रमजीवी जनगण द्वारा उनकी आतिथारी सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता करने के लिए ताशकन्द भेजा गया। उस आयोग ने पार्टी और सोवियत सत्ताओं के नवीनीकरण का काम शुरू करने के अलावा फरगाना घाटी में बासमचियों के विरुद्ध और ट्रांसवासियन इलाके और जेतिसुव में सफेद गार और सफेद बज्जाओं के विरुद्ध जनता का संघर्ष संगठित करने में सक्रिय भाग लिया। उसके निर्देशन में लाल सेना का पुनर्गठन किया गया। उसे बगन्बुत दुसाहसी तथा सवेह

जनक तत्वों से बिल्कुल साफ किया गया। तुकिस्तान आयोग ने स्वेच्छा पूर्वक भरती के आधार पर स्थानीय जातियों के जनगण को लेकर ३० हजार की सेना सफलतापूर्वक संगठित की। केवल फरगाना घाटी में दस हजार स्थानीय लोग लाल सेना में शामिल हुए। फरवरी माच १९२० तक बासम चियों के विरुद्ध अभियान में काफी सफलता प्राप्त हो चुकी थी और गमियों तक फरगाना में उनके दल नष्ट कर दिये गये थे। परन्तु कुछ दल १९२३ तक लूट मार करते रहे, क्योंकि जब अनवर पाशा ने उनका नेतृत्व सभाला, तो उनमें नई जान आ गई थी। मगर १९२० के बाद बासमची सोवियत सत्ता के लिए कोई गम्भीर खतरा नहीं रहे।

इसी तरह १९२० तक ट्रांसकास्पियन इलाके और जेतीसुब में भी प्रतिप्रातिकारी मसूबों पर पानी फिर गया जब सफेद गान्ध और सफेद कज़ाखों को शिकस्त हुई और ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों को पीछे हटना पड़ा। परन्तु तुकिस्तान के लोगों को, जो बहुत दिना तक केन्द्र से कटे और चारों ओर मारचों से घिरे रहे थे, अधिकतर स्वयं अपने बल-बूते पर लड़ना पड़ा। उन्हें बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उनके पास खाद्यान्न तथा हथियारों और गोले-बारूद का अभाव था। फिर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़े। गृहयुद्ध में वे विजयी हुए, क्योंकि यह मुक्ति का यादपूर्ण युद्ध था जिसे जनगण औपनिवेशिक गुलामी और सामंती अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता और सम्पन्न जीवन के महान उद्देश्य की खातिर लड़ रहे थे। गृहयुद्ध में जनगण ने जिन महान उद्देश्यों के लिए प्राणा की बाज़ी लगायी, उमने उनमें सावियत देशभक्ति की प्रबल भावना को जन्म दिया।

गृहयुद्ध में सोवियत सत्ता की विजय के महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह था कि लेनिनवादी जातीय नीति पर ईमानदारी से अमल किया गया जिसकी बदौलत तुकिस्तान की सोवियत स्वायत्तता का निर्माण किया गया था, सत्ता की सभी संस्थाओं में स्थानीय श्रमजीवियों की व्यापक शिरकत सुनिश्चित की गई तथा औपनिवेशिक और सामंती अतीत के सभी अवशेषों को मिटाने के लिए सघन किया गया। सबहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा जातियों की मैत्री भी गृहयुद्ध के दौरान प्रबल हुई। स्थानीय जातियों के

श्रमजीवी जनगण के अलावा, जिन्होंने अपनी समाजवादी भावभूमि की रक्षा में देशभक्ति की उच्च भावना का परिचय दिया, अनेक यूरोपीय देशों के किसानों और मजदूरों ने भी, जो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध बन्दी होकर तुर्किस्तान आये थे और साथ ही पड़ोसी एशियाई देशों के जनगण के क्रांतिकारी प्रतिनिधियां ने भी, जिनमें कुछ भारत के भी थे, सोवियत सत्ता की विजय में योगदान किया।

### आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन

गृहयुद्ध का समय तुर्किस्तान के जनगण के जीवन में आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए भी उल्लेखनीय है। बावजूद इसके कि सोवियत सत्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसने गृहयुद्ध के दिनों में ही एक नये समाजवादी आर्थिक ढांचे की बुनियाद डाली और जनगण के सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन किये।

उद्योगों के समाजवादी रूपांतरण की दिशा में प्रारम्भिक कदम अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद ही उठाये गये थे। १९१७ के अंत से १९१८ के मध्य तक सभी उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और बैंकों, परिवहन तथा वैदेशिक व्यापार आदि का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। भूमि के राष्ट्रीयकरण की भी घोषणा कर दी गई थी। छाद्यान्त में राजकीय इजारा स्थापित किया गया और भूमि सुधार लागू करने के लिए गांवों में गरीबों की समिति बनाई गई। उद्योगों पर मजदूरों के नियंत्रण की स्थापना तथा मुख्य उद्योगों और रेलवे के राष्ट्रीयकरण से सबहारा के अधिनायकत्व का आर्थिक आधार तैयार हो गया। मजदूरों के नियंत्रण की पद्धति की स्थापना १९१७ के अंत में किसी हद तक स्वतः स्फूर्त ढंग से हुई और सोवियत सत्ता ने इसे पूँजीपतियों द्वारा तोड़फोड़ के विरुद्ध बग सघर्ष के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि पूँजीपति उत्पादन को कम करना और उद्योगों को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। सोवियत सत्ता ने मजदूरों के नियंत्रण की प्रथा को बग-सघर्ष के रूप में तथा औद्योगिक प्रवर्धन में उनके

प्रशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन की दिशा में वह महत्वपूर्ण मजिल सिद्ध हुई।

मार्च १९१८ में बैंक कमचारियों की तीसरी असाधारण कांग्रेस ताशकंद में हुई। कांग्रेस ने बैंक के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार किया और अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार की सहायता करने की तत्परता व्यक्त की। मई १९१८ तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अब सोवियत राज्य के हाथों में सकेन्द्रित हो चुकी थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सोवियत सत्ता ने पजीपति वर्ग को उसके आर्थिक प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र से वंचित कर दिया।

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १ मार्च, १९१८ को जेतीसुब रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ३१ मार्च को फरगाना रेलवे और अप्रैल १९१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।

मार्च अप्रैल १९१८ में अलग-अलग उद्यमों का ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों की पूरी की पूरी शाखाओं का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ५ मार्च, १९१८ को समस्त रुई उद्योग और साबुन, तेल आदि जैसे सहायक उद्योगों का भी सोवियतकोम की एन आज़ाप्ति द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। रुई की निजी खरीद बिनी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और रुई के बड़े जखीरे जम्त कर लिए गये। कोयला और तेल उद्योगों का भी उसी महीने राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च के अंत तथा अप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकड़ने का उद्योग, छापेखाने, आटा, शर्करा तथा चावल उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

जून १९१८ में पूरे क्षेत्र में उन औद्योगिक इकाइयों की संख्या गिनकर राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, २०४, जुलाई में २४५ और सितम्बर में २८३ तक पहुँच चुकी थी।\* साल के उत्तरार्द्ध में कई छोटे और मध्यम

\* व० नेपामनिन, "उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, १९१७-१९३७", पृष्ठ ६६।

उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। मगर यह गलती थी जिसका कारण अत्यधिक विचारधारात्मक उत्साह था। शुरू में राष्ट्रीयकरण के सार की उचित समझ बहुत कम थी और राष्ट्रीयकृत उद्यमों का प्रबंध मजदूरों की फ़ैक्टरी या कारखाना समिति द्वारा किया जाता, जो समाजवादी क्रान्तिकारियों के विचारों के प्रभाव में अक्सर इस अपनी सामूहिक सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादन में कुछ दुर्घटन उत्पन्न हुईं। परन्तु मार्च १९१८ में इसका सुधार हो गया, जब सोवियतकॉम ने जन-अथवा जन-अथवा की क्षेत्रीय परिषद (सोवियतकोऑ) स्थापित करने का फैसला किया। अप्रैल १९१८ में उत्पादन की एक क्षेत्रीय परिषद गठित की गई और उसे उत्पादन संगठित करने और क्षेत्र के आर्थिक जीवन को नियमित करने के लिए मानदंड और योजनाएँ तैयार करने का काम सौंपा गया। आगे चलकर इस संस्था का पुनर्गठन जनअथवा की उच्च परिषद के रूप में किया गया जिसके कार्य वही थे। प्रत्येक ओब्लास्त में औद्योगिक उद्यमों का निरीक्षण करने के लिए जनअथवा की परिषद की स्थापना की गई। अगस्त सितम्बर १९१९ में जनअथवा की परिषदों की प्रथम कांग्रेस के समय १८ ऐसी परिषदें (सोवियतकोऑ) थीं। १९१९ के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई थी। परन्तु बाद में कुछ की भग और दूसरा का विलयन कर दिया गया जिससे उनकी संख्या घट गई। जुलाई १९२० में सोवियतकोऑ की दूसरी कांग्रेस ने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सोवियतकोऑ के वायकनाम के परिणामों पर विचार विमर्श किया। १९२० तक उनकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १९२१ में फ़ैक्टरी-प्लांट किस्म के कोई ८६६ उद्यम थे जिनमें ३२,५३३ मजदूर काम करते थे। इन ८६६ में से ४०५ गृहयुद्ध के दौरान पदा हुई आर्थिक दुर्घटन के कारण चालू नहीं थे।\*

१९१८ की गमियों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमें श्रम-अनुशासन के सवाल पर विचार किया गया और इस संबंध में कई सिफारिशें की गईं। तुर्किस्तान केन्द्रीय वायकारिणी समिति ने कारखानों और फ़ैक्टरी में

\* वही, पृष्ठ १०१-१०२।

पशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन की दिशा में वह महत्वपूर्ण मजिल सिद्ध हुई।

मार्च १९१८ में बक कमचारियों की तीमरी असाधारण वाग्रस ताशकद में हुई। कांग्रेस ने बैंको के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार किया और अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार की सहायता करने की तत्परता व्यक्त की। मई १९१८ तक बैंको का राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अब सोवियत राज्य के हाथों में सकेन्द्रित हो चुकी थी। बैंको का राष्ट्रीयकरण करके सोवियत सत्ता ने पजीपति वर्ग को उसके आर्थिक प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र से वंचित कर दिया।

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १ मार्च, १९१८ को जेतीसुव रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ३१ मार्च को फरगाना रेलवे और अप्रैल १९१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।

मार्च अप्रैल १९१८ में असंगतलग उद्यमों का ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों की पूरी की पूरी शाखाओं का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ५ मार्च, १९१८ को समस्त रूई उद्योग और साबुन, तेल आदि जैसे सहायक उद्योगों का भी सोवनारकोम की एक आनप्ति द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। रूई की निजी खरीद बिनी पर प्रतिबध लगा दिया गया और रूई के घड़े जखीरे जन्त कर लिए गये। कोयला और तेल उद्योगों का भी उसी महीने राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च के शत तथा अप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकड़ने का उन्नाग, छापेखाने, आटा, शक्कर तथा चावल उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

जून १९१८ में पूरे क्षेत्र में उन औद्योगिक इकाइयों की सख्या जिनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था २०५, जुलाई में २८५ और सितम्बर में २८३ तक पहुँच चुकी थी।\* साल के उत्तरार्द्ध में कई छोटे और मध्यम

---

\* व० नषामनिन, उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, १९१७-१९३७, पृष्ठ ९९।

उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। मगर यह गलती थी जिसका कारण अत्यधिक विचारधारात्मक उत्साह था। शुरू में राष्ट्रीयकरण के सार की उचित समझ बहुत कम थी और राष्ट्रीयकृत उद्यमों का प्रबंध मजदूरों की फँटनी या कारखाना समिति द्वारा किया जाता जो समाजवादों आतिकारिषा के विचारों के प्रभाव में अक्सर इसे अपनी सामूहिक सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादन में कुछ दुर्गन्धवस्था उत्पन्न हुई। परन्तु मार्च १९१८ में इसका सुधार हो गया, जब सोवियतकोम ने जन अथतः की क्षेत्रीय परिषद (सोवियतखोज) स्थापित करने का फैसला किया। अप्रैल १९१८ में उत्पादन की एक क्षेत्रीय परिषद गठित की गई और उस उत्पादन संगठित करने और क्षेत्र के आर्थिक जीवन को नियमित करने के लिए मानदंड और योजनाएँ तैयार करने का काम सौंपा गया। आगे चलकर इस संस्था का पुनर्गठन जन अथतः की उच्च परिषद के रूप में किया गया जिसके कार्य वही थे। प्रत्येक ओब्लास्त में औद्योगिक उद्यमों का निदेशन करने के लिए जन अथतः की परिषद की स्थापना की गई। अगस्त मितम्बर १९१९ में जन अथतः की परिषदों की प्रथम कांग्रेस के समय १८ ऐसी परिषदें (सोवियतखोज) थीं। १९१९ के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई थी। परन्तु बाद में कुछ का भग और दूसरों का विलयन कर दिया गया जिससे उनकी संख्या घट गई। जुलाई १९२० में सोवियतखोजों की दूसरी कांग्रेस ने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सोवियतखोजों के कामकाज के परिणामों पर विचार विमर्श किया। १९२० तक उनकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १९२१ में फैक्टरी-प्लांट किस्म के कोई ८६६ उद्यम थे जिनमें ३२५३३ मजदूर काम करते थे। इन ८६६ में से ४०५ गृहयुद्ध के दौरान पैदा हुई आर्थिक दुर्गन्धवस्था के कारण चालू नहीं थे।\*

१९१८ की गमियों में ट्रेड-यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमें धर्म-अनुशासन के सवाल पर विचार किया गया और इस संबंध में कई सिफारिशें की गईं। तुर्किस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने कारखानों और फैक्टरी में

\* वही, पृष्ठ १०१-१०२।





देने की इजाजत केवल अपवाद के रूप में स्थानीय भूमि समिति की आज्ञा से और वह भी एक साल में अधिक के लिए नहीं दी जाती थी और इसके लिए भी स्थानीय सोवियत की अनुमति जरूरी थी। भूमि समितियों के संगठन के संबंध में अस्थायी सरकार का अधिनियम बदल दिया गया।\* दिसम्बर १९१७ में सोवियतकोम ने आप्रवासी प्रशासन द्वारा आप्रवासियों को जमीन देने से रोक दिया।\*\* बाद में कई बड़ी जमींदारियां का राष्ट्रीयकरण किया गया। १३ मार्च, १९१८ को जारी की गई सोवियतकोम की आज्ञा के तहत सभी सिचाई नहरें और नाले भूमि कमिसारियत के जिम्मे वर दिये गये। तुकिस्तान में सोवियत सत्ता की भूमि नीति के इन बुनियादी सिद्धांतों का अनुमोदन १७ नवम्बर, १९२० को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा सोवियतकोम द्वारा स्वीकृत अधिनियम के तहत कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रारम्भिक धाराओं में घोषणा की गई कि तुकिस्तान जनसत्ता के भीतर सारी भूमि और जल जनगण की राजकीय सम्पत्ति है।

परन्तु भूमि-सुधार को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। जमींदारी और सामंती भूमि व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया बहुत धीरे चल रही थी और १९२५-१९२८ तक जाकर पूरी हुई। इस विलम्ब का कारण तुकिस्तान की विशेष स्थितियां, वहां के सामाजिक आर्थिक संबंधों का अधिक पिछड़ापन, रूस के मध्यवर्ती इलाकों की तुलना में यहां के बेहकानों की चेतना और उनके संगठन का अपेक्षाकृत धीरे विकास, पितृसत्तात्मक कबायली स्थिति के अतगत किसानों पर सामंतवादियों और मुल्ताओं का असर तथा बासमन्तियों के विरुद्ध लम्बा संघर्ष था।

परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद इस अवधि में कृषि के समाजवादी पुनर्गठन की दिशा में कुछ प्रारम्भिक कदम उठाये गये। १९१८-१९१९

\* 'तुकिस्तानस्कीये वेदोमोस्ती', अंक १६०, ६ दिसम्बर, १९१७।

\*\* "तुकिस्तान में महान् अवतूवर समाजवादी आति की तैयारी और तामील, दस्तावेजों का संग्रह", ताशकन्द, १९६७, पृष्ठ २४१। (रूसी संस्करण)

मे ही तुकिस्तान मे ४०० कृषि कम्पून और आर्तेल उत्पन्न हुए। चालीस हजार किसान उनमे शरीक हुए और उनके पास ३५ हजार बेसियातीना जमीन थी। मगर ये प्रारम्भिक कम्पून बस जीवन निर्वाह कर लेते थे। उनका कोई ठोस आर्थिक और तकनीकी आधार नहीं था। उनका उद्देश्य यह था कि युद्ध के प्रारम्भिक कठिन दिना में गावों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गरीबों की बड़ी संख्या को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया जाये। ये कम्पून बिल्कुल स्वेच्छाकृत थे और अलग बेहकानों के अथवात्र को मिलाया नहीं गया। केन्द्र से खाद्यान्न की सप्लाई की बदौलत इन कम्पूनों की कोई जरूरत नहीं रह गई और उन्हें तोड़ दिया गया। परन्तु इनसे कुलको और बाई लोगों के प्रचार का खोजलापन जाहिर हो गया कि सामूहिक कृषि अवास्तविक चीज है। इन कम्पूनों के अलावा तुकिस्तान में १७ सोवखोज (राजकीय फार्म) भी संगठित किये गये जिनके पास कुल २८,५०० बेसियातीना जमीन थी। इन फार्मों को भी शुरू में बड़ी कठिनाइयाँ हुईं। मवेशी की बड़ी कमी थी और इसलिए जमीन किसानों का बटाई पर देनी पड़ी, मगर बटवारा अधिक न्यायपूर्ण, यानी फसल के ४/५ से ७/८ तक के आधार पर किया जाता था।

सोवियत सत्ता ने जेतीसुव में भूमि सुधार के काम पर तत्काल ध्यान दिया। वहाँ रूसी आप्रवासियों के आकर बसने से देशी किगिज़ लोगों को बहुत हानि पहुँची थी। किगिज़ खानाबदोशों को उनकी सबसे अच्छी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इन रूसी अधिवासियों द्वारा भूमि पर अधिकार उस समय बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, जब इसे १९१६ के विद्रोह में किगिज़ों के भाग लेने के कारण उनके खिलाफ दंड के रूप में हस्तमाल किया जाने लगा। तुकिस्तान में सोवियत शासन के प्रथम दो वर्षों में जेतीसुव में भूमि-सुधार की समस्या को कई कारणों से हाथ नहीं लगाया जा सका था। फिर, जेतीसुव के सोवियत और पार्टी संगठन पर भी कुछ कुलफ रंग चढ़ा हुआ था और इससे भी वहाँ भूमि-सुधार पर अमल करने में बाधा पड़ी।

परन्तु तुकिस्तान आयोग ने जेतीसुव में भूमि-सुधार की समस्या के समाधान के लिए भुस्तैदी से और दृढ़तापूर्वक बंदम उठाया। इन्होंने पहले ता

पार्टी और सोवियतों से पैरी वर्गों के लोगों को निकाला। जा किगिज़ भागकर चीन चले गये थे, उन्हें वापस वुतान का प्रबंध किया गया। ४ मार्च, १९२० का जव्ती ज़मीने स्मानीय श्रमजीवी किसानों का वापस देने के मस्ये में आज्ञापति जारी की गई। अप्रैल १९२० में तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अस्थायी भूमि-वादपत्ती की। चीन से वापस आनेवाले किगिज़ के पुन आवास पर ४ करोड़ ४५ लाख रुबल की रकम खर्च की गई। सोवियतों की नवी क्षेत्रीय कार्यक्रम ने भी आदेश दिया कि हमी अधिवासियों ने १९१६-१९१८ की अधि म देशी विमानों और खानावदार्थों की जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है उन्हें वापस किया जाये। इसने तुकिस्तान में बाहर से सभी प्रकार के लोगों के आकर बसने और देशी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया।\* इस तरह भूमि-मुधार की सबसे पहली कारवाई उन इलाकों में की गई, जहाँ रूसी कुलक आवासन के कारण समस्या ने जातीय रूप धारण कर लिया था। यह वित्कुल स्वाभाविक भी था, क्योंकि देशी धार् और मानव लोग स्थिति में लाभ उठाकर अपने वर्गीय हित में जातीय भावनाओं का उत्तेजित कर रहे थे।

सोवियत सरकार ने गृहयुद्ध के दौरान कृषि अथनत्र को पुन युद्धपूर्व के स्तर पर पहुंचाने के लिए काफ़ी काम किया। लनिन ने १७ मई, १९२० का एक आज्ञापति पर हस्ताक्षर करके तुकिस्तान में सिचाई प्रयोजना के निर्माण के लिए पाच करोड़ रुबल की रकम मंजूर की। २ नवम्बर, १९२० का उन्होंने तुकिस्तान और आज़रबैजान में कपास की खेती की बहाली के लिए २० सो० स० स० जनतंत्र के सावनारखोज के फ़मने पर हस्ताक्षर किया। अप्रैल १९१८ में सोवनारखोज ने तुकिस्तान में कपास की खेती और रुई उद्योग के नवीनीकरण के लिए ५० करोड़ २० लाख रुबल पूजी निवेश किया।\*\* इसके तुगत बाद दो सूती मिला को

\* "सोवियतों की कार्यक्रमों की दस्तावेज़ें", पृष्ठ ४३५।

\*\* स० मुरावेइन्की, "मध्य एशिया में नातिवारी आंदोलन के इतिहास संबंधी 'पृष्ठ', ताशकन्, १९२६, पृष्ठ २२। (रूसी संस्करण)

तुकिस्तान भेजने का फैसला किया गया। इन प्रारम्भिक प्रयासों के फलस्वरूप कपास की खेती के क्षेत्र में १९१८ की तुलना में तीन लाख हेक्टेयर जमीन की वृद्धि हुई। सोवियत संघ ने मक्खी और औजारों से बेहकानों की सहायता की। कपास उपजानेवाले किसानों का काफी रकम वेशगी दी गई और उन्हें बीज और खाद भी मुहैया की गई। इन भौतिक प्रोत्साहनों के कारण कपास की खेती के क्षेत्र में केवल १९२० में ही पिछले वर्ष की तुलना में २१,००० हेक्टेयर जमीन की वृद्धि हुई। मगर इन सब प्रयासों ने बावजूद तुकिस्तान में १९२० में कुल बोवाई का क्षेत्र १९१८ का ३५ प्रतिशत ही था।\*

गह्युद्ध के दिनों में खाद्यान्न की समस्या बहुत तीव्र हो गई। तुकिस्तान में बहुत दिनों में खाद्यान्न चला आ रहा था और वह मध्य रूस से खाद्यान्न की आपूर्ति पर निर्भर करता था। वहाँ से हर साल सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ पौंड अनाज का आयात होता था। अक्टूबर क्रान्ति से पहले लगातार तीन वर्ष फसल भारी गई। इससे समस्या और तीव्र हो उठी। १९१८-१९१९ में तुकिस्तान सोवियतसंघ ने दो करोड़ रुबल की रकम अनाज खरीदने के लिए अलग की। परन्तु खुली मंडी में दाम गेज बढ़ रहा था, इसलिए कोई भी निश्चित दाम पर राज्य के हाथ अनाज बेचने को तैयार नहीं था। तब सरकार को किसानों पर जिस ह्मी कर लगाना पड़ा — फसल का ४ प्रतिशत। परन्तु इस तरह केवल ४५ लाख पौंड अनाज मिला, जबकि लक्ष्य दो करोड़ पौंड था। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को मजबूर होकर खाद्यान्न के राजकीय इजारे के संवर्ध में एक आज्ञापत्र जारी करनी पड़ी। शहरों में राशनिंग करनी पड़ी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का १/४ से एक पाउंड तक रोटी मिलती थी। इसकी मात्रा उस व्यक्ति की सामाजिक उत्पादितता पर निर्भर करती थी।\*\* कुल मिलाकर सोवियत प्रशासन ने अपनी खाद्य नीति पर सफलतापूर्वक प्रयत्न किया, उसमें कोई चिह्नित नहीं हान दी, यद्यपि कुछ अधिकारियों द्वारा

\* म० वहावोव उपराक्त पुस्तक पृष्ठ २६३।

\*\* वही, पृष्ठ २६५-२६६।



तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खुल गये थे, जिनमें १,६५,१२२ बच्चों में से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियों के थे।\* शिक्षा पर बजट का खर्च १९१७ के २३ लाख ५० हजार रूबल से बढ़कर १९२० में ६५ लाख रूबल हो गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम अवधि के पाठ्यक्रम जारी किये गये। १९२० तक १,०४६ व्यक्ति इस तरह के ११ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सगठित किये गये जिनमें १,०६२ व्यक्तियों ने भाग लिया। वयस्कों के निरक्षरता उन्मूलन अभियान में सभी शहरों में सध्या स्कूल खोले गये। १९२० में ३१ पेशावर और तकनीकी स्कूल थे जिनमें ५,५०० व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।

२१ अप्रैल, १९१८ को ताशकन्द में तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। नाति से पहले तुकिस्तान में उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय में पांच विभाग थे जिनमें १९१८-१९१९ में १२०० विद्यार्थी थे। १९१९-१९२० में यह संख्या बढ़कर १,४७० हो गई। ७ सितम्बर, १९२० को लेनिन के हस्ताक्षर से एक आज्ञापित जारी करके तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन तुकिस्तान राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। मास्को और पेत्रोग्राद ने मध्य एशिया के इस पिछड़े हुए इलाके की सांस्कृतिक प्रगति के लिए अपने सवश्रेष्ठ प्रोफेसर भेजे। १९२० के अंत तक ताशकन्द के विश्वविद्यालय में २,६४१ छात्र थे।

गह्युद्ध की अवधि में ही तुकिस्तान में सावियत बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ। हमजा और जीकी, जो उदार विचारों के जनवादी थे, बोल्शेविकों के सत्रिय समयक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूंजीवादी-राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका संघर्ष मध्य एशिया में सोवियत बुद्धिजीवियों के विकास में एक नये युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। फरगाना में उर्जेक सावियत थियेटर का जन्म सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष की आग में हुआ। हमजा इसने संस्थापक थे। उसी साल ताशकन्द संगीत विद्यालय कायम हुआ

जहाँ उर्बेक और ताजिक संगीत का नियमित अध्ययन किया जाने लगा।  
 उन्हीं दिनों सोवियत जातीय अखबार और पुस्तक प्रकाशन शुरू हुआ।  
 १९१८-१९२० के दौरान में उर्बेक भाषा में ११ अखबार प्रकाशित होते  
 थे और इनके अलावा बज़ाख और ताजिक भाषा के अखबार भी थे।  
 इसी दौर में उर्बेक लिपि में सुधार करने के प्रारम्भिक प्रयास हुए। कई  
 अक्षर, जिनकी उर्बेक भाषा में जरूरत नहीं थी, निकाले गये और  
 कई नये अक्षर जोड़ दिये ताकि लिपि उच्चारण के अधिक अनुकूल हो  
 जाये।

इस प्रकार गहयुद्ध का काल केवल बर्बादी और विनाश का ही काल  
 नहीं था। वह तुर्किस्तान के जनगण के जीवन के आर्थिक और सांस्कृतिक  
 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का भी दौर था। गहयुद्ध के दिनों में जन  
 राजनीतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ि हुई जिसका केन्द्र बिन्दु सोवियत सत्ता  
 थी। सभी प्रयासों का उद्देश्य सशस्त्र प्रतिक्रांति को परास्त करना था  
 जिसे वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप की सहायता मिल रही थी।

### अधराष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवाद के विरुद्ध पार्टियों का संघर्ष

मध्य एशिया में सोवियत सत्ता की सफलता का कारण बड़ी हद तक  
 जातीय संघर्षों के क्षेत्र में उसकी सही नीति है। अधराष्ट्रवादी तथा राष्ट्रवादी  
 भटकावों के विरुद्ध तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष वैदेशिक तथा  
 सोवियत दोनों ही ऐतिहासिक साहित्यों में बहुत वाद विवाद तथा भ्रम  
 का विषय रहा है। सोवियत लेखकों की कुछ प्रारम्भिक कृतियों में  
 अधराष्ट्रवादी भटकाव पर जरूरत से ज्यादा खोर देने और उन्हें बड़ा चढ़ाकर  
 पेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अतः हम उनमें से कुछ को इसी  
 की रट लगाते पाते हैं कि स्थानीय बोलशेविकों ने चारशाही की "अपनि-  
 वैशिक विरासत" पायी थी। प्रारम्भिक स्थानीय रूसी बोलशेविकों में से  
 अधिकांश को "अधिक अभिजात समुदाय" कह दिया गया, जो सवहारा  
 के अधिनायकत्व के परदे में अपनी अधिकांश स्थिति को ज्यों का त्यों  
 बनाये रखना चाहते थे। उनकी राय में "यूरोपीय सवहारा" और "देशी

तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खुल गये थे, जिनमें १,६५,१२२ बच्चों में से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियों के थे।\* शिक्षा पर बजट का खर्च १९१७ के २३ लाख ५० हजार रूबल से बढ़कर १९२० में ६५ लाख रूबल हो गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम अवधि के पाठ्यक्रम जारी किये गये। १९२० तक १,०४६ व्यक्ति इस तरह के ११ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संगठित किये गये जिनमें १,०६२ व्यक्तियों ने भाग लिया। वयस्कों के निरक्षरता उन्मूलन अभियान में सभी शहरों में सघ्ना स्कूल खोले गये। १९२० में ३१ पञ्चावर और तकनीकी स्कूल थे जिनमें ५,५०० व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।

२१ अप्रैल, १९१८ का ताशकन्द में तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। नाति से पहले तुकिस्तान में उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय में पांच विभाग थे जिनमें १९१८-१९१९ में १२०० विद्यार्थी थे। १९१९-१९२० में यह संख्या बढ़कर १,४७० हो गई। ७ सितम्बर, १९२० को लेनिन के हस्ताक्षर से एक आज्ञा जारी करके तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन तुकिस्तान राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। मास्को और पेत्रोग्राद में मध्य एशिया के इस पिछड़े हुए इलाके की सांस्कृतिक प्रगति के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर भेजे। १९२० के अंत तक ताशकन्द के विश्वविद्यालय में २,६४१ छात्र थे।

गृहयुद्ध की अवधि में ही तुकिस्तान में सोवियत बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ। हमजा और जोकी, जो उदार विचारों के जनवादी थे, बोल्शेविकों के सक्रिय समर्थक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूँजीवादों राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका संघर्ष मध्य एशिया में सोवियत बुद्धिजीवियों के विकास में एक नया युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। परगाना में उन्नेक सोवियत थियेटर का जन्म सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष की आग में हुआ। हमजा इसके संस्थापक थे। उसी साल ताशकन्द संगीत विद्यालय कायम हुआ



जहाँ उर्बेक और ताजिक संगीत का नियमित अध्ययन किया जाने लगा।  
उन्ही दिना सोवियत जातीय अखबार और पुस्तक प्रकाशन शुरू हुआ।  
१९१८-१९२० के दौरान में उर्बेक भाषा में ११ अक्षर प्रकाशित होते  
थे और इनके अलावा बच्चाख और ताजिक भाषा के अखबार भी थे।  
इसी दौर में उर्बेक लिपि में सुधार करने के प्रारम्भिक प्रयास हुए। कई  
अक्षर, जिनकी उर्बेक भाषा में जरूरत नहीं थी, निकाले गये और  
कई नये अक्षर जोड़े गये ताकि लिपि उच्चारण के अधिक अनुकूल हो  
जाये।

इस प्रकार गहयुद्ध का काल केवल बर्बादी और विनाश का ही काल  
नहीं था। वह तुर्किस्तान के जनगण के जीवन के भाग्यिक और सांस्कृतिक  
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी दौर था। गहयुद्ध के दिनों में जन  
राजनीतिक भाषाकलाप में भी वृद्धि हुई जिसका केन्द्र बिन्दु सोवियत सत्ता  
थी। सभी प्रयासों का उद्देश्य सशस्त्र प्रतिशक्ति को परास्त करना था  
जिसे वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप की सहायता मिल रही थी।

### अधराष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवाद के विरुद्ध पार्टों का संघर्ष

मध्य एशिया में सोवियत सत्ता की सफलता का कारण बड़ी हद तक  
जातीय संघर्षों के क्षेत्र में उसकी सही नीति है। अधराष्ट्रवादी तथा राष्ट्रवादी  
भटकावों के विरुद्ध तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष वैदेशिक तथा  
सोवियत दोनों ही ऐतिहासिक साहित्या में बहुत बार विवाद तथा भ्रम  
का विषय रहा है। सोवियत लेखकों की कुछ प्रारम्भिक श्रुतियाँ में  
अधराष्ट्रवादी भटकाव पर जरूरत से ज्यादा जोर देने और उन्हें बड़ा चढ़ाकर  
पेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अतः हम उनमें से कुछ को इसी  
की रट लगाते पाते हैं कि स्थानीय बोलशेविकों ने ज़ारशाही की "ओपनि  
बेशिक विरासत" पायी थी। प्रारम्भिक स्थानीय रूसी बोलशेविकों में स  
अधिकारों की "अधिक अधिकृत समुदाय" कह दिया गया, जो सवहारा  
के अधिनायकत्व के परदे में अपनी अधिकारप्राप्त स्थिति को ज्यों का त्यों  
बनाये रखना चाहते थे। उनकी राय में "यूरोपीय सवहारा" और "देशी

एशियाई जनगण" का राष्ट्रीय अंतर्विरोध इन दोनों समूहों के भीतर के वर्गीय अंतर्विरोध से ज्यादा गहरा था। पश्चिम के अधिकांश लेखकों ने भी कमोवेश यही मत अपनाया है और उन सोवियत लेखकों से व्यापक उद्धरण दिये हैं जो तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पकितया में अधराष्ट्रवादी प्रवृत्तियों पर जोर देते हैं।

लेकिन इस धारणा को इतिहास के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी की पकितियों में कुछ अधराष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति मौजूद हैं, मगर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनकी मख्या किसी भी समय इतनी अधिक थी कि उन्होंने जातीय समस्या के बारे में पार्टी की आम स्वस्थ नीति को विकृत कर दिया। पार्टी में हमेशा ठोस मार्क्सवादी-लेनिनवादी तत्वों का सशक्त दल मौजूद रहा है जिसने पार्टी नीति से अधराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी हर तरह के भटकाव के विरुद्ध निरन्तर सघर्ष किया है।

कभी कभी केन्द्र को बहुत श्रेय दिया जाता है कि उसने स्थानीय गुमराह बोल्शेविकों की गलतियों का सुधार किया, और ऐसी धारणा पदा करने का प्रयत्न किया जाता है मानो सितम्बर १९१९ में केन्द्र से तुर्किस्तान का सबंध बहाल होने से पहले पार्टी और सोवियतों के ढांचे पर रूसी अधराष्ट्रवादी छाये हुए थे, जो स्थानीय लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और सरकार में उनके उचित स्थान से उन्हें बचित रखते थे, और माना पूरी परिस्थिति में परिवर्तन केवल उस समय हुआ जब केन्द्र के प्रतिनिधि आये और आयागा आदि की नियुक्ति हुई। परंतु अधराष्ट्रवादी के विरुद्ध सघर्ष रूसी तथा देशी कम्युनिस्टों के बीच का सघर्ष नहीं था, इसमें देशी कम्युनिस्टों को केन्द्र के ऐसे प्रतिनिधियों का समर्थन मिलता था, जैसे विशेष कमिस्सरी कावोजेव और फ़ेजे, कूडिशेव तथा तुर्किस्तान आयोग तथा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के तुर्किस्तान ब्यूरो के दूसरे सदस्य।

पार्टी नीति से भटकावों के विरुद्ध सघर्ष का असल में पार्टी के भीतर जातीय समूहों से कोई सबंध न था। अतः अनेक स्थानीय रूसी कम्युनिस्टों ने अधराष्ट्रवादी विचार के रूसी कम्युनिस्टों के विरुद्ध समान सघर्ष में अपने

मुस्लिम साथियों का साथ दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह मुस्लिम साथियों ने पूँजीवादी राष्ट्रवादियों का परदाफाश करने में रूसी कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। इसमें सन्देह नहीं कि केंद्र के प्रतिनिधियों ने पार्टी को अधराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने जातीय सवाल पर पार्टी नीति की शुद्धता के लिए सघन अपने आप और अकेले किया। इस सघन में उह पार्टी की पक्तियों और ग्राम जनगण से व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश, कुछ सोवियत कृतियों में, जो व्यक्ति पूँजा के प्रभाव में लिखी गई थी, विभिन्न आयोगों और व्यूरा की भूमिका को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है पर अधराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरुद्ध सघन के जन स्वरूप की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

निस्सन्देह, तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्टूबर क्रांति के बाद के प्रारम्भिक दिना में स्थानीय जातियों के लोगों के प्रति कुल मिलाकर बड़ी हद तक सही नीति अपनायी। जातीय सवाल हमेशा तुकिस्तान के बोल्शेविकों के ध्यान का केंद्र बना रहा। १९०५-१९०६ में ही बोल्शेविकों ने तामकन्द और समरकन्द से जो गैरकानूनी पत्र प्रकाशित किये, उनमें जातीय सवाल पर काफी ध्यान दिया गया था। उन्होंने देशी लोगों में काम करने के महत्त्व पर जोर दिया था।\* तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस (१७-२६ जन, १९१८) ने मुस्लिम जनगण में पार्टी काय पर अपने प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया था कि व्यापक मुसलमान जनता को नये जीवन के निर्माण काय में खींच लेना जरूरी है। उसने स्थानीय जातियों की भाषाओं को रूसी के साथ-साथ राज्य भाषाओं के रूप में स्वीकार किया। उसने मांग की कि सभी ओब्लास्तों, जेरेन्दों आदि में जातीय मामलों की कमिसारियत नियुक्त की जाए जिनका काम मुसलमानों को सोवियत निकायों में लाने के लिए प्रचार करना हो। उसने

\* मजारा, "१९०५-१९२० में मध्य एशिया में क्रांतिकारी आंदोलन (स्मृति) ", तामकन्द, १९३४ पृष्ठ १९। (रूसी संस्करण)

मुस्लिम मेहनतकशों में पूरा विश्वास प्रकट किया और मुस्लिम सवहारा में से लाल सेना के दस्ते संगठित करने का आह्वान किया।\*

दिसम्बर १९१८ में तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस के समय ही पार्टी सदस्यों की कुल संख्या का लगभग आधा भाग देशी कम्युनिस्ट थे और मुस्लिम श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधि अप्रैल १९१८ में तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम जैसे सोवियत सत्ता के उच्च निकायों में नियुक्त किये जाने लगे थे। यह ध्यान रहे कि पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने मुस्लिम जनता में शैक्षणिक और प्रचार कार्य पर असतोष प्रकट किया था और यह मांग की थी कि सोवियतों और अन्य सामाजिक संगठनों में स्थानीय जातियों के श्रमजीवी जनगण को ज्यादा व्यापक पैमाने पर खींचा किया जाये जिसके लिए उन्हें प्रशासकीय तथा अन्य पदों पर नियुक्त किया जाये।\*\* इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि नाति के तुरंत बाद के जमाने में जातीय संवाद पर पार्टी की नीति सही थी।

अक्सर तोबोलिन के नेतृत्व में “पुराने कम्युनिस्टों” के समूह पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे स्थानीय कम्युनिस्टों के प्रति अधराष्ट्रवादी रव्य अपनाते थे।\*\*\* परन्तु इसके लिए ठोस सबूत देना अभी बाकी है। यह सही है कि इस गिरोह ने पार्टी के भीतर अपना एक गुट संगठित करने का अनुचित कदम उठाया था जिसका एकमात्र आत्मनिष्ठ दावा यह था कि ताशकन्द नगर पार्टी संगठन में अनेक व्यक्तियों को इस गिरोह के लाग पसंद नहीं करते थे और उन्होंने पार्टी अनुशासन मानने से इनकार कर दिया था जिसके लिए दूसरी कांग्रेस ने इनकी निंदा की। परन्तु इसके अलावा ताबोलिन पर अधराष्ट्रवाद का कोई ठोस आरोप नहीं लगाया जा सकता। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने “पुराने कम्युनिस्टों”

\* “तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेसों के प्रस्ताव और निष्पत्ति, १९१८-१९२४”, ताशकन्द, १९५८ पृष्ठ ११-१२। (रूसी संस्करण)

\*\* “तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस की दस्तावेजें”, मास्को-ताशकन्द, १९६४, पृष्ठ ६२। (रूसी संस्करण)

\*\*\* “उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास”, खण्ड २, पृष्ठ ६१।

के समूह और ताशकन्द नगर पार्टी इवाई में कोई विचारधारात्मक विभेद नहीं पाया। इस इकाई के नेता भी रूसी कम्युनिस्ट थे। उनके बीच अधराष्ट्रवादी भटकाव का कोई सवाल नहीं था।

इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि जनवरी १९१९ से पहले जातीय सवाल पर पार्टी नीति को महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद की ओर सकोई खतरा था। उस महीने आसिपाव के प्रतिनातिकारी विद्रोह से तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को बड़ा धक्का लगा। ओसिपोव की घोखेबाजी के फलस्वरूप अनेक अनुभवों और विश्वसनीय स्थानीय नेताओं की हत्या कर दी गई। पहले ही जुलाई १९१८ में कई महत्वपूर्ण बोल्शेविक नेता अशकाबाद और किज़िल अरवात में प्रतिनातिकारी पड़यत्तकारियों द्वारा मारे जा चुके थे। इन भारी नुकसानों के कारण जो कि पार्टी को १९१८-१९१९ में उठाने पड़े पार्टी में सुयोग्य नेतृत्व का अभाव हो गया और इसलिए अधराष्ट्रवादी भटकाव को सिर उठाने का मौका मिल गया। तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बज़ाकव वामपक्षी समाजवादी नातिकारी उत्पत्तकी के साथ अनचाहे ही उस नीति की धारा में बह गये। परन्तु इस भटकाव की जिम्मेदारी बोल्शेविकों से अधिक वामपक्षी समाजवादी नातिकारियों पर थी और फिर भी संपूर्ण भटकाव कभी नहीं होने पाया। वह सोवनारकोम तथा पार्टी की क्राइकोम (क्षेत्रीय समिति) में अलग अलग नेताओं द्वारा कुछ इक्की-डुक्की घटनाओं तक ही सीमित रहा।

१९१९ के प्रारम्भ से पार्टी तथा सावियत कार्यक्षेत्र में महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध तीव्र सघर्ष शुरू हुआ। यह पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पूँजीवादी राष्ट्रवादी देशों महानतकशों में रूसी मजदूर वर्ग के विरुद्ध असंतोष का बीज बाने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे। परन्तु अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध सघर्ष कोई मध्य एशिया की ही परिघटना नहीं थी। वेड्रम लेनिन को भी बुखारिन और प्याताकोव के विरुद्ध सघर्ष करना पड़ा था जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवाँ कांग्रेस द्वारा वीर्युत कार्यक्रम में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को शामिल करने का रोध कर रहे थे।

तुकिस्तान की सोवियतों की सातवीं कांग्रेस (मार्च १९१८) और तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन में अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया। पार्टी के ठोस मार्क्सवादी तत्व कोवोजेव के गिद जमा हो गये, जो मार्च १९१९ में केन्द्र के विशेष प्रतिनिधि के रूप में ताशकन्त आये थे। सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में कोवोजेव के नेतृत्व में जातीय विभाग की स्थापना हुई, जिसने खाद्यान्न के मोरचे पर कज़ाक-उस्पेस्की गिरोह के सरकारी तथा पार्टी नेताओं की गलतियों की आलोचना की। कांग्रेस में रिस्कूलोव ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें खाद्यान्न निदेशालय की नीति की आलोचना थी। कांग्रेस ने कहा कि इस नीति के कारण सबहारा के दो भाग—रूसी और देशी—एक दूसरे के विरुद्ध बना लिये गये थे।

सोवियतों की सातवीं कांग्रेस के जातीय विभाग ने मांग की कि सरकार मुस्लिम सबहारा को प्रतिनाति के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियारों से लैस करे। उसने आतंककारी संघर्ष में मुस्लिम मेहनतकशों की भूमिका को कम करके आंकने के लिए सरकार के कुछ सदस्यों की आलोचना की। उसने नारा दिया कि ताल गाड़ में से सभी सदेहजनक तत्व निकाले जायें और क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस का शीघ्र आयोजन किया जाये। उसने इस बात पर असंतोष प्रकट किया कि नई सरकार में देशी आगदी के प्रतिनिधियों को केवल सात स्थान दिये गये थे।

कज़ाकोव, उस्पेस्की और सोलकिन ने सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में जातीय विभाग कायम करने का विरोध किया और जातीय मामलों की कमिसारियत को भंग करने का प्रस्ताव पेश किया। परंतु कांग्रेस ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कज़ाकोव-उस्पेन्स्की गिरोह ने यह भी दावा दिया कि ५० सा० स० स० जनतंत्र की सरकार द्वारा स्वीकृत हर कानून का तुकिस्तान में लागू होने के लिए यहां की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह की क्षेत्रीय मांगों के ज़रिए अधराष्ट्रवादी मिराह अपने मत को तुकिस्तान की प्रभुता के अधिनारा के लिए तथा केन्द्र से इसकी तयकथित स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का रूप देना चाहता था।

अगर सोवियतों की सातवी कांग्रेस में कोबोर्जेव दल को विजय हुई, तो पार्टी के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन ने पलड़ा किसी हद तक बज़ाकोव के पक्ष में झुका दिया। पार्टी सम्मेलन ने सोवियतों की सातवी कांग्रेस में रिस्कूलोव द्वारा तुकिस्तान पार्टी की पूरी केन्द्रीय समिति की व्यापक आलोचना को अनुचित ठहराया। उसने कहा कि गलतियाँ पूरी पार्टी नीति की नहीं, व्यक्तिगत पार्टी नेताओं की थी। उसने पार्टी की फ्राइवूम (क्षेत्रीय समिति) में विश्वास प्रकट किया और सावियता की सातवी कांग्रेस के जातीय विभाग द्वारा प्रतिरोध को निराधार कहकर अस्वीकार किया। सम्मेलन ने मुस्लिम जनता में प्रचारवाप करने के लिए पार्टी में एक मुस्लिम ब्यूरो कायम करने का निश्चय किया। मुस्लिम ब्यूरो को पार्टी का सहायक निकाय होना था। और उसकी निगरानी और नियंत्रण में काम करना था। पार्टी के दूसरे सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा उनको को वापस बुलाने की भाग दी। उन्हें पदच्युत कर दिया गया और उनकी हरकतों की जाँच करने का आदेश दिया गया।\* कोबोर्जेव की कारवाइया से खीज आकर फ्राइवूम के कुछ सदस्यों ने शकीरोव को पार्टी की केन्द्रीय समिति के सामने कोबोर्जेव के खिलाफ शिकायत करने के लिए मात्को भेजा।

तुकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस (११५ जून, १९१९) में अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध सभ्य ने तुकिस्तान में मुस्लिम सवहारा के अस्तित्व पर सिद्धांतवादी बहस का रूप लिया। सोलकिन का कहना था कि चूंकि मुसलमानों में अभी सामंती सबंध छाये हुए हैं और खानाबदोशी के सबल अवशेष भी मौजूद हैं, इसलिए कोई मुस्लिम सवहारा नहीं है। उनका समयन वास्तानतिनोपोल्स्की ने किया। इनका कहना था कि तुकिस्तान में केवल भद्र-सवहारा बग है और कोई सवहारा नहीं, जो ऐतिहासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाये। वोन्स्तानतिनोपोल्स्की ने भय प्रकट किया कि देशी सवहारा के अभाव में तुकिस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन कहीं

\* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस की दस्तावेज़," ताशक़न्द, १९१९, पृष्ठ १३४-१३५।

सब-इसलामवाद के हाथ में न पड़ जाये। परन्तु कोबोजेव इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बताया कि अभी ही पार्टी के आगे से अधिक सदस्य देशी कम्युनिस्ट हैं जिससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम जनता पार्टी के कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुई है।\* पार्टी की फाइकोम के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हुए तीसरी पार्टी कांग्रेस ने सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में जातीय विभाग का संगठन करने की कार्यनीति को गलत ठहराया। फाइकोम की रिपोर्ट पर अपने प्रस्ताव में तीसरी पार्टी कांग्रेस ने यह विचार प्रकट किया कि पिछली पार्टी कांग्रेसों द्वारा जो काम उसके सिपुद किये गये थे, उन सबों को फाइकोम ने पूरा नहीं किया है। प्रस्ताव ने खासकर जिन बातों की चर्चा की, उनमें स्थानीय क्षेत्रों, विशेषकर मुसलमानों में सही आतिकारी काम का अभाव तथा पार्टी पक्षियों में अनुशासन की कमी थी। कांग्रेस ने पार्टी के सामने अनुशासन को सुदृढ़ करने और मुस्लिम व्यूरो के जरिये स्थानीय आवादी में पार्टी कार्य को तेज करने का कार्यभार रखा।

तीसरी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी समितियों के भीतर काम करनेवाले मुस्लिम विभागों को वही हैसियत दी, जो पार्टी इकाइयों की थी, और उन्हें मुस्लिम व्यूरो के नियंत्रण में रखा जिसे हर सम्भव सहायता देनी थी। तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की फाइकोम में कोबोजेव, रिस्कुलोव, आफन्दीयेव, खोजायेव और अलीयेव के निर्वाचन से बजाकोव का अधराष्ट्रवादी गिराह कुछ कमजोर हुआ। परन्तु यह गिराह अभी भग नहीं हुआ था। बजाकोव अभी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। थोड़े ही दिनों में इस गिराह के खिलाफ लम्बा संघर्ष शुरू हुआ।

इस संघर्ष के पुनः छिड़ने का कारण १२ जुलाई, १९१६ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रीय समिति का यह संदेश था कि क्षेत्रीय प्रशासन में स्थानीय आवादी का सानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान पार्टी और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि "तुकिस्तान की स्थानीय आवादी को राजस्व

\* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस की दस्तावेजें", पृष्ठ ५०।



कायकलापो में सानुपातिक शिरकत होनी चाहिए, जिसके लिए पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर मुस्लिम मजदूरों के संगठन उनकी उम्मीदवारी का अनुमोदन कर दें, तो यह काफी है।" \* कजाकोव उस्पेस्की गिरोह के अधराष्ट्रवादी विचार के लोगो ने देखा कि अगर इस आदेश पर अमल किया गया, तो उनकी स्थिति खतर में पड़ जायेगी। उन्होंने यह तक पेश किया कि पार्टी की केन्द्रीय समिति तुकिस्तान की स्थिति को ठीक तरह नहीं समझती है और कि स्थानीय मजदूर और किसान अभी परिपक्वता के उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, जो राजकीय कायकलाप में शिरकत के लिए जरूरी है। उन्होंने अखबारों में विज्ञप्ति के प्रकाशन में बाधा डाली। २० जून, १९२० को उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति के पास एक तार भेजा, जिसमें इस आदेश पर अमल करना असम्भव बताया।

इस प्रकार सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय समिति के आदेश के संबंध में तीव्र सघर्ष छिड़ गया। इसपर ताशकंद, समरकंद और फरगाना जैसे विभिन्न स्थानों में पार्टी और जन-सभाओं में बहस हुई। १६ जुलाई, १९१९ को ताशकंद के पुराने शहर में एक सावजनिक सभा में, जिसमें पार्टी की क्षेत्रीय समिति तथा मुस्लिम ब्यूरो के कई सदस्य उपस्थित थे, एक प्रस्ताव स्वीकार करके इसकी फौरी तामील की, खासकर सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन की मांग की गई। कजाकोव उस्पेस्की गिरोह ने कोवोजेव को बदनाम करना शुरू किया और उनपर देशी लोगो को रूसी मजदूरों के विरुद्ध उभारने का आरोप लगाया। उसने मांग की कि केन्द्र कोवोजेव को वापस बुला ले, क्योंकि वह व्यक्तिगत सत्ता की खातिर मुस्लिम वगच्युत तत्वा, भूतपूर्व व्यापारिया और काराबारियों आदि के साथ साजबाज कर रहे हैं। केन्द्र के आदेश का व्यापक पैमाने पर समर्थन किया गया। समरकंद तथा अन्य शहरों में पार्टी इकाइया ने अपनी पूरी सहमति प्रकट की।

\* 'तुकिस्तानस्की काम्युनिस्त', अंक ६२, १६ जुलाई, १९१९।

तुकिस्तान की सोवियतों की आठवीं कांग्रेस तथा तुकिस्तान का कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी कांग्रेस, जो सितम्बर १९१६ में आयोजित हुई, एक बार फिर पार्टी और सरकार में अधराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघर्ष का अखाड़ा बन गई। सोवियतों की आठवीं कांग्रेस में कज़ाखोव-उस्पेस्की गुट ने एक प्रस्ताव पेश करके मांग की कि जातीय मामला की जन कमिसारियत को तोड़ दिया जाये। कज़ाखोव-उस्पेस्की गुट की अधराष्ट्रवादी प्रवृत्ति के जवाब में पार्टी में राष्ट्रवादी भटकाव उत्पन्न हुआ जिसके अगुआ रिस्कूलोव थे। इसका पहला इजहार सोवनारकोम का भंग करने का प्रस्ताव था, जो रिस्कूलोव के पेश करने पर सोवियतों की आठवीं कांग्रेस में स्वीकृत हो गया। सोवनारकोम को भंग कर दिया गया और इसका स्थान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के भीतर की तीन परिपदों ने लिया। इससे सरकार के कार्यकारी निकायों के निपुण काम पर बुरा असर पड़ा।

चौथी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के जरिये सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सवध में केन्द्र के आदेश के बुनियादी सिद्धांतों को मंजूर किया। उसने तुकिस्तान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी तामील के व्यावहारिक उपाय निकाले। चौथी कांग्रेस ने निश्चय किया कि हर अलग अलग सूरत में सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर अमल अभी किया जायगा जब सोवियतों की क्षेत्रीय या स्थानीय कांग्रेस वाक्यांश इसकी मांग करेगी। इसपर अमल सोवियत विधान की धाराओं के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की क्षेत्रीय और स्थानीय समितियां तथा मुस्लिम व्यूरो के आम निर्देशन में किया जायेगा।\* यह याद रखना चाहिए कि तुकिस्तान में मुस्लिम जनता अभी अच्छी तरह संगठित नहीं हो पायी थी और इसलिए स्वयं अपनी जाति के शोषकों के बहकावे में आने का वास्तविक खतरा था।

सितम्बर १९१६ में तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी कांग्रेस में अधराष्ट्रवादी गुट को पार्टी के स्वस्थ तत्वों के हाथों मुंह की खानी पड़ी। मुसलमान ही नहीं, कई रूसी प्रतिनिधियों ने भी सानुपातिक प्रतिनिधित्व

---

\* 'तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेसों के प्रस्ताव और निर्णय', पृष्ठ ४६-५१।

वे सबध में केन्द्र के तार का समर्थन किया। बुनाचे श्वात्स ने कहा कि किसी जाति की सध्या को ध्यान में नहीं लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि "जहाँ तक प्रशासन में लोगा के भाग लेने का सवाल है किसी जाति का सांस्कृतिक स्तर कोई भूमिका भदा नहीं करता, क्योंकि राजकीय कायबनाप के दौरान में ही जानि इसका सबूत देती है कि वह उन कामा को पूरा कर सकती है या नहीं, जो उसके सिपुद्ध किये गये हैं।" • कोबोर्जेव ने कहा कि केन्द्रीय समिति का तार तुकिस्तान की जातियों के आत्मनिर्णय की दिशा में एक नया कदम है।"

अधराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघष जारी ही था, जब तुक आयोग नवम्बर १९१६ में ताशकन्द पहुँचा। आयोग ने पार्टी और सोवियत सगठना से उन लोगा को निकालना शुरू किया जो उसकी राय में अधराष्ट्रवादी भटकाव में अपराधी थे। उसने कजाकाव उत्प्रेत्स्की, सोरोकिन और कई और व्यक्तियों को तुकिस्तान से चले जान का आदेश दिया। कई जारशाही अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कारवाइया शुरू की गई। आयोग ने मुर्तदी से कदम उठाकर जेतीसुव में पार्टी की उपेक्ष और अधस्तात्त समितियों को अधराष्ट्रवादी तत्वों से मुक्त किया। जेतीसुव के प्रलावा करगाना और तिरदरिया अधस्तात्तों में भी इसी तरह के कदम उठाये गये।

ऐसी सही जातीय नीति के लिए, जो भटकावा से मुक्त हो, सघष को तैज करने में तुकिस्तान के कम्युनिस्टों के नाम लेनिन के पत्र ने बड़ी भूमिका भदा की। लेनिन ने इसी कम्युनिस्टों की सलाह दी कि तुकिस्तान के लोगा से व्यवहार करने में अत्यंत सहिष्णुता और भराते से काम ले और इस बात पर जोर दिया कि इसी साम्राज्यवाद के सभी चिह्न मिटा दिये जायें। अपने पत्र में लेनिन ने कहा कि तुकिस्तान के जनगण से सही सबध कायम करने का "जबरदस्त, युगांतरकारी"

\* 'तुकिस्तान में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) का मुस्लिम व्यूरो', पृष्ठ ५२। (रूसी संस्करण)  
• वही, पृष्ठ ६३।

महत्त्व है। \* लेनिन के पत्र पर तुर्किस्तान भर में पार्टी तथा सावजनिक सभाओं में विचार किया गया और बहुत सताप प्रकट किया गया।

जब तुर्क आयोग के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी सारी शक्ति और छ पार्टी से अधराष्ट्रवादी भटकाव का उन्मूलन करने में लगा दिया तो पूंजीवा राष्ट्रावाद के मरुद्ध सघर्ष की किसी हद तक अपेक्षा की गई। नतीजा हुआ कि शीघ्र ही राष्ट्रवादी भटकाव उभरकर सामने आ गया और तुर्किस्तान की पिछड़ेपन की स्थिति में सोवियत काम के निगमभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

राष्ट्रवादी भटकाव जनवरी १९२० में सामने आया। इसने पांच क्षेत्रीय पार्टी सम्मेलन में तथा मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में मर उठाया। मुस्लिम ब्यूरो ने कुछ दिनों तक मुस्लिम जनता में अल्पकाम किया, उनमें सोवियत तथा पार्टी आदर्शों का प्रचार किया, उन सोवियत सत्ता के नज़दीक लाया। परंतु थोड़े ही दिनों में वह पार्टी समानान्तर स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करना लगा और रिस्कूला आदि के राष्ट्रवादी विचारों के अंतर में प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद का अंग बन गया।

पार्टी के पांचवें क्षेत्रीय सम्मेलन ने निश्चय किया कि पार्टी के तीनों अग्रिम निकायों, यानी तुर्किस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आइकोम, क्षेत्रीय मुस्लिम ब्यूरो तथा वैदेशिक कम्युनिस्टों की क्षेत्रीय समिति के तुर्किस्तान की एक ही संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी में मिला दिया जाना चाहिए। यह सही फैसला था जिससे पार्टी की एकजुटता और अधिक बनी थी। परंतु सम्मेलन ने रिस्कूलोव के कहने पर एक प्रस्ताव स्वीकार करने में भारी गलती की जिसमें पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। रिस्कूलोव की राय में मुस्लिम जनता ने आइकोम का मानना छोड़ दिया था और इसने फनस्वरूप तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी अब उसपर अपना विचारधारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती थी इसलिए उन्होंने पार्टी के नाम में परिवर्तन करने का मुझाव दिया।

\* अना० ६० लेनिन, संपादित रचनाएँ (चार भागों में), प्रथम प्रकाशन मास्को, १९६६, भाग ३, पृष्ठ २५६-२६०। (हिन्दी संस्करण)

पार्टी के पाचवे क्षेत्रीय सम्मेलन व साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिस्टों का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन भी हो रहा था। उसमें रिस्कूलाव ने स्वायत्तता और तुकिस्तान के संविधान पर अपनी रिपोर्ट में अपना राष्ट्रवादी भटकाव थोपने का प्रयास किया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुकिस्तान जनतंत्र का नाम बदलकर तुर्की जनतंत्र कर दिया जाये। उनकी दलील यह थी कि कजाख, बिश्किज, तुर्कमान, ताजिक और उज्बेक अलग अलग जातियाँ नहीं, बल्कि एक ही जाति, यानी तुर्क है। मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन ने रिस्कूलाव का यह सुझाव मान लिया। उसने तुकिस्तान के अधिवारों में वृद्धि करने के लिए संविधान में संशोधन की धावाज उठायी। अगर सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव से क्रांतिकारी शतावली को अलग कर दिया जाये, जिसका उद्देश्य उससे समर्थकों के असल इरादा पर परदा डालना था, तो वास्तव में वह इस से अलग होने की मांग थी। वह सर्व-तुर्कवाद की और दरअसल घोर प्रतिरियावादी मांग थी।

पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की पार्टी रखने का रिस्कूलाव का सुझाव पाचवें पार्टी सम्मेलन द्वारा स्वीकार हो गया। इसका कारण यह था कि तुकिस्तान आयोग के सदस्यों में इस सवाल पर एक मत नहीं था। आयोग के अध्यक्ष एलिआवा ने रिस्कूलाव के सुझाव का समर्थन किया और कूडबिशेव और गोलोश्चोकिन विरोध किया। फ्रूजे ने आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह तुकिस्तान से बाहर थे। ताशकन्द पहुँचने पर उन्होंने आयोग को इस पर राजी कर लिया कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति का आदेश आने तक पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रखा जाय।\*

मार्च १९२० में तुकिस्तान आयोग ने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन तथा पार्टी के पाचवें क्षेत्रीय सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति व पास उसकी

\* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संवर्धन में लेख" कद, १९६४, खण्ड ३, पृष्ठ १३६। (रूसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतन्त्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धान्त के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाले नहीं थे। उन्होंने रिस्कूलोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मांगें रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने माग की कि सार अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण किया जाये। उन्होंने यह भी माग की कि डाक-तार, वैदेशिक मामला और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतन्त्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाय, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में हों। व उजबेक, कजाखो तुकमानो, और किर्गिजों को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्की जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिस उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इस्लामवाद और सब-तुक्वाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में खतम हो चुका था।\*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मांगा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को ब्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किए गये मसविदे का देखा और उमम कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

\* "उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के सच में सच", पृष्ठ ७७।

भटकाववादिया की मागा को लेनिन ने अस्वीकार कर दिया और मुझाव दिया कि "मुल्ताआ, सब इसलामवादी और पूजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन से सघप के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।"।<sup>\*</sup>

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० का तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी कायमारा पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केंद्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे के साथ उसमे लेनिन के मुझावा और विचारों का भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटज्युरो के प्रस्ताव में जनतंत्र के आर्थिक जीवन में सामती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटाने तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतता का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, जो महानतकश जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान के अमजीवी जनगण और रूस की जातियां क बीच अंतरजातीय मत्ती को खल बनान और विक्षिप्त करने के लिए अथक सघप का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबप्रथम रूसी सवहारा की बिरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातियां स्वतंत्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के माग पर विकास कर सकती हैं। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग का रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और ८० सो० स० स० जनतंत्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कायम रखना जरूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादिया की इस माग को कि तुर्कों जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाये दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका नतीजा यह होता कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरूसी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। उसने तीनों स्थानीय क्षेत्रीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमोदन किया। राष्ट्रवादियों के गिरोह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आइकोम से तथा तुकिस्तान की

\* लेनिनी सग्रह, खण्ड ३४ पृष्ठ ३२६। (रूसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतंत्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर लिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धांतों के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाला नहीं थे। उन्होंने रिस्कलोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मार्ग रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने माग की कि सारे अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवियत-कॉम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण किया जाये। उन्होंने यह भी माग की कि डाक तार, वदेशिक मामलों और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतंत्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में हों। वे उज्बेकों, कज़ाखों तुकमानों, और किर्गिज़ों को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्की जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इस्लामवाद और सब-तुर्कवाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में जनम हुआ चुका था।\*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मागा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को प्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे को देखा और उनमें कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

\* "उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संवर्ध में लेख", पृष्ठ ७७।



भटकाववादिया की माग को लेनिन ने अस्वीकार कर दिया और मुझाव दिया कि "मुल्लाभा, सब इसलामवादी और पूजीवादी-राष्ट्रवादी आंदोलन से सघप के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।" \*  
 इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० को तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी व बुनियादी कायभारा पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केन्द्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मतविदे के साथ उसमें लेनिन के मुझावो और विचारा को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव में जनतन्त्र के अधिक जीवन में सामती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटाने तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियता का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर ज़ार दिया गया था जो महानतकश जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान के थमजीवी जनगण और इस की जातिया व बीच अंतरजातीय मैत्री का सबल बनाने और विकसित करने के लिए अथक सघप का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबसेप्रथम इसी सबहारा की बिरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातिया स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के माग पर विकास कर सकती है। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग को इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और रू० सो० स० स० जनतन्त्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कायम रखना ज़रूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादियों की इस माग को कि तुर्कों जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाये दुबतापूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका नतीजा यह होता कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरूसी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। उसने तीना स्थायीय क्षेत्रीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमान्न किया। राष्ट्रवादिया के गिरोह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आइकोम से तथा तुकिस्तान की

\* लेनिनी संग्रह खण्ड ३४, पृष्ठ ३२६। (रूसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतंत्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की मांग को अस्वीकार कर लिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धान्त के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाला नहीं था। उन्होंने रिस्कूलाव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मांगें रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने मांग की कि सारे अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवियत-कॉम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से हथी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण किया जाये। उन्होंने यह भी मांग की कि डाक-तार, वैदेशिक मामला और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतन्त्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में हों। वे उपरोक्त, मजाया तुकमाना, और किमिया को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्की जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इस्लामवादी और सब-तुक्वाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में घनम हो चुका था।\*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मांगा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को व्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किए गये मसविदे का देखा और उसमें कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

\* "उजबेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संवध में लेख", पृष्ठ ७७।

भटकाववादियों की भाषा को लेनिन न अम्बीकार कर दिया और मुझाव दिया कि "मुल्लाघा, सब इसनामवादी और पूजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन से मध्य के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।"\*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० को तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी कार्यक्रमों पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केन्द्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे के साथ उसमें लेनिन के मुझावों और विचारों को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव में जनतन्त्र के आर्थिक जीवन में सामंती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटाना तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, जो महत्त्वपूर्ण जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान में श्रमजीवी जनगण और रूस की जातियों के बीच अन्तरजातीय मैत्री को सबल बनाने और विवसित करने के लिए अथक मध्य का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबप्रथम रूसी सबहारा की विरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातियाँ स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के भाग पर विकास कर सकती हैं। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और रू० सो० स० म० जनतन्त्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में त्रायम रखना जरूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादियों की इस मांग को कि तुर्की जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाय दृढ़तापूर्वक अम्बीकार कर दिया, क्योंकि उसका नतीजा यह होना कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरूसी कम्युनिस्ट पार्टी अलग-अलग हो जाती। उसने ताना स्थानीय क्षेत्रीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमोदन किया।

राष्ट्रवादियों के गिरोह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की फाइकोम से तथा तुकिस्तान की

\* लेनिनी मग्नह, खण्ड ३४, पृष्ठ ३२६। (रूसी संस्करण)

केन्द्रीय कायकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया। इससे १६ जुलाई, १९२० को तुर्क आयोग द्वारा काइकोम को भग करना और तुर्किस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की नयी अस्थायी केन्द्रीय समिति का निर्माण करना जरूरी हो गया। यह भी निश्चित किया गया कि केन्द्रीय कायकारिणी समिति को भग किया जाय और उसको नये ढंग से पुनर्गठित किया जाये। तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की नई अस्थायी केन्द्रीय समिति के प्रधान तियुराक्लोव और नई केन्द्रीय कायकारिणी समिति के प्रधान रहीमबायेव थे। तुर्किस्तान आयोग की पहलकदमी पर काइकोम और केन्द्रीय कायकारिणी समिति के भग किये जान का विभिन्न स्तरों पर पार्टी संगठनों ने व्यापक रूप में स्वागत किया। रिस्कूलोव के नेतृत्व में पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने भूमि और सिचाई सुधारों को लागू करने में बाधा डालने का प्रयत्न किया। रूसी कुलको तथा आप्रवासियों के विरुद्ध तुर्किस्तान आयोग के अभियान का उन्होंने समर्थन किया था, मगर जब मुस्लिम बाई और मानप लोगों के विरुद्ध आक्रमण की योजना बनी, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। वे दशमी पूँजी के विरुद्ध संघर्ष को अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखना चाहते थे। उनकी राय में फौरी कार्यभार बग चेतना को नहीं, बल्कि जातीय चेतना को जाग्रत करना था। इस प्रकार पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने अपने आपको तुर्किस्तान की आम जनता की नज़रों में बिल्कुल बेतुका बना दिया। तियुराक्लोव और रहीमबायेव जैसे ईमानदार और सच्चे मुस्लिम कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों के हानिकारक विचारों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया।

तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी केन्द्रीय समिति ने पाचवी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के आयोजन की तैयारियाँ शुरू कीं। वापस का अधिवेशन ताशकन्त में १२ से १८ सितम्बर तक, १९२० को बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ क्योंकि लाल सेना ने प्रतिनाति और नैदेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष में महान सफलताएँ प्राप्त की थीं। उसने सबसे अधिक से तुर्किस्तान आयोग के फैसले के जरिये काइकोम के भग किया जान का अनुमोदन किया और राष्ट्रवादी भट्ठावावादियों के आचरण और नीतियों की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रवादियों ने बानू में पूँव की जातियों की

कांग्रेस के समक्ष जो निगाधार आराप लगाये थे, उनका कांग्रेस ने खंडन किया। कांग्रेस की रिपोर्टों और भाषणा में इस बात पर जोर दिया गया था कि पार्टी के सामने बुनियादी कायधार सोवियत रूस के मजदूरों और किसानों के साथ तुर्किस्तान के मेहनतनशा की एकजुटता को सुदृढ़ करना और व्यापक बनाना, जातीय असमानता के समस्त अवशेषों को मिटाना तुर्किस्तान के गरीब जनगण का कुलकोष आई और मानव सोगा के शापण से मुक्त करना तथा अमजीवी खानाबदोशों, भूमिहीन खेतिह्य मजदूरों और गरीब किसानों का जमीन देना है। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि गांधी के गरीब तथा मसोल किसानों के हिता का मुनिश्चित करने के लिए कोइसी-गरीब किसानों के सघ-मगठिन करने की आवश्यकता है।

तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पाचवी कांग्रेस ने नियुराकूनोव के मतृत्व में नई केन्द्रीय समिति का गठन किया। उस कांग्रेस ने तुर्किस्तान में पार्टी के संगठनात्मक और विचारधारात्मक दृढीकरण में बड़ी भूमिका प्रदा की। वह इस बात का सबूत थी कि महाशक्तिवादी अधरारप्टवादी और पूजीवादी राष्ट्रवादी भटकावों दोनों से मुक्ति पाने के लिए पार्टी का सघय सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

तुर्किस्तान की सोवियत की नवी कांग्रेस ने, जो सितम्बर १९२० में आयोजित हुई, तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र के लिए नया संविधान मजूर किया। उसने तुर्किस्तान को उस क्षेत्र में रहनेवाली मुख्य जातिया, यानी तुर्कमाना, उरबेका, किगिजों आदि का स्वायत्त जनतंत्र घोषित किया। संविधान १ वैदेशिक मामलों, पतिरसा, वित्त, टाक-तार और संचार को स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के एकमात्र अधिकार में रहने दिया। याद रहे कि १९१८ के संविधान ने भी इन कार्यों को संघीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में धायित किया था, परन्तु उसने तुर्किस्तान के पदाधिकारियों का यह अधिकार दिया था कि वे स्थानीय स्थितियों के अनुकूल सघ की आज्ञानिया और आदशा में फेरबदल कर सकते हैं। तुर्किस्तान स्वायत्त जनतंत्र ऋण भी इकट्ठा कर सकता था तथा पड़ोसी दशा से सीमित वैदेशिक सघय भी स्थापित कर सकता था। वह सघ के उन अधिकारियों को वापस बुलाने की माग भी कर सकता

था, जो उसे स्वीकार नहीं थे। वैदेशिक सवधो, रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक तार तथा वित्त जैसे मामलो में सघ के एकमात्र अधिकार-क्षेत्र पर वे पारदर्शिता बड़ी हद तक गृहयुद्ध और वैदेशिक हस्तक्षेप के कारण जरूरी हो गई थी। १९१८ में तुकिस्तान का केन्द्र से कोई स्थायी सम्पर्क नहीं था। परन्तु १९२० में स्थिति बदल चुकी थी। केन्द्र से अब तुकिस्तान का लगातार सीधा सम्पर्क लक्ष्यमय था। फिर गत तीन वर्षों के अनुभव ने बता दिया था कि इन कार्यभारों का तुकिस्तान जनतंत्र द्वारा समवर्ती अधिकारों की पारदर्शिता के बिना मधोय सरकार के एकमात्र अधिकार-क्षेत्र में रहना ज्यादा अच्छा है। इसके लिए १९१८ के संविधान में हेरफेर करने का प्रयत्न था जिसे तुकिस्तान की सोवियतों की नवी कांग्रेस ने किया। पूँजीवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि १९१८ में जो स्थिति थी, उस स्थापना बना दें और उसे और अधिक बढ़ावें तथा कानून के जरिये उसकी पुष्टि करें। अवश्य ही यह तुकिस्तान के भ्रमजीवी जनगण के वास्तविक हितों के विपरीत था जिसका तकाजा था कि अन्य साक्षित जातियाँ से घनिष्ठ एकता कायम हो।

तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पाँचवीं कांग्रेस और तुकिस्तान की सोवियतों की नवी कांग्रेस के समय तक अधराष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी भटकावों के विरुद्ध तीव्र संघर्ष का दौर समाप्त हो चुका था। मगर ये प्रवृत्तियाँ, घासकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ १९२५ में पुनः १८ के गुट के रूप में उत्पन्न हुई। पार्टी के कुछ सदस्यों पर पूँजीवादी राष्ट्रवादी प्रभाव के जमे रहने का मुख्य कारण नयी आर्थिक नीति के दौर में व्यापारी पक्षधरता, कुल्लुओं तथा अन्य शोषक तत्वों का अस्तित्व था, जो हर सम्भव उपाय से राष्ट्रवादी अवशेषों से लाभ उठाना चाहते थे। प्रशासन का देशी बनाने का कार्यभार से भी समस्याएँ पैदा हुईं और पूँजीवादी राष्ट्रवादी तथा अधराष्ट्रवादी भटकाव उत्पन्न हुए। अधराष्ट्रवादी प्रवृत्ति के लोग दशो लोगों की सजनामा योग्यता में विश्वास नहीं करते थे, जबकि पूँजीवादी राष्ट्रवाद बहन राष्ट्रीय आधार पर दशोकरण की माँग करते थे जिना यह माने हुए कि हमारे लिए वास्तविक तयारियाँ बहा तब हुई हैं और समस्या का मामाजिन और राजनीतिज्ञ स्वरूप क्या है। जातीय गठान पर पार्टी







लाइन में इन दोनों में से किसी भी भटकाव के पुन उत्पन्न होने के विरुद्ध पार्टी अत्यंत चौकसी से काम लेती रही। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वो०) की दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं कांग्रेस ने भी दोनों भटकाव के विरुद्ध, सवप्रथम अधराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघन का नारा दिया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बारसवी कांग्रेस ने भी पार्टी के नये कार्यक्रम में अधराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के अवशेषों के विरुद्ध सघन के कार्य-भार को नहीं भुलाया।

बुद्धारा और खीवा में

जननानि का स्वरूप

बुद्धारा और खीवा में १९२० में जा शानि हुई उन किमाना का मोवियतो के रूप में अमजीवी जनमण की नत्ता स्थापित की। वहा का शानि गरीब किमाना और कारीगरा की शक्तिशाली द्वारा लाल मेना का मनिय सहायता में की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मन है कि बुद्धारा और खीवा की शानि का स्वरूप पूजीवादी-जनवादी था और इन जननत्रा का सामाजिक ढांचा भी पूजीवादी-जनवादी था। वास्तव में, खीवा और बुद्धारा की शानि में सबसे प्रथम पूजीवादी-जनवादी शानि का कायमार पूरा

न प्रयास किया कि किसानों की सोवियतता का अपने वर्गीय शासन के निकाया के रूप में इस्तेमाल करे और पजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम करके क्रांति को खत्म कर दे। परन्तु इन जनतन्त्रों के जनसाधारण ने अकतूबर क्रांति के शक्तिशाली प्रभाव में पजीपति बग की इन आकांक्षाओं का विरोध किया। शुरू ही से उनका प्रयत्न था कि क्रांति का और आगे विकास हो और किसानों की सोवियतता को रूपांतरित करके लोक सोवियत व्यवस्था का आधार बना दिया जाये।

बुखारा और खीवा में क्रांति लोक सोवियत जनतन्त्रों की घोषणा के साथ समाप्त नहीं हुई। समाज का क्रांतिकारी पुनर्गठन और आगे जारी रहा यहाँ तक कि ये जनतन्त्र समाजवादी जनतन्त्रों में परिवर्तित हो गये। दिसम्बर १९२० में सोवियतों की आठवीं अखिलरूसी कांग्रेस में अपने भाषण में बुखारा, आज़रबैजान और आर्मीनिया में सोवियत जनतन्त्रों की स्थापना और सुदृढीकरण का अभिनन्दन करते हुए लेनिन ने कहा

“य जनतन्त्र इस बात के सबूत हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सत्ता के विचार और उसूल केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही नहीं, केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ सबहारा बग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध और फौरन काम में लाये जाने योग्य है, जहाँ आधार किसान-समुदाय है। किसान सोवियतता का विचार विजयी हो चुका है। किसानों के हाथ में सत्ता सुरक्षित है उनके हाथ में ज़मीन है, उत्पादन के साधन हैं। हमारी नीति के व्यावहारिक नतीजों द्वारा किसान सोवियत जनतन्त्रों और रूसी समाजवादी जनतन्त्र के दोस्ताना सम्बन्ध पक्के हो चुके हैं।”\*

आर्मीनिया और आज़रबैजान में विमान जन-साधारण ने अपनी सोवियतों के जरिये मजदूरों से अपनी वर्गीय एकता स्थापित की और अपने जनतन्त्रों को तुरत समाजवादी जनतन्त्रों में बदल दिया। खीवा और बुखारा में इसी प्रक्रिया में तीन चार साल लग गये।

\* व्ला० इ० लेनिन, सकलित रचनाएँ, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९६७, खण्ड ३, भाग २, पृष्ठ ६३-६४। (हिन्दी संस्करण)

## लोक सोवियत जनतंत्र से सोवियत समाजवादी जनतंत्र में संक्रमण

### बुखारा और खीवा में जनतांत्रिकता का स्वरूप

बुखारा और खीवा में १९२० में जो तांति हुई, उसने किसानों की सोवियतों के रूप में श्रमजीवी जनगण की सत्ता स्थापित की। वहां की तांति गरीब किसानों और कारीगरों की शक्तियों द्वारा लाल सत्ता की सश्रित सहायता से की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बुखारा और खीवा की तांति का स्वरूप पूंजीवादी जनवादी था और इन जनतंत्रों का सामाजिक ढांचा भी पूंजीवादी जनवादी था। वास्तव में, खीवा और बुखारा की तांति ने सर्वप्रथम पूंजीवादी जनवादी तांति का वास्तविक प्रारंभ किया। हमें सिवा और कुछ ही भी नहीं सकता था, क्योंकि जिन देशों में अभी सामंती व्यवस्था कायम थी, वहां समाजवादी तांति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हो सकती थीं, और किसी भी तांति का पहला और सबसे बड़ा काम मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को मिटाना था। इसलिए स्पष्टांकित था कि यहां की तांति का स्वरूप पूंजीवादी जनवादी हो।

परन्तु बुखारा और खीवा में फिर ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियों में तांति हुई, उनका प्रभाव भी उसी स्वरूप पर पड़ा। महान् अन्तर्गत तांति का विजय और कम में मावियन सत्ता की स्थापना न बड़ी है तब बुखारा और खीवा की तांति के स्वरूप का निर्धारण किया। वन के पूंजीपति वन

ने प्रयास किया कि किसानों की सोवियतों को अपने वर्गीय शासन के निकायों के रूप में उद्देश्यपूर्ण करे और पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम करके अति को खत्म कर दे। परन्तु इन जनतंत्रों के जनसाधारण ने अक्सर अति के शक्तिशाली प्रभाव में पूँजीपति वर्ग की इन आकांक्षाओं का विरोध किया। शुरू ही से उनका प्रयत्न था कि अति का और आगे विकास हो और किसानों की सोवियतों को रूपांतरित करके लोक सावित्य व्यवस्था का आधार बना दिया जाये।

बुखारा और खीवा में अति लोक सोवियत जनतंत्रों की घोषणा के साथ समाप्त नहीं हुई। समाज का अतिकारी पुनर्गठन और आगे जारी रहा यह था कि ये जनतंत्र समाजवादी जनतंत्रों में परिवर्तित हो गये। दिसम्बर १९२० में सोवियतों की आठवीं अखिल रूसी कांग्रेस में अपने भाषण में बुखारा, आजरबजान और आर्मीनिया में सोवियत जनतंत्रों की स्थापना और सुदृढीकरण का अभिनन्दन करते हुए लेनिन ने कहा

“य जनतंत्र इस बात के सबूत है और उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सत्ता के विचार और उद्देश्य केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही नहीं, केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ सबहारा वर्ग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध और फौरन काम में लाये जाने योग्य है, जहाँ आधार किसान-समुदाय है। किसान सावित्य का विचार विजयी हो चुका है। किसानों के हाथ में सत्ता सुरक्षित है, उनके हाथ में ज़मीन है, उत्पादन के साधन हैं। हमारी नीति के व्यावहारिक नतीजों द्वारा किसान सावित्य जनतंत्रों और रूसी समाजवादी जनतंत्र के दोस्ताना सम्बन्ध पक्के हो चुके हैं।”\*

आर्मीनिया और आजरबजान में किसान जन-साधारण ने अपनी सोवियतों के जरिये मजदूरों से अपनी वर्गीय एकता स्थापित की और अपने जनतंत्रों का तुरंत समाजवादी जनतंत्रों में बदल दिया। खीवा और बुखारा में इसी प्रक्रिया में तीन चार साल लग गये।

\* व्ला० इ० लेनिन, संकलित रचनाएँ, प्रगति प्रकाशन, मास्को १९६७, खण्ड ३, भाग २, पृष्ठ ६३-६४। (हिन्दी मस्वरण)

बुखारा और खीवा में जनता ने तमाम बड़े सामंती जमींदारों और मुल्ताओं की सत्ता का उन्मूलन कर दिया। अब सत्ता किसानों की सोवियतता के हाथ में सौंपी गयी। बुखारा में अमीर और उसके सगे संबंधियों की कोई ७,५०० तनाव जमीन जप्त कर ली गई। सत्ता ऊपर से लेकर नीचे तक जनता के हाथों में थी, जो सोवियतता के जरिये उस काम ले रही थी। जनता के सभी हिस्सों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, उससे वंचित केवल अमीर और खान और उच्च पदाधिकारी थे।

राज्य का सर्वोच्च निकाय जनप्रतिनिधियों की अखिल-बुखारा और अखिल-द्वारखम कुल्लुताई (कांग्रेस) थी। यही कांग्रेस जनतंत्र की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती थी, जो कुल्लुताई के अधिवेशनों के बीच की अवधि में सर्वोच्च निकाय के सारे काम पूरे करती थी। कुल्लुताई ही लोक नाजिरो की परिषद चुनती थी, जो राज्य प्रशासन का एक उच्च निकाय थी।

स्थानीय प्रशासन के निकाय विभिन्न स्तरों की, जैसे ओब्लास्त, रायोन, और योलोस्त की सोवियतें थी जिनकी अपनी-अपनी कार्यकारिणी समितियाँ होती थीं। सत्ता का निम्नतम निकाय गांव या शहर के मोहल्ले के लोगों की आम सभा होती थी।

गांव की आम सभाओं में आक्सफल और स्तारशीना चुने जाते थे। चुनावों में जातकों के सभी नागरिक धर्म पुरोहिता, नस्ल या जाति के भेदभाव के बिना भाग लेते थे। उस राजकीय व्यवस्था की पुष्टि इन जनतंत्रों के संविधानों के जरिये कर दी गई थी। इन जनतंत्रों के राष्ट्रवाद और सामाजिक ढाँचे की विशेषता व्यापक जनवाद और उनका लोकप्रिय स्वरूप था जिससे वे अवश्य ही साधारण पंजीवादी गणराज्यों से अलग थे। कुछ दिनों के लिए निजी स्वामित्व बुद्धिमान और दारुम के लोग माविया जनतंत्रों के आर्थिक आधार के रूप में कार्य कर रहे थे। उन नागरिकों का अपनी निजी तौर पर अजित या निरागत में पायी हुई वस्तु और अचल सम्पत्ति रखने का अनुमति अधिकार था। इसी विशेषता के कारण वे समाजवादी जनता से भिन्न थे।

समाजवादी जनतंत्रों में सश्रम

चरि इन गना जनतंत्रा के अधिभास लाग मरीब विमान और कारोवर में, इनलिए भरवार वा भवप्रथम वाय उनसी स्थिति ता सुधारना था। इस उद्देश वा प्राप्ति के लिए करो, व्यापार तथा दम्तवागी के क्षत्र में के महत्वपूर्ण तन्त्रागिया की गह। बुधारा में विमाना पशुपानवा और दम्तवागी पर दैव काफा कम कर दिये गये। १९१३ में एक विमान का विप्लव कर के रूप में घोषित १२,५ रुपय देना पहला था। परन्तु अब १९२३ १९४ में उन्हें कुल मिलाकर ८ रुपय यानी २ प्रशिक्षित कम देना पना था।\* छावा में भी विमाना पर कर का प्राय २५ प्रशिक्षित कम किया गया।

थे।\* उनके अलावा एक दस्तकारी और चार संगीत के स्कूल खोले गए। १९२२ में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर ५,४०६ हो गई।\*\* यह याद रहे कि आरंभ से पहले बुधारा में घम निरपेक्ष शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं था। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उत्प्रेक्षणीय सफलताएँ हासिल की गई। १९२३ में २६ स्कूल तथा कई दूसरी शैक्षणिक संस्थाएँ काम कर रही थी, जिनमें १,३६२ व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।\*\*\*

बुधारा और स्वतंत्रता के जनतंत्रा में समाजवादी उद्योग की स्थापना और उनके अपने मजदूर वर्ग के निर्माण में कई दशक लग जाते, अगर वह हमी मजदूर वर्ग और उसके राज्य की सहायता नहीं मिली होती। १९२३ में बुधारा में ३२ में से केवल ६ कारखाने चालू थे। खीवा में काई भी औद्योगिक संस्थान काम की हालत में नहीं था। इन जनतंत्रा के शहर मुख्यतः दस्तकारी के क्षेत्र थे, जहाँ व्यापारी पूँजी का बालबाला था। तीस बड़ी व्यापारी फर्मों की पूँजी ही सभी राष्ट्रीयकृत कारखानों की पूँजी से अधिक थी।

मगर इन स्थिति में भी समाजवादी जनतंत्रा में सफलता का परिस्थितियाँ बहुत सजी से परिपक्व हुई। इसका कारण आर्थिक रूप में वर्ग की राजनीति में स्थिति थी। नौजवान बुधारी और नौजवान खीवा जनतंत्रा में कम्युनिस्ट पार्टी की पद्धतियाँ में इतने बड़े पैमाने पर घुस आए थे कि बुधारा में कम्युनिस्ट पार्टी ने मई १९२२ में १६००० हो गई थी।



के नाज़िरो की परिपद मे एक भी देहकान नही था और उमके सारे पदो पर समाज के शापक तत्वो का नियुक्त किया गया था। यही हाल स्वार्ज्म का था।

इसका असर सरकार की नीतियो की तामोल पर पडे गिना नही रह सकता था। स्तालिन ने सम्मेलन मे बताया कि बुधारा के राजकीय बैंक द्वारा दिये गये कर्जों का ७५ प्रतिशत निजी व्यापारियो को दिया गया था और केवल २ प्रतिशत किसान सहकारी समितियो को मिला था। बुधारा और खीवा के राष्ट्रवादी उज्बेको और तुक्मानो के बीच जातीय दंगे की भाग भडकाते थे। बुधारा जनतंत्र के सत्ता निकायो मे उज्बेक पूजीवादी राष्ट्रवादी तुक्मानो और ताजिको के विरुद्ध जातीय भेदभाव की नीति पर अमल करते थे। खीवा मे, जहा उज्बेक और तुक्मान उच्च श्रेणियां मे काफी शत्रुता थी प्रतिक्रियावादी तुक्मान क्रायली सरकार इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करते थे। स्वार्ज्म जनतंत्र की सरकार जिममे अधिकतर नौजवान खीवादी थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी नीतियां पर अमल करती रही। हमने जनता मे आशा की भावना पैदा हुई और ६ मार्च १९२१ को जनता ने सरकार को हटा दिया और कई नाज़िरो का गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कुकूलताई के आयोजन की तैयारी करने के लिए एक क्रांतिकारी समिति नियुक्त का गई।

बुधारा जनतंत्र मे भी सरकार के पूजीवादी राष्ट्रवादी सदस्य जनगण के विरुद्ध पडपत्र रचने लगे। उनमे से कई बासमचियो से मिने हुए थे। १९२१ के अंत मे बुधारा जनतंत्र का अध्यक्ष, उस्मान खोजा म्वय एक नया बासमची दल संगठित करने लगा। बासमचियो का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रवादियो ने तुर्की से इस्लामवादी अनवर पाशा को आमंत्रित किया जिमके नेतृत्व मे मध्य एशिया के सभी बासमची दल एकताबद्ध हो गये। अगर इन घटनाओ से एक आर समाजवादी व्यवस्था की दिशा मे बुधारा और खीवा के नोव सोवियत जनतंत्र के विकास मे निस्सन्देह बढिनाइया पदा हुई तो दूसरी ओर पूजीवादी राष्ट्रवादियो की जन विराधी नीति के कारण उनके विरुद्ध जन आक्रांश बढा। इसकी वजह से थमजीवी जनगण के राजनीति कायकलाप मे वृद्धि हुई। बासमची के विरुद्ध सघन

थे।\* इनके अलावा एक दस्तकारी और चार संगीत के स्कूल खोल गये। १९२२ में विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर ५,४०६ हो गई।\*\* यह याद रहे कि माति से पहले बुधारा में घम निरपेक्ष शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं था। स्वराज्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएँ हासिल की गईं। १९२३ में २९ स्कूल तथा कई दूसरी शैक्षणिक संस्थाएँ काम कर रही थी, जिनमें १,३६२ व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।\*\*\*

बुधारा और स्वराज्य के जनतंत्रों में समाजवादी उद्योग की स्थापना और उनके अपने मजदूर वर्ग के निर्माण में कई दशक लग जाते अगर उन्हें समी मजदूर वर्ग और उसके राज्य की सहायता नहीं मिली होती। १९२३ में बुधारा में ३२ में से केवल ६ कारखाने चालू थे। खीवा में बाद भी औद्योगिक संस्थान काम की हालत में नहीं था। इन जनतंत्रों के शहर मुख्यतः दलनगरी के क्षेत्र थे, जहाँ व्यापारी पूजा का बालवाला था। तब बड़ी व्यापारी फर्मों की पूजा ही सभी राष्ट्रीयकृत कारखानों की पूजा से अधिक थी।

मगर इन बठिन स्थितियाँ में भी समाजवादी जनतंत्रों में सन्नमन का परिस्थितियाँ बहुत तेजी से परिपक्व हुई। इसका कारण आशिक रूप में वहाँ की राजनीतिक स्थिति थी। नीजवान बुधारी और नीजवान खीवा इन जनतंत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी की पंक्तियों में इतने बड़े पमाने पर घम आय थे कि बुधारा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या १९२२ में १६००० हो गई थी। पूजावादी राष्ट्रवादी भाई और व्यापारी भी उन राजकीय निशानों में घुस गये थे। जमा कि स्तानिन में जानिय जनतंत्रों के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के माध्यमों कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) का केंद्रीय भूमिति के चौथे सम्मेलन में बनाया बुधारा लाल साविजन जनतंत्र

\* "उत्तरेण गाविया गमाजगती जनतंत्र का इतिहास", पृष्ठ २ पृष्ठ २१६।

\*\* म० वहागन, उपरान्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४।

\* उत्तरेण गावियन गमाजवादा जनतंत्र का इतिहास, पृष्ठ २, पृष्ठ २१८।

के नाज़िरो की परिपद में एक भी देहकान नहीं था और उसके सारे पदों पर समाज के शोषक तत्वों को नियुक्त किया गया था। यही हाल ख्वारज़म का था।

इसका असर सरकार की नीतियों की तामील पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। स्टालिन ने सम्मेलन में बताया कि बुखारा के राजकीय बैंक द्वारा दिये गये बज्जों का ७५ प्रतिशत निजी व्यापारियाँ को दिया गया था और केवल २ प्रतिशत किसान सहकारी समितियों को मिला था। बुखारा और खीवा के राष्ट्रवादी उज्बेको और तुक्मानो के बीच जातीय भगड़े की आग भड़काते थे। बुखारा जनतंत्र के सत्ता निवाधों में उज्बेक पूँजीवादी राष्ट्रवादी तुक्मानो और ताजिकों के विरुद्ध जातीय भेदभाव की नीति पर अमल करते थे। खीवा में, जहाँ उज्बेक और तुक्मान उच्च श्रेणियों में काफी शत्रुता थी, प्रतिक्रियावादी तुक्मान नवायली सरकार इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करते थे। ख्वारज़म जनतंत्र की सरकार जिसमें अधिकतर नौजवान खीवाई थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी नीतिमा पर अमल करती रही। इससे जनता में आक्रोश की भावना पैदा हुई और ६ मार्च, १९२९ को जनता ने सरकार का हटा दिया और कई नाज़िरो को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कुहलताई के आयोजन की तैयारी करने के लिए एक आतंककारी समिति नियुक्त की गई।

बुखारा जनतंत्र में भी सरकार के पूँजीवादी राष्ट्रवादी सदस्य जनगण के विरुद्ध पड़्यत्न करने लगे। उनमें से कई बासमच्चियों से मिले हुए थे। १९२९ के अंत में बुखारा जनतंत्र का अध्यक्ष, उस्मान खोजा स्वयं एक नया बासमच्चो दल संगठित करने लगा। बासमच्चियों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रवाधियों ने तुर्की से इस्लामवादी अन्वर पाशा को आमंत्रित किया जिसके अन्तर्गत मध्य एशिया के सभी बासमच्चो दल एकताबद्ध हो गये। अगर इन घटनाओं से एक ओर समाजवादी व्यवस्था की दिशा में बुखारा और खीवा के लोक सावियत जनतंत्रा के विकास में निस्सन्देह बढ़ावा पैदा हुई, तो दूसरी ओर पूँजीवादी राष्ट्रवादियों की जन विरोधी नीति के कारण उनके विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा। इसकी वजह से श्रमजीवी जनगण के राजनीतिक कार्यक्रम में वृद्धि हुई। बासमच्चो के विरुद्ध संघर्ष

म श्रमजीवी किसान और कारीगर लाल सेना के नज़दीक आ गये। बासमचियो के कारण लोगो मे इतनी तवाही फैली कि १९१३ की तुलना में १९२३ मे बुखारा मे खेती करनेवालो की सख्या घटकर २८७ प्रतिशत रह गई थी और खानाबदोशो की सख्या ७५१ प्रतिशत हो गई थी।\* यही वजह थी कि गरीब किसान बासमचियो के विरुद्ध लड़ते, उत्साहपूर्वक लाल सेना मे भरती होते, जबकि बहुत से पूँजीवादी राष्ट्रवादी मंत्री बासमचियो से जा मिले, जैसे उदाहरण के लिए युद्ध मंत्री आरिफाब।

सोवियत संघ की सरकार तथा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने इन कठिन दिनों मे बुखारा और खीवा के श्रमजीवी जनगण की बड़ी सहायता की। बासमचियो के विरुद्ध लड़ाई में उनका मदद करने के लिए कई अनुभवही पार्टी नेता और सेना कमांडर भेज गये। इसके अलावा खाद्यान्न की रसद तथा औद्योगिक सामानों के रूप में उन्हें और भी भौतिक सहायता दी गई। ओर्गेनिकीदजे पार्टी तथा सोवियत संघ का सुधारने में हाथ बटाने के लिए रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधि की हैसियत से बुखारा आये। उन्होंने पार्टी और सोवियत संस्थाओं से बेरी बग के लोगो और राष्ट्रवादियों को निकालने के काम में अपने सुझावों निदेशन के जरिये मदद की।

बुखारा और रवारजम लाख सोवियत जनतंत्र सोवियत संघ की भौतिक सहायता और तन्त्रीकी निदेशन के बिना अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं सकते थे। १९२३ में १७ लाख रुबल का सामान २० सौ० स० म० जनतंत्र और तुर्किस्तान से बुखारा भेजा गया। सोवियत संघ ने बुखारा जनतंत्र से व्यापार सम्झौता किया, जो बुखारा के लिए बहुत लाभदायक था। बुखारा की कपास का नया नाम १/२ रुबल प्रति पौंड निर्धारित किया गया, जबकि लागत १० रुबल थी। अक्टूबर-नवम्बर १९२४ में २७६५१२ रुबल का माघाण्डन मन्तमाल का सामान और वृषि

\* '१९२३-१९२४ की राजवाय आधिन याज्ञा में बुखारा का स्थान', बुखारा १९२३, पृष्ठ ५८-५९। (रूसी गस्वरण)

औजार खीवा जनतंत्र भेजा गया। उसी महीन में खीवा जनतंत्र को २५ हजार पूड चीनी, १,००० पूड चमड़ा, २५ हजार जोड़े जूते और ४ हजार पूड चाय भेजी गई। सोवियत संघ ने खीवा जनतंत्र का मराम माफ करनेवाली और तेल की मिला के पुनर्निर्माण के लिए ५७५ हजार रूबल का कज दिया।\*

बुधारा के राष्ट्रवादी तत्त्वा ने सोवियत रूस से बुधारा के संघबद्ध होने के विरोध में एही चाटी का जार लगा लिया और रूस प्रचार बुधारा जनतंत्र की सोवियतों की प्रथम कार्यक्रम के निदर्श का पूरा नहीं लिया। इससे लोग म आक्रोश की लहर फैल गई। जनगण की बढ़ती हृद् शक्तों के कारण बुधारा लोक सोवियत जनतंत्र की कार्यकारिणी समिति का मन्त्रिमंडल (नातिरो की परिषद) से कई मन्त्रियों का जम फिरत नज़रन्नाह खोजा, अमीनाव आदि का, जिनसे जनगण घृणा करते थे, निकालने का फैसला करने पर बाध्य होना पड़ा। चौथी अग्निल-बुधारा कुल्लताई के चुनाव के समय जनगण की चौकसी बहुत बढ़ गई। प्रतिनिधियों का बड़ा बहुमत देहकानो और बारीगरा में से चुना गया। कुल्लताई में सभी जातियों के लोग चुन गए थे। राष्ट्रवादियों के गिलाफ संघ में बुधारा के कम्युनिस्टों को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति की सक्रिय सहायता मिली। नई कुल्लताई की बनावट से ही बग शक्तियों का बदला हुआ सतुलन पूरी तरह जाहिर हो रहा था। अभिलेखागार में नई कुल्लताई के ४२५ प्रतिनिधियों में से कोई ३६० के बारे में जा सामग्री सुरक्षित है उससे स्पष्ट है कि २२७ देहकान थे, २७ मजदूर, ६३ पदाधिकारी, १७ बारीगर, १७ बुद्धिजीवी और नौ अन्य लोग थे। प्रतिनिधियों में १३१ पार्टी-सदस्य थे। प्रतिनिधियों की जातीय बनावट से नई कुल्लताई के बहुजातीय स्वरूप का पता चलता था। उसमें २३७ उज़्बेक, ८१ ताजिक, १६ विगिज, २२ तुर्कमान और ११ यहुदी थे।\*\*

\*म० बहाबोव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७६-३८०।

\*\*वही, पृष्ठ ३८१।

१९२२ में बुधारा और खीवा में पार्टी की सफाई का अच्छा प्रारंभ पड़ा। इस सफाई के बाद १६,००० सदस्यों में से केवल एक हजार पाग में रह गये थे। इससे सदस्यों की गुणावस्था बेहतर हो गई और उनकी वाच्यता का स्तर ऊँचा हुआ। १९२३ में बुधारा में पार्टी के १,५६० सम्प्रदायी थे। इनमें ३५ प्रतिशत देहकान थे, १३ प्रतिशत मजदूर और ८५ प्रतिशत कारीगर थे। खीवा की पार्टी में सफाई के बाद केवल ५४७ सम्प्रदायी रह गये थे, जिनमें ४१५ देहकान, ८० मजदूर, १५ पदाधिकारी, १६ कारीगर और ४१ अन्य लोग थे।\*

बुधारा और ट्यारखम लोग सोवियत जनतंत्रों के जीवन में इन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से कानूना में भी परिवर्तन हुआ जिसने उन्हें समाजवादी जनतंत्रों में रूपांतरण की दिशा में मार्ग बना दिया। १९२२ के गत में अनवर पाशा के नेतृत्व में बासमची के मुख्य दल की शक्ति के बाद बुधारा में बासमचीवाद में कोई दम नहीं रह गया था। लगभग उन्ही दिना ज़ुनैद खान और अन्य तुर्कमान बचावली सरदारों के बासमची दल का भी सफाया कर दिया गया था। १९२३ में इन जनतंत्रों में शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ। जनगणना का दृढ़ यत्न, विमान सभाओं, नौजवान सच आदि जैसे विभिन्न संगठनों में संगठित करने के काम में काफी सफलता प्राप्त हुई। बुधारा में १९२३ तक ट्रेड-यूनियनों की सदस्य-संख्या १६५ हजार तक पहुँच गई थी। विमान सभाओं का संगठन भी सफलतापूर्वक किया गया था। ट्यारखम में १९२३ में उनके सम्प्रदायों की संख्या १० हजार थी।\*\* जनसाधारण अधिनायक समाजवादी विकास की धारा में आकर्षित हो रहे थे। पड़ोसी तुर्किस्तान स्वातंत्र्य सोवियत समाजवादी जनतंत्र में समाजवादी पुनर्निर्माण के लाभदायक अनुभवों ने खीवा और बुधारा के लोगों का विश्वास दिला दिया कि उनके जनतंत्रों के लिए भी वही मार्ग अपनाया ज़रूरी है।

म० यहीमान, उपरान्त पुस्तक, पृष्ठ २८०।

\*“उदात्त सोवियत समाजवादी जनतंत्रों का इतिहास”, पृष्ठ २, पृष्ठ २१७-२१८।

१९२३ के बाद बुखारा और खोवा की जनता में अपने जनतन्त्रा को समाजवादी जनतन्त्रा में पुनर्गठित करने की इच्छा प्रबल रूप में प्रकट हो रही थी। इस के लिए ज़रूरी शत यह थी कि सत्ता के निकाया का पूरा जनवादीकरण तथा सोवियत सस्यामों से शोषक वर्गों के प्रतिनिधियों को निकालकर उनका सुदहीकरण किया जाये। जसा कि हम ने देखा, यह काम इन जनतन्त्रों में सफलतापूर्वक कर लिया गया था।

बुखारा और खारज्म के जनतन्त्रा ने आर्थिक बहाली के काम में भी काफी सफलता प्राप्त की थी। नई आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो कदम उठाये गये, उनका परिणाम बहुत लाभदायक हुआ था। कपास और खाद्यान्न की फसल के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई। १९२४ में बुखारा में कुल वास्तु की जमीन का क्षेत्रफल लगभग युद्धपूर्व के स्तर पर पहुँच गया था। यह ५४,८६,००० तनाब था (१९१३ में इसका आकड़ा ५६,०३,००० तनाब था)। कपास की वास्तु की जमीन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी। १९२० में कपास १,००,००० तनाब जमीन पर उगायी गयी थी, १९२३ में १,३६,००० तनाब जमीन पर और १९२४ में १,६०,००० तनाब जमीन पर।\* कपास की वास्तु की इस वृद्धि के कारण यह ज़रूरी हो गया कि गहयुद्ध के दौरान जो कपास शोधन कारखाने बंद हो गये थे, उन्हें तेज़ी से बहाल किया जाये। १९२३ में छह कपास शोधन कारखाने चालू किये गये। सरकार ने पशुपालन, खास कर कराल भेड़ा के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये। कराल भेड़े खरीदने के लिए विशेष सहकारी समितियाँ संगठित की गईं। इन समितियों को २० लाख स्वर्ण रूबल की सहायता दी गई।

खारज्म में भी अत्यन्त बहाल वर्गों उसका युद्धपूर्व स्तर तक पहुँचाने में बहुत प्रगति हुई। कपास की वास्तु का क्षेत्रफल १९२२ में ८ हजार हेक्टेयरों से बढ़कर १९२४ में ३० हजार हेक्टेयरों हो गया।

\*अ० इशानोव, "बुखारा लोक सावियत जनतन्त्र की स्थापना", ताशकन्द, १९५५, पृष्ठ १६०-१६१। (रूसी संस्करण)

१९२४ के प्रारम्भ तक छह कपास शोधन कारखानों का पुनरुद्धार और विस्तार किया जा चुका था।\*

बुधारा और ट्वारज्म में सावियतीकरण और समाजवादी परिवर्तन का जटिल प्रक्रिया और उनका आर्थिक विकास और साथ ही तुर्कस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र का आगे विकास मध्य एशिया में सावियत जनता के आर्थिक एकीकरण से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध था। इस सवाल को इस कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने पहले पहल फरवरी १९२९ में उठाया। केन्द्रीय समिति ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के एकीकरण से ट्वारज्म और बुधारा के अत्यन्त की बहाली और विकास में बड़ी सुविधा होगी। पजीवादी राष्ट्रवादी हमके विरोधी थे। परन्तु उनका विरोध सफल नहीं हो सका। मध्य एशियाई जनतन्त्र के ताशान्द आर्थिक सम्मेलन ने तीनों जनतन्त्रों के आर्थिक कार्यक्रमों को एक समुन्नत आर्थिक नीति और समान आर्थिक योजना के आधार पर समन्वित करने का निश्चय किया। सभी आर्थिक मामला का आम निदर्शन मध्य एशियाई आर्थिक परिषद के सिपुद कर दिया गया जिसने आर्थिक सम्मेलन द्वारा तैयार और अनुमादित आदेशों के अनुसार काम किया। सम्मेलन में भविष्य सुधार आइस्तेनी और वैदेशिक व्यापार वित्त, परिवहन, महंगाई, डाक-तार तथा सिचाई के संबंध में विचारविमर्श किया गया। यह तय किया गया कि बुधारा और ट्वारज्म में एक ही मद्रा चाल का ताय, बड़ी जा पूरे इसी सा० सो० स० जनतन्त्र में चालू है। टार-तार, नयी परिवर्तन और रतव का समुन्नत प्रवर्ध पूरे मध्य एशियाई स्तर पर किया गया। मध्य एशियाई जनतन्त्रों का आर्थिक एकीकरण बुधारा और ट्वारज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे समाजवाद में संश्लेषण के काम में उन्हें बड़ी सुविधा हुई।

बुधारा और ट्वारज्म में बनने उनका अपना अर्थतन्त्र सामाजिक राजनैतिक आधार समाजवादी परिवर्तन के लिए काफी रहा था। नातिना



संघ के समाजवादी उद्योग तथा मजदूर वर्ग के आवश्यक बाहरी आधार मुहैया किया। बुखारा और स्वारज्य लोक सोवियत जनतंत्र का स्थापन सावियत संघ के साथ गहरे आर्थिक, मासृत्तिक और राजनीतिक सहयोग के बिना, सावियत संघ के अनिवार्य मजदूर वर्ग और किसानों के साथ इन जनतंत्र के साथ की एकता के बिना नहीं सम्भव हो सकता था।

बुखारा लोक सोवियत जनतंत्र की केन्द्रीय कार्यकारी समिति का असाधारण अधिवेशन, जो १४ अगस्त, १९२३ को आयोजित किया गया, उस जनतंत्र के समाजवादी स्थापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने संविधान की कई धाराओं में संशोधन करने का निश्चय किया। इन संशोधनों के अनुसार श्रमिकों के सभी भूतपूर्व पदाधिकारियों, बड़े साहूकारों और व्यापारियों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार शोषक वर्गों का राजनीतिक सत्ता का भागीदार नहीं बनने दिया गया। मजदूरों और लाल सेना के जवानों के मतानुसार का वोट दिया गया। संगठित मजदूरों का १०० मजदूरों पर एक प्रतिनिधि और लाल सेना के जवानों को २५० पर एक व्यक्ति चुनने का अधिकार दिया गया। सभी मंत्रालयों में समितियाँ नियुक्त की गईं जिससे मंत्रियों के लिए मतदान करना सम्भव हो गया।

अक्टूबर १९२३ में चौथी अखिल-स्वारज्य कुरुस्तलाई का अधिवेशन हुआ। उसने नया संविधान स्वीकार किया और स्वारज्य लोक सोवियत जनतंत्र के सोवियत समाजवादी जनतंत्र में सश्रमण की घोषणा की। संविधान ने एतान किया कि सरकार का मुख्य काम ऐसी स्थितियाँ पदा करना है जिनमें मानव द्वारा मानव का शोषण सम्भव हो जाये। सारी भूमि जनगण की सम्पत्ति घोषित कर दी गई और श्रमजीवी किसानों को मुफ्त ट्रेडिंग के लिए दे दी गई। संविधान ने सभी शोषक वर्गों को मतानुसार से वंचित कर दिया। सितम्बर १९२४ में पाचवी अखिल-बुखारा कुरुस्तलाई ने बुखारा में सोवियत समाजवादी जनतंत्र की स्थापना घोषित की। उसने सोवियत संघ के साथ अटूट और बिरादराना एकता बनाये रखने की आवश्यकता की घोषणा की, क्योंकि एकमात्र इसी से समाजवाद का और सश्रमण में सहायता मिल सकती थी। इस प्रकार

द्वारा और खारज्म लोक सोवियत जनतन्त्र का सक्रमण सोवियत राज्य से सोवियत समाजवादी राजत्व में सम्मन हुआ।

समाजवादी अवस्था में सक्रमण के बारे में अक्सर गलतफहमी पाई जाती है। कुछ लेखकों ने कृषि और औद्योगिक सबंधों के ढांचे में पटन में बुनियादी परिवर्तनों के बिना समाजवादी राजत्व में प्रवेश को गन्त बनाया है। मसलन, अ० ज० पाक ने बुखारा और खारज्म का समाजवादी अवस्था में लाने के अभियान का "शब्द" "राजनीतिक स्तर" का अभिप्राय बताया है।\* उनके विचार में यह काम जल्दी में केवल "राजनीतिक शक्तियों के परस्पर संबंध" को ऊपर ही ऊपर बदल कर, यानी 'घोरे वीरे गैर कम्युनिस्ट नेताओं को अलग करके", पहले से काई घात समाजवादी उद्घाटीकरण या कृषि संबंधों में शामिल परिवर्तन किए बिना किया गया।

परन्तु पाक भूल जाते हैं कि समाजवादी राजत्व का काम ही इन परिवर्तनों का लाना है। समाजवादी राज्य ही समाजवादी समाज का निर्माण करता है। इसके अलावा बुखारा और खारज्म में सोवियत दौर में जो सामाजिक आर्थिक तन्दीलियां हुई, उन्हें पाक नजरअन्दाज करत हैं और समाजवादी राजत्व में सक्रमण की तैयारी में उनकी भूमिका का महत्व नहीं समझते। किसी राज्य का सामाजिक स्वरूप ठीक इस बात से निर्धारित होता है कि राजनीतिक सत्ता का मालिक कौन है। किसानों के व्यापक बायबलाप और राजनीतिक चेतना में वृद्धि तथा व्यापारियों और साहूकारों जैसे शापक तत्वा के विरुद्ध उनके निरन्तर संघर्ष की बन्तन इन तत्वा का पार्टी और राज्य निवासा में निकलना पड़ा। युसूपान और उसमान खोजायेव जैसे व्यापारियों के प्रजाय राजनीतिक सत्ता में देहकाना और श्रमजीवी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई, जो अपने जनता का समाजवादी के रास्ते पर चिन्तित करना चाहते थे। इसलिए खारज्म और बुखारा के जनता का समाजवादी जनता

\* A G Park *Bolshevism in Turkestan 1917-27* New York 1957 pp 107-108

मे सत्रमण ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नम था। उनकी विशेष भौगोलिक स्थिति और इस म अस्तुतर प्राति के ऐतिहासिक प्रसंग म उनके लिए सामाजिक विकास की पूजावादी व्यवस्था स गुजरन की ज़रूरत नहीं रही। रूसी मज़दूर वग स उनके विमाना की एवना न अपन देशी मज़दूर वग की कमी पूरी कर दी।

# सोवियत जातीय जनतन्त्रों का निर्माण

## १९२४ का जातीय राज्य सीमा निर्धारण — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण १९२४ में किया गया, जिसके फलस्वरूप जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों का निर्माण हुआ। इनमें से दो—उज़्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और तुर्कमान सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण सोवियत संघ के भीतर संघीय जनतन्त्रों के रूप में हुआ। दूसरे जैसे मिसाल के लिए ताजिक, का निर्माण उज़्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के भीतर स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के रूप में हुआ। मध्य एशिया के कज़ाख़ रूसाना को रूसी सो० म० सं० जनतन्त्र के भीतर उस समय के किर्गिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में एकताबद्ध किया गया। क़रग़न्दाविया स्वायत्त ओल्लास्त की हैगियत से किर्गिज़ स्वायत्त सो० सं० जनतन्त्र में शामिल हुआ। किर्गिज़ में स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना की और रूसी सो० म० सं० जातन्त्र के भीतर क़राकिर्गिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के नाम से शामिल हुए। इन जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों और स्वायत्त ओल्लास्तों में मध्य एशिया का मौलिक जातीयता का उनका जानाया गया का रूप में इतिहास में पहला बार एकताबद्ध किया गया।

तुर्कमेन स्वायत्त सोवियत समाजवादी जातन्त्र का निर्माण, जो रूसी सो० म० सं० जनतन्त्र में शामिल हुआ, मध्य एशिया



तुक्मान सो० म० जनतन्त्र की  
विज्ञान अकादमी अशकाबाद

कज़ाख सो० स० जनतन्त्र की  
विज्ञान अकादमी अशकाबाद

१९२४ का जातीय राज्य सीमा-निर्धारण

— ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

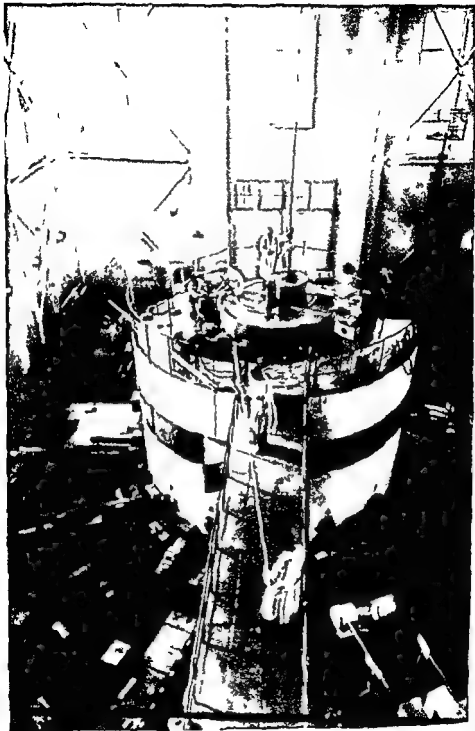
मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण १९२४ में किया गया, जिसके पन्त्ररूप जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों का निर्माण हुआ। इनमें से दो—उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और तुर्कमान सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण सोवियत संघ के भीतर मधीय जनतन्त्रों के रूप में हुआ। दूसरा जैसे मिसाल के लिए ताजिक, का निर्माण उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के भीतर स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के रूप में हुआ। मध्य एशिया के कजाख स्लावों को इसी मा० स० स० जनतन्त्र के भीतर उस समय के किगिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में एकराबद्ध किया गया। कगनल्पाकिया स्वायत्त ओग्लास्त की हैगियत में किगिज़ स्वायत्त सा० म० जनतन्त्र में शामिल हुआ। किगिज़ा में स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना का और इसी मा० स० स० जनतन्त्र के भीतर किराकिगिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के नाम से शामिल हुए। इस जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और स्वायत्त ओग्लास्तों में मध्य एशिया की मौलिक जातियाँ का उनका जातीय राज्यों के रूप में इतिहास में पहला बार एकराबद्ध किया गया।

तुर्किष्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण जो मध्य एशिया की दूसरी सा० म० स० जनतन्त्र में शामिल हुआ, मध्य एशिया



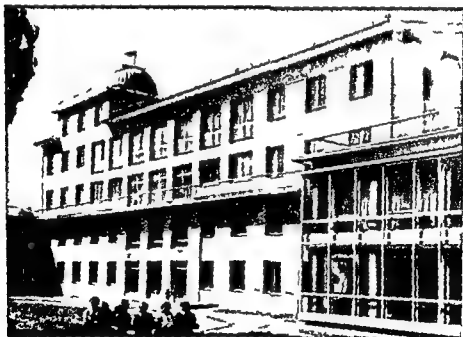
तुकमान सो० म० जनतंत्र की  
विज्ञान अकादमी अशकावाद

कजाख सो० स० जनतंत्र की  
विज्ञान अकादमी, अन्मा-अता



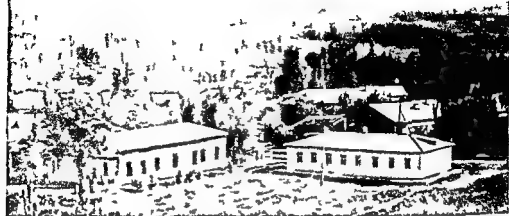
उत्तम गा० म० जनतंत्र की  
विज्ञान परामर्शी की नाभिकीय  
भौतिकी सभा में परमाणु रिएक्टर



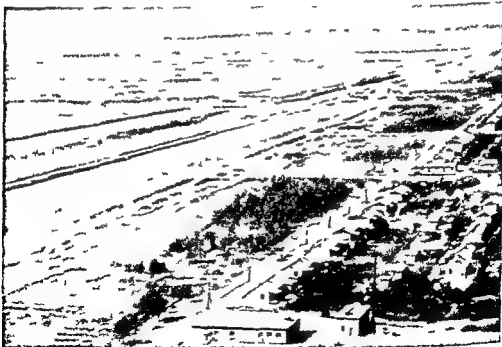


ताशवन्द में लेनिन राजकीय  
विश्वविद्यालय

अल्मा अता में युवा पाथानियर  
तथा छात्र भवन



हिस्सार जिले में ज़दानाब सामूहिक  
फार्म ताजिक सा० स० जनतंत्र





वराहम नहर के नट पर स्थित  
वराकूम राजकीय काम, तुकमान  
सा० म० जनतल



भन्दीवान प्रन्त म गुनवध  
 राजकीय काम म बपाम की  
 बटार् उरवेर गा० म० जनात

यत्  
 १२  
 मा.  
 मा.



यादगार नसरिहीनोवा, १९५९-१९६० की अवधि में उज्बेक सो. सो. जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल की अध्यक्षता

भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खां की मलाकात, ताशकन्द, १९६६।



ਸ਼੍ਰੀਮੇਰ ਨਵਾਇ ਤਰੇਰ ਸਰਸਾਧ  
ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ ਧੀਰ ਬਾ ਪਿਥਰ

ਸੰ. ਤਰਸਾਰ ਫ਼ਾਗ ਰਿਧਿ  
ਤਰੇਰ ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ  
ਤਰੇਰ ਸ ਮਾਸਿਧਿਤ ਸਧ ਕਾ ਸਾਰ  
ਸ਼੍ਰੀਮਿਤ ਰਿਧਿਤ ਨਮਾਸਤਾ

वे लोगो के सोवियत जातीय राजत्व के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। बहुजातीय स्वायत्त तुकिस्तान जिसका अस्तित्व १९२४ तक रहा, याना जातीय सीमा निर्धारण के समय तक, उस भूखण्ड खारशाही उपनिवेश में राजकीय ढांचे का एकमात्र सही और उचित रूप था, जो उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुकूल था। अस्तूबर नाति के तुरंत बाद मध्य एशिया के लोगो के जातीय निर्माण की धीमी प्रक्रिया के कारण विभिन्न जातियों के परस्पर सम्बन्धों की कठिनाइयों के कारण, जो अतीत से चली आ रही थी, और अन्य कारणों से भी जातीय सीमा-निर्धारण असम्भव था।

पहले यह जरूरी था कि अस्तूबर नाति की उपलब्धियों की रक्षा की जाय और उन्हें सुदृढ़ किया जाय, अदरुनी प्रतिनाति और वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप को शिक्स्त देकर सोवियत सत्ता को मजबूत बनाया जाय। इसके अलावा बुखारा और खीवा में नाति १९२० तक नहीं हुई थी और मध्य एशिया में जातीय सीमा के निर्धारण का सवाल बुखारा और खीवा के बिना उठ ही नहीं सकता था। सफलतापूर्वक जातीय सीमा निर्धारण के लिए यह भी जरूरी था कि अमजोबी जनता राजकीय कामकाज में व्यापक भाग ले सके। जातीय सीमा निर्धारण की एक और बात यह थी कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में तथा समाजवादी जातियों के निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी हो।

जातीय-अन्तर्जातीय सीमा निर्धारण योजना, जिसके अनुसार मध्य एशिया में उस समय के बहुजातीय तुकिस्तान, बुखारा और खारखम के बजाय उस इलाके की प्रत्येक मुख्य जाति के लिए अलग जातीय जनतन्त्र का निर्माण किया गया सावियत और गर-सावियत विद्वानों में बहुत बाद-विचार का विषय रही है। कुछ सोवियत-विराधी लेखकों को इस योजना के पीछे सावियत अधिवास्या का 'छत्रपट और घुरा विचार' दिखाई दिया जिसका उद्देश्य उन लोगो के जिज्ञासु बहुमत का, जो "जाति और भाषा की दृष्टि से समरूप" और "तुर्की" जाति के थे, कृत्रिम रूप से फूट डालकर अलग अलग करना था। उदाहरण के लिए, मुस्तफा चोबायव, जो एक समय कोकान 'स्वायत्त' सरकार के अध्यक्ष थे, इस

योजना को "तुकिस्तान को बर्बादली राज्यों में विभाजित करने" की योजना बताते हैं जिसे बोल्शेविकों ने इसलिए ईजाद किया था कि "मुसलमान कम्युनिस्टों" द्वारा तमाम तुर्की कबीलों का सोवियत तुकिस्तान के गिद एकताबद्ध करने के प्रयासों का विफल बनाया जाये।\* एक इसी उत्प्रेक्षाशील विद्वान प्रिंस सोवोनाव-रोस्तोव्स्की का कहना है कि सीमा निर्धारण की योजना को "नस्ली जातीय मोरखों को हल करने की चिन्ता उतनी नहीं थी, जितनी इस समस्या से उत्पन्न राजनीतिक पहलू की" थी और कि वह केवल बासमन्ची विद्रोह को बोल्शेविकों का जवाब था।\*\* अन्य लोगों की तरह में जातीय सीमा निर्धारण की योजना "लड़ाकू और राज कर के पुराने साम्राज्यवादी उसूल" का इजहार थी।\*\*\* हयुग सीटन-वाट्सन का जातीय सीमा निर्धारण में यह "स्पष्ट उद्देश्य" लिखा है दिया कि "अन्य भिन्न भिन्न जातियाँ" बनायी जाये जिन्हें एक दूसरे से अलग रखा जा सके, एक दूसरे से लड़ाया जा सके और अलग अलग स्वीकृति से जाड़ा जा सके"। उनकी राय में, यह इसलिए किया गया कि "मध्य एशिया के मुसलमानों का समुक्त मोरचा" बनने का खतरा दूर हो जाय।\*\*\*\*

परन्तु ये दावे मनुष्य पूर्वग्रहों का नतीजा हैं और इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मध्य एशिया के जातीय सीमा निर्धारण का मूल निष्ठा स्वयं वांछित जातीय नीति का प्रत्यक्ष नतीजा था। उपयुक्त आरोप लगाने का मतलब खूब सावधानी विचारों के बिना सोवियत जातीय नीति की मौजूदगी

---

\* Mustapha Chokayev *Turkestan and the Soviet Regime*, —*Journal of Royal Central Asian Society* London XVIII, 1931, p 414

\* Lobanov Rostovsky *The Muslim Republics in Central Asia*,—*Journal of the Royal Institute of International Affairs* London 7 (1928) pp 249-50

\*\*\* *The Central Asian Review* London 8 (1960) pp 342-43

\* Hugh Seton Watson, *The New Imperialism*, London 1964, Third Impression p 58



और मध्य एशिया की जातीय समस्या की जटिलता से इनकार करना है। जातीय सीमा निर्धारण के विचार का १९२४ में आविष्कार नहीं हुआ। वह बहुत पहले से मौजूद था, मगर केवल १९२४ में उसको कार्यान्वित किया गया, जब इसके लिए ऐतिहासिक परिस्थितियाँ परिपक्व हो गई। १९१३ में ही लेनिन ने अपनी वृत्ति “राष्ट्रीय प्रश्न के संबंध में आलोचनात्मक अभ्युक्तियाँ” में ज़ारशाही रुस के पुराने मध्ययुगीन विभाजनों को बदलने और जहाँ तक हो सके आबादी की जातीय बनावट के अनुसार नये विभाजन कायम करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया था।\* १९१३ में रुसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय समिति ने ‘स्वयं स्थानीय आबादी द्वारा उनके आधिक्य और नस्ली भेद तथा जातीय बनावट, आदि के अनुसार क्षेत्रीय स्वायत्त और स्वशासित इकाइयों की सीमाओं के निर्धारण’ की आवाज़ बुलंद की थी।\*\* अप्रैल १९१७ में पार्टी के सातवें सम्मेलन ने इस पूरी बात की पुनः पुष्टि की थी।\*\*\* जातीय सीमा निर्धारण के सिद्धांत पर उज़्बेकी, बेलोरूसी, ज़ाज़ियाई, आरमीनियाई, आज़रबैजानी, तातार, बाश्कीर, चुवाश, काश्मिक और याकूती जातीय जनतन्त्रों की स्थापना करके पहले ही अमल किया जा चुका था। परंतु तुर्किस्तान में इस पर अमल नहीं किया जा सका था, क्योंकि वहाँ की स्थिति अधिक पचीदा थी। भिन्न मध्य एशियाई जातियाँ तुर्किस्तान, बुखारा और खीवा के तीन भिन्न राज्यों में घुली मिली हुई थी।

मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण का सवाल सबसे पहले लेनिन ने जुलाई १९२० में तुर्किस्तान जनतन्त्र के संबंध में तुर्किस्तान आयोग द्वारा प्रस्तुत मसविदा पर अपनी टिप्पणियाँ में उठाया था। लेनिन ने तथाकथित तुर्की जनतन्त्र की स्थापना के बारे में रिस्क्लाव के राष्ट्रवादी मसविदे को अस्वीकार कर दिया था। निम्न भविष्य में जातीय सीमा

\* V I Lenin, *Collected Works*, vol 20 p 48

\*\* “सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव”, १९५४, भाग १ पृष्ठ ३१५। (रूसी संस्करण)

\*\*\* वही, पृष्ठ ३४६।

निर्धारण की सम्भावना की परिकल्पना करते हुए उन्होंने तुर्किस्तान का एक नस्ली नक्शा तैयार करने का आग्रह किया जिसमें उज़्बेक, किर्गिज़ और तुर्कमान विभाजन दिखाया गया हो और इन तीनों भागों के विलयन या अलगाव की सहायक परिस्थितियों का आलोचनात्मक, व्यापक मूल्यांकन किया गया हो।\* यद्यपि लेनिन अनेक जातीय जनतंत्रों में तुर्किस्तान के विभाजन के जरिये उसकी जातियों के साविक जातीय राजत्व के आगे के विकास की प्रवृत्ति के महत्त्व को पूरित समझ रहे थे मगर उन्होंने इस सवाल में जल्दबाज़ी करने से मना किया। प्रस्तावित सीमा निर्धारण करने से पहले सारी ज़रूरी तयारियाँ कर लनी थीं।

तुर्किस्तान आयाग में उस क्षेत्र की नस्ली और आर्थिक स्थिति का अनुसार तुर्किस्तान का प्रशासकीय पुनर्विभाजन करने के पक्ष में निश्चय किया था। परन्तु उसने तुर्किस्तान जनतंत्र के इलाक़ों का तुरत कई जातीय जनतंत्रों में बांटने के सुझाव का विरोध किया। ५ जून, १९२० का उसने तार के जरिये अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मंडल और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति को सूचना दी कि इस प्रकार के विभाजन से तुर्किस्तान में अव्यवस्था फैल जायेगी और राष्ट्रप्राप्ति तत्वा का अवश्य इसमें मदद मिलेगी। राजनीतिक परिस्थिति के कारण कुछ दिनों तक समुक्त तुर्किस्तान जनतंत्र का समय रूकना था।\*\* केन्द्र ने जातीय सीमा निर्धारण का स्थगित करने में सहमति प्रकट करत हुए तुर्किस्तान आयाग का आग्रह किया कि इस मसाले में सवध में तयारी का काम जारी रहे। जमा कि ठगर कहा गया, य आदेश ननिन न जुनाई १९२० में जारी किये थे। इन आग्रहों के अनुगार मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण की सामग्रीपूर्ण तयारियाँ शुरू हुई और उनका कार्यान्वित कराना अग्रे केवल समय का मसाल था।

\*नेतिना सग्रह, मण्ड ३४ पृष्ठ ३२२-३२६। (रूसी मसूरा)

य० त० तुगुनाय द्वारा उद्धृत "मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण का बार म", तागान्द, १९५७ पृष्ठ ६। (रूसी मसूरा)

१९२१ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की दसवीं कांग्रेस ने पार्टी का आह्वान किया कि वह अतीत में आरशाही द्वारा उत्पीड़ित गैर-रूसी जातियों की श्रमजीवी जनता की सहायता करे ताकि वह हर तरीके से, जो उसकी जातीय तथा श्रम जीवन स्थितियों के अनुकूल हो, अपने सोवियत राजत्व को विवसित और सुदृढ़ कर सके।\* १९२३ में बारहवीं पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर जातीय जनतंत्रों को सुदृढ़ बनाने और आगे निकालने के लिए परम आवश्यकता पर जोर दिया।\*\*

तुर्किस्तान बुखारा और ख़्वाज़ेम की सोवियत सरकारों की नीति ने जातीय विभागा के निर्माण, जातीय स्वायत्त प्रोन्लास्तो की स्थापना, देशी जातियों की भाषाओं साहित्य तथा अख़बारों के विकास के जरिये जातीय सीमा निर्धारण के लिए ज़मीन तैयार की है। तीनों मध्य एशियाई जनतंत्रों की सरकारों ने इस दिशा में जो कदम उठाये, उनसे विभिन्न जातियों में अपने-अपने अलहदा जातीय राजत्व की इच्छा ने जोर पकड़ा। जातीय मामलों की कमिसारियत ने, जिसकी स्थापना १९१८ में हुई थी, अपने अतगत उज़बेक, ताजिक, तुर्कमान, किर्गिज़, तातार, आरमीनियाई, उज़्बेक तथा देशी यहुदिया के अलग-अलग विभाग कायम कर लिए थे। ३१ मार्च, १९२१ को तुर्किस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अतगत कज़ाख़ \*लाओ की सुखसमृद्धि का ध्यान रखने के लिए एक अलहदा कज़ाख़ विभाग खोला गया। तुर्किस्तान में जातीय मामलों की कमिसारियत को भंग करने के बाद इसके अतगत जातीय विभागों का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के हवाले कर दिया गया और उनकी वही हैसियत थी, जो कज़ाख़ जातीय विभाग की थी। उन जातीय विभागों ने उन लोगों की, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे जीवन स्थिति ससृजित और भाषा को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने तुर्किस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की अपनी जातियों की आवश्यकताओं से अवगत

---

\* "सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव", भाग १ पृष्ठ २५६।

\*\* वही, पृष्ठ ७१५।

कराया। तुकिस्तान की जातियाँ के आत्मनिर्णय की तैयारी के लिए अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अगस्त १९२० में तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को यह सुझाव दिया कि वह जातीय बनावट के अनुसार तुकिस्तान के प्रशासकीय जिला के पुनर्विभाजन की योजना बनाये। अगस्त १९२१ में ट्रांसकास्पियन ओब्लास्त का नाम बदलकर तुक्मान ओब्लास्त रख दिया गया, क्योंकि वहाँ तुक्मान जाति के लोग बहुमत थे।\* अप्रैल १९२२ में जेतीसुव, सिर-दरिया और फरगाना ओब्लास्तों के विभिन्न बहुमतवाले क्षेत्रों का मिलाकर विभिन्न ओब्लास्त का संगठन किया गया। बुखारा और ख़ारख़म की केन्द्रीय कार्यकारिणी समितियाँ में तुक्मान और विभिन्न जातीय विभाग कार्य में लिये गए। बुखारा जनतंत्र में चारज़ू को केन्द्र मानकर तुक्मान ओब्लास्त बनाया गया। १९२२ में पूर्वी बुखारा, जहाँ ताजिकों का बहुमत था, के प्रशासन के लिए एक विशेष आयोग स्थापित किया गया। अक्टूबर १९२३ में ख़ारख़म जनतंत्र में एक तुक्मान और एक करानत्याक ओब्लास्त संगठित किए गए। उरगेंच बहुमत के इलाक़ों को अलग करके नोवा-उरगेंच ओब्लास्त और ख़ीवा रायोन बनाया गया।\*\*

१९२० में विभिन्न (बज़ार) स्वायत्त सावित्त समाजवादी जनतंत्र का निर्माण के साथ जातीय सीमा निर्धारण का सवाल सामने आ गया। अक्टूबर १९२० में तुकिस्तान स्वायत्त सावित्त समाजवादी जनतंत्र का ट्रांसकास्पियन ओब्लास्त के उत्तरी भाग का बज़ार लागू की इच्छा का अनुसार विभिन्न स्वायत्त सावित्त समाजवादी जनतंत्र में मिला दिया गया। विभिन्न जातियों की स्वायत्तता के सङ्घ में रु० सा० स० स० जनतंत्र का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा १ मिय्र, १९२० का जारी की गई घोषणा की धारा २ में यह प्रथम था कि तुकिस्तान स्वायत्त सावित्त

\* श० इ० मुल्मजाराज़ "१९२४ में मध्य एशिया का जातीय राज्य सीमा निर्धारण का इतिहास की यात्रा", - "मासिक नामाकरण" १९४१ वर्ष १ पृष्ठ ८८। (रूसी मसूदा)

\*\* यही, पृष्ठ ८६।

समाजवादी जनतंत्र के विगिज (कज़ाख) क्षेत्र को इन घोषणास्तो के जनगण को इच्छा के अनुसार विगिज स्वा० सो० सं० जनतंत्र में मिला दिया जाय।\* जनवरी १९२१ में तुकिस्तान स्वा० सो० सं० जनतंत्र के कज़ाख शरीफो को प्रथम क्षेत्रीय कांग्रेस ने तुकिस्तान स्वा० सो० सं० जनतंत्र के गिर-दरिया और जेतीसुव घोषणास्तो के कज़ाख इलाका को विगिज स्वा० सो० सं० जनतंत्र में मिला देने का भाग की। मार्च १९२२ में ६० सो० सं० म० जनतंत्र की जातीय मामला की कमिसारियत में इस सवाल पर विचारविमर्श तथा अप्रैल १९२२ में तुकिस्तान और विगिज स्वा० सो० सं० जनतंत्र के ग्यारहवीं पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह साफ हो गया कि तुकिस्तान स्वा० सो० सं० जनतंत्र के कज़ाख क्षेत्रों को विगिज स्वा० सो० सं० जनतंत्र में मिलान का सवाल अभिन्न रूप से मध्य एशिया के जातीय राज्य सीमा निर्धारण के भाग सवाल से सम्बद्ध है। इस तरह हम देखते हैं कि जातीय सीमा निर्धारण की भाग मध्य एशिया की जातियाँ न स्वयं बनने की। सबसे पहले स्थानीय पार्टी तथा अन्य सामाजिक संगठन न ही इनकी भाग की और केन्द्र न १९२४ में जातीय सीमा निर्धारण करने केवल इस भाग की पूर्ति की।

फरवरी १९२४ में जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर बुधारा के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन हम नतीजे पर पहुँचा कि सवाल ज़िल्बुन सुमायियन है। इसका बुधारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति न २५ फरवरी, १९२४ को अपने पूर्णाधिवेशन में इस प्रश्न पर विचार किया। पूर्णाधिवेशन ने भी इसकी अनुमति दी। मार्च १९२४ में छवारसम के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भी जातीय सीमा निर्धारण करने के विचार का समर्थन किया। १० मार्च १९२४ को तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, तुकिस्तान की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और ताशकंद के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के संयुक्त सम्मेलन ने जातीय सीमा

\*इ० खादारोव, "मध्य एशिया का जातीय सीमा निर्धारण" - 'नोवी वोस्तोक', १९२५, अंक ८-९ पृष्ठ ६६।

निर्धारण के विचार का पूणत समथन किया। २३-२४ मार्च, १९२४ का तुकिस्नान कम्युनिस्ट पार्टी के पूणाधिवेशन ने जातीय सीमा निर्धारण का माग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी।

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल का तय करने में ट्वारज्म जनतन्त्र में कुछ कठिनाइयां हुई। ट्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य समिति की कार्यकारिणी समिति ने जिना काई उचित कारण बताए हुए इसका विरोध किया। परन्तु बड़ी हद तक पार्टी के आम सदस्या के समथन के दबाव से ट्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति का अपना गलत मत बदलना पड़ा। उसने भी ट्वारज्म जनतन्त्र के जातीय सीमा निर्धारण की आवश्यकता का स्वीकार किया।

५ अप्रैल १९२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्राय समिति के पालिटब्यूरो ने मध्य एशिया के जनतन्त्र का जातीय सीमा निर्धारण करने के सन्ध में मध्य एशिया के पार्टी-मगठना के मुताबा की मिढातत स्वीकार कर लिया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) ने मध्य एशिया व्यूरा का आवश्यक तयारिया करने का आन्श लिया। २८ अप्रैल १९२४ का मध्य एशिया व्यूरा ने उरजेका, तुर्कमाना, बजार्गा किगिजा और ताजिका के लिए क्षेत्रीय आयाग तथा उप आयाग नियन्त्रण लिये। उह यह कायभार दिया गया कि जिन जनतन्त्र और सोव्हास्ता का निर्माण करना है उनका इतारे तय करने सीमा निर्धारण का ध्येयनार में कायाबिन करे।

मई १९२४ में तुकिस्नान कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस ने भाष्य सवान पर विचार लिया। इस कांग्रेस में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने ट्वरज्म का स्थायी कम्युनिस्ट के विभाग का जातारा समित्त कर के लिए भेजा था। तुकिस्नान कम्युनिस्ट पार्टी के गतिव ने जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर निम्नागूना प्रकाश गता। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में गाविया जातीय नीति की तामात में "यह एक प्रगतिशील काम" है। उक्त में प्रतिनिधियां ने यह बात पर

जोर दिया कि जातीय सीमा निर्धारण स मध्य एशिया की जातियों के अधिक और सांस्कृतिक विकास की सम्भावनाएँ बहुत बढ जायेंगी। एक ताजिक प्रतिनिधि सगिजवायेव ने बताया कि अगर यह प्रस्तावित सुधार नहीं लिया गया, तो जातीय मतभेदों का कारण समाजवादी निर्माण के काम में बाधा पड़ती रहेगी।\* हज़रुताव ने "मन की लहरा" के आंदोलन के छतरे से छबरदार किया और पार्टी कायकर्ताओं का आवाहन किया कि ऐसे आंदोलन को "स्वस्थ कम्युनिस्ट मार्ग" से विचलित नहीं होने दें।\*\*

### जातीय राज्य सीमा निर्धारण व्यवहार में

१० मई, १९२८ का जातीय सीमा निर्धारण आयोग ने जातीय आयोगों की सिफारिशों पर विचार किया। उसने पूरा रूप में उज़बेक और तुर्कमान जातीय जनतन्त्रों की तथा ताजिक और गिर्गिज सोव्स्लात्सों की स्थापना का समर्थन किया। उसने तुर्किस्तान के कज़ाख इलाक़ों का कज़ाख स्वा० सा० सं० जनतन्त्र में मिलान और एक मध्य एशियाई मध्य स्थापित करने के लिए कज़ाख जातीय आयोग की सिफारिशों का अस्वीकार कर दिया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति ने मध्य एशियाई व्यूरो ने जातीय सीमा निर्धारण आयोग की सिफारिशों का रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पास भेज दिया।

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पोलिटब्यूरो ने २ और १२ जून, १९२४ का इन सिफारिशों पर विचार किया। १२ जून को उसने मध्य एशिया के जनतन्त्रों के जातीय सीमा निर्धारण के संबंध में एक प्रस्ताव पास कर निम्नलिखित बातों का मुझाव दिया

१ स्वतंत्र उज़बेक और तुर्कमान जनतन्त्रों का निर्माण किया जाय और टारसम जनतन्त्र का, उससे तुर्कमान इलाक़ों को अलग करने के बाद वर्तमान रूप में कायम रखा जाये।

\* वही।

\*\* वही, अथ १८१ (४५८), १८ अगस्त, १९२४।

निर्धारण के विचार का पूणत समथन किया। २३ २४ मार्च, १९२४ का तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णाधिवेशन ने जातीय सीमा निर्धारण का भाग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी।

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल को तय करने में स्वारज्म जनतंत्र में कुछ कठिनाइयां हुई। स्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्राय समिति की कार्यकारिणी समिति ने बिना कोई उचित कारण बताये हुए इसका विरोध किया। परन्तु बड़ी हद तक पार्टी के आम सदस्या के समथन के दबाव से स्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति को अपना गलत मत बदलना पड़ा। उसने भी स्वारज्म जनतंत्र के जातीय सीमा निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार किया।

५ अप्रैल, १९२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्राय समिति के पालिटब्यूरो ने मध्य एशिया के जनतंत्रों का जातीय सीमा निर्धारण करने के संबंध में मध्य एशिया के पार्टी संगठनों के मुद्दाओं को मिद्धातत स्वीकार कर लिया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) ने मध्य एशिया ब्यूरो को आवश्यक तयारिया करने का आदेश दिया। २८ अप्रैल, १९२४ का मध्य एशिया ब्यूरो ने उज्बेको, तुकमाना, बजाया किगिजो और ताजिको के लिए क्षेत्रीय आयोग तथा उप आयोग नियुक्त किये। उन्हें यह कार्यभार दिया गया कि जिन जनतंत्रों और ओब्लास्तों का निर्माण करना है उनके इलाके तय करके सीमा निर्धारण को व्यवहार में कार्यावित कर।

मई १९२४ में तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस ने भी इस सवाल पर विचार किया। इस कांग्रेस में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति ने रुदजुताव को स्थायी कम्युनिस्टा के विचारों का जानकारी हासिल करने के लिए भेजा था। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ने जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में सावियत जातीय नीति की तामील में "यह एक प्रगतिशील कदम" है।\* बहुत से प्रतिनिधियां ने इस बात पर

\* 'तुकिस्तानस्वाया प्राब्दा' अंक १०० (३७७) ८ मई, १९२४।



जोर दिया कि जातीय सीमा निर्धारण से मध्य एशिया की जानियों के आर्थिक और सामूहिक विकास की सम्माननाएँ बहुत बढ़ जायेंगी। एक ताजिक प्रतिनिधि सगिजरायव ने बताया कि अगर यह प्रस्तावित सुधार नहीं किया गया, तो जातीय मतभेदा के कारण समाजवादी निर्माण के काम में बाधा पड़ती रहेगी।\* रूदजुताव ने "मन की लहरा" के आन्दोलन के छतरे से छपरदार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि ऐसे आन्दोलन को 'स्वस्थ कम्युनिस्ट भाग' से विचलित नहीं होने दें।\*\*

### जातीय राज्य सीमा निर्धारण व्यवहार में

१० मई, १९२४ को जातीय सीमा निर्धारण आयोग ने जातीय आयोगों की सिफारिशों पर विचार किया। उसने पूर्ण रूप में उद्देश्य और तुल्यमान जातीय जनतन्त्रा की तथा ताजिक और किर्गिज ओस्तास्तो की स्थापना का समर्थन किया। उसने तुबिस्तान के कजाख इलाका को कजाख स्वा० सो० सं० जनतन्त्र में मितान और एक मध्य एशियाई मध्य स्थापित करने के लिए कजाख जातीय आयोग की सिफारिशों का अस्वीकार कर दिया। इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के मध्य एशियाई व्यूरो ने जातीय सीमा निर्धारण आयोग की सिफारिशों को इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पास भेज दिया।

इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पोलिटब्यूरो ने २ और १२ जून १९२४ को इन सिफारिशों पर विचार किया। १२ जून को उसने मध्य एशिया के जनतन्त्रा के जातीय सीमा निर्धारण के संबंध में एक प्रस्ताव पास कर निम्नलिखित बातों का मुद्दा दिया

१ स्वतंत्र उज्बेक और तुल्यमान जनतन्त्रा का निर्माण किया जाये और एवारजम जनतन्त्रा को उससे तुल्यमान इलाका को अलग करने के बाद, वर्तमान रूप में कायम रखा जाये।

\* वही।

\*\* वही अंक १८१ (४५८) १८ अगस्त १९२४।

२ तुकिस्तान के किगिज़ (यानी कजाख) इलाकों का किगिज़ (कजाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र में मिला दिया जाये।

३ एक स्वायत्त कराकिगिज़ (यानी किगिज़) ओब्लास्त की स्थापना करके उसे रूसी सो० स० म० जनतंत्र में मिला दिया जाये।

४ उज्बेक जनतंत्र के भीतर ताजिकों का एक अलहदा स्वायत्त ओब्लास्त कायम किया जाये।

५ सोवियत संघ की सोवियता की आगामी कांग्रेस में सोवियत संघ तथा स्वतंत्र तुर्कमान और उज्बेक जनतंत्रों के बीच इन जनतंत्रों के संघ में शामिल होने के बारे में संधि की जाये।\*

आगे चलकर एवारज़म भी जातीय सीमा निर्धारण के दायरे में आ गया। एवारज़म की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के कार्यकारिणी ब्यूरो ने २६ जुलाई, १९२४ की अपनी बैठक में एवारज़म के जातीय सीमा निर्धारण के प्रति अपना विरोध का मत बदल दिया।

क्षेत्रीय आयोग ने अपना काम सितम्बर १९२४ में पूरा किया। उस में ममस्त जातियों का समान प्रतिनिधित्व था। १६ सितम्बर, १९२४ को तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के असाधारण अधिवेशन ने सीमा निर्धारण के प्रस्ताव पर अपनी कानूनी महार लगा दी और उज्बेकों, तुर्कमानों, कजाखों, ताजिकों और किगिज़ों को इस जनतंत्र से अलग होने और स्वयं अपना जातीय राजत्व स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। २० और २९ सितम्बर, १९२४ का क्रमशः पाचवीं अखिल-बुखारा और अखिल एवारज़म कुस्तताइयो के अधिवेशन ने भी इन जनतंत्रों में रहनेवाली विभिन्न जातियों का यही अधिकार दिया। १४ अगस्त १९२४ का अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के १६ सितम्बर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और तुकिस्तान स्वा० मो० म० जनतंत्र को रूसी सो० स० स० जनतंत्र से अलग कर

---

\* व० नपोमनिन द्वारा उद्धृत 'उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव', पृष्ठ १६८-१६९।

दिया।\* अखिल रूसी वैद्रीय कायकारिणी समिति ने ताजिक स्वायत्त ओग्लास्त को उजबेक जनतत्व के भीतर एक स्वायत्त जनतत्व का दर्जा देने का निश्चय किया। २७ अक्टूबर १९२४ को सोवियत सघ की वैद्रीय कायकारिणी समिति ने एक परिविधि स्वीकार करके मध्य एशिया के सोवियत जनतत्वों के जातीय सीमा निर्धारण तथा उजबेक सो० स० जनतत्व और तुक्मान सो० स० जनतत्व के सघ में प्रवेश को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार मध्य एशिया का जातीय सीमा निर्धारण सम्पन्न हुआ। मध्य एशिया की जातियाँ को इतिहास में पहली बार अपने जातीय राज्य के गठन का मौका मिला। यह काम सोवियत सत्ता ने कुल मिलाकर सहज ढंग से कर लिया, यद्यपि अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने स्थिति से फायदा उठाना चाहा। उन्होंने जातीय अग्र राष्ट्रवादवाद की भावना को उत्तेजित करने की कोशिश की। उजबेक पूँजीवादी राष्ट्रवादी त्वावरज्म जनतत्व को जातीय सीमा निर्धारण से बचाये रखना चाहते थे। इसी प्रकार वज़ाख पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्वों ने ताशकन्द शहर को उजबेक जनतत्व में देने के फँसले को बदलवाने के लिए अभियान करने की कोशिश की। उनकी माँग थी कि पूरे ताशकन्द और मिर्जाचुल ज़ेरेबो को वज़ाख स्वा० सो० स० जनतत्व में मिला दिया जाये। उजबेक राष्ट्रवादियों की उलट्टे इच्छा यह थी कि सिर-दरिया ओग्लास्त के उन शहरों को जहाँ उजबेकों की बड़ी आबादी थी स्वायत्त शहरों के रूप में संगठित किया जाये। याद रहे कि चिमकन्द और तुकिस्तान शहरों में उजबेकों का बहुमत था परन्तु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कज़ाख बहुमत में थे।

१९२४ में मध्य एशिया की परिस्थितियों में इस प्रकार के जातीय वाद विवाद का उत्पन्न होना वित्कुल स्वाभाविक था। प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी तत्वों का यद्यपि राजनीतिक दमन और किसी हद तक आधिक तौर पर उन्हें कमजोर कर दिया गया था परन्तु वे उस समय तक पूरी तरह लुप्त नहीं हुए थे। भूतपूर्व शोपक वर्गों को उचित मौकों का इंतज़ार था।

\* व० नेपोमनिन द्वारा उद्धृत, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६८-१६९।

भूमि सुधार अभी पूरा नहीं हुआ था और कृषि का सामाहिकीकरण और समाजवादी उद्योगीकरण अभी शुरू नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्व कभी कभी पार्टी में घुस आने में सफल हो जाते थे। परन्तु पार्टी और सोवियत सरकार के लिए यह बात श्रेयस्कर है कि राष्ट्रवादी तत्वों को कभी यह मौका नहीं दिया गया कि विभिन्न जातीय समूहों में घणा की भाँति भड़काए और हिंसा और मारकाट का बाजार गम करें। तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता में फट डालने की पूँजीवादी राष्ट्रवादियों की कोशिशों को विफल करने के लिए जातीय सीमा निर्धारण की योजना के उसूलों के बारे में जनगण को शिक्षित करने के लिए जन अभियान चलाया। जातीय सीमा निर्धारण पर अपने थीसिस में पार्टी ने कहा

“मध्य एशिया की श्रमजीवी जनता को सीखना चाहिए कि अलहदा स्वतंत्र सोवियत जनतंत्रों का निर्माण हमारे सामने अंतिम राष्ट्रीय कार्यभार और ध्येय नहीं पेश करता किसी जाति की श्रमजीवी जनता के जातीय अलगाव और अलहदगी तो और दूर की बात है। जातीय दुश्मनी नहीं, बल्कि सहकारा अंतराष्ट्रीयवाद नये जनतंत्रों के भावी काम का आधार है। जो कोई उलटी बात सोचता है, वह जान या अनजान मजदूरों और किसानों की सत्ता का दुश्मन है।”\*

जातीय सीमाओं का निर्धारण कोई आसान काम नहीं था। जातीय सीमा निर्धारण आयोग को अनेक विवादास्पद इलाकों की जातीय बनावट का अध्ययन करने और वहाँ के जनगण की रूढ़ि मालूम करने के लिए उन जगहों पर जाना पड़ा। सोवियत जातीय जनतंत्रों और स्वायत्त गणराज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का निर्धारण करने में जातीय तत्व निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण था। जातीय राज्य संरचना में उन इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया गया जहाँ एक जातीय समूह के लोग गठित रूप में रहते थे। परन्तु जातीय तत्व के अलावा जातीय जनतंत्रों में गठित

---

\*ख० त० तुसूनोव द्वारा उद्धृत, “मध्य एशिया के जातीय राज्य सीमा निर्धारण के बारे में ” पृष्ठ १८।

इलाके या स्वायत्त ओग्लास्त की जीवन-मदति तथा आधिक अण्डना का भी ध्यान रखा गया। लेनिन न अपनी वृत्ति "राष्ट्रीय प्रश्न पर आलाचनात्मक भ्रम्युक्तिमा" न जहा तब सम्भव हो आवादी की जातीय वनावट के अनसार क्षेत्र व विभाजन की आवश्यकता पर जार देते हुए, यह भी कहा है कि अगरचे आगनी की जातीय वनावट अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है, अगर यह एवमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है, उसके प्रतिरिक्त और भी कारण है।

मध्य एशिया न जातीय सीमा निर्धारण करत समय लेनिन के इस कथन का पालन किया गया। वहा जातीय जनतन्त्रा और स्वायत्त ओग्लास्तो का निर्माण गठित जातीय इलाका के आधार पर किया गया, परन्तु ऐसे अलग अलग इलाके जहा एक जातीय समूह का बहुमत था अगर जो आधिक या भीमोनिक दष्टि न हमारे जातीय समूह के क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे (जस सिर-दरिया ओग्लास्त के बजाय इलाको में उर्रेक शहर) उह आम तौर पर इन्ही न मिला लिया गया। कई ताजिक इलाका का घनिष्ठ आधिक और मास्ट्रिक सग्रा के कारण उर्रेक जनतन्त्र न मिला लिया गया।

जातीय सीमा निर्धारण के कारण मध्य एशिया न भूतपूर्व तीन बहुजातीय राज्या के स्थान पर अनेक एकजातीय राज्य कायम हो गये। इससे जटिल जातीय मुल्की की सुलमाने में काफी आसानी हुई, जो समाजवादी विकास के रास्ते न बाधा बनी हुई थी। पुरानी राजनीतिक और प्रशासकीय सीमाएं बबल जारशाही विजय के समय के सनिक, सामरिक तथा राजनीतिक उद्देश्या का नतीजा थी। और इस कारण उनसे जातीय समस्या और विगडती जाती थी। पुरानी सीमाएं मध्य एशिया के जनगण के जातीय विभाजन का काटती चलती थी और तुकिस्तान, बुखारा और छोवा के पुरान शासन उनका इस्तेमाल करके अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक जातीय समूह का दूसरे से लडाया करते थे। जातीय सीमा निर्धारण से यह स्थिति बदल गई और जातीय शत्रुता का वह आधार ही खिसक गया, जिसपर पूजीवादी राष्ट्रवादी हमेशा पनपते थे।

अगर १९२४ के सीमा निर्धारण से पहले उज्बेको का बड़ा भाग, यानी ६६५ प्रतिशत तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र में रहते थे, मगर उस जनतंत्र की कुल जनसंख्या में उनका अनुपात केवल ४१४ प्रतिशत था, तो सीमा निर्धारण के बाद मध्य एशिया के कुल उज्बेकों का ८२६ प्रतिशत उज्बेक सो० स० जनतंत्र में आ गया जहाँ उनका बहुमत बना—७६१ प्रतिशत। जानिये सीमा निर्धारण से पहले तुक्माना का मध्य एशिया के तीनों जनतंत्रों में से किसी में भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, मगर अब कुल तुक्मानों में ९४२ प्रतिशत तुक्मान सो० स० जनतंत्र में आये और जनतंत्र की कुल जनसंख्या में वे ७१९ प्रतिशत थे। इसी प्रकार ताजिक, जो तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की आबादी का ७७ प्रतिशत और बुखारा जनतंत्र की आबादी का ३१ प्रतिशत थे, उज्बेक सो० स० जनतंत्र के भीतर ताजिक स्वा० सो० स० जनतंत्र में आबादी का ७१२ प्रतिशत थे। मध्य एशिया के समस्त ताजिकों में ७५२ प्रतिशत ताजिक स्वा० सो० स० जनतंत्र में आ गये थे जिसे १९२९ में सघीय जनतंत्र का दर्जा दे दिया गया। किर्गिज, जो तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की आबादी में केवल १०८ प्रतिशत थे, रूसी सो० स० स० जनतंत्र के भीतर नव संगठित कराकिगिज स्वायत्त ओब्लास्त की आबादी का ६६ प्रतिशत थे। मध्य एशिया के सभी किर्गिजों का ८६७ प्रतिशत अब इस स्वायत्त जातीय ओब्लास्त में था जिसे १९२६ में किर्गिज स्वा० सो० स० जनतंत्र बना दिया गया। १९३६ में उस एक सघीय जनतंत्र का दर्जा दे दिया गया। कराकल्पाक में ७९३ प्रतिशत अब किर्गिज (कजाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र के भीतर कराकल्पाक स्वायत्त ओब्लास्त में शामिल थे, जहाँ कुल जनसंख्या में उनका एक ख़ासा बड़ा हिस्सा था—३८१ प्रतिशत। १९३२ में कराकल्पाक स्वायत्त ओब्लास्त का ६० मा० स० स० जनतंत्र के भीतर कराकल्पाक स्वा० सो० स० जनतंत्र बना दिया गया। १९३६ में वह एक स्वायत्त जनतंत्र के रूप में उज्बेक सो० स० जनतंत्र में शामिल हो गया। ६० सो० स० स० जनतंत्र के भीतर किर्गिज (कजाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र में सभी कजाखों का ९३४ प्रतिशत शामिल थे, जो इस

जनतन्त्र की जनसंख्या में ५७४ प्रतिशत थे। १९३६ में वजाख स्वा० सो० स० जनतन्त्र को भी सघीय जनतन्त्र बना दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जातीय सीमा निर्धारण के बाद मध्य एशिया का जातीय नक्शा ज्यादा 'यायोचित' हो गया। पुरानी जातीय भ्रमगतियाँ को दूर करके मध्य एशिया की जातीय समस्या का बेहतर हल ढूँढ़ निवाला गया। इससे जनगण को प्रशासन के अधिक नज़दीक लाकर मध्य एशिया की जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जल्दी दूर करने का स्थायी आधार तैयार हुआ। इससे प्रशासन का अधिक जनवादीकरण आँचा और आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक प्रगति की रफ्तार बहुत तेज हो गई। इसने पंजीवादी राष्ट्रवाद और महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद की जड़ों पर घातक चोट पहुँचाई। विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति को सुनिश्चित करके इसने सोवियत संघ की जातियों के बीच मैत्री और भ्रातृत्व का प्रोत्साहित किया। जातीय संघर्षों का आधार खत्म करके उसने मध्य एशिया की जातियों को समाजवाद के निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में शामिल होने के योग्य बना दिया। संक्षेप में, जहाँ तक मध्य एशिया की जातियों की प्रगति और सुख-समृद्धि का संबंध है, जातीय सीमा-निर्धारण के परिणाम पूणतः सकारात्मक और लाभदायक थे।

मध्य एशिया में १९२४ में जो जातीय राज्य सीमा निर्धारण हुआ, उसका विश्वव्यापी महत्त्व था, खासकर पूर्व के उन देशों के लिए, जिन्हें सामान्य औपनिवेशिक जूएँ से मुक्ति पाने के बाद अपने प्रशासकीय विभाजनों के पुनर्गठन का सवाल खड़ा हुआ था। भारत भी ऐसा ही एक देश था, जहाँ प्रशासकीय पुनर्गठन का सवाल ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक हो गया था। ब्रिटिश शासन-काल का देश का पुराना प्रशासकीय विभाजन औपनिवेशिक कब्जे और उसके दलीकरण की पदावार था और जनसाधारण की इच्छा के विपरीत था।

मध्य एशिया का ऐतिहासिक अनुभव इस बात का सबूत है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो कदम उठाये गये, वे सही थे।

## आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन

### समाजवादी उद्योगीकरण

सावियत सरकार ने सोवियत संघ की जातियाँ में वास्तविक समानता स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। यह एक बहुत कठिन और जटिल कार्य था। वास्तविक समानता कैसे हो सकती थी, जब मध्य एशिया के सावियत जनतंत्रों के पास अभी अपना कोई उद्योग नहीं था, जब उनकी वृत्ति बहुत पिछड़ी हुई थी और लोग अनपढ़ थे?

पार्टी की दसवीं कांग्रेस (१९२१) ने विभिन्न जातियों के बीच वास्तविक असमानता के उन्मूलन का उद्देश्य अपने सामने रखा। पार्टी को गैर रूसी जातियों की श्रमजीवी जनता की सहायता करनी थी ताकि वे सफलतापूर्वक मध्य रूस के स्तर तक पहुँच जायें। बारहवीं कांग्रेस (१९२३) ने भी पिछड़ी हुई जातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर को उँचा करके जातियों के बीच असमानता को दूर करने का आह्वान किया। इस भारी आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को मिटाने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने की और बड़ी संख्या में अत्यंत निपुण विशेषज्ञों की ज़रूरत थी। इतना बड़ा काम इतिहास की एक छोटी सी अवधि में केवल अधिन उन्नत रूसी जनगण की निरादराना सहायता से ही हो सकता था। मध्य एशियाई जनतंत्रों की सहायता नाना प्रकार से—राजनीतिक, वित्तीय, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में—समाजवादी निर्माण की प्रक्रिया में की गई। इस सहायता का मतलब यह था कि रूसी जनगण का कुवानीया दनी और कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि दश उस समय तक गरीब था और



उन्नत पूँजीवादी देशों की तुलना में आर्थिक दृष्टि में काफी कमजोर था। परंतु अपनी अन्तर्राष्ट्रीय कृतव्य पूरा करने के लिए रूसी मजदूर वगैरह इस कुर्बानी के लिए तैयार था।

मध्य एशियाई जनतन्त्रों की सावियत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता उनके आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे भी साल हुए हैं, जब कुछ जनतन्त्रों को उनके खर्च का ८०-९० प्रतिशत मध्य से आर्थिक सहायता के रूप में मिला। मध्य एशिया की औद्योगिक उद्योगों और कृषि के लिए तकनीकी सामान और मशीनें भी दी गईं। अनेक अनुभवों की राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य विशेषज्ञ भी रूस से मध्य एशिया भेजे गये। यह उदार सहायता "गरीब रिश्तेदारों" को अपमानजनक दान नहीं थी। मध्य एशिया के जनगण ने जितनी ही आर्थिक प्रगति की उतनी ही अधिक उन्होंने सोवियत संघ के समाजवादी निर्माण में योगदान दिया। मध्य एशिया में कपास की पैदावार में वृद्धि हुई, तो सोवियत संघ को बाहर से उसके आयात की विल्कुल जरूरत नहीं रही। तुकमान सा० स० जनतन्त्र में तेल तथा तेल की वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा जा द्रुतगति से विकास करनेवाले सोवियत उद्योग के लिए आवश्यक था। सोवियत जनतन्त्रों में सबसेतुम्हरी परस्पर-सहायता और सहयोग से उनकी प्रमत्तता को औद्योगिकीकरण द्वारा करने और उनकी मैत्री को सबल बनाने में सहायता मिली। सोवियत संघ की जातियाँ की इस मैत्री और भ्रातृत्व की ताजी मिसाल ताशकंद को दी गई वह उदार सहायता है, जो अप्रैल १९६६ के भयंकर भूकंप के बाद देश के कोने-कोने से उमड़ पड़ी। विभिन्न सावियत जनतन्त्रों से हजारों स्वयंसेवकों ने उज्बेकिस्तान की राजधानी में नये घरों का निर्माण किया। विरादराना जनतन्त्रों ने ताशकंद में दस लाख वर्ग मीटर गृह निर्माण किया है।

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की तरह समाजवाद के लिए भी एक निश्चित स्तर की उत्पादन शक्तियाँ की एक निश्चित भौतिक तथा तकनीकी आधार की जरूरत थी। समाजवाद के लिए यह आधार बड़े पैमाने का भारी उद्योग है, जो कृषि को मशीनें तथा खाद मुहैया कर सके। बड़े पैमाने के उद्योग के बिना समाजवाद का निर्माण असम्भव है। अतः समाजवादी

अथर्व्यवस्था का निर्माण करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश को सबसे पहले उद्योगीकरण करना होता है।

जैसा कि कहा जा चुका है, आति से पहले मध्य एशिया का उद्योग बहुत अर्धविकसित था। और फिर मध्ययुद्ध में उसका बड़ा नुकसान पहुँचा। १९२८ में ही उद्योग को उसके प्रातिपूर्व स्तर पर पुनः बहाल किया जा सका।\* कृषि की बहाली में भी बड़ी सफलताएँ प्राप्त हुई। कपास की खेती को उसके युद्धपूर्व स्तर पर पुनः स्थापित करने का लक्ष्य १९२७ में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कपास की खेती का कुल क्षेत्र १९१३ में ४२३५ हजार हेक्टर था। १९२८ में वह युद्धपूर्व के स्तर से बढ़कर ५८८५ हजार हेक्टर तक पहुँच गया था।\*\*

मध्य एशिया के श्रमजीवी जनगण ने १९२६-१९२७ में अपने जनतन्त्र का उद्योगीकरण शुरू किया। मार्च १९२७ में उज्बेक सो० सं० जनतन्त्र में सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने सूती कपड़ा उद्योग का निर्माण, कृषि वच्चा सामान को तैयार करने के उद्योग की नई शाखाओं का संगठन, बिजलीकरण की योजना की पूर्ति और कृषि मशीना और औजारों का उत्पादन का संगठन करना जरूरी समझा। १९२७ में उज्बेकिस्तान के उद्योगीकरण की दिशा में प्राथमिक कदम उठाये गये। उस साल वह

---

\* कपास ओटाई उद्योग, जो मध्य एशिया का मुख्य उद्योग था, बहाली की अवधि के अंत में अपने युद्धपूर्व स्तर से कुछ पीछे था (१४७९ हजार टन जबकि १९१३ में १७७८ हजार टन था)। परन्तु तेल और बिजली के उत्पादन में वृद्धि सतोपजनक थी। १९१३ में तुर्किस्तान में तेल का उत्पादन १३२ हजार टन था। १९२७-१९२८ में वह बढ़कर ४७७ हजार टन हो गया, यानी युद्धपूर्व स्तर से ३५ गुना अधिक। बिजली का उत्पादन १९२३ में ३३ लाख किलोवाट घंटे था, वह बढ़कर १९२७-१९२८ में ३४३ लाख किलोवाट घंटे हो गया। ("उज्बेकिस्तान १५ वर्षों के दौरान", ताशकंद, १९३८, पृष्ठ ३७-३९, रूसी संस्करण) ह्योलर का यह कथन कि "मध्य एशिया के उद्योग का उत्पादन (१९२८ में) सब मिलाकर १९१३ के स्तर का लगभग आधा था" स्पष्टतः गलत है और स्थिति को कम करके आकता है (उपरोक्त पुस्तक, पृ० १५९)।

\*\* "उज्बेकिस्तान १५ वर्षों के दौरान", पृष्ठ ५३।

आधिव तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन २७५

विजलीघरो का निर्माण हुआ। मंगिलान और पुराने बुयारा में रेशमी कपड़े की फैक्टरिया लगाई गई। फरगाना में एक कताई-बुनाई फैक्टरी और ताशकन्द में जूते और तम्बाकू फैक्टरिया खोली गई। तेल निस्सारण में भी कुछ प्रगति हुई। भारी उद्योग के विकास के लिए अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा थी।

१९२७-१९२९ के बीच किर्गिजस्तान के उद्योगीकरण के लिए भी कुछ कदम उठाये गये। इस अवधि में विजित किया और मुलूक्तह कोयला खदानों का विस्तार किया गया, करासुव में एक कपास शोधन कारखाना, ओश में एक रेशम फैक्टरी तथा फ्रूजे में दो चमड़े की फैक्टरिया कायम की गई। दो आरा मिले भी खोली गई। इन कारखानों के निर्माण के बावजूद किर्गिजस्तान में १९२९ में औद्योगिक पैदावार का कुल मूल्य केवल २ करोड़ ६० लाख टबल था जबकि १९१३ में २ करोड़ ८० लाख था।\* किर्गिजस्तान के वास्तविक उद्योगीकरण के लिए भी अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना का इंतजार था।

तुर्कमानिस्तान में रेशम-कटाई बुनाई और कताई फैक्टरियों का अशकाबाद में निर्माण किया गया। लगभग उसी समय तुर्कमान सो० स० जनतंत्र के साधना का भगर्भीय सर्वेक्षण शुरू किया गया। तुर्कमान मजदूरों के आधुनिक औद्योगिक उत्पादन में प्रशिक्षण का कार्य तात्कालिक महत्त्व का था, क्योंकि जनतंत्र में उसके अपने देशी औद्योगिक कमियों का बड़ा अभाव था। १९१६ में केवल २४२ तुर्कमान मजदूर थे जिनमें ७ दक्ष मजदूर थे।\*\* इस वर्गी को पूरा करने के लिए तुर्कमान सूती मिलों और तेल कारखाना के मजदूरों को क्रमशः मास्को और बाकू में प्रशिक्षित किया गया।

ताजिकिस्तान में उद्योगीकरण प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ। उससे पहले १९२४-१९२५ में कुछ तेल मिला और विजलीघरों का निर्माण किया गया था।

\* 'सोवियत संघ में समाजवादी जाति का निर्माण', मास्को १९६२, पृष्ठ ४९६। (रूसी संस्करण)

\*\* वही, पृष्ठ ५९७।

मध्य एशिया में उद्योगीकरण का प्रथम महत्वपूर्ण चरण प्रथम पंचवर्षीय योजना ही से शुरू हुआ। पार्टी की चौदहवीं कांग्रेस ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए अपने निदेश में इस बात पर जोर दिया था कि योजना में पिछड़े हुए इलाकों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सवाल पर खास ध्यान देना चाहिए।\* प्रथम योजना मध्य एशिया में वास्तविक औद्योगिक गति की शुरुआत साबित हुई।

नवम्बर १९२७ में उज़्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। उनमें उज़्बेकिस्तान के विकास की योजना पर सम्पूर्ण सोवियत संघ की योजना के एक आवश्यक अंग के रूप में विचार किया। प्रथम योजना का एक मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के वस्त्रोद्योग के लिए कपास में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना ने उज़्बेकिस्तान में कोयला और तेल उद्योगों के विकास की ओर बहुत ध्यान दिया। उसने मध्य एशिया में एक धातुकर्म-उद्योग के निर्माण पर भी जोर दिया। कृषि की पैदावार के उपयोगीकरण से संबंधित अन्य उद्योगों की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। उज़्बेकिस्तान के लिए योजना का पहला प्रारूप जून १९२८ में तैयार हुआ। दूसरा संशोधित प्रारूप मई १९२९ में उज़्बेकिस्तान की सोवियत की तीसरी कांग्रेस में बहस के लिए पेश किया गया। तीसरा और अंतिम प्रारूप जुलाई १९२९ में केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन द्वारा स्वीकृत हुआ।

उज़्बेक सो० सं० जनतंत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारी रकम लगाई गई। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास के लिए २,८८४ लाख रूबल की रकम दी गई, जो जनतंत्र की योजना के अन्तर्गत कुल पूँजी विनियोग का २६ प्रतिशत थी। इससे पहले के चार वर्षों (१९२४-१९२८) की तुलना में वह छह गुना ज्यादा था।\*\*

---

\* "सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव", भाग २, पृष्ठ ३४३।

\*\* श० न० उत्तमस्वायेव, 'सोवियत उज़्बेकिस्तान का औद्योगिक विकास', ताशवन्द, १९३८, पृष्ठ १०८। (रूसी संस्करण)

उज्बेकिस्तान में उस योजना के अंतर्गत जा पूँजी लगाई गई, उसका बड़ा हिस्सा केन्द्र ने दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उज्बेकिस्तान के औद्योगिक विकास का तात्क्षणिक पहलू विजली-उत्पादन, मशीन निर्माण तथा धातुव्यय-उद्योग का विकास था। ताशकन्द में एक कृषि मशीनरी कारखाना बनाया गया, जो जनतंत्र में कृषि, घासकर बपास की खेती की जरूरत की मशीनें तथा अन्य सामान मुहैया करता था। कृषि मशीनों की भरपूरता के लिए भी एक कारखाना खोला गया। आत्मात्मीक ताम्र प्रोसेसिंग प्लांट तथा चिरचिक रामायनिक कारखाने का निर्माण भी प्रथम योजना के ही दौरान हुआ। दूसरी योजना में उनका आगे विकास हुआ और वे अखिल-संघीय महत्व के विशाल औद्योगिक उद्यम बन गये। प्रथम योजना के दौरान दो सीमेट फैक्टरिया भी कायम की गईं। १९३२ में ताशकन्द में एक बड़ा सूती बपड़ा कारखाने का निर्माण शुरू हुआ। बुखारा, फरगाना और मगिलान में रेशम बाटने और कातने की कई फैक्टरिया कायम की गईं। इनके अलावा फल और साग सब्जी की डिब्बाबंदी के भी कई कारखाने खोले गये। १९२८-१९३० की अवधि में खाद्य-पदार्थ उद्योग की कुल पैदावार के मूल्य में २३ गुना, सूती बपड़ा उद्योग में ५६ गुना और रेशम उद्योग में ५४ गुना वृद्धि हुई।\*

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उज्बेक सो० सं० जनतंत्र ने समाजवादी उद्योगीकरण में बड़ी सफलता प्राप्त की। जबकि केन्द्रीय इलाका में तो दो गुना वृद्धि हुई उज्बेकिस्तान में औद्योगिक पैदावार २६ गुना बढ़ी।

ताजिकिस्तान में प्रथम योजना के दौरान मुख्यतः ऐसे उद्योगों का निर्माण हुआ, जिनका संबंध कृषि की पैदावार के विधायन के पहले चरण से था यानी बपास की सफाई, फल और सब्जी की डिब्बाबंदी और रेशम बाटने की फैक्टरिया कायम की गईं। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास में केवल ०० प्रतिशत पूँजी लगाई गई और कृषि में ५० प्रतिशत।\*\*

\* श० न० उत्तमस्वायेव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १२३।

\*\* "साविपत संघ की समाजवादी जाति का निर्माण", पृष्ठ ५३२।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किर्गिजस्तान में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई। प्रथम योजना के अंतर्गत किर्गिजस्तान के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ७७ ७५१ हजार रूबल की रकम लगाई गई। इसमें से आधी से ज्यादा यानी ४०,८७८२ हजार रूबल भारी उद्योगों में लगाये गये।\* ४१ बड़े औद्योगिक उद्यमों का निर्माण किया गया। १९३२ में औद्योगिक उत्पादन का अनुपात कुल उत्पादन का २३.५ प्रतिशत हो गया था।\*\* किर्गिजस्तान में औद्योगिक पैदावार १९२९ की तुलना में चार गुना और १९१३ की तुलना में ६१ गुना बढ़ गयी।\*\*\*

तुर्कमानिस्तान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सूती कपड़ा, रासायनिक तथा खाद्य उद्यमों का निर्माण हुआ। योजना में जनतंत्र की अथर्व्यवस्था में २७,०८ लाख रूबल पंजी लगाने का प्रबंध था।\*\*\*\* यह रकम १९२५-१९२८ की अवधि के पूँजी विनियोग की चौगुना से अधिक थी। कपास की सफाई, सूती कपड़ा, तेल और रेशम की फ़ैक्टरियाँ तथा कृषि की पैदावारों के प्रथम विधायन से संबंधित अन्य उद्यमों का व्यापक पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। योजना ने तेल रासायनिक तथा निर्माण वस्तुओं के उद्यमों जैसे भारी उद्यमों की आधारशिला रखी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कालीन बुननेवाली स्त्रियों का औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में संगठित किया गया और हर सम्भव तरीके से उनकी तकनीकी और वित्तीय सहायता की गई।

---

\* "किर्गिजस्तान का इतिहास", खण्ड २, फ़ूजे १९५६, पृष्ठ १७१। (रूसी संस्करण)

\*\* "किर्गिजस्तान सावियन सत्ता के ३० वर्षों की अवधि में" फ़ूजे, १९४८, पृष्ठ ३७। (रूसी संस्करण)

\*\*\* म० लितुनोम्बकाया, "किर्गिज सा० स० जनतंत्र का बजट और आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास", फ़ूजे, १९५८, पृष्ठ ११। (रूसी संस्करण)

\*\*\*\* "तुर्कमान सा० स० जनतंत्र का इतिहास" अशकाबाद, १९५७, खण्ड २, पृष्ठ ३१५। (रूसी संस्करण)

मध्य एशियाई जनतन्त्रों में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सफलतापूर्वक पूरा किया गया। योजना के दौरान रुम के वैदेशीय ऋणों की तुलना में यहाँ के औद्योगिक विकास की रफ्तार ज्यादा तेज थी। अगर प्रथम योजना के दौरान घुग्ने औद्योगिक इलाकों में औद्योगिक पैदावार का गुना बढ़ी, तो जातीय जनतन्त्रों में बढ़ि की दर ३५ गुना थी।\* योजना के दौरान सोवियत जनगण न समाजवादी प्रतियोगिता में बड़ी सङ्घा में आम मजदूरों की शिरकत के जरिये श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जनगण के तकनीकी और साम्प्रतिक स्तर का सुधारने की हर कोशिश की गई। पार्टी और ट्रेड-यूनियनों के बड़े प्रयत्न के फलस्वरूप आविष्कारकों के आदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। केन्द्र ने मध्य एशियाई जनतन्त्रों के उद्योगीकरण में बड़ी सहायता प्रदान की। उन्हें अत्यंत दक्ष विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गई और इनके अलावा ताशकंद टेक्सटाइल मिल, खिरविक बिजली रासायनिक कारखाने जैसे विशाल औद्योगिक उद्यमों तथा कई बड़े बिजलीघरों के निर्माण के लिए घन सघीय बजट से दिया गया था। जाहिर है कि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पित पूँजी विनियोग के कारण मध्य एशिया के जातीय जनतन्त्रों के बजटों में अचानक घाटे की पूर्ति करना उनके बूते और साधनों में बाह्य की बात थी। १९२६-१९२७ में यानी प्रथम योजना की पूर्ववर्ती के वर्ष में उखेक सो० सं० जनतन्त्र के बजट में तीन करांड रूबल का घाटा था। १९२४-१९२५ के दौरान उखेक सो० सं० जनतन्त्र को १० करोड रूबल सुवमान सो० सं० जनतन्त्र को सात करांड रूबल और किर्गिजस्तान का तीन करांड रूबल से अधिक कम इन जनतन्त्रों के घाटे की पूर्ति के लिए सोवियत सघ के सोवियतखोज के बजट से दी गई।\*\* ताजिकिस्तान में प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ४३५ करोड रूबल पूँजी मधीय बजट से लगायी गई।\*\*\*

\* "सोवियत सघ के अत्यंत व विकास की प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम" मास्को १९३३, पृष्ठ २३६। (रूसी संस्करण)

\*\* घ० अ० गादिमेंको, "मध्य एशिया में सोवियत जातीय राज्यों की स्थापना", पृष्ठ २२३।

\*\*\* वहीं, पृष्ठ २२६।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२ अरब रूबल (प्रथम योजना की २२ गुनी) रकम उज्बेक सो० स० जनतंत्र की अर्थव्यवस्था में लगायी गई।\* योजना के अंतर्गत कुल पूँजी विनियोजन का ४६ प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिए अलग कर दिया गया था (प्रथम योजना में यह २६ प्रतिशत था)। उज्बेक सो० स० जनतंत्र में दूसरी योजना के अंतर्गत उद्योगों में जो रकम लगाई गई, वह १११६ करोड़ रूबल थी।\*\*

दूसरी योजना का उद्देश्य सभी शोषक वर्गों को मिटाना और समाजवाद की स्थापना करना था। उद्योग के क्षेत्र में यह उद्देश्य चार वर्ष तीन महीने में पूरा हुआ और कृषि में लक्ष्य की अधिपूरति हुई। सोवियत संघ में औद्योगिक पैदावार १९१३ की तुलना में ८ गुना और १९२६ की तुलना में ४३ गुना बढ़ गई जबकि पूँजीवादी देश १९२६ की तुलना में मुश्किल से १०२५ प्रतिशत तक पहुँचे होंगे और १९३७ के उत्तरार्द्ध में वहाँ औद्योगिक पैदावार घटन लगी। १९३८ में पूँजीवादी देशों में औद्योगिक पैदावार १९२६ की तुलना में ६० प्रतिशत रह गई थी। परंतु सोवियत संघ में १९३७ की तुलना में ११३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीवादी देशों में उसी साल में १३५ प्रतिशत की कमी हुई।\*\*\*

दूसरी योजना में भारी उद्योगों की ओर बहुत ध्यान दिया गया। इसमें उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र में चिरचिक नदी का बाधन और बिजली शक्ति पैदा करने का लक्ष्य सामने रखा गया था। प्रथम बिजलीघर का निर्माण उसी समय शुरू हुआ, जब पहली योजना पूरी हुई और दूसरी में तुरंत हाथ लगा दिया गया था। इस बिजली शक्ति को इस्तेमाल करके चिरचिक में एक रासायनिक कारखाने का निर्माण पूरा किया गया। आत्मालीक में, जहाँ तांबा निकाला जाता था, ताँबे प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया। कृषि मशीनें बनाने के ताशकन्द कारखाने का विस्तार किया गया और

\* श० न० उरुमस्वायेव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४१।

\*\* "उज्बेकिस्तान का उद्योग, विकास का संक्षिप्त विवरण, १९१३-१९३८", ताशकन्द, १९४१, पृष्ठ १४। (रूसी संस्करण)

\*\*\* "सोवियत संघ के अर्थतंत्र के विकास की दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", मास्को, १९३६, पृष्ठ १२। (रूसी संस्करण)



एक सूती बपटा बाग़छाने का निर्माण दूसरी योजना के दौरान पूरा किया गया। उरखे सो० स० जनतंत्र में औद्योगिक पैदावार का मूल्य १९३२ के ६८४ करोड़ रूपय से बढ़कर १९३७ में १६६८ करोड़ रूपय हो गया (२४ गुना वृद्धि)।\* सूती बपटा उद्योग में इस योजना के दौरान पैदावार ४८ गुना बढ़ी, तेल और गन्ध उद्योग में ७८ गुना बिजली-शक्ति उत्पादन में ३ गुना और धातुकर्म-उद्योग में ५ गुना।\*\*

श्रम की उत्पादनशीलता की वृद्धि के लिए दशवर्षीय भावजनिक आन्दोलन दूसरी योजना की अवधि में शुरू हुआ। आन्दोलन १९३५ के अग्रस्त में दोनबास में गहरा हुआ और वहाँ के एक कोयला मजदूर के नाम पर, जिसने मानव सं १४ गुना अधिक कायला निवाले का रियाज कायम किया था, उस आन्दोलन की ध्याति स्तूपानाव आन्दोलन के नाम से हुई। दूसरी योजना में समाजवादी प्रतियोगिता नई उत्पादन-तकनीक के आधार पर की गई। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर फैल गये। १९३७ तक उरखे सो० स० जनतंत्र में उद्योग में काम करनेवाले ४४ प्रतिशत मजदूर किसी न किसी प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। अगर १९२८ में १४०० इंजीनियर और तकनीकी मजदूर उरखेविस्तान में उद्योग में काम कर रहे थे, तो १९३७ में उनकी संख्या ६,००० तक पहुँच चुकी थी। तकनीकी विद्यालया तथा अन्य संस्थानों में छात्रों की संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक २६,००० हो गई थी।\*\*\* उरखे सो० स० जनतंत्र में उद्योगों में श्रम-उत्पादनशीलता १९१३ की तुलना में चार गुना बढ़ गई थी।\*\*\*\*

अब हम दूसरी योजना के दौरान उरखे सो० स० जनतंत्र की उपलब्धियाँ का खुलासा यहाँ कर सकते हैं। बिजली-शक्ति का उत्पादन जो १९३२ में ६३६ कराट किलोवाट घटे था, १९३७ में बढ़कर २७६२ करोड़ किलोवाट घटे हो गया। १९१३ में केवल ३३ लाख किलोवाट-

\* वही, पृष्ठ ५४।

\*\* वही, पृष्ठ ५५।

\*\*\* श० न० उरखेविस्तान, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १३८।

\*\*\*\* 'उरखेविस्तान १५ वर्षों के दौरान', पृष्ठ ३६।

घटे था। अतः १९१३ की तुलना में ७३ गुना वृद्धि हुई।\* तेल का उत्पादन, जो १९३२ में ४६८ हजार टन था, १९३८ में बढ़कर १९६४ हजार टन हो गया, यानी १९२४-१९२५ की तुलना में ३५८ गुना वृद्धि हुई।\*\* सूती कपड़े की पैदावार १९३२ में ८५ लाख मीटर थी, वह बढ़कर १९३६ में ६१३ करोड़ मीटर हो गई।\*\*\* उज्बेकिस्तान में भारी उद्योग का उत्पादन १९२४-१९२५ की तुलना में १५ गुना बढ़ गया। इसका पैदावार का मूल्य १९३२ में ६३ करोड़ रूबल था और १९३७ में बढ़कर १५१२ करोड़ रूबल हो गया।\*\*\*\* इस प्रकार उज्बेकिस्तान के उद्योगीकरण में बड़ी सफलता प्राप्त हुई और वह एक दशक के भीतर एक शक्तिशाली औद्योगिक जनतंत्र बन गया।

मध्य एशिया के अन्य जनतंत्रों के उद्योगीकरण में भी बड़ी प्रगति हुई। तुर्कमान सो० सं० जनतंत्र में औद्योगिक पैदावार का मूल्य दूसरी योजना के दौरान १२९ करोड़ रूबल से बढ़कर २९३ करोड़ रूबल हो गया, यानी २३ गुना बढ़ गया।\*\*\*\*\* औद्योगिक पैदावार १९२५ में जनतंत्र की कुल पैदावार का २७.९ प्रतिशत थी, वह उससे बढ़कर १९३७ में ६८.९ प्रतिशत हो गई। मगर कृषि की पैदावार उत्पादन की आम वृद्धि के बावजूद ७२.१ प्रतिशत से घटकर ३१.१ प्रतिशत पर पहुँच गई।\*) दूसरी योजना के दौरान तुर्कमान सो० सं० जनतंत्र के आर्थिक विकास की एक विशेषता तेल और रासायनिक उद्योग का द्रुत विकास थी। कृषि बोगाज गोल खाड़ी के खनिज साधनों के उपयोग के साथ रासायनिक उद्योग में बड़ी प्रगति हुई। तेल की पैदावार १९३२ में ३४ हजार टन थी, वह बढ़कर १९३७ में ४५२ हजार टन हो गई (१३ गुना वृद्धि हुई)।\*\*)

\* वही, पृष्ठ ३७।

\*\* वही, पृष्ठ ३८।

\*\*\* वही, पृष्ठ ३९।

\*\*\*\* वही पृष्ठ ३३।

\*\*\*\*\* "दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", मास्को १९३९, पृष्ठ ५३-५४।

\*) "तुर्कमान सो० सं० जनतंत्र के १५ वर्ष", अशवाबाद, १९३९, पृष्ठ ९। (रूसी संस्करण)

\*\*) "दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", पृष्ठ ५३-५४।

आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन २८३

डिगिजल सो० स० जनतंत्र में १९३२-१९३७ में ६१ बड़े औद्योगिक उद्योगों का निर्माण किया गया। स्थानीय कृषि की उपज से सवधित हलके उद्योगों के साथ-साथ कई भारी उद्योगों का भी निर्माण हुआ। १९३५ में ताशा-कुमिर बोयला प्लान पर काम शुरू किया गया। करा वाल्ती चीनी कारखाना और फ्रूजे चमड़ा कारखाना भी उसी अवधि में चालू किये। कश्मिरिस्तान मध्य एशियाई जनतंत्रों का बोयला क्षेत्र बन गया। बोयले ने पैदावार ७२० हजार टन से बढ़कर ८६६ हजार टन हो गई।\*

इसी प्रकार ताजिकिस्तान में भी उद्योगीकरण ने बड़ी प्रगति की। अक्टूबर क्रांति से पहले इस इलाके में आधुनिक उद्योगों का नाम निशान तक नहीं था। प्रथम योजना के अंत तक इस जनतंत्र में १०० के करीब औद्योगिक उद्यम स्थापित हो चुके थे। दूसरी योजना के दौरान यह संख्या और बढ़कर १२५ हो गई। औद्योगिक पैदावार का मूल्य १९३२ के ५१ करोड़ रूबल से बढ़कर १९३७ में १८७ करोड़ रूबल तक, यानी ३७ गुना बढ़ गया।\*\* तेल का उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ा। शुराब बोयला खदानों की तयारी के काम में प्रगति हुई। दुशाबे और इसफारा में सिलवड़ी और चूने के कारखानों का निर्माण हुआ। बर्जाव में एक बड़ा बिजलीघर बनाया गया। दुशाबे की विशाल टेक्सटाइल मिल पर भी काम दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया।

इन जनतंत्रों के आर्थिक ढांचे में बड़े परिवर्तन हुए और उनका सामाजिक आर्थिक रूप इतना बदल गया कि पहचाना नहीं जाता था। समाजवादी उद्योगीकरण के साथ मध्य रूस के इलाकों के और मध्य एशिया के विकास स्तर का फास बड़ी हद तक दूर हो गया और इस समानता के आधार पर जातीय प्रश्न को सफलतापूर्वक हल किया गया। दूसरी योजना की अवधि में पूरे सोवियत संघ में औद्योगिक पैदावार ने गुरुत्व २२०६ प्रतिशत वृद्धि हुई, मगर रू० सो० स० स० स० जातक में गुरुत्व २२०४ प्रतिशत, जबकि सो० स० जनतंत्र में २४३० प्रतिशत और

\* वही, पृष्ठ ५७।

\*\* वही, पृष्ठ ५५।

ताजिकिस्तान में ३५५७ प्रतिशत थी।\* आम तौर से पूँजी विनियोग की दर भी मध्य एशिया के जनतंत्रों में सोवियत संघ से अधिक थी। दूसरा योजना के दौरान जहाँ इसमें सोवियत संघ में २८ गुना वृद्धि हुई, वहाँ उज्बेक सो० सं० जनतंत्र में ३८ गुना हुई।\*\* मध्य एशियाई जनतंत्रों के बड़े उद्योगों में मजदूरों की संख्या में १९३२-१९३७ में ५६५ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों में यह वृद्धि २२२ प्रतिशत थी।

### समुचित क्षेत्रीय विकास

ज० ह्वीलर ने इस बात की चर्चा करते हुए कि मध्य एशिया का ६० प्रतिशत कपास सूत के रूप में सोवियत संघ के अन्य भागों में भेजा जाता है, मध्य एशियाई अर्थव्यवस्था के “अपनिवेशिक” स्वरूप का उल्लेख किया है।\*\*\* परन्तु इससे सोवियत मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था का एकांगी “अपनिवेशिक” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, जसा कि मालूम है, कपड़ा उद्योग में ही नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि इसका प्रयोग मोटर-कार और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है और इनके विकास की अधिक अनुकूल परिस्थिति सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों में है। कपास के सूत का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के अन्य भागों में सूती कपड़ा धारणाना में भेज दिया जाता है, क्योंकि मध्य रूस के इलाकों

\* “दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम”, पृष्ठ ११४।

\*\* “उज्बेकिस्तान के अर्थतंत्र का इतिहास”, खण्ड १, ताशकंद, १९६२, पृष्ठ २७३। (रूसी संस्करण)

\*\*\* ज० ह्वीलर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्वीलर इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहते कि उज्बेकिस्तान, जिसकी जन संख्या सोवियत संघ की कुल जन-संख्या का ४६ प्रतिशत है, संघ का १५ प्रतिशत गन्ध, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ५० प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग का सामान, ७२ प्रतिशत कपास-मफाई सामान तथा १०० प्रतिशत कपास चुनने की मशीनें पैदा करता है।

का प्राप्ति के पहले ही सूती कपड़ा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। मध्य एशिया अपनी कपास केवल रूस ही में नहीं, बल्कि समाजवादी देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के अंतर्गत पोलैंड और चेकोस्लावाकिया में भी भेजता है। हमारे अलावा अगर मध्य एशिया की कपास की सारी पदावार की छपत स्थानीय कारखाना में ही कर ली जाये, तो हमारे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जायेगा और यह उद्योग की श्रम १०० शाखाओं को, जो आज वहाँ हैं, निवसित करने की सम्भावना से वंचित हो जायेगा। आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यंत विकसित पंजाबादी देश में भी कपास उत्पादक राज्यों का औद्योगिक विकास सूती कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है और उनकी कपास का बड़ा हिस्सा श्रम राज्यों का भेजा जाता है।

मध्य एशिया से कपास की बड़ी मात्रा के निर्यात का यह मतलब नहीं कि वहाँ सूती कपड़ा उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। उदाहरण स्वरूप सो. सं. जनतंत्र ने १९५८ में देश के कुछ सूती कपड़े के ४ प्रतिशत का उत्पादन किया।\* कपड़े का प्रतिव्यक्ति सालाना उत्पादन सोवियत संघ में २५ मीटर और उत्तरेकिसान में २७ मीटर था।\*\*

इसी तरह हॉलर का यह कहना भी सही नहीं है कि १९५७ में पशुओं की सख्या प्रातिपूव की तुलना में केवल १७ प्रतिशत अधिक थी,

\* "१९६१ में सोवियत संघ का अथतः", मास्का, १९६२, पृष्ठ २५२। (रूसी संस्करण)

\*\* यह सही है कि उत्तरेक सो. सं. जनतंत्र में सूती कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन हाल के वर्षों में कुछ गिर गया है। १९६६ में वह २१ ३ मीटर था। इसका कारण यह है कि एन आर सूती कपड़ों की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई है और दूसरी ओर शुद्ध और कृत्रिम रेशम की मांग तथा सिनथेटिक कपड़ों की मांग उड़ी है। रेशमी कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन १९५० में १४ मीटर से बढ़कर १९६० में २८ मीटर और १९६६ में ४ मीटर हो गया। ("५० वर्षों की अवधि में उत्तरेक सो. सं. जनतंत्र का अथतः", तशवन्द, १९६७, पृष्ठ ५३, रूसी संस्करण)।

ताजिकिस्तान में ३५५७ प्रतिशत थी।\* ग्राम स्तर से पूँजी विनियोग की दर भी मध्य एशिया के जनतंत्रों में सोवियत संघ से अधिक थी। दूसरी योजना के दौरान जहाँ इसमें सोवियत संघ में २८ गुना वृद्धि हुई, वहाँ उज्बेक सो० सं० जनतंत्र में ३८ गुना हुई।\*\* मध्य एशियाई जनतंत्रों के बड़े उद्योगों में मजदूरों की संख्या में १९३२-१९३७ में ५६५ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों में यह वृद्धि २२२ प्रतिशत थी।

### सतुलित क्षेत्रीय विकास

ज० ह्वीलर ने इस बात की चर्चा करते हुए कि मध्य एशिया का ६० प्रतिशत कपास सूत के रूप में सोवियत संघ के अन्य भागों में भेजा जाता है, मध्य एशियाई अर्थव्यवस्था के “औपनिवेशिक” स्वरूप का उल्लेख किया है।\*\*\* परन्तु इससे सोवियत मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था का एकांगी “औपनिवेशिक” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, जसा कि मालूम है, कपड़ा उद्योग में ही नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि इसका प्रयोग मोटर कार और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है और इनके विकास की अधिक अनकूल परिस्थिति सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों में है। कपास के सूत का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के अन्य भागों में सूती कपड़ा कारखानों में भेज दिया जाता है, क्योंकि मध्य रूस के इलाकों

\* “दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम”, पृष्ठ ११५।

\*\* “उज्बेकिस्तान के अर्थतंत्र का इतिहास” खण्ड १, ताशकंद, १९६२, पृष्ठ २७३। (रूसी संस्करण)

\*\*\* ज० ह्वीलर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्वीलर इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं बहते कि उज्बेकिस्तान, जिसकी जन संख्या सोवियत संघ की कुल जन-संख्या का ४६ प्रतिशत है, संघ का १५ प्रतिशत भूस, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ५० प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग का सामान, ७२ प्रतिशत कपास-मफाई सामान तथा १०० प्रतिशत कपास चुनन की मशीनें पैदा करता है।

का क्रांति के पहले ही सूती कपड़ा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। मध्य एशिया अपनी कपास केवल रूम ही में नहीं, बल्कि समाजवादी देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के अंतर्गत पोलैंड और चेकोस्लावाकिया में भी भेजता है। इससे अलावा अगर मध्य एशिया की कपास की सारी पैगावार की खपत म्यानीय बाखाना में ही कर ली जाये, तो इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जायेगा और वह उद्योग की श्रम १०० शाखाओं को, जो आज वहां है, विकसित करने की सम्भावना से वंचित हो जायेगा। आखिर संयुक्त राज्य अमरीका जैसे अत्यंत विकसित पूँजीवादी देश में भी कपास उत्पादक राज्यों का औद्योगिक विकास सूती कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है और उनकी कपास का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को भेजा जाता है।

मध्य एशिया से कपास की बड़ी मात्रा के निर्यात का यह मतलब नहीं कि वहां सूती कपड़ा उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। उज्बेक सो० सं० जनतंत्र ने १९५८ में देश के कुल सूती कपड़े के ४ प्रतिशत का उत्पादन किया।\* कपड़े का प्रतिव्यक्ति सानाना उत्पादन सोवियत संघ में २५ मीटर और उज्बेकिस्तान में २७ मीटर था।\*\*

इसी तरह हंगेरि का यह कहना भी नहीं है कि १९५७ में पशुओं की संख्या नातिपूव की तुलना में केवल १७ प्रतिशत अधिक थी,

\* "१९६१ में सोवियत संघ का अद्यतन", मास्को, १९६२ पृष्ठ २५२। (रूसी संस्करण)

\*\* यह सही है कि उज्बेक सो० सं० जनतंत्र में सूती कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन हान के वर्षों में कुछ गिर गया है। १९६६ में वह २१३ मीटर था। इसका कारण यह है कि एक ओर सूती कपड़ों की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई है और दूसरी ओर शुद्ध और कृत्रिम रेशम की मांग तथा सिन्थेटिक कपड़ों की मांग बढ़ी है। रेशमी कपड़ा का प्रतिव्यक्ति उत्पादन १९५० में १४ मीटर से बढ़कर १९६० में २८ मीटर और १९६६ में ४ मीटर हो गया। ('५० वर्षों की अवधि में उज्बेक सो० सं० जनतंत्र का अद्यतन', तशकंद १९६७ पृष्ठ ५३, रूसी संस्करण)।

जबकि जनसंख्या में ७५ प्रतिशत वृद्धि हो गई थी।\* उनका दावा है कि जाति से पहले के मुकाबले में पशुओं की प्रतिव्यक्ति संख्या कम हो गई थी। पशुओं की संख्या १९१६ के २९ लाख से बढ़कर १९५९ में ३७ लाख हो गयी थी, यानी २७ प्रतिशत, और भेड़-बकरी में ७७ प्रतिशत वृद्धि हुई थी।\*\*

पशुओं की संख्या में वृद्धि की तुलना जन-संख्या में ग्राम वृद्धि से नहीं, बल्कि कृषि आवादी में वृद्धि से करनी चाहिए, जिसमें मध्य एशिया में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई, यद्यपि इसका अनुपात १९१३ में ८१ प्रतिशत से घटकर १९५९ में ५५ प्रतिशत हो गया।\*\*\* यह बात भी याद रह कि व्यापक पशुपालन खानाबदोश अव्यवस्था से (खासकर किर्गिजस्तान और तुर्कमानिस्तान में) आवासित कृषि में सन्मरण का प्रभाव मध्य एशिया के किसानों की अव्यवस्था में पशुओं के महत्व पर और उनकी वृद्धि की दर पर पड़ा। इसके अलावा पशुओं की संख्या में वृद्धि या कमी से अपन आप कोई बात सिद्ध असिद्ध नहीं होती, जबतक पशुओं की उत्पादित तथा कृषि में उनके सानुपातिक भाग पर विचार नहीं किया जाये। मध्य एशिया में पशुओं की उत्पादित में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भेड़ों से इन निकालने में औसतन मध्य एशिया का स्थान सप्ताह के सबसे अनुशा देशों में है। जैसा कि ज्ञात है पशुओं की कुल संख्या में सप्ताह में प्रथम स्थान भारत का है (१७.५६ करोड़), परन्तु उत्पादित के मामले में उसका स्थान सबसे पीछे है। फिर, मध्य एशिया में कृषि शक्ति में पशुओं का सानुपातिक हिस्सा ६०.७० प्रतिशत से लगभग शून्य पर पहुँच गया है। १९६३ में कृषि में १.३५ करोड़ अश्व शक्ति ऊँचा का प्रयोग हुआ, जिसमें केवल २ लाख अश्व शक्ति पशुओं द्वारा प्राप्त हुई।\*\*\*\* १९६३ में मध्य एशिया के खेतों में १३० हजार ट्रैक्टर काम कर रहे थे।

\* ज० ह्वीजर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६१।

\*\* '१९६१ में सावित्त सच का अद्यतन', पृष्ठ ३८४।

\*\*\* "१९६३ में मध्य एशिया का अद्यतन", ताशकन्त १९६४ पृष्ठ ८।  
(रूसी संस्करण)

\*\*\*\* वही, पृष्ठ १८१।



पूरे सोवियत संघ तथा मध्य एशियाई जनतंत्रों के औद्योगिक उत्पादन में बड़ा अंतर नहीं है। उज्बेकिस्तान में कुल उत्पादन में उद्योग का हिस्सा ७३ प्रतिशत और कृषि का २७ प्रतिशत है, जबकि पूरे संघ के लिए ये आंकड़े क्रमशः ८० प्रतिशत और २० प्रतिशत हैं।\* परन्तु मध्य एशिया में प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन पूरे सोवियत संघ के प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का नगभन आधा है (पूरे सोवियत संघ की तुलना में प्रतिव्यक्ति उत्पादन उज्बेकिस्तान में ५२.५ प्रतिशत, तुर्कमेनिस्तान में ५०.२ प्रतिशत, किर्गिजस्तान में ४२.१ प्रतिशत और ताजिकिस्तान में ४६ प्रतिशत है।)\*\* इस "पीछे रहने" के दो कारण हैं। इसका पहला कारण है उस भयंकर आर्थिक असमानता के अवशेष, जो जारशाही औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप चौथे दशक के आरम्भ तक मौजूद थे। सोवियत पंचवर्षीय योजनाओं ने शुरू ही से मध्य एशिया में औद्योगिक विकास-स्तर को ऊंचा करने की चेष्टा की। युद्धोत्तर वर्षों में इस दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। १९५० और १९६३ के बीच सोवियत संघ की कुल औद्योगिक पैदावार ३९४ प्रतिशत बढ़ी, जबकि मध्य एशिया में ५३० प्रतिशत बढ़ी।\*\*\* आठवीं पंचवर्षीय योजना (१९६६-१९७०) में मध्य एशिया के लिए नियोजित वृद्धि दर पूरे सोवियत संघ में अधिक थी। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में उज्बेकिस्तान में ६० प्रतिशत, किर्गिजस्तान में ७० प्रतिशत वृद्धि हुई (सोवियत संघ में ४६.४६ प्रतिशत)।

नवीं पंचवर्षीय योजना (१९७१-१९७५) ने मध्य एशिया के जनतंत्रों के लिए औद्योगिक विकास की तेज गति को कायम रखा है। समस्त सोवियत संघ में ४२-४६ प्रतिशत के औसत की तुलना में उज्बेकिस्तान

\* "४० वर्षों की अवधि में सोवियत उज्बेकिस्तान का विकास", ताशकन्द, १९६४, पृष्ठ २८ और '१९६१ में सोवियत संघ का अर्थतंत्र', मास्को, १९६२, पृष्ठ ७६। (रूसी संस्करण)

\*\* "युद्धोत्तर अवधि में सोवियत संघ के समाजवादी अर्थतंत्र का विकास", मास्को, १९६५, पृष्ठ ५१६। (रूसी संस्करण)

\*\*\* वही, पृष्ठ ५१८, "१९६३ में मध्य एशिया का अर्थतंत्र", पृष्ठ २३।

गयी और ५ गुना अधिक निजलौ शक्ति का प्रयोग हो गया। इन सब कारवाइयों के फलस्वरूप कृषि की लाभकारिता लगभग उतनी ही हुई जितनी उद्योग की है और सभी सोवियत जनतन्त्रों की राष्ट्रीय आय का स्तर कमोवेश समान हो गया।

परन्तु अखिल-संघीय स्तर की तुलना में इस सीमित "पीछे रहने" के बावजूद सोवियत मध्य एशिया न गत ४० वर्षों में बड़ी प्रगति की— औद्योगिक उत्पादन के उस स्तर से, जो तुर्की से पीछे था और लगभग भारत के स्तर के समान था, वह एक विकसित औद्योगिक देश के स्तर पर पहुँच गया है। १९६१ में सोवियत मध्य एशिया न, जिसकी जन-संख्या १५ करोड़ है, पूरे संसार के औद्योगिक उत्पादन का ०.७ प्रतिशत पैदा किया। परन्तु भारत ने, जिसकी जन-संख्या संसार की १९ प्रतिशत है, केवल १२ प्रतिशत किया। उसी अवधि में उज़्बेकिस्तान न जिसकी आबादी संसार की ०.३० प्रतिशत है संसार के औद्योगिक उत्पादन का ०.४५ प्रतिशत पैदा किया।

१९५७ में यूरोप के लिए आर्थिक आयोग द्वारा प्रकाशित 'सोवियत संघ में क्षेत्रीय आर्थिक नीति' की रिपोर्ट में मध्य एशियाई जनतन्त्रों तथा मध्य एस के उन्नत क्षेत्रों के विकास स्तर का खाई को दूर करने की दिशा में दो पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र करने की चेष्टा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य एशिया का उद्योग १९२६ में बहुत छोटा था और जितने वर्षों में जितनी प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया गया है (१९२६ से १९४० तक बारह गुना से अधिक), वह एक ऐसे देश के लिए, जो पुनर्निर्माण के दौर से गुज़र रहा हो, या औद्योगिक विकास की प्राथमिक अवस्था में हो, कोई अनोखा कारनामा नहीं है। एक और मिमाल ली जाय, पाकिस्तान में १९५० से १९५६ तक\* छह वर्षों

\* ज० ह्वीलर द्वारा उद्धृत उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५६ २६८  
प्रतिशत (Statistical Year Book, United Nations New York, 1958)  
और ३६१ प्रतिशत (Economic Survey and Statistics for 1958—1959  
Karachi)

यूरोप की दो पूँजीवादी शक्तियाँ व बीच मडियों के लिए, उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए, ससार का बटवारा करने के लिए सघर्ष की स्थिति में मध्य एशिया के कमज़ार सामंती खान प्रशासित राज्यों के लिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना असम्भव था। ज़ारशाही रूस ने मध्य एशिया का समामेलन करके वहाँ के लोगों को साम्राज्यवादी ब्रिटेन के घगुल में फँसने से बचा लिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ज़ारशाही साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद से किसी तरह बेहतर था। सच तो यह है कि दो प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यों में किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। दोनों का एक ही उद्देश्य था—मध्य एशिया के लोगों का शोषण करना और उनको गुलाम बनाना। परंतु भेद का कारण निहित था रूसी साम्राज्य की परिस्थिति के विशेष स्वरूप में साम्राज्यवादी देश तथा उपनिवेश की आम जनता के विशेष राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों में, रूसी जनगण और रूसी साम्राज्य के सीमावर्ती जनगण की भौगोलिक निकटता में। इससे विपरीत भारत के जनगण अंग्रेज़ मजदूरों या किसानों से कभी मिल नहीं सकते थे। वे केवल औपनिवेशिक अधिकारियों—गोरे साहबों—को ही जानते थे।

ज़ारशाही के साम्राज्यवादी औपनिवेशिक उद्देश्यों के बावजूद रूस ने मध्य एशिया का समामेलन “इतिहास की दृष्टि से” निस्संदेह वस्तुतः प्रगतिशील था। पूँजीवाद के सारे नकारात्मक तथा स्याह पहलुओं के बावजूद मध्य एशिया के समामेलन के बाद पूँजीवादी संबंधों की उत्पत्ति प्रगतिशील थी। इससे कारण उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ और मजदूर वर्ग ने जन्म लिया। अगर ब्रिटेन का कब्जा हो गया होता तो मध्य एशिया के लोगों को रूसी जनगण के करीब आन का मोका नहीं मिलता, जो उनके भावी ऐतिहासिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। औपनिवेशिक इलाक़ों के श्रमजीवी जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का रूस के मजदूरों के आतंककारी आंदोलन के साथ एक धारा में मिल जाना वास्तव में मध्य एशिया पर ज़ारशाही के कब्जे का एक महान प्रगतिशील परिणाम था।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सिक्याम को मध्य एशिया के खिलाफ आक्रमण का अड्डा बनाने की चेष्टा की। वे चाहते थे कि परगना घाटी में अपना असर फैलाने के लिए याकूब खेग के राज्य का इस्तेमाल करे। काशगर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुर्की के सुलतान के धार्मिक प्रभाव से भी फायदा उठाया। अपनी बळपुतली याकूब खेग के पतन तथा उसके राज्य पर चीनियों का कब्जा हो जाने के बाद अंग्रेजों ने चीनियों को रियायते देने की नीति अपनायी, क्योंकि वंजारशाही हंस के खिलाफ अपनी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे।

अक्तूबर शांति ने मध्य एशिया की जातियों के जीवन में एक नए युग का प्रारम्भ किया। उसने अतीत में वंजारशाही द्वारा उत्पीड़ित जातियों को वास्तव में स्वतंत्र और समान बनाया, उन्हें राजनीतिक समानता और राजत्व ही प्रदान नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का दूर करने का अवसर भी दिया। सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पीड़न और असमानता का उन्मूलन किया और बड़ी तथा छोटी जातियों के बीच मैत्री और विरादराना सह्या की बुनियाद डाली। इस स्थिति में राष्ट्रीय समस्या का अत्यंत उल्हासपूर्ण समाधान हुआ।

सोवियत मध्य एशिया में जीवन-स्तर, सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, संचार और उत्पादन का स्तर अधिराश अभीकी और एशियाई दशा से बहुत ऊंचा है।

सोवियत शासन द्वारा मध्य एशिया के जनगण व जीवन में अठ्ठा शताब्दी व ऐतिहासिक दृष्टि से कम समय में खबरदशा सामाजिक-भारत तिक तब्दीली हा गयी है। सामाजिक रूपांतरण की सोवियत विधिया और तरीका, उनके परिणामा तथा उनके प्रति जनगण की प्रतिनियामा और अनुचारा का अध्ययन सभी नवम्वाधीन अनीकी और एशियाई दशा व लिए बहुत ही दिलचस्प और लाभदायक हागा, क्योंकि य दशा भी म्नात राष्ट्रीय विवात के माग पर सामाजिक परिवारा की व्यापक प्रशिया में गुजर रह हैं। मध्य एशिया में पुरान स नय में परिवर्तन आगान तः।

या। कभी-कभी गलतिया और कुछ ज्यादातिया भी हुईं। परन्तु इसको स्वीकार करने का मतलब इससे इनकार करना नहीं है कि जो तथ्योलिया हुई, व बड़ी हद तक जनगण की अपनी इच्छा और मर्जी से की गयी थी।

मध्य एशिया के जनगण की इन महान सफलताओं का श्रेय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था, नियोजित आर्थिक विकास तथा सोवियत जातिया की मंत्री और परस्पर सहायता को है। मध्य एशिया की जातिया का ऐतिहासिक अनुभव विश्वव्यापी महत्त्व का है। इतिहास में वे पहली जानिया थी, जिन्होंने पूँजीवादी विकास की पीड़ाओं में गुजर बिना समाजवाद का रास्ता अपनाया। आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों के लिए पूँजीवादी विकास का रास्ता दुःख और पीड़ा का रास्ता है। इससे पिछड़ापन और दरिद्रता कायम रहती है। सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के ऐतिहासिक अनुभव न साबित कर दिया है कि एकमात्र समाजवादी विकास का रास्ता ही इन देशों के लिए तेजी से प्रगति करने का रास्ता है। सोवियत मध्य एशिया के जनतंत्र पूर्व में समाजवाद के प्रकाश-स्तम्भ हैं, जो करोड़ों जनगण के लिए शांति और समाजवाद के मध्य का मार्ग उज्ज्वल कर रहे हैं।

कुछ पश्चिमी लेखकों ने सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के शांतिपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में समाजवादी व्यवस्था के महान योगदान का नजरअंदाज करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए, अमरीकी विद्वान रिचर्ड अ० पियस न टिप्पणी की है

“ये उपलब्धिया अवश्य ही वास्तविक हैं, परन्तु सिकके की दूसरी तरफ भी है। पहली बात यह कि यह विकास बड़ी हद तक शायद सोवियत व्यवस्था के बिना ही हो जाता क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती जाती है और प्रगति किसी एक व्यवस्था का इजारा नहीं है।”\*

लेकिन सोवियत मध्य एशिया के जनतंत्रों की प्रगति के स्तर का मुकाबला पड़ोस के मुस्लिम राज्यों से किया जाये, तो इसमें कोई सन्देह

नहीं रहेगा कि व्यवस्था का महत्त्व बहुत है। पिछले जमाने में तुर्की मध्य पूरव का सबसे शक्तिशाली राज्य था। १९१७ से पहले वह कई लिहाज से मध्य एशिया से आगे था। मध्य एशियाई राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के नेता उसे एक आदर्श राज्य तथा अनुकरणीय उदाहरण मानते थे। परन्तु तुर्की आज तक एक कृषिप्रधान देश है। उसकी राष्ट्रीय आय में उद्योग का हिस्सा दसव भाग से कुछ ही अधिक है। तुर्की लगभग केवल कृषि की उपज का निर्यात करता है, आयात मुख्यतः मशीन और अन्य औद्योगिक सामान का होता है। परन्तु समाजवाद की विजय न सोवियत मध्य एशिया के जनतन्त्रा को उनका औद्योगिक कृषिक क्षेत्र बना दिया है। अन्य सघीय जनतन्त्रा तथा विदेशों को उनका निर्यात कृषिक उपज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मशीनें और औद्योगिक सामान भी शामिल हैं। उज्बेकिस्तान में १९६२ में बिजली का प्रति-यक्ति उत्पादन तुर्की का लगभग सात गुना था। अन्य देश—ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान—अभी मध्य एशिया के मुकाबल में तुर्की से भी अधिक पीछे हैं।

सावियत एशिया की पिछड़ी हुई जातियाँ की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का कारण एडवर्ड बेंकशा\* और सीटन वाट्सन जैसे लोग इस तथाकथित "सत्र-न्यायी नियम" में दूढ़ने का प्रयास करते हैं कि साम्राज्यवाद सदा भौतिक प्रगति का वाहक होता है। कहा गया है कि साम्राज्यवादी राम ने यर्राप का फायदा पहुँचाया और ब्रिटिश ने अफ्रीका का। (अवश्य ही मलान, राय बलस्की, फेरबुड और स्मिथ जैसे लोग अफ्रीकी जातियों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अनमान भट है!) सीटन वाट्सन सावियत सत्ता और ब्रिटिश साम्राज्य की भौतिक उपलब्धियों के अंतर के दो कारण बताता है। एक यह कि हमी साम्राज्य की गरमा-जातियाँ सम्भन्ता के अपने आम स्तर की दृष्टि से अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों और भारत तक की भी जातियों में अधिक उन्नत थीं। (गया

---

\* Foreword to *Communism and Colonialism* by Walter Kolarz London New York 1964 p XIV

बदोश किंगिज, कज़ाख और तुक्मान, जिनकी अपनी भाषाओं की क्रांति से पहले कोई लिपि भी नहीं थी, भारत के बंगालियों और तामिला से, जिनके साहित्य की परम्परा सैंकड़ा वर्ष पुरानी है, अथिक् उन्नत थे। ) दूसरा कारण था शामक देश के लोगो तथा औपनिवेशिक जातिया के अनुपात म फर। सीटन वॉटसन के अनुसार रूसिया और मध्य एशियाई मुसलमानो का अनुपात १५ का था, जबकि अग्रेजो और उनकी एशियाई और अफ्रीकी रिआया का अनुपात १५० का था।\* परंतु भौतिक प्रगति के प्रश्न का सारतत्व गोरे और वाले लोगो की सख्या का अनुपात नहीं, बल्कि यह है कि लोग किस सामाजिक व्यवस्था में जीवन व्यतीत करते और काम करते हैं।

सोवियत युग में मध्य एशिया के जनगण ने, जो पहले ज़ारशाही रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में शतरंज के मोहरा की तरह थे, अब स्वयं अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया है। एशिया के पड़ोसी देशों से उनका बिलगाव अब अतीत की बात हो गई है और अब वे उनसे तथा ससार के अन्य देशों से सफलतापूर्वक गहरे दोस्ताना संबंध विकसित कर रहे हैं। मध्य एशिया के मुख्य शहरों के अनेक कारखाने और प्लांट ऐसा सामान और मशीनें पैदा कर रहे हैं जिनसे भारत, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान, बर्मा और नेपाल जैसे देशों के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। अनेक अफ्रोएशियाई और लैटिन अमरीकी दशों के नौजवान विशेषज्ञ ताशकंद में प्रशिक्षित हो रहे हैं। ताशकंद सारी दुनिया के लेखकों, प्राच्यवेत्ताओं, फिल्मनिर्माताओं, सांख्यिक स्वास्थ्यकर्मियों, पौधे उपजानेवालों तथा सहकारिता विशेषज्ञों का मिलन स्थान बन गया है। अफ्रोएशियाई लेखकों का पहला सम्मेलन अक्टूबर १९५८ में ताशकंद में ही हुआ था। और फिर यही अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन सेमिनार, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिक्षा पर गोष्ठी, उष्णदशोष्ण रागा के संबंध में सम्मेलन, शुष्क इलाकों के अध्ययन के लिए यूनेस्को सलाहकार समिति का अधिवेशन तथा महिलाओं की शिक्षा के सवाल पर एशियाई

और अफ्रीकी देशों की महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था।

ताशकन्द घोषणापत्र जिसके जरिये दो एशियाई दशा—भारत और पाकिस्तान—में शान्ति स्थापित हुई, इस बात का शानदार सबूत है कि मध्य एशिया के लोग अपने दो महान एशियाई पड़ोसियों के बीच सामान्य सवध पुनः स्थापित करने में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उज्ज्वल जनगण ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के सम्मेलन की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण कायम करने का पूरा प्रयत्न किया। अनेक मध्य एशियाई राजनीतिज्ञ और जन नेता जैसे शरफ रशीदोन, मिर्जा तुसुन जादा और बाबाजान गफूराव अफ़ा एशियाई एकजुटता, राष्ट्रीय मुक्ति तथा विश्वशक्ति के आन्दोलनों में प्रमुख भाग ले रहे हैं। स्वतंत्र और समान साक्ष्यित जातियों की विरादरी में मध्य एशिया की जातियाँ धीरे-धीरे उस स्थान पर पहुँच रही हैं, जहाँ वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभा सकें। इस प्रक्रिया का सभी शांतिप्रेमी एशियाई दशा, खासकर भारत द्वारा सक्रिय समर्थन और हार्दिक स्वागत किया जाता है। भारत के लोगों के मन में मध्य एशिया की जातियों के प्रति सदा ही मैत्रीपूर्ण सदभावना रही है।

### पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और डिज़ाइन सम्बन्धी आपकी विचारों के लिए आपका अनुगृहीत होगा। आपका अर्थ सुझाव प्राप्त कर भी हम बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारा पता है

प्रगति प्रकाशन, २१, जून्सकी बुलवार,  
माम्बा, साखियन सघ।







उही विशेष ध्यान उन वर्ग २१  
 तर्कालिया-सामंती अवस्था ने पूजी को  
 छाड़त हुए समाजवादी समाज में रन मण  
 की विशेष प्रक्रिया-की आर दि जा  
 इन जनतंत्रा में पिछले पचाम वर्षों में हुई है।  
 लेखक ने बताया है कि हसी जलमण नया  
 सावियन मध्य की मध्य विमाना जातिमा  
 की सहायता से इन इलारा का जो पहले  
 जारगाही रूप के पिछड़े हुए, श्रीपनिवेशिक  
 सीमावर्ती इलाके थे, वैसे रूपांतरण हुआ और  
 वे वस बहुत कम समय में स्वतंत्र, और  
 उनमें समाजवादी जनतंत्र बन गये जहाँ  
 विविध उद्योग, मशीनीकृत कृषि है और  
 विज्ञान और संस्कृति में बड़ी प्रगति की है।

दक्कन कौशिक ने तथ्यों के आधार पर  
 सावियत मध्य एशिया के इतिहास के बारे में  
 जेफ्री ह्वीलर रिचर्ड पाइप्स और मीटन  
 वाटसन जैसे पूजीवादी इतिहासविदों के विवृत  
 विचारों का खंडन किया है।

सावियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के  
 इतिहास और वर्तमान जीवन की जानकारी  
 प्राप्त करने में अपने पाठकों की सहायता  
 करके लेखक ने सोवियत संघ और भारत के  
 लोगों में एक दूसरे की समझ सांस्कृतिक  
 समीपता और मैत्री स्थापित करने में बहुमूल्य  
 योगदान किया है।